छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **तृतीय सत्र**

मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024

(श्रावण 01, शक सम्वत् 1946)

[अंक 02]

webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024

(श्रावण 1, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी 4 इंच खिसकेंगे तो आज नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- आपकी बारी कब आएगी? यह दो में जगह है या नहीं है?

श्री दिलीप लहरिया :- कल आप दोनों का जो झगड़ा चल रहा था, वह वाला बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल। श्री धरमलाल कौशिक।

जल जीवन मिशन अंतर्गत फर्मो/कंपनियों/संस्थाओं का इम्पैनलमेंट

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 326) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021 से जून, 2024 तक कितनी फर्म/कंपनियों/संस्थाओं का इम्पैनलमेंट किस आधार पर, कब-कब, किस अधिकारी/समिति के द्वारा किया गया है एवं इसके सदस्य कौन-कौन थे? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अंतर्गत कितनी फर्मो/कंपनियों/संस्थाओं का इम्पैनलमेंट कब व किस आधार पर निरस्त किया गया? इन फर्म/कंपनियों/संस्थाओं को कितनी राशि का कार्य मिशन अंतर्गत दिया गया था तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? **(ग)** मिशन अंतर्गत इलेक्ट्रक्लोनीरेटर सिस्टम के संबंध में क्या-क्या शिकायत की गई है एवं क्या इन शिकायतों की जांच की गई? जांच के निष्कर्ष क्या थे एवं क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021 से जून, 2024 तक 883 संस्था के इम्पैनलमेंट, इम्पैनलमेंट का आधार, इम्पैनलमेंट करने वाले अधिकारी/समिति एवं समिति के सदस्यों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अंतर्गत 79 कंपनियों/संस्थाओं का इम्पैनलमेंट, इम्पैनलमेंट को निरस्त करने का आधार एवं दिनांक की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। इन कंपनियों/संस्थाओं को रू. 1972.98 लाख राशि का कार्य मिशन अंतर्गत दिया गया था तथा रू. 809.827 लाख राशि का भुगतान किया गया व रू. 79.47 लाख राशि का भुगतान किया जाना शेष है। **(ग)** मिशन अंतर्गत इलेक्ट्रक्लोनीरेटर सिस्टम के संबंध में प्राप्त शिकायत, शिकायतों की जांच, शिकायतों पर की गई कार्यवाही एवं जांच का निष्कर्ष की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना एक महती योजना है, जिसमें नल जल के द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है और इसकी समयावधि लगभग पूर्णत: की ओर है, लेकिन जिस प्रकार से इस विभाग में अफरा-तफरी हुई है और भ्रष्टाचार का मामला आया है तो क्या आज आप पूरे प्रदेश में एक बार उसकी समीक्षा करा देंगे कि इसमें अभी तक कितने गांवों में पानी पहुंचा है, कितने चालू हैं और कितने लोगों को पानी मिल रहा है ? वास्तविक में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया और आज छत्तीसगढ़ की जनता उसको भुगत रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब ठेकेदारों को इम्पैनल किया गया और इम्पैनल करने के बाद उनके साथ इलेक्ट्रक्लोनीरेटर खरीदने के लिए जो अनुबंध किया गया तो क्या उसमें पहले किसी फर्म या संस्था का नाम निर्धारित किया गया था कि उसकी खरीदी कहां से होनी चाहिए, उसकी रेट क्या होनी चाहिए, उसका मार्का क्या होना चाहिए और क्या उसमें बाद में तब्दीली होती चली गई ? मैं आपसे पहले यह जानना चाहता हूं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के आम लोग जो पोखर, नदी, नाले से पानी पीकर बीमार पड़ते थे, उन सबको नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। जैसे शहर के लोगों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल और ट्रीटेड वाटर मिलता है, ऐसा जल गांव के लोगों और सुदूर अंचल में रहने वाले गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जल-जीवन मिशन योजना प्रारंभ की। यही सही है कि जल जीवन मिशन के नाम से बहुत विस्तृत योजना बनाई गई। भारत सरकार ने विस्तार से इसकी गाइडलाईन जारी की और देश भर में इसे लेकर अच्छा काम हुआ। आज हमारे प्रदेश की स्थिति आप सबके सामने है। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें हमने विस्तार से एक-एक प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रदेश में कुल 883 फर्म और संस्थाओं का इम्पैनलमेंट किया गया है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन होता है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं और पी.एच.ई. विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सदस्य, सचिव होते हैं। उस कमेटी में सामान्यत: 11 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उनकी देख-रेख में जिले के अंदर का यह काम होता है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के

द्वारा 687 फर्म और संस्थाओं का इम्पैनलमेंट किया गया और मिशन कार्यालय के द्वारा 196 फर्म और संस्थाओं का इम्पैनलमेंट किया गया है। निर्माता इकाइयों का इम्पैनलमेंट सामग्रियों के लिए U.P.V.C pipe, H.D.P.I. pipe, G.I. pipe, Composite pipe, D.I. pipe, O.P.V.C. pipe, Submersible power pump, Use valve, Electro clonirater field test kit, इन सबके लिए राज्य स्तर पर इम्पैनलमेंट होता है और क्रियान्वयन सहायक एजेंसी (आई.एस.ए.), तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टी.पी.आई.) और डीपीआर तैयार करने हेतु सलाहकार इकाइयों का इम्पैनलमेंट जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा होता है। जब शिकायत आई कि वे मापदंड के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, काम में विलंब कर रहे हैं, तो79 इम्पैनल्ड फर्म्स/संस्थाओं का इम्पैनलमेंट निरस्त किया गया।जहां तक मूल प्रश्न जो माननीय सदस्य ने इलेक्ट्रोक्लोरीनेटर के संबंध में पूछा है, इस संबंध में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2022 में दिनांक 11.05.2022, दिनांक 31.05.2022 एवं दिनांक 02.09.2022 को इलेक्ट्रोक्लोरीनेटर सिस्टमके लिए 08 निर्माता इकाइयों का इम्पैनलमेंट किया गया, जिसे बाद में निरस्त किया गया। इस संबंध में शिकायत मूल रूप से यह थी कि एस.ओ.आर. में बहुत राशि है और उसकी तुलना में बहुत कम कीमत के क्लोरीनेटर लगाए गए हैं। उस शिकायत पर जांच की गईऔर जांच कर वह इम्पैनलमेंट निरस्त किया गया और बाद में फिर राज्य स्तरीय एस.डब्ल्यू.एस.एम. के द्वारा दिनांक 29.09.2023 एवंदिनांक 07.12.2023 में अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 06.02.2023 को इलेक्ट्रोक्लोरीनेटर सिस्टमकी चार निर्माता इकाइयों और दिनांक 22.02.2024 को इलेक्ट्रोक्लोरीनेटर सिस्टमकी चार निर्माता इकाइयों को कार्यादेश दिया गया है। माननीय सदस्य ने जो गंभीर विषय उठाया है, हमारी सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन का काम हो, लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और जहां पर भी अनियमितता और गड़बड़ी मिल रही है, उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। अभी-अभी 06 एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को सस्पेंड किया है,पहले 04 को निलंबित किया है। कुछ ठेकेदार जिनके काम में बहुत विलंब हुआ है, उन पर भी कार्यवाहियां प्रस्तावित हैं। विभाग अपने काम को दुरुस्त करने हेतु लगातार लगा हुआ है। इस बीच हमने 188 हैंडपंप टेक्निशियनों की भर्ती की है।इस प्रकार लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महादेय..।

अध्यक्ष महोदय :- इतना विस्तृत जवाब आ गया, कोई शंका बाकी है?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महादेय, हॉ, बहुत बाकी है। प्रश्न लगने के बाद अभी आपने 06 लोगों को सस्पेंड किया। उसके पहले आपने 03 लोगोंको सस्पेंड किया था, इस प्रकार09 तो हो गया है। निलंबित किया है, टर्मिनेट नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोक्लोरीनेटर खरीदने के लिए अनुबंध किया गया और जो बार-बार उसमें बदली की गई, इसे आपने स्वीकार किया है। पहले उन्होंने कहा कि आई.एस.आई. मार्का का आप खरीद लीजिए, खरीदने के

बाद लगा दिए, लगाने के बाद 06 लोगों को आपने उसमें सूचीबद्ध किया। जब आपने सूचीबद्ध किया और सूचीबद्ध करने के बाद फिर उसके हिसाब से खरीदी हुई, तो बाद में इसे निरस्त क्यों करना पड़ा? बाद में निरस्त करना पड़ा, इसका मतलब यह है कि क्या ये अधिकारियों के कंट्रोल में नहीं थे या अधिकारी जानबूझकर इसको उलझाना चाह रहे थे और यदि उलझाना चाह रहे थे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, ये इलेक्टोरल बॉड थोड़ी हवय?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जवाब आ रहा है।

श्री अरूण साव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि जल जीवन मिशन का कार्य भारत सरकार की गाईड लाइन के आधार पर होता है। क्लोरीनेटर के लिए एस.ओ.आर. में स्पेशिफिकेशन दिया हुआ है और लगाए गए क्लोरीनेटर उस स्पेशिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाए गए, इसलिए उनका इम्पैनलमेंट निरस्त किया गया। नया इम्पैनलमेंट किया गया है। इस पूरी योजना में सामग्री की खरीदी ठेकेदार के माध्यम से होती है। हमारी जो एजेंसियां हैं, वह जांच करती हैं और उसके आधार पर ये कार्रवाइयां होती हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी, कठोर कार्रवाई होगी। प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महादेय, कठोर कार्रवाई तब करेंगे, जब जांच होगी। आपने एजेंसी को निर्धारित किया कि इन चार जगहों से आप खरीदी करेंगे। आपने रेट तय कर दिया। तय करने के बाद आखिर बदलना क्यों पड़ा,बात तो यह है और जब बदलना पड़ा तो उसमें जांच की बात आ रही है, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से वही कहा है कि जब जांच की बात पायी गई तो एस.ओ.आर. में जो मापदण्ड दिये गये हैं, वह क्लोरीनेटर उस मापदण्ड के अनुरूप नहीं थे, इसलिए उनका इम्पैनलमेंट निरस्त किया गया है और अब हम सुनिश्चित करेंगे कि जो एस.ओ.आर. का मापदण्ड है, उसके अनुरूप क्लोरीनेटर लगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आखिरी प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न दो-तीन खण्डों में है, मैं उसमें खण्ड-ब का पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत लम्बा नहीं खींचना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें खण्ड-ब में जो दिया गया है कि कंपनी और संस्थाओं को रू. 1972.98 लाख राशि का कार्य मिशन अंतर्गत दिया गया था तथा रू. 809.827 लाख राशि का भुगतान किया गया और भुगतान करने के बाद आपने उसमें से 79 कंपनियों/संस्थाओं का इम्पैनलमेंट रिजेक्ट कर दिया। आपने जिन कंपनियों को रिजेक्ट किया और उन्हें जो राशि दी गयी है,

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसके बाद आज उसकी क्या स्थिति है ? उन लोगों को जो राशि दी गयी है, क्या आपने उन लोगों से उस राशि की वसूली की है ? क्या आपने उनके ऊपर कोई एफ.आई.आर. दर्ज कराई है ? क्या उनके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध किया गया है ? आप उसमें क्या करने वाले हैं, इसे थोड़ा-सा स्पष्ट करिये ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है कि सामग्री के क्रय का भुगतान सीधे विभाग से नहीं होता है, जल जीवन मिशन से भुगतान नहीं होता है, सामग्री का भुगतान ठेकेदार करता है। हमने इम्पैनलमेंट निरस्त किया है और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि जो एस.ओ.आर. का मापदण्ड है, उसके अनुरूप जो भी सामग्री लगना है, वह लगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ठेकेदार की बात आ रही है। मैं अपने विधान सभा में..।

अध्यक्ष महोदय :- आप कोई स्पेसिफिक प्रश्न कर लीजिए। आप विधान सभा क्षेत्र का पूछ लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा में 2 ब्लॉक हैं। मैंने उन दो ब्लॉकों की पूरी समीक्षा की। उसमें सरपंच भी उपस्थित थे, सचिव भी उपस्थित थे, जो गांव की जानकारी दे रहे थे और आपके अधिकारी भी उपस्थित थे। वहां केवल 10 प्रतिशत जगहों पर आधी-अधूरी सप्लाई शुरू हुई है और 90 प्रतिशत जगहों पर सप्लाई शुरू नहीं हुई है। इस बात को अधिकारी ने स्वीकार किया है। लेकिन आप अभी तक ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाये हैं। इसमें आप ठेकेदार को ला रहे हैं कि उसमें ठेकेदार मापदण्ड के अनुसार कार्य करते हैं। आपके अधिकारी ने उसका भुगतान किया है, उसका भुगतान ठेकेदार ने नहीं किया है। अधिकारी ने उसका भुगतान किया है और उसके बाद आपने उसको निरस्त किया तो ठेकेदार के पास जो पैसा है, विभाग उसकी वसूली करेगा या नहीं करेगा ? यदि विभाग उसकी वसूली नहीं करेगा तो इसका यह मतलब है कि उसके साथ आपके अधिकारी की मिलीभगत है, नहीं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आप यह कारण स्पष्ट करें ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि जो सामग्री सप्लाई होती है, जो इक्विपमेंट लगते हैं, वह ठेकेदार पंजीकृत निर्माता इकाई से खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो अपने क्षेत्र की बात कही है कि अनेक स्थानों पर पानी नहीं आ रहा है, हम उसकी जांच भी करने वाले हैं और जहां पर पानी नहीं आ रहा है, वहां क्या दिक्कत है, नलों में जल क्यों नहीं जा रहा है, यह हमारे ध्यान में है और हम इसके लिए पूरी सख्ती से काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने कह दिया है कि वे आपके पूरे विधान सभा क्षेत्र की जांच करा लेंगे। आप लिखकर दे दीजिए, उसकी पूरी जांच हो जाएगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी से केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि बार-बार जो गड़बड़ी आयी है, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं और आप उसके लिए एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करा दीजिए। यह बड़ा मामला है। यह पूरे प्रदेश का मामला है। यह एक विधान सभा का मामला नहीं है। यह करोड़ों रूपये का मामला है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लगा हुआ है और मुझे इसी प्रश्न में एक सवाल का जवाब चाहिए। मेरा नंबर नहीं आएगा। मेरा प्रश्न मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- हम तो आगे बढ़ गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो इसी में पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, जब यह जल जीवन मिशन इस प्रदेश में शुरू हुआ तो आपकी सरकार इधर थी, जो अभी बोल रहे हैं। इसमें बंगले में करोड़ों रूपये का लेन देन हुआ था। इसमें कहां-कहां के गधे-गंवार लोग ठेकेदार बनकर गये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके कारण ही पूरा जल जीवन मिशन कोलेप्स पोजिशन में है। मैं केवल बिलासपुर की बात नहीं कर रहा हूँ। इस सदन के 90 विधान सभा क्षेत्र में यह योजना दम तोड़ रही है। उस पर दम देने का काम, आपसे निवेदन है कि आप करिये। इस योजना की करोड़ों रूपये की लागत है। अगर उसमें और थोड़ा पैसा देकर, यह योजना लागू हो जाए तो हम लोग गांव-गांव में दौरे में जाते हैं, हमें बोलते है तो हम लोग क्या करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आपका सुझाव अच्छा है।

श्री धर्मजीत सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग क्या कर सकते हैं, यह बताईये। यह जल जीवन मिशन बड़ी योजना है। आप सरकार की तरफ से संज्ञान लीजिए। इसमें भयंकर भ्रष्टाचार हो चुका है। पिछली सरकार में जल जीवन मिशन योजना में खुले आम भ्रष्टाचार हुआ था। उसके कारण कई लोग, मंत्री का पॉवर भी कम करना पड़ा और इसमें दुनिया भर की बातें हुईं। यहां पर आप बोलिए, आप यहां बिल्कुल बचाव मत करिये। क्योंकि यह आपका मामला नहीं है आपको आगामी दिनों में जनता को जल देने का काम करना है। आप सदन को यह करने के लिए आश्वस्त करिये। हर विधान सभा की योजनाओं को रिव्यूह करिये।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ सदस्य जी की भावनाओं से सहमत हूँ। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेगी।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय संगीता जी, आप इसमें आखिरी एक प्रश्न कर लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी जल जीवन मिशन में जानकारी चाही थी और उसकी जानकारी आ गई है। मेरे संज्ञान में जो आया है । माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है।

इसमें वहां पर कई कार्य ऐसे हैं जो अभी अपूर्ण है। वहां कहीं टेस्टिंग होकर, छोड़ दिया गया है, कहीं पर कार्य चालू ही नहीं हुआ है। यहां पर इसमें शुरू से लेकर नीचे तक पूरा पूर्ण लिखाया हुआ है। मेरा गुरूर ब्लॉक में अकलवारा गांव है वहां अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है और इसमें यहां पर पूर्ण लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे मंत्री जी यह बतायें कि पूर्णता की परिभाषा क्या होती है? आप किसे पूर्ण कहते हैं? मुझे आपसे केवल पूर्णता की परिभाषा चाहिए ?

श्री रामकुमार यादव :- ददा हो,ए अमृतकाल मिशन हे। ए हा 8 महीना के अमृतकाल हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव ऐसा है जहां केवल 15 दिनों से नल चालू हुआ है, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। यह खर्रा गांव की बात है। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र के बगदई गांव में टेस्टिंग हुई है, उसके बाद कार्य को बंद कर दिया गया है। ऐसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगी, जहां पर केवल 15 दिन नल चालू हुआ है, उसके बाद उससे बंद कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप मंत्री जी को लिस्ट दे दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मेरा आपसे निवेदन है कि उसे जल्द से जल्द पूर्ण करायें। अगर मुझे पूर्णता की परिभाषा दे देंगे तो यह बहुत अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसे पूर्ण कब करेंगे, यह बता दीजिए ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्णता की परिभाषा दे दें।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की मंशा, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बहुत स्पष्ट किया है। जब से माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। जल जीवन मिशन के काम को व्यवस्थित करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। जो इस जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य है, उसको पूरा करने में पूरी ताकत से लगे हैं। निश्चित रूप से उसके अनुरूप वह काम होगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने प्वाईंटेड प्रश्न पूछा है कि पूर्णता की परिभाषा क्या है ? दूसरा, उन्होंने दो गांवों जिनमें एक अकलवारा और बगदई गांव का नाम बताया है कि वहां 15 दिन नल चालू हुआ, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। यह शुरू होगा या नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप दोनों गांवों का दिखवा लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णता की परिभाषा दे दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्णता की परिभाषा चाहिए।

श्री अरूण साव :- आपकी बारी आती तो आपके प्रश्न का पूरा जवाब देता, आपके जो...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आसंदी ने अनुमति दी तो प्रश्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके जो प्रश्न हैं वह मुझे बता देंगे। मैं उसका परीक्षण करवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न आ रहा है। माननीय कवासी जी प्रश्न करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी रिपेयरिंग का कार्य हुआ है। उसमें सिर्फ 1 से 2 इंच कांक्रीटीकरण हुआ है, जो बरसात में उखड़ गया है। मैं आपसे यह निवेदन करती हूँ कि कृपा करके, उसमें गुणवत्ता लाईये।

<u>बस्तर संभाग में ब्रिज निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति</u>

[लोक निर्माण]

2. (*क्र. 87) श्री कवासी लखमा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक बस्तर संभाग में कौन-कौन से ब्रिज निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी ? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ख)** स्वीकृत कार्यों को कब तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य था ? स्थल वार जानकारी देवें ? **(ग)** इनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं तथा कौन-कौन से अपूर्ण हैं ? अपूर्ण हैं तो क्यों ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जाएगा ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक बस्तर संभाग में सेतु परिक्षेत्र रायपुर के अंतर्गत कुल 95 सेतु निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बस्तर संभाग में सेतु विभाग के द्वारा कितने पुल स्वीकृत थे ? और वहां पर कितने अधूरे हैं ? उन्होंने कुछ-कुछ जानकारी लिख कर दी है। मैं इसमें और जानना चाहता हूँ कि इसमें और बता कर देखिए कि बस्तर संभाग में सेतु विभाग के द्वारा कितने पुल स्वीकृत हैं, इसमें कितने पूर्ण और कितने अपूर्ण हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने पूछा है कि वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक बस्तर संभाग में सेतु परिक्षेत्र रायपुर के अंतर्गत कुल कितने सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत हैं? इसकी संख्या 95 है। बस्तर जिले में 07, दंतेवाड़ा जिले में 03, बीजापुर जिले में 09, सुकमा जिले में 11, कोण्डागांव जिले में 19, नारायणपुर जिले में 09, कांकेर जिले में 37, इस प्रकार कुल 95 सेतु

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निर्माण कार्य 768.98 करोड़ रुपये के स्वीकृत हैं। इन 95 कार्यों में राज्य योजना मद से 19 कार्य, C.G.R.I.D.C.L. से 36 कार्य, R.C.P.L.W.E. योजना के अंतर्गत 40 कार्य हैं। इन 95 कार्यों की स्थिति इस प्रकार है। इन 95 कार्य में से 19 कार्य पूर्ण हो गये हैं, 45 कार्य प्रगतिरत हैं, 5 कार्यों का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है और पुन: निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। निविदा की प्रक्रिया में 25 कार्य हैं, 1 कार्य जमीन की अनुलब्धता के कारण निरस्त किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के जिले का विषय है, माननीय सदस्य के जिले में 11 सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत हैं, 01 कार्य पूर्ण हो गया है, 03 कार्य प्रगतिरत हैं, 1 कार्य निविदा आमंत्रण की प्रकिया मे है, 05 कार्य धीमी गति होने के कारण निविदा निरस्त की गई है और पुन: निविदा की प्रक्रिया की जा रही है, 01 कार्य जमीन की अनुपलब्धता होने के कारण निरस्त किया गया है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुकमा जिले में 01 कार्य जमीन की अनुपलब्धता के कारण निरस्त किया गया है, वह कौन सा कार्य है, उस कार्य का नाम बतायें?

श्री रामकुमार यादव :- आपके जवाब देय बर कैसे खोजे लागथे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- वह डोण्डरा के के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आप जो डोण्डरा में कार्य चला रहे थे।

श्री रामकुमार यादव :- एला बस्तर टाइगर कहथे, कैसे जवाब ला खोज रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- डोण्डरा में जो कार्य चल रहा था, उसके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी जा, माननीय सदस्य के जवाब ला 10 मनिट खोजे लागथे।

श्री कवासी लखमा :- आप लोग मीटिंग में चले जाते हैं, यह काम कलेक्टर ऑफिस का है।

श्री केदार कश्यप :- आपके नेतृत्व में हमने पूरा उड़ीसा, आन्ध्रा को पुलिया से जोड़ दिया है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सुकमा के सुकमा से मलकानगिरी मार्ग में किलोमीटर 3/4 पावारासनाला, शबरी रीवर बैंक वाटर पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य जमीन की अनुपलब्धता के कारण निरस्त हुआ है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही तो जानना चाह रहा था जिला सुकमा में कलेक्टर ऑफिस पॉवर हॉउस के पास में हैं, जिला हॉस्पिटल और एस.पी ऑफिस भी वही हैं, हर समय पॉवर हॉउस में शबरी नदी का पानी घुस जाता है, उसके कारण से इस पुल की स्वीकृति दी गई थी। उसमें जमीन है, रोड है, आप यह क्यों कह रहे हैं कि जमीन उपलब्ध नहीं है। क्या कलेक्टर ऑफिस में आना-आना बंद है? इसमें किसी प्राइवेट आदमी के बोलने से इस रोड को कैन्सिल किया गया है, क्या इस कार्य को पुन: स्वीकृत करेंगे? इसमें पूरा जिला से जुडा हुआ है, वहां कलेक्टर ऑफिस, एस.पी. ऑफिस,

हॉस्पिटल है और पॉवर हॉउस भी स्थित है और बीच में नाला है। वह अभी भी डूबा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए उसकी मांग कर रहा हूं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है, मैं इस काम का परीक्षण करा लूंगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 95 कार्य हैं, सुकमा जिला नक्सली से पीड़ित क्षेत्र है इसलिए पिछली सरकार ने पुल-पुलिया को निरस्त किया था। गादीरास, राऊतपारा देख लीजिए, पूरे पिलर हो गये हैं, एक स्लैब की ढलाई हो चुकी है, उस पुलिया को कैन्सिल करने का क्या मतलब है? गादीरास, झीरमपाल, बोखलाघाट, कांजीपाली हो, वहां एक-एक स्लैब ढल चुका है, उसको आपने कैंसल कर दिया। वह पुल बनेगा या नहीं बनेगा और उस क्षेत्र में विकास कैसे होगा? दूसरा, आपने डोंडरा पुल की जानकारी नहीं दी है। मंत्री जी जो मोटू पुल बता रहे थे। मोटू पुल 32 करोड़ रूपये का पुल है, वह अभी तक बन रहा है। थोड़ा-बहुत बना था, वह भी बाढ़ में ढह गया, उड़ीसा में कट गया। आप उसको कब तक बनायेंगे?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय लखमा जी मंत्री थे और वहां से इतने वर्षों से विधायक हैं। इन्होंने वहां एक भी पुलिया स्वीकृत होंगे तो वह बता दें?

श्री अजय चन्द्राकर :- केदार जी, वह लोक निर्माण विभाग के मंत्री थोड़ी थे, वह आबकारी विभाग के मंत्री थे। बस्तर में शराब की कमी थी, यह बताईये?

श्री विक्रम मंडावी :- अभी तो आप मंत्री हैं, आप शराब दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, बस्तर में शराब की बिल्कुल कमी नहीं थी। आपने डोंडरा में खोल कर रखा था, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बतायेंगे?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मजाक वाली बात नहीं है। डोंडरा में आपके समय का 32 करोड़ रूपये के स्वीकृत पुल है। पुल बन चुका है, एप्रोच रोड बना था, लेकिन एप्रोच रोड टूट गया है। वह कब तक बनेगा? क्योंकि यह आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा को कोंटा से जोड़ने वाला पुल है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बता दीजिये।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हम बस्तर के विकास के लिए ..।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, हमन एला सुन-सुन के थक गए हन। एक ही एक ओइ बात ला रिपीट करिहा ता हमन ओला सुन-सुन के थक गए हन। मोदी जी के सरकार बने हे, विष्णु देवस साय के सरकार बने हे तो आप मन रोड ला भी बनाहौं या नई बनाहौ? एला हमन नई जानत हन का कि मोदी जी बने हे, विष्णुदेव साय बने हे। रोड कब बनही? (हंसी)

श्री अरूण साव :- रोड बनावत हन, बनावत हन। तोर क्षेत्र के जनता पूछथे, भैया।

श्री रामकुमार यादव :- मोर क्षेत्र मा पांच ठन रोड स्वीकृति होए रिहीस, ओमा एक ठन रोड हा ध्वस्त होए के स्थिति मा आ गे हे। ये रोड कब तक बनही? जो रोड स्वीकृत होए हे, तेला आप रोक के रख देहा।

श्री अरूण साव :- हाँ, बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर के आम लोगों के जीवन में विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हम परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बस्तर के विकास के लिए हम प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- अब मंत्री जी ने बता दिया।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, आप भाषण बढ़िया दे रहे हैं। यह प्रश्नकाल है, यह भाषण देने का समय नहीं है। उन्होंने प्वाइंटेड प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दीजिये क्योंकि दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसमें उत्तर आना है, लेकिन आप ऐसे भाषण देकर चले जायेंगे। आप विष्णु देव साय जी की खूब तारीफ कीजिए, उसमें हमको कोई इनकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने जो डोंडरा और गाजीरास की बात कही है, वहां एप्रोच रोड कट गया है, उसको आप कब तक पूरा करेंगे? यह प्वाइंटेड प्रश्न है। आप दुनिया भर की, पूरे बस्तर की बात कह रहे हैं। इन्होंने कोंटा की बात की है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैंने उसका बहुत विस्तार से एक-एक बात का उत्तर दिया है। उन्होंने जो मोटूघाट पुल का प्रश्न कहा है, वह निर्माण हो चुका है, मार्ग का काम प्रगतिरत है, यह बहुत जल्द ही बन जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- मोटूघाट पुल बन जाएगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आखिरी सवाल है। विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री हैं। हम भी उनकी तारीफ करते हैं। आप काम करें, जनता ने आपको काम करने के लिए आपको सत्ता सौंपी है, लेकिन एक काम पहले से स्वीकृत हैं, 95 काम अभी प्रगति में नहीं है। बस्तर का यह 95 काम जो पुल से कटा हुआ है, जोकि नक्सलाईट क्षेत्र में है, उसी का लाभ नक्सलाईट उठाते हैं। उसके कारण ही पिछली सरकार ने उसकी स्वीकृति दी थी। सिर्फ सुकमा का यह पांच काम को कैंसल करने का क्या कारण है? बाकी जगह का काम स्वीकृत भी नहीं हुआ है। सिर्फ सुकमा का ही काम कैंसल करने का क्या कारण है?

श्री अरूण साव :- मैंने कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी। विभाग के द्वारा बार-बार कहा जा रहा था, लेकिन तब भी काम में प्रगति नहीं आ रही थी। हमारी प्रतिबद्धता है कि वह काम जल्दी पूर्ण हो इसलिए हम फिर से उसकी निविदा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री अुनज शर्मा।

औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस-1 में स्थापित उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर

[श्रम]

3. (*क्र. 214) श्री अनुज शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022 से जून, 2024 के मध्य औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस-1 में स्थापित किन-किन उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर का आयोजन किया गया? **(ख)** इन जांच शिविर में क्या-क्या अनियमितता पाई गई? **(ग)** संचालनालय स्तर पर इन अनियमितताओं पर अभियोजन की क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) विभाग द्वारा वर्ष 2022 से जून, 2024 के मध्य औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस-1 में स्थापित किसी भी उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर का आयोजन नहीं किया गया है। **(ख)** निरंक **(ग)** निरंक।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में पिछले सत्र में सवाल पूछा था तो उसमें विभाग ने मुझे 108 खतरनाक उद्योगों की जानकारी दी थी। इन उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके आंखों में जलन, सांस की बीमारी, त्वचा की बीमारी और कैंसर जैसे गंभीर रोगों की शिकायतें काफी बढ़ी हैं। मैंने इस विषय में सवाल पूछा था कि इन मजदूरों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिये क्या व्यवस्था रही है तो मेरे पास उसका बहुत निराशाजनक जवाब आया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह मामला है कि विभागीय नियमों का डर और कसावट नहीं होने के कारण फैक्ट्री प्रबंधन निरंकुश होकर लगातार कामगारों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि समय-समय पर मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच के संबंध में क्या प्रावधान है, क्या पॉलिसी है ? और यह फॉर्म-21 क्या है इसको थोड़ा स्पष्ट करके बता देंगे ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कारखाना चलाते हैं उनके द्वारा साल में एक-बार प्रशिक्षण स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है और सिलतरा क्षेत्र के ऐसे 6 खतरनाक श्रेणी के जो उद्योग हैं उन्होंने स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया है, हम लोगों ने उनका श्रम न्यायालय में वाद दायर किया है और न्यायालय से जो फैसला आयेगा । यदि माननीय सदस्य महोदय किसी का पर्टिकूलर बताना चाहते हैं जिसमें शिविर नहीं लगा है तो उसमें निश्चित तौर पर हम लोग कड़ाई से पालन करवायेंगे ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में यह उत्तर आया है कि वर्ष 2022 से 2024 के मध्य सिलतरा फेस-1 में स्थापित किसी भी उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी कोई भी शिविर आयोजित नहीं किया गया है तो माननीय मंत्री जी अपनी बात को Contradict (खंडन)

कर रहे हैं कि केवल 6 उद्योगों ने नहीं लगाया है और आपके सामने यह जवाब है और इस जवाब में यह कहा गया है कि एक भी शिविर नहीं लगाया गया है तो माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने वाले कौन हैं ? माननीय मंत्री जी, पहली बात यह है कि आपके जवाब और इस जवाब में फर्क है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे ? दूसरी बात यह है कि जितनी जांच होती हैं उसको साईट पर अपलोड करना जरूरी है और यह नियम है । यह नियम जारी किया गया है इसके अंतर्गत अपलोड करना जरूरी है और अपलोड करने की हालत यह है कि जी.आर.स्पंज लिमिटेड में 291 जांच होती है और केवल 31 जांच को अपलोड किया जाता है । भगवती पॉवर में 241 जांच होती हैं और केवल 23 वर्करों की रिपोर्ट अपलोड की जाती है, ड्रोलिया इंडस्ट्रीज में 312 और उसमें भी बहुत कम जांच को अपलोड किया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने सदन को गुमराह किया है, जिन्होंने मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है क्या ऐसी मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि 6 कारखानों में जांच शिविर नहीं लगा है और सिलतरा क्षेत्र में 32 कारखाने स्थापित हैं जिसमें 25 खतरनाक श्रेणी के हैं और मात्र 6 में ही स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और विभाग के द्वारा शिविर नहीं लगाया जाता है परंतु उद्योग के द्वारा शिविर लगाया जाता है । यदि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि किसी उद्योग ने जांच नहीं करायी है तो हमको बता देंगे, हम कड़ाई के साथ उसका पालन करवायेंगे और जो नहीं करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है । लगभग 108 का यह जवाब मेरे हाथ में है और अभी 32 उद्योगों का नाम लिया गया है और जांच कराने वालों की संख्या में भी मामला बड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने वाले, चूंकि मेरे पास आज का जवाब रखा हुआ है । इसमें ऐसा लिखा गया है कि आज के सवाल के उत्तर में एक भी कैम्प आयोजित नहीं किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो गुमराह कर रहे हैं, जो सदन में गलत जवाब दे रहे हैं आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे ? माननीय मंत्री जी, हर बार आपका जवाब अलग-अलग आ रहा है ।

श्री लखन लाल देवांगन :- देखिये कोई भी गुमराह वाला जवाब नहीं आ रहा है और न कोई गलत कर रहा है ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 108 लोगों की लिस्ट है। यह है, यह मेरे हाथ में है और यह भी सदन से ही मुझे प्राप्त हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आप जांच कर लें, इसमें बराबर सील लगी हुई है । मेरे हाथ में ओरिजनल प्रति है । बार-बार संख्याओं में

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

परिवर्तन हो रहा है । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे केवल यह जानना चाह रहा हूं कि क्या आप ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे जो सदन को गुमराह कर रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- ये अधिकारी मन काकरो नइ हे, न तुंहर हे, न हमर हे।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सिलतरा के बारे में जानकारी मांगी है और वे 108 उद्योग की बात कर रहे हैं और जो जानकारी मांगी गई है, उसमें सिलतरा क्षेत्र के उद्योग क्षेत्र के बारे में जानकारी मांगी गई है। अगर उन्हें पूरे प्रदेश की जानकारी चाहिए तो मुझे बता देंगे, उनको पूरे प्रदेश का उपलब्ध करा दिया जाएगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इसमें लिखा हुआ है सिलतरा, फेस वन एवं फेस टू में स्थापित कारखानों की सूची और इसे विभाग ने मुझे दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि सदन को जिन्होंने गुमराह किया है, उन पर कार्रवाई करेंगे या हमारे मज़दूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, विधायक जी जिन बातों की बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी जांच करा लें। जब उनको लगता है कि वह अधूरा है तो आप दिखवा लें।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, ये साक्ष्य मेरे पास है।

श्री लखनलाल देवांगन :- बिल्कुल, अगर आप बता रहे हैं तो मुझे दे दीजिएगा। हम जांच करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप दे दें, वे जांच करा लेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- जी, अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद। पुन्नूलाल मोहले जी।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कार्य

[लोक निर्माण]

4. (*क्र. 80) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र मुंगेली अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री सड़क/मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक कितने नवीन सड़क की स्वीकृति हुई हैं? बजट में प्रावधान एवं वर्षवार जानकारी देवें। मार्गों की अद्यतन स्थिति क्याह है? उक्तव अवधि में कितनी सड़कों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य किया गया है, नहीं,तो क्योंतथा कितनी राशि व्यय की गई? कितनी सड़कें शेष हैं, उन्हेंस कब तक किया जायेगा ? विकासखण्डवार जानकारी देवे? यदि नहीं किया गया तो क्योंअ ? **(ख)** लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में कितने सड़क मार्ग हैं, एवं कितने प्रस्तावित हैं, विकासखण्डवार जानकारी देवें?

(ग) पूर्व में बजट में स्वीकृति कितने सड़क निर्माण के कार्य लैप्स हो चुके हैं एवं कितनी सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति आज दिनांक तक प्रदान नहीं की गई है तथा क्यों, कब तक दी जावेगी, समयावधि बतावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) लोक निर्माण विभाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' एवं प्रपत्र-'ब'**अनुसार है। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सड़क योजना की जानकारी प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, सिविल लाईन्स रायपुर से प्राप्त कर जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ई'**अनुसार है। **(ख)** लोक निर्माण विभाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'द'**अनुसार है। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सड़क योजना की जानकारी प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, सिविल लाईन्स रायपुर से प्राप्त कर जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ई'**अनुसार है। **(ग)** लोक निर्माण विभाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'स'**अनुसार है। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सड़क योजना की जानकारी प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, सिविल लाईन्स रायपुर से प्राप्त कर जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ई'**अनुसार है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री ने ये जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री रोड, लोक निर्माण रोड और मुख्यमंत्री रोड तीन रोड की वर्ष 2021 से वर्ष 24 तक मैंने जानकारी मांगी। तो वे बताने का कष्ट करें कि इन्हीं सन् में कितने रोड पास हुए? कितने स्वीकृत हुए? आपने रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेषित, ये लिखे हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता कि कितने रोड का बजट में प्रावधान है? कितने रोड की प्रशासकीय स्वीकृति हुई या कितने रोड की नहीं दी गयी? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आज सारे प्रश्न जिले वालों का आ रहा है, क्या मंत्री के साथ बैठकर समाधान नहीं करते क्या? पूरे जिले वाले सारे लोग जो लगातार प्रश्न कर रहे है? चलिए मंत्री जी।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने तीनों सड़क योजनाओं के बारे में जानकारी पूछी है। लोक निर्माण विभाग के बारे में, प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में और मुख्यमंत्री सड़क योजना के बारे में। ग्रामीण विकास विभाग से प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना की भी जानकारी मैं माननीय सदस्य के लिए लेकर आया हूं और उन्होंने जो जानकारी चाही है, बहुत विस्तार से जानकारी उन्हें दी है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक कुल नवीन सड़क कार्य 23 स्वीकृत किए गए। बजट के काम 6 हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना के 17 कार्य, जिसकी बजट की प्रावधान राशि 3 करोड़ 50 लाख रूपये है, जिसमें से 17 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पांच कार्य अपूर्ण हैं। एक काम की जिसकी आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने ये भी पूछा है, उसके हिसाब से पेंच रिपेयरिंग सड़कों की संख्या 59 है और 11 सड़कों का नवीनीकरण का कार्य इस प्रकार से 70 कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराए गए हैं और इसके लिए कुल मिलाकर 7 करोड़ 6

लाख रूपये की राशि खर्च की गई है। जहां तक मरम्मत सड़कों का विषय है, ये सतत् कार्य है और आवश्यकतानुसार लगातार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मुंगेली में 105 सड़क मार्ग हैं, जो मुंगेली विकास खंड के अंतर्गत 90 और पथरिया विकास खंड के अंतर्गत 15 मार्ग हैं। 13 प्रस्तावित कार्य हैं। वर्ष 2023-24 में पांच और वर्ष 2024-25 में आठ कुल मिलाकर 13 कार्य जो हैं, प्रस्तावित हैं। इन 13 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति अभी नहीं हुई है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण करने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक पेंच नवीनीकरण के 31 कार्य स्वीकृत हुए। इसकी कुल राशि 26 करोड़ 49 लाख 5 हजार रूपये है। विकासखंड मुंगेली के अंतर्गत चार सड़क हैं। नवीनीकरण, जिनके वर्ष 2024 तक पूर्ण करा लिए जायेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मुंगेली में कुल 66 मार्ग हैं। मुंगेली विकास खंड के अंतर्गत 57 और पथरिया के अंतर्गत 9 सड़क हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक नवीन कार्य कोई स्वीकृत नहीं हुए हैं। पेंच रिपेरिंग नवीनीकरण के 6 काम थे, जिसकी लागत 3 करोड़ 85 लाख 81 हजार रूपये है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मुंगेली विधानसभा में 75 मार्ग हैं। मुंगेली विकासखंड के 66 और पथरिया विकास खंड के 9 मार्ग आते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मोहले जी, और कोई शंका है?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी तो लिखित में आ गई है । मैं यह जानना चाहता हूं बजट में जो मार्ग प्रावधानित हैं, आपने 14 मार्गों की जानकारी दी है, उन मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति देंगे या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं ? क्या समय सीमा बताना संभव है ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, जिन कामों को बजट में शामिल किया गया है, उन कामों का परीक्षण किया जा रहा है । उसके उपरांत उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह तो मैं भी जानता हूं कि अग्रिम कार्यवाही की जाएगी । बजट में प्रावधानित सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति कितने वर्षों में जारी की जाती है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, बजट में शामिल कामों के लिए 2 साल की अवधि रहती है, 2 साल के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति और प्रशासकीय स्वीकृति के बाद 3 साल तक वे काम कराए जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, पूछ लीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मोहले जी को पूछने दीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- 2021 से यह कार्य शामिल है और यदि 3 साल की समय सीमा है तो उस कार्य को तो 4 साल हो गए हैं, ऐसे कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दिए जाने का क्या कारण है, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति देंगे क्या ?

श्री अरूण साव :- प्रशासकीय स्वीकृति देते समय बहुत सारी बातों का परीक्षण करना होता है, परीक्षण के उपरांत ही आगे की कार्यवाही होती है । जो 13 काम बजट में शामिल हैं, उनका परीक्षण कर रहे हैं और आदरणीय मोहले जी वरिष्ठ सदस्य हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा जल्दी करा लें, मोहले जी का काम है ।

श्री अरूण साव :- जी, जी । मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि वरिष्ठ सदस्य हैं और मुंगेली जिले से हैं, मेरे अभिभावक के जैसे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं पांच सालों तक लोक लेखा समिति का चेयरमेन था । 2 साल में यदि प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलती है तो फिर से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है, फिर से बजट में लाइए और करिये । देश में मापदंड माना जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि एक दिन में इतने किलोमीटर सड़क बन रही है, एक दिन में हम 20 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं । पीडब्ल्यूडी विभाग के माननीय मंत्री जी यह बताएंगे क्या कि जो कार्य बजटेड है, उसमें आपकी प्रक्रिया क्या है ? कितनी दिनों के अंदर परीक्षण होता है, कितने दिनों के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति होती है और कितने दिनों के अंदर कार्यादेश जारी कर दिया जाता है और कितने दिनों के अंदर सड़क बनाकर तैयार कर देते हैं । इसकी कोई प्रक्रिया सुनिश्चित है या नहीं है । या फिर यह अपनी मर्जी पर है ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी सड़कें स्वीकृत हैं, जो बन चुकी हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए या नवीनीकरण के लिए कितनी अवधि होती है ? एक तो पांच वर्ष की अवधि होती है, दूसरी उस वर्ष की अवधि होती है । जिन सड़कों को पांच साल से ज्यादा हो गए, दस साल से ज्यादा हो गए हैं, क्या उनकी मरम्मत करवाएंगे ? इसके लिए समय सीमा निर्धारित है या नहीं, यह बता दें ?

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ी प्रक्रिया बता दीजिए ।

श्री अरूण साव :- बजट में शामिल होने के बाद डीपीआर बनता है, जमीन की उपलब्धता और अन्य बातों का परीक्षण होता है । परीक्षण के उपरांत फिर उसकी प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही होती है ।

श्री अजय चन्द्रकार :- माननीय मंत्री जी, मैं भी 10 साल मंत्री रहा हूं, मैं प्रक्रिया जानता हूं । मैंने कहा कि पीडब्ल्यूडी में किसी भी प्रक्रिया के लिए समय सीमा का निर्धारण है या मर्जी है, एक लाईन की बात है । ऐसा उदाहरण है कि बजट में आने के बाद कार्य लेप्स हुए हैं, आप जितनी प्रक्रिया बताते

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं, उसके लिए समय सीमा है या फिर अधिकारियों या विभाग की मर्जी पर है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हुडको में बहुत जल भराव की समस्या हो रही है । बजट में वह काम शामिल हुआ और टेंडर होने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, लोग बहुत परेशान हैं । मैं माननीय मंत्री जी से इस पर भी प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, छोटे से प्रश्न हे, एके संग बता दिही ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया की समयावधि है या किसी की मर्जी पर निर्भर है ? बजट में आने के बाद प्रक्रिया से काम होगा या किसी की मर्जी से होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया बता दीजिए ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बड़ा प्रश्न है और यह सभी विधायकों का प्रश्न है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां बोरी नाला है, जो आज टापू बन गया है । वह भी स्वीकृत हो चुका है लेकिन इन लोगों ने टेंडर पास नहीं किया है । बहुत गंभीर समस्या है । हमारे यहां अभी बारिश हो रही है और जो बोरी नाला है, मैं संज्ञान में लाना चाहूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं आएगी।

श्री अजय चंद्राकर :- रामकुमार, ओतका अकन ला देख के तैं जियत कइसे हस तेला तो बता।

श्री रामकुमार यादव :- मैं तुंहला देख के जियत हों।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर समस्या है।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरा उत्तर तो आने दीजिए, उसके बाद पूछ लेना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भी बारिश हो रही है जो बोरी नाला है, मैं संज्ञान में लाना चाहूंगी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, ए प्रदेश में तीन सौ रोड के प्रशासकीय स्वीकृति हो गे हे जेमा चंद्रपुर के दो ठन टेंडर खुल गे हे, ठेकेदार मन बर भी कर दे हे, ओखर बावजूद भी काम ला नई करत हे, तुंहर से निवेदन हे जो प्रशासकीय स्वीकृति हो गे हे, टेंडर भी हो गे हे, तेला तो आप कम से कम कर देव। मोर आपसे निवेदन हे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरा उत्तर तो आने दीजिए, सभी का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें सरकार की सारी प्रक्रिया मालूम है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल ठीक है।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, सरकार और सरकारी विभाग, सरकारी काम किसी की मर्जी से नहीं चलती है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से कार्यवाहियां होती है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, टेंडर खुल गे हे, प्रशासकीय स्वीकृति जा चुके हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर जा चुका है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने समयावधि पूछी कि समयावधि मर्जी पर है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए अजय जी हो गया।

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए उसके कारण समयावधि का पालन नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बता दीजिए। मोहले जी हो गया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप पलट-पलटकर प्रश्न में आ रहे हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक मिनट अनुरोध करूंगा। जो रोड पांच साल और दस साल से बन चुके हैं, ऐसे रोड जो मरम्मत के हैं, आपके पास प्रस्ताव में है, जब मर्जी नहीं चलती है, नियम कानून है तो नियम कानून में पांच और दस साल के रोड का निर्माणाधीन करते ही हैं, नवीनीकरण, जीर्णोद्धार करते हैं, इसमें करेंगे क्या, मेरा सीधा प्रश्न है। आप यह बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपके प्रश्न के बाद एक विषय जो अजय जी ने मूल प्रश्न उठाया था तो बजट में जो भी कार्य सम्मिलित होता है और उसके बाद पूर्ण होने और समस्त प्रक्रियाओं में लगने वाली अवधि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके संबंध में माननीय मंत्री जी सभी विधायकों को सत्र के बाद आपको पूरी जानकारी फीट कर देंगे। एक बार बैठकर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, सब संतुष्ट हो जाएंगे। सब हाथ उठा रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। गंभीर प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, एक लाईन में आ गया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोरी लाला टापू बन चुका है। अभी बारिश हो रही है। उसको प्लीज संज्ञान में लीजिए। उसमें आप अभी के अभी काम चालू करवाईए। वहां पर टापू बन चुका है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश जी, आप प्रश्न करिए।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देवभोग का बेलास नाला है। पिछले बीस साल से लंबित पड़ा है जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 4 करोड़ 85 लाख हो चुका है, उसके बावजूद भी टेंडर नहीं हो रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में और खल्लारी विधानसभा में जो कार्य स्वीकृत हो चुके थे, टेंडर लग चुका है, इस विधान सभा में इस सरकार ने ऐसी कौन सी नई नीति लागू की है कि फिर से वित्त विभाग से अनुमति का आदेश हुआ है। उसको फिर से वित्त विभाग में ले जाने के पीछे क्या कारण है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। दोबारा वित्त विभाग में ले जाने का क्या कारण है।

श्री अजय चंद्राकर :- ओखर उत्तर भूपेश बघेल जी से पूछ लेबे ना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करने उठ गये हैं। हो गया। आपकी बात आ गयी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, काम चालू हो चुका है, काम शुरू होने के बाद उसको बंद करवा दिया गया है। स्वीकृत होने के बाद फिर से दोबारा वित्त विभाग में भेजना पड़ रहा है। यह कहां का नियम है।

अध्यक्ष महोदय :- बात आ गयी। समाप्त हो गया।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सेम कंडिशन मेरे विधान सभा का है। देवभोग के बेलास नाला की प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद भी टेंडर जारी नहीं किया है। इसी तरह मैनपुर नाला के पास का है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, आगे बढ़ गये। आप बैठिए। प्लीज आप बैठ जाईए। थोड़ा आगे बढ़ें।

श्री भूपेश बघेल :- देखिए, पुन्नूलाल मोहले जी का जो प्रश्न है, वह तो बहुत ही गंभीर, सर्वव्यापी है। इसलिए आसंदी से निर्देश हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- बस अब उसको आगे कर लेंगे।

<u>**प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही**</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (*क्र. 962) श्री भूपेश बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राज्य में जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को शासन द्वारा योजना का लाभ दिया गया है? जिलेवार जानकारी देने के कष्ट करें। **(ख)** उक्त अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केन्द्र सरकार से कितना आबंटन प्राप्त हुआ है तथा राज्यांश की कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है? **(ग)** प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं? पूर्ण हुए कितने आवास का भौतिक सत्यापन किया जाकर हितग्राहियों के पक्ष में राशि अंतरित की जा चुकी हैं? तथा कितने आवासों का भौतिक

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सत्यापन किया जाना शेष है? यदि पूर्ण हुए आवास का भौतिक सत्यापन अभी शेष है तो उसका कारण क्या है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत प्रश्नांकित अवधि जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक किसी भी हितग्राही हेतु आवास स्वीकृत नहीं किये गए हैं। अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत केन्द्र सरकार से राशि रू 165.30 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू 94 13 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। **(ग)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक अन्तर्गत स्वीकृत आवासों में से अब तक 1,66,196 आवास पूर्ण हो चुके हैं। पूर्ण आवासों में से 1,59,182 हितग्राहियों को भौतिक सत्यापन उपरान्त अंतिम किश्त की राशि जारी की जा चुकी है एवं शेष 7,014 पूर्ण आवासों का अंतिम किश्त का भुगतान किया जाना अद्यतन शेष है। पूर्ण आवासों में से 3,201 आवासों का भौतिक सत्यापन किया जाना शेष है। भौतिक सत्यापन एक निरंतर प्रक्रिया है एवं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा पूर्ण किये जा रहे आवासों का नियमित भौतिक सत्यापन किया जाकर अंतिम किश्त की राशि संबंधित हितग्राहियों को अंतरित की जा रही है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रश्न है। विज्ञापन में जो 18 लाख आवास लगा हुआ है, उससे बाहर है कि यह उसी में से है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत वाजिब प्रश्न माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूछा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उनका प्रश्न है। जो प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर बहुत विस्तार से दिया गया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह पूछा है कि जो विज्ञापनों में 18 लाख आवास लगा है, यह शहरी आवास उसके भीतर ही है या उसके बाहर है। हां या ना में उत्तर दे दीजिए। उसमें बहुत विस्तार से उत्तर देने की जरूरत नहीं है। यह है या नहीं है। बस इतना ही प्रश्न है या इससे अलग है ? यह शहरी आवास का 18 लाख से अलग है, जो विज्ञापनों में लगा है। यह उससे अलग है या उसके भीतर है।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, उसके भीतर ही है और प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे सभी को पता है कि पूर्व में यह योजना दिसम्बर 2024 तक की अवधि के लिये थी, अभी 10 जून को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि....।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं इतना विस्तार से नहीं चाह रहा था, मैंने यह पूछा है कि 18 लाख आवास के अंदर है या नहीं है या बाहर है ? उसका उत्तर आ गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- बता दीजिए ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा-छोटा प्रश्न है, गरीब लोगों का मामला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे प्रश्न है, बहुत विस्तार से उत्तर देने की जरूरत नहीं है, छोटे आंकड़े हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी तक भारत सरकार को शहरी क्षेत्रों में कितने डीपीआर बनाकर भेजे गये हैं और आप इसके आंकड़ें बता दें और उसकी कितनी स्वीकृति आई है ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पास पूर्ववर्ती सरकार के 19,906 आवासों की स्वीकृति लंबित है । अब नई दिशानिर्देश की प्रतीक्षा हो रही है, जो तीन करोड़ नये आवास स्वीकृत हुये हैं...।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के लिये 3 करोड़ आवास नहीं हुये हैं, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ....।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पास 19,906 आवासों का डीपीआर लंबित है, माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से मिलकर इसकी स्वीकृति के लिये हमने आग्रह किया है । अध्यक्ष महोदय, इसके उच्च स्तर पर भी लगातार प्रयास हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उसके अनुरूप होगा । अध्यक्ष महोदय, जहां तक पिछले 6 महीनों में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिये जो राशि जारी की है, उसकी भी जानकारी आपने मांगी है...।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं वह प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे अतिरिक्त उत्तर नहीं चाहिये । मैंने इतना पूछा है कि आपने 19,906 के आंकड़े बताये हैं, इसकी स्वीकृति के लिये आपने भेजा है, लेकिन वहां से स्वीकृति कितनी आई है ? अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि पिछली सरकार ने भेजा था, आपकी सरकार को 8 महीने होने जा रहे हैं, भारत सरकार ने कितनी स्वीकृति प्रदान की ? हां, इतना किया है या नहीं किया है, बस इतना उत्तर है, फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर स्पष्ट दिया हुआ है कि दिसम्बर 2024 तक की योजना थी, अभी जनवरी 2024 के बाद नये प्रधानमंत्री आवास (शहरी) की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है और ...।

श्री भूपेश बघेल :- बस, इतना ही चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने 8 महीनों में एक भी शहरी आवास स्वीकृत नहीं किया है । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि शहरों में हमारे कितने कच्चे मकान है, क्या आप उसके डीपीआर बनायेंगे ? उसके लिये आपकी क्या योजना है ? अध्यक्ष महोदय, एक अन्य बात यह है कि उसमें पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी, अभी भी पट्टा लंबित है । अध्यक्ष महोदय, जो कच्चे मकान है, उसका डीपीआर बनाकर भारत सरकार की अनुमति के लिये भेजेंगे या उसको अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, योजना में है या नहीं है, मैं केवल आपसे इतना ही जानना चाहता हूँ ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि 19,906 आवास के डीपीआर भारत सरकार के पास लंबित है और उसके मापदण्ड है कि कितने मकान स्वीकृत होंगे और उस मापदण्ड के अनुरूप 19,906 मकानों के बाद और भी जो आयेंगे तो निश्चित रूप से और भेजेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले ...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नहीं आया है, मैं तो आपसे पाईन्टेड पूछ रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री जी के पास और भी प्रश्न आयेंगे । अध्यक्ष महोदय, कच्चे जो मकान है, क्या उसको पट्टा देंगे, उसकी डीपीआर बनेगी या नहीं बनेगी या बनाने की योजना है तो कब तक बनायेंगे ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है जो प्रधानमंत्री आवास को लेकर भारत सरकार की गाईड लाईन है, उस मापदण्ड के अनुरूप निश्चित रूप से लोगों को लाभ दिया जायेगा, चूंकि पट्टा की कार्यवाही अन्य विभाग से होती है, मापदण्ड में आयेगा तो और डीपीआर बनायेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक प्रधानमंत्री आवास उन्हें मिल मिल सके ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपको यह पता नहीं है कि कच्चे मकानों के डीपीआर बनाना है या नहीं बनाना है । आपने जिक्र किया कि भारत सरकार के जो गाईड लाईन है, आपने विवेक में उत्तर दे दिया । अध्यक्ष महोदय, आपसे यही चाहूँगा कि कच्चे मकान के लिये पट्टा देना आपके हाथ में है और उसका डीपीआर बनेगा या नहीं बनेगा, वह भारत सरकार की गाईड लाईन है । सवाल यह उठता है कि जो पट्टे बने रखे हुए हैं, चाहे वह एस.डी.एम. कार्यालय में हो, चाहे तहसीलदार कार्यालय में हो, चाहे सी.एम.ओ. के कार्यालय में हो, चाहे नगर निगम के कमिश्नर के पास हो, उसको वितरित करेंगे या नहीं करेंगे और उन लोगों का डी.पी.आर. आप बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पट्टे की बात है । सरकार इस पर विचार कर रही है, परीक्षण कर रही है । परीक्षण कर उस पर निर्णय लेंगे । प्रधानमंत्री आवास में जो भूमि स्वामी होता है, वही प्रधानमंत्री आवास का हितग्राही होता है ।

श्री भूपेश बघेल :- पट्टा देंगे, तभी तो भूमि स्वामी बनेंगे ।

श्री अरूण साव :- उसके अनुरूप सरकार के पास मामला विचाराधीन है । सरकार विचार कर रही है, परीक्षण कर रही है ।

श्री भूपेश बघेल :- धन्यवाद । आपकी नीति अभी अस्पष्ट है । माननीय अध्यक्ष जी, आपने संरक्षण दिया है, मैं एक छोटा सा प्रश्न और करना चाहता हूं । चूंकि यह आवास योजना 2015 के डी.पी.आर. से बना है, आज 2024 चल रहा है । इस योजना को बने हुए 9 साल हो गए हैं । महंगाई भी दोगुना हो गया है, लागत भी दोगुनी हो गई है, चाहे सीमेंट हो, छड़ हो, गिट्टी को, मजदूरी हो, सबकी कीमत बढ़ गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको फिर से पुन: परीक्षण कराएंगे क्या? 2015 के बाद 2024 आ गया है । इसको पुन: परीक्षण कराकर नये राशि, क्योंकि उतनी राशि में आवास नहीं बन

रहा है क्योंकि कोई छोटा बना देता है, कोई बड़ा बना देता है, फिर शिकायतें आती हैं कि आपने छोटा आवास बना दिया तो क्या इसमें चेंजेस करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य का सुझाव है । निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, एक अंतिम प्रश्न है, गरीबों का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- 5 प्रश्न हो गए ।

श्री भूपेश बघेल :- यह बहुत स्पेशिफिक प्रश्न है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब प्रश्नकाल में सिर्फ 4 मिनट ही बचे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि प्वाइंटेड उत्तर दीजिए । माननीय अध्यक्ष जी, जिनको आवास योजना का लाभ मिला है, उसके पहले से खाते हैं, उसने लोन लिया हुआ है । सरकार बैंक में पैसा भेजती है, वह उसमें समायोजित हो जाता है और उसके बाद वह बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं या आधार लिंक नहीं मिलने के कारण से चक्कर लगाते रहते हैं । ऐसी शिकायतें आई हैं क्या ? यदि ऐसी शिकायतें आई हैं तो इसमें आपके पास निराकरण की क्या व्यवस्था है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न किया है तो मैं इसको संज्ञान में लेकर इस पर जरूर विचार करूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- आपकी जानकारी में नहीं है ?

श्री अरूण साव :- बिल्कुल नहीं है ।

जिला जशपुर अंतर्गत संचालित उद्योग

[वाणिज्य एवं उद्योग]

6. (*क्र. 7) श्रीमती गोमती साय : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जशपुर में कौन-कौन से उद्योग कहॉ-कहॉ स्थापित हैं? उन उद्योगों के मालिक कौन-कौन हैं? **(ख)** कंडिका ''क'' के तहत स्वीकृत उद्योगों द्वारा संचालन में नियम शर्तो का पालन नही किये जाने से उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही विगत 02 वर्षो से जून,2024 में की गई है? **(ग)** कंडिका ''क'' के तहत स्वीकृत एवं संचालित उद्योगों में कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :(क) विभाग में पंजीकृत जानकारी के अनुसार जशपुर जिले में कुल 387 उद्योग स्थापित हैं, विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** पर दर्शित है। **(ख)** कंडिका ''क'' में दर्शित उद्योगों के संबंध में विभाग में विगत 02 वर्षो में विभिन्न विभागों से संबंधित 02 शिकायतें प्राप्त हुई है- 1. ग्राम-रघुनाथपुर में कृषि भूमि में बिना डायवर्सन कराये

स्टोन क्रशर के संचालन के संबंध में है। प्राप्त शिकायत के बिन्दु के आधार पर राजस्व विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। 2. ग्राम-बालाछापर, जशपुर में राईस मिल को प्रदूषण फैलाने के संबंध में प्राप्त शिकायतें के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायगढ़ को शिकायत प्रेषित की गई थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इकाई द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण कराया गया है । विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** में पूरक जानकारी संलग्न है। 3. कंडिका ‘‘क‘‘ में वर्णित उद्योगों द्वारा कुल 3804 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जो कि विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** के कॉलम नंबर-08 पर दर्शित है।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से है । मेरा प्रश्न है कि स्वीकृत उद्योगों द्वारा संचालन में नियम शर्तों का पालन नहीं किये जाने से दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? जो दो जशपुर जिला में है । कृपा करके मैं इतना जानना चाहती हूं कि उन दोषियों के खिलाफ आप कितने दिनों में कार्रवाई करेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, शीघ्र कार्यवाही करेंगे, जानकारी दे देंगे ।

नगर पालिका परिषद जामुल एवं नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग में अवैध प्लाटिंग

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (*क्र. 140) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नगर पालिका परिषद जामुल एवं नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग अंतर्गत वर्ष 2021 से जून, 2024 तक अवैध रूप से भू-खंडों का क्रय-विक्रय के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? स्थान व खसरा नम्बर सहित पृथक-पृथक बतायें? **(ख)** क्या उक्त नगर पालिक निगम अंतर्गत अवैध रूप से विक्रय कर रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु वर्ष 2021 से जून, 2024 तक आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा जिला कलेक्टर व पंजीयक को पत्राचार किया गया था? क्या अवैध प्लाटिंग भूमि का नक्शा-खसरा एवं बटांकन की जानकारी तहसीलदार से मांगी गयी थी? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कितने प्रकरणों में अवैध कब्जा हटाये गये व पंजीयन निरस्त किया गयाऔर कितने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी एवं कितने खसरों के पंजीयन पर बैन (ब्लाक) किया गया है? पृथक-पृथक बतायें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) नगर पालिका परिषद जामुल एवं नगर पालिक निगम भिलाई जिला-दुर्ग अंतर्गत वर्ष 2021 से जून, 2024 तक अवैध रूप से भू-खंडो का क्रय-विक्रय के 126 प्रकरण दर्ज किये गये है। स्थान व खसरा नम्बर सहित पृथक-पृथक **जानकारी संलग्न प्रपत्र**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अनुसार है।[1] **(ख)** जी हां। आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा वर्ष 2021 से जून, 2024 तक अवैध रूप से विक्रय कर रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु जिला कलेक्टर व पंजीयक को पत्राचार किया गया था। जी हां।अवैध प्लाटिंग भूमि का नक्शा-खसरा एवं बटांकन की जानकारी तहसीलदार से मांगी गयी थी। 61 स्थलों पर तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया गया है, जिनमें से 02 स्थलों की जानकारी तहसीलदार द्वारा दी गई। 61 स्थलों पर निर्मित मार्ग संरचना की बेदखली की कार्यवाही की गई है एवं पंजीयन निरस्त करने की संख्या निरंक है। 03 प्रकरणों में 16 व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए गए है। 482 खसरों के पंजीयन पर बैन (ब्लाक) किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध भूखण्डों के क्रय विक्रय के 126 प्रकरण दर्ज हैं । यह प्रकरण किसके द्वारा दर्ज की गई है और कब-कब दर्ज की गई? आप उनके प्रमोटरों का नाम बताईए और 126 प्रकरणों में सिर्फ 61 स्थलों पर तहसीलदार द्वारा बेदखली की कार्यवाही की गई, बाकी 65 स्थलों का क्या हुआ ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार प्रश्न पर गौर करेंगे। माननीय सदस्य प्रश्न "ख" जिसका प्वाइंट आऊट कर रहे हैं । क्या उक्त नगर पालिका निगम, जो प्रश्न है, वह नगर पालिका, जामुल और नगर निगम, भिलाई का है । प्रश्न "ख" केवल नगर निगम से संबंधित है । इसलिए माननीय सदस्य को नगर निगम के आंकड़े दिए गए हैं । जामुल के 65 प्रकरण हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है । जो परिशिष्ट है, उसमें नगर पालिक निगम, भिलाई और उसके बाद नगर पालिका, जामुल, दोनों की जानकारी परिशिष्ट में दी गई है । आप परिशिष्ट देख लीजिए । जो परिशिष्ट में दिया है, मैंने उसी का प्रश्न पूछा है । आप यह बता दीजिए कि अवैध रूप से 126 प्रकरण दर्ज हैं, उसमें आ जाएं । आपने इसमें 126 प्रकरण दिया है, उसके प्रमोटर्स कौन-कौन हैं और 61 स्थानों पर तहसीलदार ने बेदखली की कार्यवाही की है, बाकी 65 स्थल में क्या हुआ, यह बता दीजिए ।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा..।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

[1] परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय
12.00 बजे

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मेहनत करे मुर्गी और अण्डा खाये फकीर।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये मुर्गी मन करे हे, फकीर अभी निकलेगा।

सदन को सूचना

"एक पेड़ मॉ के नाम" के तहत पौधरोपण कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय :- पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 05 जून, 2024 को **"एक पेड़ मॉ के नाम"** अभियान की शुरूआत की गई है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा सचिवालय स्थित आवासीय परिसर के समीप "एक पेड़ मॉ के नाम" अभियान के तहत वन विभाग के सहयोग से गुरूवार दिनांक 25 जुलाई, 2024 को दोपहर 1.30 बजे से 3.00 बजे तक पौधरोपण किया जाना है।

आप समस्त सदस्यों से आग्रह है कि उक्त कार्यक्रम में पौधरोपण करने हेतु सम्मिलित होने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय ओ.पी. चौधरी वित्त मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मॉ के नाम एक पेड़ तो लगा देंगे, लेकिन हमारे पुरखे जो पेड़ बचाकर रखे थे, वह सांय-सांय कट रहे हैं, उसका क्या होगा ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हसदेव में जाकर उसे पिता जी के नाम से लगवा दें।

श्री रामकुमार यादव :- इही ला छत्तीसगढ़ी मा कहथे कि साबर के चोरी अउ सूजी के दान।

समय
12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पटल पर रखता हूं।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

(2) छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखता हूं।

(3) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2022-23 (दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2022-23 (दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक) पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2021-2022

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2021-2022 पटल पर रखता हूं।

(5) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(6) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मार्यादित का अंकेक्षण एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मार्यादित का अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक (वर्ष 2022-23) पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और अभी कृषि कार्य जोरों पर चल रहा है। अभी वर्षा प्रारंभ ही हुआ है, लेकिन फिर भी बिलासपुर और सरगुजा संभाग के बहुत सारे जिलों में अभी भी पानी की कमी है। ऐसे समय में कृषि कार्यों में जुटे किसानो को सोसयटियों में डी.ए.पी. नहीं मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उसके बदल दूसरे खाद देने की कोशिश की जा रही है। नकली दवाईयां मिलने की शिकायतें, नकली खाद मिलने की शिकायतें मिल रही हैं वह चाहे मुंगेली जिला हो, चाहे बेमेतरा जिला हो, चाहे कवर्धा जिला हो, चाहे राजनांदगांव हो, सभी जगह इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। बीज की स्थिति तो यह है कि उसे हल्दी पानी में डूबाकर, सूखाकर वितरीत किया जा रहा है और वह अंकुरित नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से पिछले 1 सप्ताह से पानी गिर रहा है, इसके पहले से बिजली कटौती से किसान इतने परेशान थे । (शेम-शेम की आवाज)

श्री अजय चंद्राकर :- क्योंकि स्थिति सुधर गई है तो अब आप बिजली कटौती वाले को काट दीजिए। आप दूसरे विषय में बोलिये।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं। अजय जी, मैंने पहले कहा कि अभी भी बिलासपुर संभाग के कुछ जिले और सरगुजा संभाग के सभी जिलों में अवर्षा की स्थिति है। अभी वहां पानी गिर तो जाए। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपने अपने भाषण में स्वयं स्वीकार किया है कि पिछले एक हफ्ते से स्थिति सुधर गई है। आप एक हफ्ते वाले को काट दीजिए। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप कल के लिए नया स्थगन दे दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- लेकिन खाद्य की स्थिति तो वही है। नहीं, मैं किसान आदमी हूं और पानी गिर रहा है तो खुशी व्यक्त कर रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम आज ही स्थगन देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने ही तो अपने भाषण में स्वीकार किया है कि स्थिति सुधर गई है तो आप कल के लिए नया स्थगन दे दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- पानी की।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पानी की स्थिति सुधरी है, बिजली की स्थिति बहुत ही अस्त-व्यस्त है। 24 घण्टे से बिजली बंद है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, बैठिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं। दबाव में आ जाए, करके यह गलत बात बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- किसान मन के चिंता करे के बजाय ए मन हा गलत बात बोलत हे। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपने एक हफ्ते पहले अपने भाषण में कहा था कि स्थिति सुधर गई है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह पूरे प्रदेश की समस्या है। पानी तो अभी गिरा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपने बोल दिया, हो गया। प्लीज बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से इनको दण्ड मिलना चाहिए। आप अजय जी को दण्ड दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप भूपेश जी को बोलने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने कहा कि एक हफ्ते में स्थिति सुधर गई है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- नहीं अध्यक्ष जी।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- पानी की स्थिति सुधरने की बात कही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- कवासी जी, आप शुरू कीजिए।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष जी, असल में यह स्थगन एक हफ्ते पहले का है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा स्थगन का विषय खाद, बीज और नकली दवाई के ऊपर है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने एक हफ्ते पहले कहा था।

श्री भूपेश बघेल :- भाई, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिये । अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन बिजली की कमी पर है। मैंने तो कहा कि पिछले एक सप्ताह से पानी गिरना शुरू हुआ है। अभी पूरे प्रदेश भर में पानी नहीं गिरा है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग अभी भी अवर्षा की चपेट में है। मैंने यह कहा है। हमारा स्थगन अवर्षा को लेकर नहीं है। हमने नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयों और एक्सपायरी

डेट दवाइयों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए आप इसे ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराइये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। पटेल जी, थोड़ा संक्षिप्त में बताइये।

श्री उमेश पटेल :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है।

श्री अजय चंद्राकर :- बांगो में पानी चल रहा है।

श्री उमेश पटेल :- क्या चल रहा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- बांगो में पानी चल रहा है और खरसिया में स्थिति अच्छी है। बांगों में पानी चल रहा है और किसानों को पानी मिल रहा है। आपका स्थगन एक हफ्ता पुराना है। आपने इसको एक हफ्ते पहले लिखा था, उस पर आप आज चर्चा मांग रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ खरसिया की स्थिति नहीं है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। जिस तरह से किसानों को बीज बांटा जा रहा है।

श्री रामविचार नेताम :- भाई, उस दिन आपने बीज के बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री उमेश पटेल :- किस दिन ?

श्री रामविचार नेताम :- मैं आपके साथ बैठा तो था।

श्री उमेश पटेल :- आपके अधिकारी एजेण्डा ही नहीं लाये थे और मुझे जल्दी जाना था, इसलिए नहीं बताया।

श्री रामविचार नेताम :- एजेण्डा से क्या मतलब है ? यदि आपके पास कोई तथ्य था तो उसको रखना था।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन शायद उमेश पटेल जी वहां पर चाय-नास्ता के लिए गये होंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना है, आप रूक जाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिले में जिस तरह से बीज बंट रहे हैं। रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र के एक किसान ने मुझे फोन करके बताया कि उसने सोसायटी से बीज लिया है और बीज लेने के बाद उसमें केवल 10 प्रतिशत उत्पादन हुआ है। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जिस तरह से लगातार घटिया बीज का वितरण हो रहा है। इसी तरह से लगातार पिछले 6-8 महीने से बिजली की कटौती को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता प्रभावित है।

श्री अजय चंद्राकर :- उमेश जी, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं।

श्री उमेश पटेल :- यह शून्यकाल है, प्रश्नकाल नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप विद्वान आदमी हैं।

श्री उमेश पटेल :- आप भूल जाते हैं कि हम लोग सत्ता में नहीं हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- आप विद्वान हैं। आज बिजली का जितना उत्पादन हो रहा है, वह डिमाण्ड से ज्यादा है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन यह बिजली नहीं दे रहे हैं। जनता को बिजली नहीं मिल रही है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- बिजली का उत्पादन इम्प्रूव कर रहा है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अगर बिजली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो बिजली को कौन खा रहा है ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन बिजली की डिमाण्ड कम है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्पादन को बाहर दे रहे हैं, बेच रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी मोर करा कतका उत्पादन हे, तेला देखात हों, मोर डाहर के घांव बिजली बंद हे तेला।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी, आप अनुपूरक देख लीजिए। अभी अनुपूरक पर आपकी बात पर बोलूंगा, रुकिए। अध्यक्ष महोदय, बार-बार वह पूरे विषय को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि किसान बहुत आशाभरी निगाह से देख रहा है। बिजली की जिस तरह से लगातार कटौती हो रही है, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बार रायगढ़ जिले में 26 घंटे लगातार बिजली बंद रहने का रिकार्ड बना है। इससे पहले आज तक 26 घंटे तक कभी लाइन बंद नहीं रही।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी वहां पर कलेक्ट्रेट में बैठक लेने गए थे, तो उसमें क्या आप चाय-नाश्ता के लिए गए थे?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, तो क्या मैं इस बड़ी पंचायत में कुछ न बोलूं?क्या आप चाहते हैं कि क्षेत्र की बैठक में बोलूं, यहां न बोलूं?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मंत्रीमन के क्षेत्र में घलोक लाइट गोल होवत हे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप नाराज मत हों, बोलते जाओ। आप अपने फ्लो में बोलिए। ये आपको रोकना चाहते हैं, आप बोलते जाओ। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- इन्होंने कहा कि उत्पादन कम हुआ तो यह पिछली सरकार का बीज वितरण था या इस सरकार का था? क्योंकि अभी तो बीज रोपा गया है। (व्यवधान)

श्रीमती अंबिका मरकाम :- उत्पादन अभी जोरदार आया है, आप बीज दे नहीं रहे हैं, इसे बोलिए। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज..। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, उमेश जी अपनी बात बोल रहे हैं, आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?इनको बोलने दीजिए।

श्री बालेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, डिस्टर्ब हम लोग नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप चालू रखिए। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से इनको दंड मिलना चाहिए।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप तो चालू रखिए।(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- [XX][2]

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,पूरे छत्तीसगढ़ के किसान बहुत आशाभरी निगाह से देख रहे हैं। नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। मेरे जांजगीर के साथी यहां बैठे हैं, वह बतायेंगे कि जांजगीर से रायगढ़ जिले के लोगों को नहरों से पानी तक नहीं मिल रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली वर्षा की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में बराबर नहीं है। बस्तर में बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे साइड में अच्छी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप नियम-प्रक्रिया देख लीजिए कि स्थगन, ध्यानाकर्षण तत्काल घटित घटना पर होता है। भूपेश बघेल जी के तथ्य में यह आया है कि एक हप्ते पहले स्थिति यह थी, तो इनका ड्राफ्ट एक हप्ते पहले का है। मैं बार-बार वही कह रहा हूं कि सूचना देकर यह चर्चा मांगें ना। एक हप्ते पहले की घटना पर आज स्थगन चर्चा कैसे होगी?(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम वर्तमान की समस्या पर चर्चा चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लगातार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। ये लोग जानबूझकर किसानों के मामले में व्यवधान कर रहे हैं। आप लोग पहले भी उन्हें बर्बाद कर चुके हैं और इन पांच सालों में भी किसानों को बर्बाद करने की सोच रखते हैं।(व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे पांच साल अमानक बीज, अमानक खाद, अमानक पेस्टीसाइड के बारे में हमने प्रश्न उठाये और प्रश्न उठाते-उठाते प्रदेश की जनता ने इनको अमानक कर दिया और जो अमानक मंत्री थे, वह बेचारे यहां पर आ भी नहीं पाए। अमानक पांच साल किए, इसलिए यहां पर आकर बैठे हो। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अमानक को इधर बिठा दिया दादा लेकिन मानक को उधर बिठाया बाकी आपको अमानक कर दिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज। सदस्यगण, बैठिए। उमेश जी, आप समाप्त कीजिए।

[XX][2]अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात शुरू कर रहा हूं, यह लोग करने ही नहीं दे रहे हैं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं जैसे ही अपनी बात शुरू कर रहा हूं, कोई न कोई सत्ता पक्ष के सदस्य मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह शून्यकाल की सूचना है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, हम लोग आज विपक्ष में है, कल फिर सत्ता में आयेंगे, आप लोग भी विपक्ष में आयेंगे, वह अलग विषय है। मैं एक चीज कहता हूं कि यहां छत्तीसगढ़ में अगर कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, यहां की इकोनॉमी में कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, तो वह छत्तीसगढ़ का किसान होगा, यहां का अन्नदाता होगा (मेजों की थपथपाहट) । मैं इसीलिए आप सब से कहता हूं कि बिजली की कटौती लगातार चल रही है। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, आप के पास ही बिजली विभाग है। यहां लगातार 26 घण्टे बिजली गुल होने का रिकॉर्ड बना है। इससे किसान हैरान व परेशान है। यहां जब ट्रांसफार्मर जलता है, तो 7 दिनों तक ट्रांसफार्मर नहीं लग पाता है, इससे किसानों की स्थिति बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, हम सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे, बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस विषय में चर्चा कराईये।

अध्यक्ष महोदय :- संगीता सिन्हा जी, अपनी बात रखिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहलाता है। आज की स्थिति इतनी खराब है, चाहे मैं बीज के विषय में कहूं, चाहे बिजली के विषय में कहूं, चाहे खाद के विषय में कहूं। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, तो वहां 90-92 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। यदि कोई किसान खेत में धान की बोआई करता है, तो उसे सबसे पहले बीज, खाद और पैसे की जरूरत होती है। यदि आप खाद की स्थिति देखेंगे तो लोग तरस रहे हैं। वहां पर हमारे ओरमा के लोग, करही भदर के लोग कलेक्टर से जाकर मिल रहे हैं, खाद, डी.ए.पी. की मांग कर रहे हैं। वे उनके बदले में उन्हें दूसरा खाद पकड़ा रहे हैं, जिसे 3-4 बोरी डालने में भी असर नहीं हो रहा है। साथ ही जो खाद की बोरी 50 किलो की होती थी, उसे 45 किलो की कर दिये हैं। यह सरकार सिर्फ किसानों को लूटने का कार्य कर रही है। मैं बीज की बात करना चाहूंगी। हमारे यहां पुराने जमाने में एक रिवाज था। उस समय रूमाल में बांधकर बीज को चेक किया जाता था, आज भी वह रिवाज चल रहा है। आज भी किसान जब खेत में बीज को बोते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि उसमें कितना अंकुरण हो रहा है, उसके लिए वे रूमाल में बीज को बांधकर उसका अंकुरण देखते हैं। उसमें 10 प्रतिशत बीज का ही अंकुरण होता है, 90 प्रतिशत बीज का अंकुरण होता ही नहीं है। यह स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे मांग करते हैं कि इसमें स्थगन ग्राह्य किया जाये। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वह बिजली का विषय है, बिजली बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास सत्ता पक्ष के लोग आकर बैठते हैं, सत्ता पक्ष के

लोगों की भी शिकायतें हैं, वह बोल नहीं पा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग शांत है क्योंकि वे लोग विपक्ष में नहीं बोल पायेंगे, विरोध नहीं कर पायेंगे। इसलिए हमारे पास बैठकर सत्ता पक्ष के कुछ साथी इस विषय में चर्चा भी किये हैं।

समय :

12.17 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- सभापति महोदय, इसीलिए तो आपको स्थाई रूप से उधर भेज दिया गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं चैलेंज करती हूं कि हमारे राज्य की जनता आप लोगों से इतनी त्रस्त्र है कि यदि आज चुनाव करा दिया जाये तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आ जायेगी (मेजों की थपथपाहट)।

एक माननीय सदस्य :- आप चुनाव के लिए 5 साल इंतजार करिये।

श्री राम विचार नेताम :- संगीता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लोकसभा में बहुत अच्छा सपोर्ट किया है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप विषय में बोलिये। आप मंत्री जी की तरफ ध्यान मत दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं बिजली के बारे में बता रही हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कन्हारपुरी गांव है। आज मेरे पास वहां से फोन आया कि वहां 48 घण्टों से बिजली नहीं है। यदि आपको लाईट गोल में रहने बोल दिया जाये तो आप 5 मिनट में फोन कर दें।

सभापति महोदय :- आप इधर देखकर बोलिये। आप अधर देखकर बोलेंगी तो मामला बिगड़ने लगता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है। जबकि पांच साल में हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, हमने बिजली बिल हॉफ किया था। विष्णु देव साय जी की सरकार ने जब पूर्ववर्ती सरकार की बात मानी कि हम बिजली बिल हॉफ योजना को जारी रखेंगे तो हमने उनको बधाई दी। लेकिन उसका उल्टा हो गया। इन्होंने बिजली बिल हॉफ तो किया लेकिन बिजली का बिल बढ़ा दिया। आज हमारे जो गरीब तबके के साधारण लोग हैं, वह 50-100 रूपये बिजली बिल पटाते थे, वह आज एक हजार रूपये बिजली का बिल पटा रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात मैं संज्ञान में ला देती हूँ। यहां इस सदन में माननीय मंत्री जी लोग बैठे हैं। मेरे यहां का एक किसान है, उसका आधा एकड़ खेत है, उसके पास डेढ़ लाख रूपये का बिजली का बिल आया। सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश

में बिजली का उत्पादन उतना ही है, जितना पहले था। अभी हमारे सदस्य, सत्तापक्ष के लोगों ने कहा कि ...।

श्री सुशान्त शुक्ला :- सभापति महोदय, यहां पर दीदी बता नहीं रही हैं। वह पिछले कार्यकाल का बिल बता रही हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा है तो यह बिजली कहां जाती है ? यदि यहां पर बिजली का उत्पादन है तो आप क्या दूसरे प्रदेश को बिजली बेच रहे हैं। यह हो सकता है कि आप लोग चिटिंग करके, दूसरे राज्यों को बिजली दे रहे हैं और हम से बिजली की कटौती कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि ....।

श्री सुशान्त शुक्ला :- सभापति महोदय, यहां पर माननीय बहन जी अपनी बात बता रही हैं। हमारी बात नहीं बता रही है।

सभापति महोदय :- माननीय सुशान्त जी, आप बैठिए। उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि आपको क्षेत्र की जनता ने चुना है। उनकी जो सोच है, उसे सही करिये।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये। इस विषय में बोलने वाले माननीय सदस्यों की बहुत लम्बी सूची है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करती हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। इसमें स्थगन लाकर, चर्चा करायी जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, माननीय सदस्या बोल रही हैं कि यहां स्थगन लाकर चर्चा करायें। आपने स्थगन प्रस्ताव तो लाया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि कार्यवाही रोककर, इस स्थगन में चर्चा करायी जाए।

सभापति महोदय :- देखिए। मेरा आप सब से यह आग्रह है । मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलवा रहा हूँ। अभी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य कवासी लखमा जी बोल रहे हैं। मेरा अन्य माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि आप बातों को रिपिट मत करिये और यहां पर जो नयी-नयी चीजें छूटी हैं, उनको बोलिएगा। मैं एक-एक करके, सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे रहा हूँ।

श्री कवासी लखमा (कोंटा):- सभापति महोदय, हम लोगों ने यहां स्थगन प्रस्ताव दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से माननीय विष्णु देव जी की सरकार बनी है तब से इस छत्तीसगढ़ में क्या

हो गया ? यहां बिजली का बिल अधिक आ रहा है। यहां के गरीब लोग बिजली का बिल नहीं पटा पा रहे हैं। अब कम वर्षा के कारण, बस्तर और कोण्डागांव जिले में जो मोटर चल नहीं पा रहे हैं, वहां पर लगातार चल रहे हैं। उसके साथ-साथ हमारे बस्तर में जो खाद, बीज नहीं मिल रहा है। इतना महंगा होने के बाद भी, अभी तक बस्तर में खाद, बीज नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। हम उधर से भी बात करें और इधर से भी बात करें । यह किसानों का मौसम है। यह किसानों का प्रदेश है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इधर, उधर की नहीं, कोई एक तरफ की बात करिये।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, यह किसानों का प्रदेश है। इसलिए प्रतिपक्ष के लोगों को बहुत दु:ख है। माननीय सदस्य मंत्री नहीं बनने पर कितने कलप रहे हैं। सदन में यह बार-बार उठ रहे हैं कि मुझे कब मंत्री बनायें। हम क्या करेंगे। माननीय विष्णु देव साय जी नहीं सहेंगे। एक ऐसा ही कर रहे थे तो उनको दिल्ली भेज दिया गया। न उनको उधर कुछ मिला, न इधर कुछ मिला। इनका भी यही होगा। आप यहां पर चुपचाप बैठिए। जब मोदी जी देंगे तब मिलेगा। यह न माननीय विष्णु देव जी के पास है न इनके पास है और न ही किसी के पास है। आपके केवल एक ही नेता हैं।

सभापति महोदय :- आप बिजली खाद में आ जाईये। आप प्रधानमंत्री में पड़े हो।

श्री कवासी लखमा :- इसलिये आप आराम से बैठिए। हम लोगों का आशीर्वाद होगा।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय दादी कितना स्टॉक है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अब उधर चला गया।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, जब केदार कश्यप बांटेंगे। केदार कश्यप भईया, दोनों बाजू वाले हट जाएंगे तभी आपको मौका मिलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, एक बात स्थापित है। अभी यहां पर खाद, बीज की कमी पर स्थगन लाये हैं, लेकिन पूर्व में दादी जिस विभाग के मंत्री थे उन्होंने कभी प्रदेश में उसकी कमी नहीं होने दी।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, अभी क्या हालत है कि अब सड़कों में नकली शराब बिक रही है। यहां पर डबल इंजन की सरकार है तो उसका डबल रेट है। यहां डबल इंजन की सरकार है तो यहां भी रखना है और ऊपर भी भेजना है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय दादी, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके पास स्टॉक है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी बैठिए। मेरा आग्रह सुन लीजिए। आप बहुत बढिया बोल रहे हैं। अपनी पूरी बात बोलिए। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य के भाषण में टोका-टाकी मत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करिये। क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है। आगे की कार्यवाही पेंडिंग है। सब महत्वपूर्ण विषय है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ही उठ रहे हैं। बाकी मंत्री उठ रहे हैं। सब छोड़ कर चले गये। यहां पर न विधायकों का काम होता है, न कुछ होता है वे भी बहुत नाराज हैं। उनके क्षेत्र में भी खाद, बीज की समस्या है। उनके क्षेत्र में बिजली नहीं है। जनता इन लोगों को भी सिखा रही है। आप लोग वहां जाकर, क्या कर रहे हैं ? आप वहां बैठकर क्या कर रहे हैं ?

सभापति महोदय :- वे आपसे मिलकर, अपनी समस्या का निराकरण कर लेंगे। आप तो अभी भाषण दे दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, मैं ज्यादा न बोलकर, मेरा आपसे यही निवेदन है कि कल भी हम लोगों ने स्थगन लगाया था । हमारा छत्तीसगढ़ किसान लोगों का प्रदेश है, इसलिए चाहे सामान्य क्षेत्र के लोग हों, आदिवासी लोग हों, 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य मिलेगा इसलिए मरार, भाटा, हर खेत में ज्यादा मात्रा में धान बोये हैं। लेकिन उनके पास बिजली नहीं है, खाद नहीं है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि इस स्थगन को ग्राह्य करें, हम लोग उसमें गहराई से जानकारी देंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप जी। एक, डेढ मिनट में बोल दीजिए। अभी 18-20 लोगों की सूचना है।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, किसान होने के नाते कृपा करके मुझे ज्यादा बोलने का अवसर दें, मैं खेती किसानी की नब्ज को जान रहा हूं। वर्तमान में प्रदेश में बढ़ती मंहगाई का असर खेती किसानी पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। खाद, बीज, डीजल और मजदूरी के रेट में दोगुना इजाफा होने के चलते किसानों को अब प्रति एकड़ लगभग 25000 रुपये से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा धान पर दिये जाने वाले बोनस से राहत मिलने के आसार थे लेकिन इस साल खाद, बीज, मजदूरी, बिजली के दाम में वृद्धि और बढ़ोत्तरी होने से अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। केन्द्र एवं राज्य की सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किये जाने के लिये सिर्फ घोषणायें एवं वादे किये जाते हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही मंहगाई से खेती, किसानी झुलस रही है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य स्थगन पढ़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि स्थगन पढ़ रहे हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं खेती किसानी के विषय में अवगत करा रहा हूं न। मैं मंहगाई के विषय में बात कर रहा हूं कि किसान को खेती किसानी में वर्तमान में कितनी लागत आ रही है।

श्री रामकुमार यादव :- वह गंभीर विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- कोई तथ्यात्मक विषय आये, तब बात करें।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं विषय को तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूं।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, आप आसंदी की तरफ देखिये। आप सीधे विषय में आ जाईये।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, एक किसान होने के नाते वर्ष 2023 में हम सामान्य रूप से मोटा धान 2800 रुपये में खरीदते थे, इस बार हम 3400 रुपये में मोटा धान खरीद रहे हैं। पतले धान को 3900 रुपये में और सुंगधित धान को 4500 रुपये में खरीदे हैं। बीज विकास निगम से मैं खुद पंजीकृत कराता हूं। पंजीकृत कराने के बाद वहां पर हमारा बीज जाता है, जब हमारा ग्रीडिंग होता है, ग्रीडिंग के अतिरिक्त हमें पैसा कम मिलता है। जब हमारा धान सूखकर बिल्कुल कम हो जाता है, पैकिंग में पैसा मिलता है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि हम सब किसानों को जब ग्रीडिंग हो जाये, ग्रीडिंग के बाद पैसा मिलना चाहिए। उस समय भी 10 प्रतिशत की कमी हो जा रही है, वहां लगातार इतनी कटौती कर दी जाती है, इतने भूसे और दाने निकलवा दिये जाते हैं। किसानों को बीज निगम में लाभ के अनुरूप नुकसान हो रहा है। इस साल जब किसानों ने देखा कि सरकार 3100 रुपये में धान खरीदेगी। इस बार बीज निगम में धान कम गया और धान कम जाने के कारण धान के बीज की पूर्ति इस बार खरीफ फसल में किसानों को कम हुई। किसानों को मजबूरीवश बाजार से बीज लेना पड़ा। बीज विकास निगम ने ऐसे बीज सप्लाई किये जो प्राइवेट बीज कंपनी से खरीदे गये हैं। मैं सरकार को इस बात से अवगत करना चाहूंगा कि ऐसे प्राइवेट संस्थान पता नहीं कहां से बीज लेकर आते हैं जिनके बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। हम लोगों को दो बार, तीन बार तक लगाना पड़ा है। मैं स्वयं इस बार धान लगाया था। वह धान का उपार्जन, जर्मिनेशन नहीं हुआ। मुझे दूसरी बार धान का बीज लेकर लगाना पड़ा है। ऐसा इस बार क्यों हो रहा है ? इसका एक मात्र कारण है कि सही ढंग से उसका परीक्षण नहीं हो पाता। बीज का सही ढंग से परीक्षण नहीं होने के कारण ये स्थिति बन रही है। खाद के संबंध में कहना चाहूंगा कि जान-बूझकर डी.ए.पी. की कमी की जा रही है। हम सबको पता है कि खरीफ की फसल में हमें डी.ए.पी. की पूर्ति आवश्यक रहती है। हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में हमारी इतने हेक्टेयर जमीन में इतनी डी.ए.पी. लगेगी। लेकिन यह सरकार डी.ए.पी. की पूर्ति नहीं कर पा रही है। 20:20:0:13 जिसमें सल्फर की मात्रा रहती है, जान-बूझकर ऐसे खाद की सप्लाई नहीं की जा रही है जिनकी कीमत अधिक है, हम जनरली सुपर फास्फेट खाद का उपयोग नहीं करते। बाजार में सुपर फास्फेट खाद 50 रुपये कम कीमत में मिल रही है। हमें जान-बूझकर सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सुपर फास्फेट खाद थमाई जा रही है। यूरिया की भी कमी आ रही है। हम 266 रुपये की यूरिया को 350 रुपये में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्यायें हैं। इस बात के लिए इस सदन में स्थगन के माध्यम से चर्चा करना आवश्यक है।

सभापति महोदय :- धन्यवाद।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं कुछ और चीज में बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- आप सुनिये न। आप दूसरे सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक बिंदु पर बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- आपके ही लोग तो बोल रहे हैं तो उनको अवसर दीजिये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, हमारे ही लोग बोलेंगे। विशेष रूप से कुछ बिंदु है। आपका संरक्षण चाहिए।

सभापति महोदय :- समाप्त करिये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं एक बात आवश्यक रूप से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश तो है ही परंतु 100 प्रतिशत कृषि हमारे जांजगीर-चांपा जिले में होती है। चूंकि सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सरकार के द्वारा बैंक की घोषणा की गई थी, लेकिन बैंक नहीं खुला है। एक ही बैंक से 50 हजार किसान पैसा लेते हैं। धुरकोट और केरा गांव में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा उस समय जिला सहकारी बैंक की घोषणा की गई थी, वह प्रक्रियाधीन है। कृपा करके मैं शासन से मांग भी करूंगा कि धुरकोट और केरा गांव में जिला सहकारी बैंक प्रारंभ किया जाए, जिससे हम सबको लाभ होगा।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। श्री दलेश्वर साहू जी।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, एक और विषय है। किरित सोसायटी में वर्ष 2020-21 में धान खरीदी की गई थी, धान खरीदी का भुगतान नहीं हो पाया है। कुछ किसानों को धान का भुगतान हुआ है, उसको भी वर्तमान सरकार के द्वारा डी.पी.आर. के माध्यम से वापस लेने का काम किया जा रहा है। जांच में किसानों को गलत नहीं पाया गया है। किसानों को कृपा करके परेशान न किया जाए। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री दलेश्वर साहू जी। आप भी थोड़ा शार्ट में अपनी बात रखियेगा। बहुत से लोग हैं।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, खरीफ एवं रबी फसलों के लिए कृषि विभाग द्वारा जिला स्तर के मांगों के अनुसार से खाद की पूर्ति तीन-चार विभाग मिलकर करते हैं, जिसका मुख्य जिम्मेदारी मार्कफेड के द्वारा होता है और मार्कफेड का दायित्व बनता है कि वह 60 प्रतिशत खाद किसानों के लिए सुरक्षित करना अनिवार्य करे। एक सामान्य तौर पर अगर 60 प्रतिशत से भी ज्यादा खाद हो तो निजी फर्म को 40 प्रतिशत खाद उपलब्ध कराये, लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे पूरे राज्य में खाद की किल्लते दिखाई पड़ रही है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस 60 प्रतिशत को इधर कर दिया गया है और 40 प्रतिशत को उधर कर दिया गया है। मेरे पास राजनांदगांव का चार्ट है, मैंने कृषि विभाग से निकलवाया है। यह लादन शब्द कहां से आया? हमारी

Uncorrected and unedited/Not for Publication Tuesday, July 23, 2024

सरकार के पहले पिछली सरकार में भी लादन चालू हुआ था। फिर से भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आने के बाद यह लादन, नैनो यूरिया, नैनो डी.ए.पी. खाद, लिक्विड खाद यह मार्कफेड के माध्यम से नहीं लेकिन कृषि विभाग के निजी संस्थाओं के माध्यम से निजी फर्म को लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह लादन किसानों को जबरदस्ती दिया जा रहा है और किसान को कटौती करके निजी क्षेत्र को ज्यादा पूर्ति करते हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि हमारे दिए हुए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए, जिससे हमारे क्षेत्रीय विधायक इस पर विस्तार से अपने-अपने हिसाब से चर्चा करेंगे। इस पर पक्ष भी चर्चा करेंगे और विपक्ष भी चर्चा करेंगे और अपने क्षेत्र की बात रखेंगे। यह तो किसानों की हित का मामला है और डी.ए.पी. खाद और यूरिया जैसे खाद की किल्लत होना क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके चर्चा कराई जाये।

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव जी। शार्ट में बोलियेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में किसान खाद, बीज, बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर को लेकर जितना परेशान हैं, जब से किसान खेती कर रहे हैं शायद वे इतना परेशान कभी नहीं रहे हैं। विष्णु देव साय सरकार में किसान साय-साय परेशान हैं। दोनों हाथों से उनको लूटा जा रहा है। किसान को ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, अगर उसे दूसरा दिन ट्रांसफार्मर चाहिए तो उसका अलग रेट है, तीन दिन बाद चाहिए तो उसका अलग रेट है। आप उसका एक रेट तक कर दीजिये, उसकी सार्वजनिक रूप से रेट सूची चिपका दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 25 के.व्ही. के ट्रांसफर्मार उड़ जाते हैं और 63 के.व्ही. का ट्रांसफार्मर लगवाते हैं तो उसका भी अलग रेट है। दोनों हाथों से ट्रांसफार्मर के नाम से किसानों को लूटा जा रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आपके रिकॉर्ड में स्पष्ट है कि कितना डी.ए.पी. खाद सोसायटी में पहुंचा है। आप भी किसान पुत्र हैं, आप इस बात को जानते हैं कि डी.ए.पी. खाद किसान के लिए कितना जरूरी है, लेकिन आप किसानों को डी.ए.पी. खाद क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर इसका क्या कारण है ? सरप्लस बिजली, साय सरकार बनते ही वह बिजली कहां चली गयी ? यह भी जांच का विषय है और इसमें भी चर्चा होनी चाहिये । किसानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जानबूझकर जब खेती का समय होता है उस समय किसानों को बिजली नहीं मिलती । इस प्रदेश में उद्योगपतियों के लिये बिजली है, उद्योगपतियों की एक मिनट भी बिजली गोल नहीं होती है लेकिन गांव में रहने वाले गरीब मजदूर-किसानों के लिये बिजली नहीं है, खेती के लिये बिजली नहीं है इसलिये यह स्थगन बहुत आवश्यक है ।

सभापति महोदय :- थोड़ा जल्दी करिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह किसानों का मामला है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसानों को असली बीज ही नहीं मिलेगा तो फसल कैसे पैदा होगी ? मैं आपके

माध्यम से यह मांग करता हूं कि नकली बीज की सप्लाई हुई है जिससे समूचे प्रदेश में कितने किसानों को नुकसान हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और मैं आपसे यह मांग करता हूं कि उनके नुकसान के जो सप्लायर हैं उससे रिकवरी करके उनको मुआवजा दिया जाये । यह स्थगन बहुत आवश्यक है । माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि कृपया इसको ग्राह्य करें इसी निवेदन के साथ धन्यवाद ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, खाद, बिजली अउ बीज ला लेके हमन जौन स्थगन के प्रस्ताव लाये हन निश्चित ही आज पूरा प्रदेश के किसान अपन आप ला ठगे हुए महसूस करत हे । खाद के किल्लत पूरा प्रदेश में जेन हिसाब से चलत हे, डीएपी ला देखबो तो जेन निजी व्यापारी हे ओखर मन के गोदाम में भरे पड़े हे लेकिन सोसायटी में डीएपी काबर नइ आत हे ये चिंताजनक विषय हे । किसान मन ला कहत हे या तें एसएसपी डाल दे या एनपीके डाल दे । जेन ला डीएपी के जरूरत हे ता ओहा डीएपी डारही । काबर एनपीके अउ एसएसपी डारही ? लेकिन किसान मन ला डाले बर मजबूर करत हे, किसान ला जरूरत हे ता ओ हा डारबे करही । हरियर बोरा नागपुर ले आत हे । खातु के बोरा हरियर रंग के नागपुर ले आत हे अउ खातु ला छिंछबे ता बराबर ओखर गुणवत्ता नइ मिल पात हे । यह स्थिति हे । हमन बीज के बात करन तो सुवर्ण । पर्याप्त मात्रा में जेन बीज के भण्डारण सोसायटी में होना चाहिए तेन नइ हे । समय में नइ मिल पइस । कुछ मन ला मिलिस अउ जेन मन ला नइ मिलिस तेन मन का करए जबर्दस्ती जाकर निजी दुकान से बीज ला खरीदिन । माननीय सभापति महोदय, मैं आप ला बता देना चाहत हऔं कि धान के एक ठन नुजिवीडू (Nuziveedu) करके बीज आये हे, संपदा । माननीय मंत्री महोदय, जेन ला किसान मन लेत हे, 10 प्रतिशत घलो बीज में अंकुरण नइ होत हे फेर दोबारा बोत हे तो जेन कंपनी नुजिवीडू (Nuziveedu) के जो बात करत हंऔं ओखर उपर कार्रवाई होना चाहिए जेन मन किसान ला ठगे के काम करत हे ।

माननीय सभापति महोदय, इस बीज में तो प्रतिबंध होना चाहिए । जेखर कारण आज किसान मन ला डबल धान के बीज ला छींछे बर पड़िस अऊ आज ओमन ऊपर वाले के बाट जोहत हे । सबसे बड़े बात यह है कि बिजली के जेन आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होना रही लेकिन अभी मैं स्वयं अपन विधानसभा के बात बतात हंऔं खामभाट फीडर वितरण केंद्र । तेमे 4 ठन गांव अइसे हे फूलसुंदरी, खामभाट, रीवागहन अउ आदरणीय महाराजपुर । रीवागहन में 72 घंटा से बिजली के सप्लाई बंद । एक-दू घंटा बर बीच में चलथे लेकिन एक सप्ताह से आज स्थिति यह है कि आज ओ गांव वाले मन कथे कि पीये बर मत मिलय लेकिन एकाध-दू घंटा घर में चलय ता लोग-लइका ला आराम से सुता सकन या बिजली मिलय ता कहीं कुछ कर सकन तो यह स्थिति हे, आज बिजली के आपूर्ति नइ होत हे । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूं कि हमन एक उम्मीद के साथ धान के जेन बीज ला लेथन । जब हमर सरकार रिहिस हे तो 2640-2660 रूपये तक धान के समर्थन मूल्य बढ़ायेन ओखर बाद अंतिम तक 2800 रूपये । आप 3100 रूपया देकर पाछू डहर ले बीज के कीमत ला बढ़ा के 600 से

1100 रूपये प्रति क्विंटल लेत हओ तो ऐमे हमन स्थगन लाये हन । माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन हे कि ये स्थगन ला स्वीकार करके आप ऐमे चर्चा कराहू । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- धन्यवाद, सभापति महोदय। अभी जो बात हो रही थी, लगभग जांजगीर जिले में भी वही हाल है। जहां तक 90 प्रतिशत जर्मिनेशन होना चाहिए। 10 से 20 प्रतिशत तक की भी शिकायतें गांव से आ रही हैं। हमारे यहां डी.ए.पी. और बाकी खाद भी कई सोसाइटी में नहीं है और वहां पर कहा जा रहा है कि आप दूसरी खाद खरीदिए। ये सरकारी आंकड़ा ही मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां पर पोटाश और एन.पी.के. खाद को 119 और 103 प्रतिशत बताया गया है कि इतनी खाद हम लोगों ने सप्लाई कर दी है, वितरण की जा चुकी है और वहीं जब यूरिया और डी.ए.पी. की बात आ रही है तो 63 और 79 प्रतिशत पर उसको रोक दिया गया है। जब किसान बार-बार खाद मांग रहा है, उसको खाद दी नहीं जा रही है और कहा जा रहा है कि आप दूसरी खाद का उपयोग करिए। हमारे यहां टेल एरिया में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। यहां पर अभी बांध के भरने की बात हो रही थी । हसदेव, बांगो अभी भी 50 प्रतिशत के ऊपर नहीं गया है। पानी वहां से छोड़ा नहीं जा रहा है और बीच में स्थिति ये थी कि 2 दिन इतना पानी छोड़ दिया गया कि किसानों ने जो फसल लगाई थी, वह पूरी की पूरी खराब हो गई। उसके बाद पानी कम किया और अब इतना पानी कम कर दिया गया है कि वह टेल एरिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी किसानों को बोला जा रहा है कि बाजार से आप खाद खरीदिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सभापति महोदय, लगातार बिजली जा रही है, साथीगण बार-बार कह रहे हैं कि बिजली ज्यादा आ रही है तो यह जानने की भी आवश्यकता है कि अगर प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है तो गांव वालों तक पहुंच क्यों नहीं रही है? बार-बार बिजली काटी जा रही है। सभापति महोदय, बस 1 मिनट आपका लूंगा। 719 के.व्ही.ए. हमारे बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मरों में वृद्धि करना प्रस्तावित किया है। लेकिन वृद्धि तो छोड़िए वहां पर ट्रांसफार्मर तक नहीं बदले जा रहे हैं और 7-10 दिन तक बिना बात वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाने पर लो वोल्टेज में लोग जी रहे हैं। आपसे निवेदन है इसे ग्राह्य करें और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय जी, वर्तमान में खेती-किसानी का काम तीव्र गति से चालू है और किसानों को धान, बीज, खाद से लेकर कीटनाशक और खरपतवार नाशक की एक्सपाइरी सामग्री कृषि केंद्र में मिल रही है। जांजगीर जिले में पामगढ़ विधानसभा की बात करूं तो किसानों का ही यह निवेदन था कि उनको किसानी में प्रयोग के लिए डी.ए.पी. खाद में विश्वास है और एन.पी.के. खाद में उपलब्ध सल्फर की उपयोगिता भूमि में कम है। ज्यादातर तिलहन की खेती में सल्फर का प्रयोग होता है और हमारे जिला में तिलहन नहीं के बराबर होता है। अभी उपलब्ध खाद में

20:20:0:13 में पोटाश का प्रतिशत भी जीरो है, जबकि पोटाश पौधे की मजबूती के लिए आवश्यक है। अब किसानों को पोटाश की कमी के लिए अलग से खरीदना पड़ रहा है जिससे लागत में भी वृद्धि हो रही है। और रही बात ट्रांसफार्मर की तो रोज़ दिन में चार से 6 ट्रांसफार्मर के लिए किसानों की शिकायत आती है और लगने में भी बिजली विभाग में बात करने में हफ्ता से 10 दिन लग जाता है क्योंकि हमारे यहां ट्रांसफार्मर रायगढ़ से आता है। तो इसके लिए विशेष निवेदन है कि हमको इसके लिए बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए समय दिया जाए।

सभापति महोदय :- जी, आपकी उपस्थिति हो गई। जी, बिल्कुल सही। श्रीमती अनिला भेंडिया। आप 2 मिनट में बोल लीजिए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय सभापति महोदय। आज हमारे सदस्यों के द्वारा स्थगन लाया गया है किसानों को अमानक बीज, अमानक खाद, बिजली में कटौती होने के कारण आज पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं, क्योंकि आज सोसाइटी से भी खाद मिल रहा है, वह भी कम है और वही खाद अगर हमारे प्राइवेट क्षेत्र में प्राइवेट लोगों के पास दुकानदारों के पास खाद है, उसी से महंगे रेट में हमारे किसान खरीद रहे हैं, जबकि सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है और आज जो अमानक धान है, जो आज हमारे कुंवर सिंह निषाद जी जो बोल रहे थे, वह धान पूरे बालोद जिला में बंटा हुआ है। किसानों ने उसमें जो बीज डाला, उसके बाद जगह नहीं, उसके बाद से उन लोग प्राइवेट दुकानों से लेकर, महंगे में खरीदी कर फिर से डबल बुवाई किये हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान चारों तरफ से मारे जा रहे हैं। एक तो बारिश लेट हुई उसके कारण भी और एक तो सरकार की जो नीतियों के कारण हैं। आज हमारे पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। आज किसान बिजली ऑफिस में जाते हैं तो बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों से इतनी अनाप-शनाप मांग की जाती है तो किसान उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कहां से किसान इतना पैसा से उनकी फीस जमा कर पाएंगे? इसलिए एक निर्धारित रेट तय कर देना चाहिए, बिजली ऑफिस में चस्पा कर देना चाहिए कि इतने के.व्ही. का लगाएंगे तो इतना लगेगा। इतना लगाएंगे तो इतना लगेगा। निर्धारित कर दे तो किसान भी संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि महंगाई की दर और बिजली की जो आज स्थिति है, वह बहुत ही गंभीर है। इसलिए आज हम सरकार से शासन से मांग करेंगे कि स्थगन पर चर्चा कराई जाए।

सभापति महोदय :- जी। श्री अटल श्रीवास्तव।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश कहलाता है । जब से यह सरकार बनी है, जब से बीजों का रेट 30 से 40 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, जिससे किसान हलाकान हैं । बिजली की समस्या की बात आई, खाद की बात आई । खाद की यह स्थिति है कि बिचौलिए चारों तरफ फैल चुके हैं । बिचौलियों को यदि डीएपी का खाद बेचना है तो उसके साथ 400 रूपए का कीटनाशक केमिकल बेचते हैं । यदि आप वह खरीदेंगे, तभी आपको डीएपी खाद

मिलेगी, यह किसानों की स्थिति हो रही है । पूरा का पूरा राज्य बिचौलियों से घिर गया है चाहे वह अमानक बीजों की बात हो या खाद की सप्लाई की बात हो । माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं बिजली की समस्या ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे कोटा विधान सभा क्षेत्र में सांप पकड़ने वाली सौंरा जाति के लोग हैं, उनके यहां बिजली बिल 10 हजार, 20 हजार और 25 हजार रूपए तक पहुंच रहा है । उन्होंने कहा था कि यदि हमारा बिजली बिल कम नहीं हुआ तो हम बिजली ऑफिस में जाकर सांप छोड़ेंगे । आप देखिए कि क्या स्थिति है, सांप के जरिए रोजी रोटी कमाने वालों का बिजली बिल 10 से 15 हजार रूपए आ रहा है और ट्रांसफार्मर की स्थिति इतनी खराब है कि एस.टी. इलेक्ट्रिकल पुणे की कंपनी को काम दिया गया है, जिसे 100 करोड़ के ट्रांसफार्मर सप्लाई का काम दिया गया है । सभापति महोदय, उन्होंने अभी तक केवल 6 परसेंट काम पूरा किया है । पता नहीं कौन सी कंपनी है, किसकी कंपनी है, कहां से आई है । हमारे गांव के किसान बिजली के लिए हाहाकार कर रहे हैं, इसलिए निवेदन है कि हमारे स्थगन को स्वीकार किया जाए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- अटल भइया जानकारी की कमी है । आपकी सरकार के कार्याकल में टेंडर हुआ था, जो उनको मिला है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप केस चढ़ा दो ना, कमीशन लेकर बैठ गए क्या ।

सभापति महोदय :- आप डायरेक्ट मत बोलिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जानकारी का अभाव है ।

सभापति महोदय :- मुझे भी मालूम है, आप बैठिए ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- सभापति जी, आज हमर दल के द्वारा किसान के संबंध में बहुत अच्छा स्थगन प्रस्ताव लाए गे हे । आज छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाथे । अउ किसान के हित मा आज बड़े सदन में चर्चा नइ होही ता कहां पर होही । किसान के दुख का ये सरकान ला हमन नइ बतबो ता कोन मेर बताबो । आज मोला वो प्रधानमंत्री जी के याद आवत हे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी कहे रिहिस हे जय जवान, जय किसान । आज प्रदेश अउ देश में अगर किसान के अउ जवान के सम्मान होथे तो वो प्रदेश ला आगे बढ़े ले कोई रोक नइ सकय । लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्तमान सरकार किसान ला रूलाए के काम करते हे । जइसे के बीज, किसान मन ला जो बीज देत हे वो बीज सड़ जात हे । तीन बेर छिटव ता लटपट जागत हे । बिजली के बात कहते हे, सुन लवव तुमन के बिजली अइसने जलत हावय, वो बिजली ला लालटेन लेकर जाकर देखे बर लागत हे । ओतके कन कमजोर बिजली जलत हे अउ बिजली बिल ला भरपूर भेजत हावव । मोर आपसे निवेदन हे, गरीब के बिजली ला कम करव, किसान के बिजली ला कम करव अउ लाल बहादुर शास्त्री कहे रहिस हे जय जवान, जय किसान । वइसने काम करव, दिल्ली मा घेलो किसान मन ला दुख देवत हौ, इहौं दुख देवत

हौ, ओखर आंसू ला पोंछने वाला कोई नइ हे । किसान के आह तुमन ला जरूर लगही, अउ किसान के आह लगही । अउ किसान के आह लगही तो जर के भसम हो जाहौ ।

सभापति महोदय :- श्रीमती चातुरी नंद । समय कम है थोड़ा जल्दी बोलिएगा।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहत हौं कि एक तरफ सरकार हर खाद के कमी नइ हे काहत हावय । अउ दूसर तरफ किसान मन खाद के कमी के कारणा खेती किसानी छोड़कर सोसायटी मा घूमत हावय। एखर अलावा किसान मन ला डीएपी नइ दिए जाव हे । अउ दूसर खाद थमा दिए जात हे, दूसर खाद के रूप मा एनपीए खाद उपलब्ध कराए जात हे । सोसायटी में डीएपी कम, अउ दूसर प्रायवेट दुकान में डीएपी की मात्रा में कोई कमी नहीं है, मतलब भरपूर भंडार हे । किसान ला गारंटी देवइया सरकार आज किसान मन ला खाद तक नइ दे पात हे ये बहुत बड़ा विडंबना के बात हे । संगवारी हो, साथ मा यह बताना चाहत हौं कि बीज समय पर नइ मिलत हे । मूंगफली, उरिद, मूंग एखर समय रथे जून के लास्ट महीना मा । अउ जून के अंतिम सप्ताह मा भी ये बीज सोसायटी मा उपलब्ध नइ होय हावय ।

समय :

12:50 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बीज अभी-अभी सोसायटी मा आए हे तो अगर समय पर बीज उपलब्ध नइ कराए जाही तो जगाए और बोए के दिन में उपलब्ध नइ होही तो एखर कोई महत्व नइ रही । मैं एक चीज अउ कहना चाहत हौं कि अभी अभी सोसायटी मा भेजे गे हे ओखर जगाय के समय निकल गे हावए। मोर क्षेत्र में एक मोहन मुंडा गांव हे। अभी बात होत रिहिस कि 48 घंटा और 72 घंटा बिजली नई आवत हे, बिजली कटौती होवत हे। लेकिन मैं बता देना चाहत हौं कि मोर क्षेत्र के एक गांव मोहन मुंडा हे, वहां 15 दिन तक बिजली कटौती करे गे रिहिस हे। साथ ही जो बिजली बिल आवत हे, ओ डबल आवत हे। गरीब किसान मन, गरीब मइनखे मन, जेखर एकल बत्ती हे, ओमन ला हर महीना बिजली बिल नई दे के आमन ला इकट्ठा बिजली बिल देवे जात हे। जेन मइनखे हा जब कमात हे, तब खात हे, तेखर अगर महीना मा या 6 महीना मा, 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार बिजली बिल आत हे, त रोज के कमईया व्यक्ति ए बिजली बिल ला कइसे पटाही। संगवारी हो, मैं अंत में यही कहना चाहत हौं कि

बिजली बिल के कटौती होवत हे साय-साय
बिजली बिल के कटौती होवत हे साय-साय
और बिजली बिल आवत हे, आय-बाय।
अउ जनता करत हे कांय-कांय।
अउ ट्रांसफार्मर घलो उड़त हे ठाय-ठाय।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहत हों कि स्थगन ले के ऐमा चर्चा करे जाए। धन्यवाद।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांकेर के भानुप्रतापपुर सोसायटी में व्यापारी लोग डी.ए.पी. खाद का फायठा उठाकर जो निर्धारित मूल्य है, उससे अधिक दाम में बेच रहे हैं। साथ ही खाद लेने के लिए इन समितियों को चार पांच दिन तक लगातार उस सोसायटी का चक्कर लगाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि कांकेर जिले के पखांजूर में नकली खाद का गोरखधंधा चल रहा है, बीते दिनों पखांजूर में कृष्णों कृषि सेवा केन्द्र के गोदाम से 20 बोरिया नकली खाद मिली है। इतना ही नहीं इसी व्यापारी के नाम से ई वे बिल जनरेट हुआ है जिसमें 830 बोरी खाद का लाट राजस्थान के जयपुर से मंगाया गया था। जो व्यापारी है, वह खाद को मात्र 330 रूपये प्रति क्विंटल में खरीदकर वहां के स्थानीय किसानों को 50 किलोग्राम का पैकिंग बनाकर 1760 रूपये में बेचता था। वह व्यापारी पहला लाट खपाने के बाद दूसरा लाट मंगाया था। इस प्रकार से उस आदिवासी इलाके में सुदूर अंचल के किसानों को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ नकली खाद से फसल का नुकसान होने की बहुत संभावना है। इस प्रकार की घटना से स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों के मामले में गंभीर नहीं है। यह मेरे कांकेर जिले का मामला है, हो सकता है कि पूरे प्रदेश में इस तरह का नकली खाद का गोरखधंधा फल-फुल रहा हो। माननीय विभागीय मंत्री जी इस गंभीर विषय पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही इस गंभीर विषय पर चर्चा कराई जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए अंत में आप बोल लीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानी पर जीवन निर्भर है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, यह सभी जानते हैं। आज खाद और बीज की समस्या को लेकर किसान इतने ज्यादा परेशान हैं कि हर जगह शिकायत का मौका मिल रहा है। सबसे ज्यादा डी.ए.पी. खाद की मांग है। जब फसल की शुरूआत होती है तो सबसे ज्यादा डी.ए.पी. खाद की जरूरत होती है। जब भी सोसायटियों में जा रहे हैं तो सीधा कहा जा रहा है कि डी.ए.पी. खाद आ ही नहीं सकता। उसका सीधा कारण यह है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में चस्पा कर दिया गया है। डी.ए.पी. खाद की जगह पर एस.एस.पी., एवं एन.पी.एन. खाद का उपयोग किया जाए, जिसकी उपलब्धता है ही नहीं, जिसको किसान चाह ही नही रहे हैं, वह खाद उनको मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी जैविक खाद के लिए भी लोग तत्पर रहते हैं लेकिन जैविक खाद सोसायटियों में मिलना बंद हो गया है, पहले कंपोस्ड खाद, सुपर कंपोस्ड खाद, जो कि हमारे गौठान से निर्मित होते थे, उसको बंद करवा दिया गया । अध्यक्ष महोदय, आज किसानों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, आज कृषि उपकरणों में निरंतर महंगाई

को देखते हुये भी 28 परशेंट का भारी-भरकम जीएसटी लगाया गया है और तो और पोटाश की कीमत 3 गुना बढ़ा दी गई है । अध्यक्ष महोदय, खाद, बीज और कीटनाशक के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में कृषि कार्य 15 फीसदी महंगा हो चुका है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतना अधिक धान में मिलावट हो रहा है, अभी बदरा के बाद हल्दी पानी से डूबाकर धान दिया जा रहा है, किसानों को बीज सरलता से उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानी ठप्प होती जा रही है और किसान बाजार में जाकर बीज खरीद रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जब इस कदर महंगाई बढ़ रही है, उनके साथ अनाचार हो रहा है, अत: मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इसको सदन में लाया जाये । अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है, बिजली की शिकायत आये दिन हो रही है, किसान जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं कि ट्रांसफारर्मर जल गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर उपलब्ध होगा तभी तो लगायेंगे...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, न केबल उपलब्ध है, न ट्रांसफार्मर उपलब्ध है, 6-6 दिनों तक बिजली बंद रहती है, किसान हर जनप्रतिनिधि को संपर्क करते हैं । अध्यक्ष महोदय, हम इसमें स्थगन लाना चाहते हैं, आपसे इसे ग्राहय करने के लिये निवेदन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

समय
12.57 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में किसानों को अमानक खाद, बीज, कीटनाशक एवं बिजली कटौती के संबंध में

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में किसानों को अमानक खाद, बीज, कीटनाशक एवं बिजली कटौती की समस्याओं के संबंध में 34 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है :-

प्रथम सूचना	-	श्री भूपेश बघेल
दूसरी सूचना	-	श्री उमेश पटेल
तीसरी सूचना	-	श्रीमती संगीता सिन्हा
चौथी सूचना	-	श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
पांचवी सूचना	-	श्री दलेश्वर साहू
छठवी सूचना	-	श्री द्वारिकाधीश यादव
सातवीं सूचना	-	श्री रामकुमार यादव
आठवीं सूचना	-	श्री कुंवर सिंह निषाद
नवमीं सूचना	-	श्री कवासी लखमा

दसवीं सूचना	-	श्री विक्रम मण्डावी
ग्यारहवीं सूचना	-	श्री बघेल लखेश्वर
बारहवीं सूचना	-	श्री भोलाराम साहू
तेरहवीं सूचना	-	श्रीमती अनिला भेंडिया
चौदहवीं सूचना	-	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
पन्द्रहवीं सूचना	-	श्री दिलीप लहरिया
सोलहवीं सूचना	-	श्री फुलसिंह राठिया
सत्रहवीं सूचना	-	श्रीमती शेषराज हरवंश
अठारहवीं सूचना	-	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
उन्नीसवीं सूचना	-	श्री लालजीत सिंह राठिया
बीसवीं सूचना	-	श्री संदीप साहू
इक्कीसवीं सूचना	-	श्री बालेश्वर साहू
बाईसवीं सूचना	-	श्री अटल श्रीवास्तव
तेईसवीं सूचना	-	श्री इन्द्र शाह मण्डावी
चौबीसवीं सूचना	-	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
पच्चीसवीं सूचना	-	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
छब्बीसवीं सूचना	-	श्रीमती अम्बिका मरकाम
सत्ताइसवीं सूचना	-	श्री इन्द्र साव
अट्ठाईसवीं सूचना	-	श्रीमती कविता प्राण लहरे
उन्नतीसवीं सूचना	-	श्री जनक राम ध्रुव
तीसवीं सूचना	-	श्री ओंकार साहू
इक्तीसवीं सूचना	-	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
बत्तीसवीं सूचना	-	श्रीमतली विद्यावती सिदार
तैंतीसवीं सूचना	-	श्रीमती चातुरी नंद
चौतीसवीं सूचना	-	श्री देवेन्द्र यादव

चूँकि श्री भूपेश बघेल की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :-

हमारे कृषि प्रधान प्रदेश में खरीफ वर्ष 2024 के लिये किसानों की खाद-बीज की मांग तथा बिजली की मांग सरकार समय पर पूरी नहीं कर पा रही है । D.A.P. 18 : 46 खाद की मांग की जा रही है, लेकिन वितरण केन्द्रों के द्वारा D.A.P. के बदले दूसरी खाद लेने के लिये ऋणी किसानों को बाध्य किया जा रहा है । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं में नोटिस चस्पा किया गया है कि D.A.P.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

18:46 की कमी को देखते हुये विकल्प के रूप में S.S.P. एवं N.P.K. खाद का उपयोग किया जाए । वैकल्पिक खाद की आपूर्ति भी अब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं की गई है। कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव आदि जिलों में नकली खाद व बीज बेचे जाने की शिकायतें लगातार किसानों से प्राप्त हो रही है । बीज वितरण केन्द्रों में धान के बीज को हल्दी के पानी में डुबाकर फिर इसे सुखाकर किसानों को बेचा जा रहा है। वितरित बीजों में अंकुरण बहुत कम हो रहा है । किसानों द्वारा अधिकारियों को शिकायत किए जाने के बाद भी नकली खाद बीज विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है । बाजार में अमानक कीटनाशक बेचने वाले भी सक्रिय है । राजनांदगांव-मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी में गांवों में खाद, बीज माफिया पहुंचकर सीधे साधे किसानों को झांसे में लेकर कृषि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में खेती किसानी का काम तीव्र गति से चालू है । किसानों को धान बीज, खाद से लेकर कीटनाशक और खरपतवार नाशक की एक्सपाइरी सामग्री कृषि केन्द्रों से पहुंच रही है । राजनांदगांव के चंडी मंदिर के समीप छत्रपति बीज भण्डार द्वारा एक्सपायरी दवाइयां विक्रय की जा रही है । शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । बेमेतरा, पंडरिया के दुकानदारों के पास चार या छः कम्पनी का प्रिंसपल सर्टिफिकेट एवं लायसेंस रहता है, लेकिन वे अधिक कम्पनियों की दवाएं, कीटनाशक, बीज व खाद गैर कानूनी तरीके से विक्रय कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राजधानी के पास मंदिर हसौद में ग्वालियर से ट्रकों में भरकर लाई गई अमानक खाद को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, परन्तु मामले को समाप्त कर दिया गया । इन अनेक समस्याओं के कारण प्रदेश के लाखों किसान त्रस्त हैं ।

समय :

1:00 बजे

कम वर्षा के कारण खेती के लिए बिजली की मांग बढ़ी है, परन्तु गांवों में अघोषित कटौतियां की जा रही हैं । सरकार के संरक्षण में निजी दुकानों में खाद किसानों को दोगुने दाम पर उपलब्ध हो रही है । विभाग द्वारा अधिकृत निजी संस्थाओं से प्राप्त करके सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले प्रमाणित बीज की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि कर कम अंकुरण क्षमता वाले बीज देकर किसानों को आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है । बिजली की दरों में वृद्धि की मार भी पड़ रही है । खाद, बीज की कमी तथा अघोषित बिजली कटौती से सिंचाई नहीं होने के कारण धान की फसल गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है ।

इस प्रकार प्रदेश में खाद, बीज की कमी, अघोषित बिजली कटौती आदि बहुत संवेदनशील मुद्दा बन गया है ।

अत: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे विपक्ष की ओर से आज स्थगन के माध्यम से प्रदेश भर के किसानों की समस्या, खाद-बीज की समस्या, बिजली कटौती की समस्या को लेकर स्थगन लाया गया है । मैं समझता हूं कि सदस्य पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, उसमें से 80 प्रतिशत जन प्रतिनिधि किसान बैकग्राउण्ड से ही हैं । उससे ज्यादा ही होंगे । आपकी चिन्ता उतनी ही है, हमारी चिन्ता उतनी ही है । जहां तक अल्पवृष्टि की बात है, इसे भी कोई नकार नहीं सकता । कहीं अतिवृष्टि हो रही है तो कहीं अल्पवृष्टि है । खासकर कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक बारिश हुई है, जिसके चलते वहां पर स्थिति दूसरी बनी हुई है । वहीं पर सरगुजा में खासकर बलरामपुर जिला, जशपुर जिला, अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया में बहुत कम बारिश हुई है । इन बैक क्षेत्रों में अचानक बिजली की आवश्यकता अधिक पड़ रही है, पावर की जरूरत अधिक पड़ रही है । इन तकनीकी की वजह से भी उन क्षेत्रों में कुछ अव्यवस्था हो रही है, वरना प्रदेश भर में कहीं भी स्थिति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद-बीज की बात है । मैं वक्तव्य में अपनी बात को रख रहा हूं कि अभी पूरे प्रदेश में जो भण्डारण किया गया है, खासकर यूरिया, डीएपी, एनपीके के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं, । यूरिया का भण्डारण 104 प्रतिशत किया गया है । डीएपी 84 प्रतिशत है और एनपीके भी पर्याप्त है । हम लोग लाखों जनता से चुनकर आते हैं, हम जनता की ही नुमाइंदगी करते हैं । पूरे प्रदेश में हम जनप्रतिनिधि होने के नाते एक जिम्मेदार जवाबदेह हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप वक्तव्य पढ़ दें ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, हम सबको कम से कम वैसा परसेप्शन नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप वक्तव्य पढ़ दें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बोल रहा था ।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक बार पूरा वक्तव्य पढ़ दें ।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खरीफ वर्ष 2024 के लिए रासायनिक उर्वरकों की कुल मांग 13 लाख 68 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 14 लाख 5,987 हजार मीट्रिक टन उर्वरकों का भण्डारण कराया गया है, जिसमें से दिनांक 22.07.2024 की स्थिति में 10 लाख 28 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में 9 लाख 63 हजार मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया था। प्रदेश में खरीफ 2024 हेतु डी.ए.पी. की कुल मांग 3 लाख 40 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 2 लाख 84 हजार मीट्रिक टन का भण्डारण किया जाकर 2 लाख 35 हजार मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में 48,523 मीट्रिक टन डी.ए.पी. का स्कंध वितरण हेतु शेष है। राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डी.ए.पी. की कम आपूर्ति के दृष्टिगत एस.एस.पी. एवं एन.पी.के. का उपयोग करने किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। एस.एस.पी. की कुल मांग 2 लाख मीट्रिक टन के विरूद्ध 2 लाख 6 हजार मीट्रिक टन का भण्डारण किया जाकर 1 लाख 31 हजार मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। इसी तरह एन.पी.के. की कुल मांग 1 लाख 20 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 1 लाख 64 हजार का भण्डारण करते हुए 1 लाख 25 हजार मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया गया है। अत: यह कहना सही नहीं है कि राज्य शासन द्वारा डी.ए.पी. विकल्प के रूप में एस.एस.पी. एवं एन.पी.के. खाद की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

खरीफ वर्ष 2024 हेतु बीज की कुल मांग 9 लाख 78,191 क्विंटल आंकलित की गई थी, जिसके विरूद्ध राज्य की कुल बीजों की उपलब्धता 10 लाख 20 हजार क्विंटल है। 9 लाख 38 हजार क्विंटल से अधिक बीज का भण्डारण किया जा चुका है, जिसमें 8 लाख 53 हजार क्विंटल से अधिक बीज का उठाव कृषकों द्वारा किया जा चुका है, जो गत वर्ष के इसी अवधि के उठाव से 7 लाख 92 हजार क्विंटल से 61 हजार क्विंटल अधिक है। इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि बीज की पर्याप्त पूर्ति नहीं की जा सकी है।

कृषि आदानों के गुण नियंत्रण के उद्देश्य से बीज कुल 5,065 नमूने प्रयोगशाला को प्रेषित किए गए हैं, जिसमें से मात्र 137 नमूने अमानक पाये गये हैं। इस प्रकार कीटनाशक रसायनों के 338 नमूने अभी तक प्रयोगशाला को प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 89 प्रतिशत नमूने मानक पाये गये हैं तथा मात्र 25 नमूने अमानक पाये गये हैं

उर्वरक के कुल 3,469 नमूने विशलेषण हेतु प्रेषित किये गये हैं, इनमें से 1,460 नमूने विशलेषित किये जा चुके हैं, जिनमें से मात्र 24 नमूने अमानक पाये गये हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि गुणवत्ता सनिश्चित करने सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

पुलिस महानिरीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मंदिर हसौद क्षेत्र अन्तर्गत अमानक खाद पकड़े जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में खाद विक्रेता द्वारा सीधे किसानों तक पहुंचकर उन्हें झांसा देने सम्बन्धी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में त्वरित कार्यवाही करते हुए जैविक खाद एवं वाहन को जब्त कर जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस जिले में विभागीय निरीक्षकों के माध्यम से 89 बीज विक्रय केन्द्र, 40 उर्वरक विक्रय केन्द्र एवं 38 कीटनाशक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण अब तक किया गया है, जिनमें कालातीत दवाओं का भण्डारण एवं विक्रय नहीं पाया गया है।

बेमेतरा जिले में केवल 02 किसानों के द्वारा बीज अंकुरण के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मेसर्स तिवारी कृषि केन्द्र ग्राम-घोटमर्रा, विकासखण्ड-बेरला को जारी बीज विक्रय अनुज्ञा निरस्त कर दी गई है।

राजनांदगांव जिले के चंडी मन्दिर के समीप छत्रपति बीज भण्डार द्वारा कालातीत दवाईयां विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित परिसर का दिनांक 06.07.2024 को कीटनाशक निरीक्षक डोंगरगांव द्वारा निरीक्षण कर कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 की धारा 21(1) (डी) के तहत कार्यवाही कर कीटनाशी दवाओं को जब्त किया गया है, जिसके अनुक्रम में संबंधित फर्म द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने के फलस्वरूप उप संचालक कृषि सह अनुज्ञापन अधिकारी (कीटनाशक) के आदेश क्रमांक-1858 दिनांक 15.07.2024 के माध्मय से संबंधित को जारी अनुज्ञप्ति प्राधिकार पत्र क्रमांक- 761 को 30 दिवस के लिये निलंबित किया गया है संबंधित से 9 लीटर कीटनाशी रसायन एवं 32 कि.ग्रा. कीटनाशी पावडर जप्त किया गया है।

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा किसानों की मांग अनुसार प्रमाणित बीजों की निरंतर आपूर्ति की जा रही है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित बीजों का ही भण्डारण किया जाता है। कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव जिले में निगम द्वारा भण्डारित बीजों के संबंध में कहीं भी नकली बीज विक्रय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह कथन सर्वथा असत्य है कि बीज वितरण केन्द्रों में धान बीजों को हल्दी पानी में डूबाकर किसानों को बेचा गया है। बीज निगम द्वारा वितरित प्रमाणित बीजों में उपरोक्त उल्लेखित जिलों सहित प्रदेश में कहीं भी अंकुरण कम होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं प्रदेश में प्रमाणित बीजों की कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्तानुसार स्थगन सूचना में अंकित आक्षेप तथात्मक नहीं है। यह सब मनगढ़ंत हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। अतः स्थगन सूचना ग्राह किये जाने योग्य नहीं है।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। आपने अपने भाषण में जशपुर की बात कही, कोरिया की बात कही और सरगुजा की बात कही और उसे स्वीकार किया। आपने दूसरी बात यह भी बताई कि भारत सरकार की ओर से डी.ए.पी. कम मिल रहा है। आपने तीसरी बात स्वीकार किया है कि बीज अमानक है, टेस्ट किया गया है और 133 फेल हैं, खाद में 25 फेल हैं। आपने सभी चीजों को स्वीकार कर लिया है तो फिर यह राजनीति से प्रेरित कहां है? खाद भी नकली, बीज भी नकली, दवाई एक्सपायरी डेट और बिजली कटौती को आपने स्वयं स्वीकार कर लिया है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थगन को ग्राह्य करके इसपर चर्चा कराएं। मंत्री जी ने स्वयं कहा कि यहां 80 प्रतिशत नहीं, बल्कि शत प्रतिशत किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, उसके विकल्प के तौर पर बाकी चीजें हैं।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, मैं तो वही बात कह रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप ट्रेजरी बेंच में हैं, आप आसंदी से आग्रह कीजिए। आपने स्वयं कहा कि यहां सत्ता पक्ष के विधायक भी बैठे हैं और वह भी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप उसे ग्राह्य कर लें, ताकि सत्ता पक्ष के

विधायक भी अपने क्षेत्र की बात कह लें और हमारे विपक्ष के साथी भी अपनी बात कह लें। स्थगन का मतलब सरकार को घेरना नहीं होता है । इसका मतलब यह है कि जो समस्या आ रही है, उसका समाधान करना। आप जो कह रहे हैं, उसको आपने स्वीकार कर लिया। आपने कह दिया कि एनर्जी मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आपने कह दिया कि आपको रैक नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। आपने भारत सरकार पर भी आक्षेप कर दिया। आपने यह भी स्वीकार कर लिया कि आप आप स्वयं अक्षम हैं। आपको खाद-बीज नहीं मिल रहा है, फाउण्डेशन सीड नहीं मिल रहा है और व्यापारियों से खरीदना पड़ रहा है। आपने यह सब स्वीकार कर लिया है। आप इसको ग्राह्य कर लें और इस पर चर्चा करवा लीजिए। यह किसानों का प्रदेश है और हम सब किसानों के प्रतिनिधि हैं। सबके यहां समस्याएं हैं। रेट बढ़ने के बारे में भी भाई ब्यास जी ने कहा। आप बीज निगम से 2,800 रूपये में बीज खरीद रहे हैं और धान को 3,100 रूपये में खरीद रहे हैं तो आपके बीज निगम में कौन धान बेचेगा? जब बीज निगम में बीज ही नहीं है तो फिर आपने बीज का वितरण कहां से कर लिया? आपके पास बीज ही नहीं है, जिसके कारण से आपने प्रायवेट सोसायटियों के माध्यम से बीज खरीदा और उसको हल्दी पानी में डूबा-डूबा कर और सूखाकर फिर से बेचने का काम कर रहे हैं। आपने दो का स्वीकार किया कि जनरेट नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में स्थिति यह है कि आप हर विधान सभा क्षेत्र में देखेंगे कि ऐसी सोसायटियों के द्वारा वितरीत धान अंकुरित नहीं हुए। किसानों को ठगा गया है। यह षडयंत्र भी है कि उत्पादन कम हो। यह षडयंत्र भी हो रहा है। आपसे यह निवेदन है कि आप इस स्थगन को स्वीकार कर लीजिए, ताकि इस पर सत्ता पक्ष के सदस्य भी चर्चा कर लें।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय मंत्री जी, आप हमारी सारी बातों से सहमत हैं। हमने स्थगन में जितने बिंदु लाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वयं इन सब चीजों को मान रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- हमने उत्तर में दिया है। यह मानने की बात नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसपर दोनों पक्ष के सदस्य चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि यहां से कुछ सोल्यूशन निकल जाए और छत्तीसगढ़ के किसानों को इस स्थगन से फायदा हो जाए। आपसे निवेदन है कि इसको ग्राह्य करके इसपर चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् शासन का वक्तव्य आने के बाद मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह किसानों के हित का मामला है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह किसानों के हित का मामला है। (व्यवधान)

श्री बालेश्वर साहू :- ये गंभीर मामला है, किसानों के हित का मामला है।(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- यह गंभीर मामला है।(व्यवधान)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आ गए।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। ये पेपर और न्यूज के माध्यम से, अलग-अलग वॉट्सअप के माध्यम से अपना स्थगन बनाए हैं। इनके पास कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में निरंतर नारे लगाए गए।)

समय :
1.18बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

अध्यक्षमहोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

1. श्री भूपेश बघेल
2. श्रीमती अनिला भेंडिया
3. श्री उमेश पटेल
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री भोलाराम साहू
7. श्री लालजीत सिंह राठिया
8. श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े
9. श्री दिलीप लहरिया
10. श्री रामकुमार यादव
11. श्री द्वारिकाधीश यादव
12. श्रीमती अंबिका मरकाम
13. श्रीमती संगीता सिन्हा
14. श्री कुंवर सिंह निषाद
15. श्री देवेन्द्र यादव
16. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा
17. श्री इन्द्रशाह मण्डावी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

18. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
19. श्री विक्रम मण्डावी
20. श्रीमती विद्यावती सिदार
21. श्री फूलसिंह राठिया
22. श्री अटल श्रीवास्तव
23. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
24. श्री ब्यास कश्यप
25. श्री बालेश्वर साहू
26. श्रीमती शेषराज हरवंश
27. श्रीमती चातुरी नंद
28. श्री संदीप साहू
29. श्री इन्द्रसाव
30. श्री जनक ध्रुव
31. श्री ओंकार साहू
32. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें ।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए 3.00 बजे तक स्थगित।

(1.20 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :
3.00 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

निलंबन समाप्ति की घोषणा

सभापति महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, निलंबन बहाल होने से पहले ही विपक्ष यहां आकर बैठ गया है।

सभापति महोदय :- यह उनकी सदाशयता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री उमेश पटेल :- संसदीय कार्यमंत्री जी, आप तो ऐसा मत बोलिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, वास्तविकता यह है कि इनके तथ्यों में कोई सत्यता नहीं थी। इसके कारण केवल दिखावा करने के लिए इन्होंने स्थगन लाया था। लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ, फिर इनका निलंबन हो गया और यह निलंबन समाप्त होने के पहले ही यहां आकर बैठ गये।

सभापति महोदय :- चलिये, जो हुआ सो हुआ। श्री राजेश मूणत जी।

समय :
3.01 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(1) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बिना निविदा एवं कार्यादेश के टी-शर्ट एवं टोपी की खरीदी की जाना।</u>

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने गोल्डन मोमेंट्स संस्थान को रूपए 250 (जी.एस.टी. सहित) की दर से 1.25 लाख टी-शर्ट का एवं रूपए 50 (जी.एस.टी. सहित) की दर से 1.25 लाख टोपी का राजीव युवा मितान क्लब सम्मेलन दिनांक 02/09/2023 के पूर्व आपूर्ति करने का मौखिक आदेश दिया एवं हॉकी स्टेडियम कोटा से सामान वितरण करने का निर्देश दिया गया। संस्थान से उल्लेखित मटेरियल दिनांक 20.08.2023 से दिनांक 01/09/2023 के बीच में गाड़ियों के माध्यम से हॉकी स्टेडियम कोटा में लाया गया तथा उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला खेल अधिकारीगणों ने इन टी-शर्ट एवं टोपी को प्राप्त किया। रजिस्टर में पावती दी तथा गाड़ियों के माध्यम से इन्हें ले गए। पावती में टी-शर्ट एवं टोपी की गणना, गाड़ी का विवरण भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया। इस पूरे कार्य हेतु न कोई निविदा आमंत्रित की गई न कार्यादेश जारी किया गया। सब कुछ मौखिक आदेश से हुआ और यह कार्य कुल रूपए 3 करोड़ 75 लाख (जी.एस.टी. सहित) है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तात्कालीन सरकार में नियम प्रक्रिया की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई एवं मनमाने रूप से कार्य कराया गया। इस नियम विरूद्ध कार्य से शासन एवं प्रशासन के विरूद्ध रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- सभापति महोदय, उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना के सबंध में लेख है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने गोल्डन मोमेंट्स संस्थान को रूपए 250 (जी.एस.टी. सहित) की दर से 1.25 लाख टी-शर्ट का एवं रूपए 50 (जी.एस.टी. सहित) की दर से 1.25 लाख टोपी को विषयांकित सम्मेलन दिनांक 02.09.2023 के पूर्व आपूर्ति करने का मौखिक आदेश एवं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हॉकी स्टेडियम कोटा से सामान वितरण करने का निर्देश नहीं दिया एवं आहरण या भुगतान नहीं किया गया।

नियम प्रक्रिया की अवहेलना नहीं की गई, अतः कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की नियम प्रक्रिया की अवहेलना नहीं की गई। मैं, आपके माध्यम से इतना जानना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम हुआ, खेल एवं विकास विभाग ने उस कार्यक्रम में राजीव युवा मितान क्लब सम्मेलन में टी-शर्ट, टोपी की पूर्ति और इसकी व्यवस्था की या नहीं की ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रक्रिया की अवहेलना इसलिए नहीं की गई चूंकि विभाग ने यह सामग्री क्रय करने का आदेश ही नहीं दिया है। विभाग के पास सामग्री क्रय करने का कोई आदेश नहीं आया, न निविदा हुई है, न खरीदी हुई है और न ही भुगतान हुआ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विभाग के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिये इसमें कोई कार्यवाही या अवहेलना वाली बात नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। मैंने जो प्रश्न पूछा है। मैंने आपसे सीधा प्रश्न पूछा कि जगदलपुर में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में राजीव युवा मितान क्लब सम्मेलन के तहत जो टी-शर्ट, टोपी वितरण की गई, क्या यह विभाग ने वितरण किया या नहीं किया ? मैं इतना ही तो पूछ रहा हूँ। माननीय मंत्री जी केवल उसका उत्तर दे दें। यदि विभाग ने वितरण नहीं किया है तो माननीय मंत्री जी मना कर दें।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, विभाग ने सामग्री का वितरण नहीं किया है। विभाग ने उस कार्यक्रम में कोई टी-शर्ट, टोपी नहीं बांटा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है। मैं यह बहुत दु:ख के साथ कह रहा हूँ। राजीव युवा मितान योजना सम्मेलन के तहत राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर एक पत्रक निकला है। उस पत्रक में डायरेक्टर ने स्पष्ट लिखा है। उसके बाद प्रदेश सरकार से फंडिंग की मांग की है। इसमें केवल फंडिंग की मांग ही नहीं की। विभाग जिस व्यक्ति से कोई सामान नहीं ले रहे हैं, मना कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने विभाग को एक आवेदन दिया। उस आवेदन में विभाग का सील, ठप्पा लगा हुआ है। उसमें स्पष्ट है कि मैंने, आपको इतना-इतना माल सप्लाई किया है। इसका भुगतान किया जाये। अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज सप्लाई नहीं की और आपने कहीं कुछ नहीं लिया तो क्या कोई व्यक्ति सिरफिरा होगा जो वहां आकर आवेदन दे दे और विभाग उसको रिसिप्ट करके रख ले। उसकी प्रोसिडिंग को आगे बढ़ा दे। मैं पुराने इतिहास को नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपके विभाग की बैठक हुई। राजीव युवा मितान सम्मेलन की बैठक हुई । यह होने के बाद आपने राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए टी-शर्ट,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

टोपी का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर देने के बाद, पार्टी ने सप्लाई की। जिस पार्टी ने सप्लाई की है। मुझसे एक अधिकारी ने चैट की है। मेरे पास उसके दस्तावेज हैं, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि इतने टी-शर्ट, टोपी में इतने बाकी है, आप जल्दी पहुंचाईये, कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप कहें तो मैं उस अधिकारी का नाम ले दूं। उस समय की तात्कालीन डायरेक्टर ने मना भी किया कि मैं यह प्रक्रिया नहीं कर सकती क्योंकि किसी भी कार्य के लिए टेण्डर की प्रक्रिया होती है जिसमें हम इतने तक का माल, तीन लाख रूपये तक की साड़ी ले सकते हैं। उसके बाद हमें टेण्डर प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। उस समय मौखिक आदेश दिया गया। तब गिरोह टाईप का पार्टी को बुलाकर, वर्क ऑर्डर दिया है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है। मेरे पास इसके दस्तावेज हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं इसे पटल पर रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास राजीव युवा मितान क्लब सम्मेलन के टी-शर्ट, टोपी के कुछ फोटोग्राफ हैं। यह सब चीजें हैं। अगर ऐसा नहीं था और यदि आपने उस सामग्री का वितरण नहीं किया तो मैं आपके सामने वह चैट भी प्रस्तुत कर सकता हूँ जिस पर विभाग के एक व्यक्ति, अगर आप कहेंगे तो उस व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ। यह हेमंत महापात्र कौन है? उसने चैट की, उसने यह लिखा कि इसमें इतनी चीजें आयी हैं और इतनी चीजें नहीं आयी हैं। यही नहीं, मेरे पास रिसिव है। अगर आप कहें तो हर पन्ने की रिसिव बता देता हूँ। उन अधिकारियों के नाम, पते, फोन नंबर, गाड़ी नंबर, किसने कहां, कितना रिसीव किया। जब विभाग ने वर्क आर्डर नहीं दिया, विभाग ने कुछ नहीं किया तो बिना वर्क आर्डर के माल किसने परचेस किया, किसने रिसीव किया ?

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप इसके ऊपर से प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, यही तो स्वार्थपूर्ण बंटवारा है। राजीव मितान योजना के तहत पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार की अवैध खरीदी हुई है। आपने उस पार्टी को बुला करके बिठा दिया और कहा कि माल सप्लाई करो। अगर आप कह रहे हैं कि माल सप्लाई नहीं हुआ है और कहीं कुछ नहीं हुआ तो मैं तथ्यात्मक जानकारी विधान सभा के पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय :- मैं उनको बोल रहा हूं। आप बोल दीजिए।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जिस फर्म ने भुगतान के लिए आवेदन किया है, जिस फर्म ने टी शर्ट और टोपी सप्लाई किया है तो उस फर्म के पास कार्यादेश भी होना चाहिए, कार्यादेश भी होगा। जब तक वह फर्म सप्लाई करने का कार्यादेश नहीं दिखायेगा, तब तक भुगतान का हकदार कैसे होगा ? खेल विभाग ने उनको सप्लाई करने का आदेश नहीं दिया है। जब खेल विभाग सप्लाई का आदेश देगा और वह फर्म सप्लाई करेगा, तब वह भुगतान का अधिकारी बनेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो वही कह रहा हूं आप कह रहे हैं कि आपने सप्लाई का कोई आदेश नहीं दिया। आपके अधिकारियों ने उस फर्म को बुला करके बात की, क्या मैं उन सबका नाम ले दूं ? अगर आपने सप्लाई का आदेश नहीं दिया तो आप मुझे यह बता दीजिए कि आपने बिना आदेश के 1 लाख 25 हजार टी शर्ट कैसे स्वीकृत ले ली ? अगर आपने आदेश नहीं दिया, आपने यह आदेश मौखिक दिया है कि खरीदी करो हम तत्काल आपको पैसा की व्यवस्था करायेंगे। इस पैसे की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आपके डॉयरेक्टर ने वित्त मंत्रालय को लिख करके भेजा है, इसकी कापी मेरे पास है। अगर ये नहीं था तो वित्त मंत्रालय को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी ? यह 20.03.2024 को लिखा गया है। आप कहें तो इस कापी को पूरा पढ़ देता हूं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, अगर आपने कहा की हमने ऑर्डर नहीं दिया और सामने वाली फर्म ने सप्लाई कर दिया, सप्लाई की रिसीव ले ली, जिले में सब जगह माल ले लिया, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम संपन्न हो गया। आज वह फर्म वाला दर-दर भटक रहा है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, राहुल गांधी जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका बार-बार नाम लिया जा रहा है, इसको विलोपित किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, विलोपित तब होता है जब हम दूसरे अर्थों में उनका नाम लेते हैं।

सभापति महोदय :- कोई आरोप नहीं लग रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वैसे तो हम किसी महापुरूष, किसी आदमी का नाम नहीं ले सकते। वह महापुरूष नहीं हैं, लेकिन किसी महापुरूष का नाम ही नहीं ले सकेंगे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे माननीय सदस्य राजेश मूणत जी क्या चाहते हैं ? क्या ठेकेदार को पेमेंट कराना चाहते हैं ? जब पेमेंट नहीं हुआ है तो इसको इतना खींचने की क्या जरूरत है ? यदि उसको पेमेंट कराना चाहते हैं तो वह बता दें, उसको पेमेंट करा दें। यदि नहीं कराना चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी बोल ही रहे हैं कि हमारे पास कोई कार्यादेश नहीं है। इसको इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या है ?

सभापति महोदय :- वह अभी प्रश्न पूछेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- वह कुछ नई चाहत हे, वह मंत्री बनना चाहत हे।

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए कि आप क्या चाह रहे हैं, फिर मैं माननीय मंत्री जी को जवाब देने के लिए बोलता हूं। मतलब इसमें आप क्या चाहते हैं ?

श्री राजेश मूणत :- मैं तो कुछ नहीं चाहता हूं। मैं तो सीधी-सीधी बात करता हूं। चाहने वाले उधर बैठे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- वह कुछ नई चाहत हे, वह मंत्री बनना चाहत हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- इनका यही उद्देश्य है। मंत्री नहीं बनने के कारण इनको कितना दु:ख हो रहा है। वह भटक रहे हैं। इनको और कोई काम नहीं है, राहुल गांधी, राहुल गांधी बोल रहे हैं। जब मंत्री जी बोल रहे हैं कि उस फर्म को कार्यादेश नहीं है

सभापति महोदय :- लखमा जी, सुनिये तो, आप उनके उद्देश्य को भटकाईये मत। वह राहुल गांधी जी के बारे में कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनके कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं। वह ध्यानाकर्षण लगाये हैं, उस ध्यानाकर्षण में वह क्या चाहते हैं, आप मंत्री जी से पूछ लीजिए। कल कोई बात होगी कि ये नेता आये थे, ये कार्यक्रम हुआ था तो इतना जिक्र हो सकता है। कोई आपत्तिजनक परिप्रेक्ष्य में जिक्र नहीं हो रहा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा स्पष्ट मत है कि माननीय मंत्री जी ने विभागीय उत्तर दिया कि हमने कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिया है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, अपने ध्यानाकर्षण में लिखा हूं। अगर आपने उत्तर में दिया है तो मैं उसमें स्पष्ट लिखा हूं कि आपने कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिया। विभाग ने स्वयं बुला करके मीटिंग की है, सामने वाली पार्टी से राजीव युवा मितान योजना के तहत, मैं उन व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा जो इसमें सदस्य हैं। पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा कि राजीव युवा मितान योजना के डायरेक्टर या इनके कितने सदस्य हैं, यह बता दीजिये। इसका संचालन कौन करता है, उसमें मैं आ जाता हूं और जो मीटिंग में थे, फिर मैं उनका नाम ले लेता हूं। जब वह बता देंगे तब फिर मैं उस पर बात करने आ जाऊंगा।

सभापति महोदय :- आपको पूरा अवसर देंगे, आप पूछते जाईये, मंत्री जी बताते जायेंगे।

श्री टंक राम वर्मा :- सभापति महोदय, राजीव गांधी युवा मितान क्लब की तीन स्तर की समितियां थीं। एक समिति राज्य स्तर पर थी, जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी थे, दूसरा जिला स्तर पर समिति थी, उनका अध्यक्ष कलेक्टर थे और तीसरा अनुभाग स्तर पर समिति बनी थी, उनका अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी थे। ये तीन स्तर पर समितियां गठित हुई थीं और यह समिति फर्म सोसायटी से पंजीकृत थी।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, हो गया। मुझे बस इतनी ही जानकारी चाहिए ।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री राजेश मूणत :- मंत्री जी, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में मीटिंग हुई या नहीं? टोपी और टी-शर्ट खरीदनी है, इसके बारे में निर्णय हुआ है या नहीं हुआ है?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बताईये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप बैठिये न। वह पूछ रहे हैं तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक मिनट। सभापति महोदय, सदन का समय इतना कीमती है कि अगर कोई व्यापारी बगैर आर्डर के मौखिक निर्देश पर सप्लाई करता है और उसकी भुगतान के लिए, उस बात के लिए वह सदन में 10-15 मिनट ले रहे हैं। प्रथम दृष्टा तो यह है।

सभापति महोदय :- वह जनहित में पूछ रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- विषय भुगतान का नहीं, विषय त्रुटि का है जो राजीव युवा मितान के नाम पर मिलकर लूटने का काम किया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, (व्यवधान) कौन समिति में है। आप मंत्री रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप यह तय नहीं करेंगे। एक मिनट।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उन्होंने सप्लाई किया है तो गलत ढंग से सप्लाई किया है। वह मौखिक आदेश पर सप्लाई किया है।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन संसार ला टोपी पहिना के टोपी के बारे मा पूछत हौं।

सभापति महोदय :- आसंदी ने उनको पूछने के लिए अवसर दिया है। यह समय की बर्बादी नहीं है। इस आसंदी की गरिमा है कि वह इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, हम उठाने दे रहे हैं और सही तथ्य आने दीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, रामकुमार जी बार-बार खड़े हो रहे हैं। मैंने सुबह पूछा था, आप भी मेरे बाजू में बैठे थे, वह उतना सारा नोट देख कर आखिर जिंदा कैसे हैं, उसको वह नहीं बता रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- वही होगा जो (व्यवधान) होगा। तुमन कुछू भी करिहा, मोर कुछ होने वाला नई हे। तुंहर बोरा-बोरा ला मैं हर बताहौं। तोर पइसा ला पैरा मा तोप के रखे हस।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। मंत्री जी। रामकुमार जी, अभी राजीव युवा मितान क्लब की बात हो रही है। दूसरा क्लब कहां से आ गया?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, दिनांक 24 अगस्त, 2023 को सी.एस. की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया कि दिनांक 02.09.2023 को एक राजीव युवा मितान क्लब का कार्यक्रम करना है और इसके लिए फिर दिनांक 28.08.2023 को संचालक को प्रस्ताव भेजा गया कि इसमें टोपी और टी-शर्ट क्रय करने के लिए 9.5 करोड़ रूपये की आवश्यकता है। इस बीच दिनांक 02.09.2023 को इसका सम्मेलन रायपुर में सम्पन्न हो गया और सम्मेलन होने के बाद दिनांक 15.09.2023 को आबंटन मिला। दिनांक 09.10.2023 को आचार संहिता लग गई। जो पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसकी खरीदी में, सप्लाई में इस विभाग का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। यह मार्केट में बाहर से ही जो गोल्डन मोमेंट संस्थान नाम बताये हैं, इसको किसने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आदेश दिया, कैसे सप्लाई किया, कैसे वितरण हुआ, यह विभाग से अलग है। हमारा विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है।

सभापति महोदय :- ठीक है। मूणत जी, बताईये।

श्री राजेश मूणत :- आप सब के सुनने लायक चीज है। आप लोग सुनिये कि विभाग कैसे खेल खेलता है। मैंने पहले ही कहा कि मीटिंग किसकी अध्यक्षता में हुई?

सभापति महोदय :- वह तो बता दिए।

श्री राजेश मूणत :- वह तो बता दिये, तारीख आ गई।

श्री कवासी लखमा :- आप भी 15 साल में ऐसी खेलते थे क्या?

श्री राजेश मूणत :- दादी, सुन लीजिये न। हम तो रहे हैं। आप लोगों में ताकत है। आप लोग 5 साल कुछ नहीं कर पाये। आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह घोर आपत्ति है। लखमा जी पूरे प्रदेश को शराबी बनाये हैं और वह कहते हैं कि लखमा जी कुछ नहीं कर सके हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- आप इनको बोलने दीजिये, प्लीज।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मेरा बहुत गंभीर प्रश्न है।

सभापति महोदय :- आप बोलिये। मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- मंत्री जी, मैं आपसे से सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं। आपने कहा कि हमने नहीं किया। मैंने तो यह पूछा है कि अधिकारियों ने जो रिसीव किया इनके नाम, पता इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

समय :
3.20 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण में सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हमने वर्क ऑर्डर नहीं दिया, आपने कुछ नहीं किया । मैं यह कह रहा हूं कि आपने मौखिक ऑर्डर दिया उसकी बैठक की । आपने कहा कि चुनाव की आचार संहिता लग गयी इसके कारण उसको वर्क ऑर्डर तो यह बात क्लियर है । ठीक है । आप केवल इतना बता दीजिये कि डिपार्टमेंट ने उसको रिसीव कैसे किया ? अगर यह तथ्य गलत हैं तो वह स्पष्ट कर दें । मैं आपके विभाग का नाम, पता, एड्रेस सहित दे रहा हूं, आप केवल इतना बता दें । अगर आपने वर्क ऑर्डर नहीं दिया तो यह रिसीव क्यों किया ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये का चाहत हे ? कइसे होगे ? कुकरी पहिली अइस कि अंडा पहिली अइस ? (हंसी) हमन ला अइसे समस्या में डाल दे हे, हमन कुछ समझे नइ पात हन ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी समझ के लायक नहीं है । (हंसी) आप बैठे रहिये । चलिये, आप बोलिये ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि गोल्डन मोमेंट संस्थान को टी-शर्ट और टोपी खरीदने का विभाग के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है । चूंकि पहले विधानसभा सत्र में राजीव युवा मितान क्लब है, इनके कार्यों को देखते हुए, इनकी गतिविधि को देखते हुए राजीव युवा मितान क्लब को भंग कर दिया गया और हमने इसमें वसूली की भी बात की थी तो 132 करोड़ 59 लाख रूपये प्रदाय की गयी राशि में 11 करोड़ 70 लाख 92,000 रूपये अभी तक वसूली की गयी है और 57 करोड़ 62 लाख रूपये की अभी तक वापसी नहीं हुई है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं । मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं । आप सीधा-सीधा बोलिये न कि भ्रष्टाचार जिसने किया, आपने थोड़ी न किया । जिन लोगों ने नियमों के विपरीत जाकर, नियमों को ताक पर रखकर अपनी पूर्ति करने के लिये उन लोगों ने वर्क ऑर्डर दिया कि नहीं दिया तो आपने कहा कि नहीं दिया तो जब आपने वर्क ऑर्डर नहीं दिया तो आपके घर में यह चीजें किसने रिसीव कीं ? आप कहें तो नाम सहित, मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया है, जिसने चेक किया, मैं बता नहीं सकता । मोबाईल एलाउ है कि नहीं, मुझे नहीं पता । नहीं तो मैं पूरा डिटेल बता दूंगा कि आपके विभाग के अधिकारी ने क्या लिखा और आपकी तरफ से क्या उत्तर गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि क्या विधायक दल की समिति से इसकी जांच करायेंगे और जो भी अधिकारी दोषी होंगे क्या उसको दंडित करेंगे ? एक लाईन का उत्तर है ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टी-शर्ट खरीदी और टोपी खरीदी का विभाग के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है, न ही उसका भंडारण किया गया है, न ही निविदा क्रय किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है । अब जो संस्थान है, फर्म है इसने सप्लाई की है तो किसी आधार पर सप्लाई की है ? जैसा कि माननीय विधायक महोदय जी कह रहे हैं कि विभाग ने पावती ली है तो हम माननीय विधायक से अभिलेख ले लेते हैं कि किसने पावती ली है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है । इसमें किंतु-परंतु विषय नहीं है । अगर कोई कहे तो इसमें यह सील लगी हुई है, यदि आंख नहीं है तो आंख का थोड़ा नंबर बढ़ा लो । यह सील देख लीजिये, आपके विभाग की लगी है । यह क्लियर दिखा रहा हूं और यह स्पष्ट है कि जिन-जिन लोगों ने दिया है, इन्होंने कहां-कहां, कितनी-कितनी संख्या में सप्लाई की है इसका पूरा का पूरा सील-ठप्पा सहित है ।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, पावती तो कहीं से भी मिल जाती है । पावती लेने में क्या है ? भैया, पावती कोई आधार नहीं है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब-कुछ होने के बाद मुझे आश्चर्य लग रहा है और आप कहते हैं कि राजीव मितान क्लब किसके अधीन आता है ? अगर विभाग कह रहा है तो विभाग ने पावती क्यों दी और जिसने पावती दी तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? अगर आपका विभाग नहीं था तो उसने लिया क्यों ? और लिया है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी, मंत्री जी प्रश्न करिये लेकिन आवाज ठीक रखिये। इतना उत्तेजित मत होईए । सिम्पल प्रश्न है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय एकदम असत्य बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं। बहुत छोटा सा प्रश्न है। मंत्री जी क्या इस विषय की जांच कराएंगे? इसके लिए तो हां बोलो या नहीं बोलो खत्म करो।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय के पास जो पावती है, जो भी पेपर है, उसको मैं ले लेता हूं और अध्ययन करने के बाद यदि लगता है कि इसमें कार्रवाई किया जा सकता है तो उसमें कार्रवाई जरूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, जांच का आदेश करना है। ठीक है।

श्री राजेश मूणत :- नहीं-नहीं, मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है। माननीय मंत्री जी किसको बचाना चाहते हैं भाई? मतलब आश्चर्य लग रहा है वह गरीब परिवार जो पौने 4 करोड़ रूपये का माल सप्लाई करके आपका डिपार्टमेंट बैठ कर गिरोहबंदी टाइप उसको लूट लिए। पौने 4 करोड़ रूपये विभाग को दे कर गया है। ये पावती है, उसके बाद में अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा और क्या लज्जाजनक बात हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई एक व्यापारी अगर आपके यहां सप्लाई कर रहे है और मैं प्रूफ देने को तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष जी आप कहें तो मैं विधानसभा में आपको सबमिट कर देता हूँ। अगर विधानसभा जो उचित निर्णय करे उसको मानने को तैयार हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा है कि छत्तीसगढ़ में गिरोह बना करके लोग बिठा कर लूटने का काम करेंगे। ऐसा मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी जवाब सुन लीजिए।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो जांच की मांग की गई है, उसके पेपर को ले लेते हैं फिर उसमें आगे। (हंसी) विभाग का उसमें कहीं कोई रोल ही नहीं दिख रहा है। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, वे सही कह रहे हैं। आप लोग डुप्लीकेट अपराधी पकड़े हैं, वैसे डुप्लीकेट होगा।

श्री टंकराम वर्मा :- सभी विषयों की जांच कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करायेंगे। हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग तो कुछ मत बोलो। गड़बड़ घोटाला तो आपका ही है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम लोग वह बर्दाश्त कर लेंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- कागज डुप्लीकेट रखे हैं। (हंसी)

श्री देवेन्द्र यादव :- फिर आप क्यों छिपा रहे हो? आप क्यों छिपा रहे हो? हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। ठीक है। उन्होंने जांच के लिए बोल दिया है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, वो कागज हो सकता है, डुप्लीकेट हो। जैसे अपराधी डुप्लीकेट पकड़ा गया तो जांच करने दीजिए न, मंत्री जी को थोड़ा मौका दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विषय आ गया। अब क्या बचा है? (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- माननीय, मैं इतना ही कह रहा हूं। मेरा इसमें कहीं मेरा कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं है, नहीं तो जीवन में आरोप तो बहुत सारे लग सकते हैं और मैं कोई पुराने किसने किया, वह नहीं जिसने प्रक्रिया में त्रुटि की है, जिसने हायतौबा मचाकर वह कार्य किया है और माननीय मंत्री महोदय इस चीज़ को नकार रहे हैं कि विभाग के अधिकारी ने नहीं किया। मेरा बहुत स्पष्ट प्रश्न है, मेरा मूल प्रश्न है, सर, इसमें मेरा एक लाइन स्पष्ट है कि अगर विभाग ने कुछ नहीं किया है तो सर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग इसको रिसीव करने का हक कैसे रखता? सीधा एक लाइन का प्रश्न है, उत्तर कुछ नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री राजेश मूणत :- और जिन लोगों ने यह त्रुटि की, उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो संस्था ने सप्लाई किया, क्या उसका पेमेंट विधिवत होगा, इसका उत्तर क्लियर है। बस, इसके आगे कोई लेना-देना नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, मैं थोड़ा बोल दूं। वे पूछ रहे हैं,मंत्री जी जवाब दे रहे हैं पर असली देवेंद्र यादव बैठे हैं और राजीव मिलान क्लब वाले।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा नाम हमारे वरिष्ठ नेता ने यहां पर लिया है तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं अगर सदस्य को इस बात की उनकी जो चिंता है कि किसी एक व्यक्ति से कागज़ देकर उनसे काम करवा लिया गया और भुगतान नहीं किया गया तो ये सही में एक तरह से जांच का विषय है कि इसकी कैसे किसी भी व्यापारी से या किसी भी व्यक्ति से अधिकारी कोई भी काम करा लेते हैं और इसके बाद उसका भुगतान नहीं होता है। वह भी अन्याय की श्रेणी में आता है तो न्याय संगत होना चाहिए। इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता मंत्री जी को इसमें बोलने पर चिंता क्यों हो रही है? न्याय-संगत होना चाहिए, जो होना चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ठीक। अजय जी कुछ बोलना चाह रहे थे? एक साथ जवाब दे देंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इतना ही जानना चाहता हूं ये गोल्डन मूवमेंट संस्थान कहां की है और इसका मालिक कौन है? (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये भी चाहता हूं केवल भुगतान की जांच न हो। नियम विरूद्ध, बगैर वर्क ऑर्डर, बगैर टेंडर, बगैर सप्लाई नीति के संबंधित व्यापारी ने सप्लाई किया तो जांच के बिंदु में यह भी रहना चाहिए कि उसने नियम विरूद्ध कैसे सप्लाई किया ?

श्री राजेश मूणत :- सहमत ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात समझ में नहीं आती कि माननीय मंत्री जी इस पर कोई स्पष्टता क्यों नहीं दे पा रहे हैं । आपको क्या चिंता है या आपका क्या सम्पर्क है ?

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी हा समझ गे हे, टी-शर्ट ला वो लिही अउ मंत्री जी ला टोपी पहनाए जात हे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए जवाब दे दीजिए ।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे विभाग के द्वारा न तो सप्लाई करने का आदेश दिया गया है और न ही निविदा, न खरीदी और न ही भुगतान किया गया है । विभाग से इसका दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है । लेकिन इस फर्म ने सप्लाई किया है । निचले स्तर पर जहां स्टेडियम में वितरण किया है । जैसा कि बता रहे हैं कि उसमें पावती भी है । फर्म भुगतान के लिए मांग रहा है तो किस आधार पर उसने सप्लाई किया, किसके कहने से सप्लाई किया । भुगतान क्यों मांग रहा है ? इन सब विषयों की जांच कराएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, हो गया अब ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गोल्डन मूवमेंट संस्थान कहां का है और उसका मालिक कौन है, यह पूछा है ?

श्री टंकराम वर्मा :- अब पता करेंगे कि यह कौन है, कहां का है ?

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मैं संरक्षण चाहता हूं । केवल इतना बता दीजिए कि ये हेमंत महापात्र आपके खेल विभाग का कौन है ?

अध्यक्ष महोदय :- जांच में सब आ जाएगा ।

श्री राजेश मूणत :- मैं पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । आप कह रहे हैं कि मेरे विभाग का कोई लेना-देना नहीं, कहीं कुछ नहीं । उसने, उस व्यक्ति के साथ चैट किया, बातचीत की, पेपर दिया, रिसिव किया । उसने कहा कि इतना सामान नहीं पहुंचा है, इतनी देर क्यों कर रहे हो, इसको पहुंचाओ । वह व्यक्ति विभाग की तरफ से संवाद कर रहा है, लिखापढ़ी कर रहा है और विभाग बिल्कुल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नकार रहा है कि विभाग ने कुछ नहीं किया । अध्यक्ष जी, इससे बड़ा बवंडर क्या हो सकता है ? यह मेरा निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ना । जवाब में सब आ गया है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- गलती तो ठेकेदार की भी है ना कि उसने कार्यादेश क्यों नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, जिन-जिन बिंदुओं पर जांच होना है, आप दे दीजिएगा । उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जांच होगी । अब कोई प्रश्न नहीं ।

श्री राजेश मूणत :- जांच होगी, रिपोर्ट कब आएगी ? इसके पहले जितनी घोषणाएं हुईं, आज तक रिपोर्ट नहीं आई ।

श्री रामकुमार यादव :- अभी बबा मरे नइ हे अउ बरा चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, शीघ्र जांच कराकर रिपोर्ट दे देंगे ।

श्री राजेश मूणत :- अगले सत्र तक दे देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, इतना पर्याप्त है ।

श्री टंकराम वर्मा :- जल्दी से जल्दी, अगले सत्र से ...।

(2) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट वितरण का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जाना.

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा), श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- भारत सरकार मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश दिनांक 24.02.2009, दिनांक 09.05.2012 एवं दिनांक 24.12.2013 में निहित निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, राज्य में रेडी टू ईट योजना का संचालन प्रदेश की पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों से वापस लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के माध्यम से रेडी टू ईट प्रदाय का निर्णय लिया गया था । वर्तमान में सरकार द्वारा एक तरफ छत्तीसगढ़ में कुपोषण दूर करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं । दूसरी तरफ इस प्रयास समें सरकार का ही विभाग रोड़ा बन रहा है । इसी के चलते प्रदेश के सभी जिलों में रेडी टू ईट की सप्लाई विगत एक माह से बंद है । प्रदेश के 52474 आंगनबाड़ी केन्द्र रेडी टू ईट का इंतजार कर रहे हैं । इसका मुख्य कारण महिला बाल विकास विभाग ने फूड का भुगतान करने वाली एजेंसी बीज विकास निगम का 162 करोड़ रूपए का भुगतान रोक रखा है । इस कारण अनुबंधित कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी । सूरजपुर में एक माह से रेडी टू ईट की सप्लाई बंद है । कवर्धा के बोडला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम तितरी में चार आंगनबाड़ी केन्द्रों में दो माह से रेडी टू ईट नहीं मिल रहा है । जगदलपुर के ग्राम पुसपाल आंगनबाड़ी केन्द्र में जून माह से रेडी टू ईट सप्लाई बंद है। रेडी टू ईट के बजट मद की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राशि बस्तर क्षेत्र में वंदन योजना में खर्च की जा रही है। बच्चों के कुपोषण रोकथाम जैसे संवेदनशील कार्य के प्रति विभाग द्वारा गंभीर लापरवाही पिछले माह से लगातार की जा रही है । जिसके कारण प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों के परिजनों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन सही है कि भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश दिनांक 24.02.2009, दिनांक 09.05.2012 एवं दिनांक 24.12.2013 में निहित निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, राज्य में रेडी टू ईट योजना का संचालन प्रदेश की पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों से वापस लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर के माध्यम से रेडी टू ईट प्रदाय का निर्णय लिया गया था। यह सत्य नहीं है कि विभाग द्वारा कुपोषण दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है एवं रेडी टू ईट की सप्लाई बन्द है। कतिपय कुछ आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट की आपूर्ति अवरोध की सूचना प्राप्त हुई थी। वर्तमान में बीज निगम द्वारा जिलों में रेडी टू ईट की आपूर्ति नियमित कर दी गयी हैं एवं बीज निगम के सभी देयकों का भुगतान कर दिया गया है। जिला सूरजपुर, कबीरधाम व बस्तर में हमारे विधायक के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि..।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको पूरा पढ़ लीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जिला सूरजपुर, कबीरधाम व बस्तर में माह जुलाई 2024 का रेडी टू ईट प्रदाय किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा उक्त प्रकरण को स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका क्रमांक 75/2023 में दर्ज किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का अपने स्तर पर परीक्षण कराया जा रहा है। अतः इस विषय पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

यह कथन सही नहीं है कि शासन रेडी टू ईट बजट मद की राशि को बस्तर क्षेत्र के महतारी वंदन योजना में व्यय किया गया है एवं बच्चों के कुपोषण रोकथाम कार्यों में विभाग द्वारा पिछले 02 माह से गंभीर लापरवाही की जा रही है। विभाग द्वारा कुपोषण दूर करने हेतु पूरक पोषण आहार कार्यकम एवं अन्य विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निरंतर संचालन किया जा रहा है। अतः प्रदेश के बच्चों के परिजनों में शासन के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त होने की स्थिति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाईए। चलिए आप लोग एक-एक प्रश्न कर लीजिए। आप तो उस विभाग को जानती हैं इसलिए छोटा-छोटा प्रश्न कर लीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने स्वीकार किया है कि कुछ आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट वितरण में अवरोध की सूचना प्राप्त हुई थी। आपको कुछ जिलों की जानकारी प्राप्त हुई है बाकी जिलों की जानकारी शायद नहीं मिली होगी। यह हो सकता है। आपने वितरण चालू कर दिया है, यह शिकायत होने के बाद किया होगा। इस तरह की शिकायत क्यों आई और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपूर्ति क्यों हुई ? आपकी सरकार के सुशासन में आप लोग यह बोल रहे हैं कि हम महिलाओं और बालकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं तो जो अनुपूरक पोषण आहार है, उसमें इस तरह का अनुरोध क्यों हो रहा है, यह आप बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अवरोध नहीं होना चाहिए, बस इतना ही बता दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप पिछले सत्र में बहुत चिल्ला-चिल्लाकर बोल रही थीं कि हम समूहों के द्वारा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आगे कोई अवरोध नहीं होगा, बस यह बता दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपने बीज निगम को दिया है। आप यह बताने की कृपा करेंगे। यह होचपोच में महिला समूहों को देंगे या बीज निगम को देंगे। इस होचपोच में हमारे बच्चों और महिलाओं को पूरक पोषण आहार नहीं मिल रहा है। यह बताने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए छोटा से छोटा जवाब दे दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि कुछ जिलों में टेक्निकल इश्यू की वजह से रेडी टू ईट का वितरण नहीं किया गया था। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि कवर्धा, सूरजपुर में जून तक रेडी टू ईट की पूरी सप्लाई हो गयी थी। आपने कवर्धा की कुछ ग्राम पंचायतों की बात की है तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से विलंब हुआ है। अभी की डेट में रेडी टू ईट की पूरी आपूर्ति कर दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। चलिए दूसरा प्रश्न कर लीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या टेक्निकल इश्यू आ गयी। सब व्यवस्थित था तो वहां पर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गयी ? टेक्निकल क्या है, उसको बताईए।

श्रीमती भावना बोहरा :- दीदी, यह वही टेक्नीकल है, जिसके कारण आप लोगों ने रेडी टू ईट का काम छीना था ना, हो सकता है इसमें भी कोई टेक्नीकल त्रुटि रही होगी ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- 7 महीना हो गया, इसको ठीक नहीं कर सकते थे क्या ? टेक्नीकल त्रुटि को सुधारने के लिये 7 महीने समय हो चुका है, इसे ठीक नहीं कर सकते हैं क्या ? यह बोलना गलत है कि प्रश्न से भागना चाह रहे है हैं........(व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- मंत्री जी ने कह दिया है कि आने वाले समय में होगा, आप पांच साल की चिंता कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- भावना जी, आप बैठिये । मंत्री जी सक्षम हैं । वह बहुत अच्छा जवाब दे रही है, इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । जवाब वह स्वयं दे रही हैं और ठीक दे रही है, आपको कोई शंका है पूछ सकते हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, क्या टेक्नीकल प्राब्लम हो गया, सारा तो व्यवस्थित था ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, टेक्नीकल कुछ हो तो बता दीजिए ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहूंगी कि थोड़ा-बहुत विलंब होता है, उसको पूरा कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- दूसरा आप करिये, मंडावी जी ?

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक प्रश्न है कि हम कूपोषण दूर करने की बात करते हैं, लेकिन कूपोषण कैसे दूर होगा ? अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र भानुप्रतापपुर का अंदर वाला मामला है, मूंगफली और सोयाबीन बड़ी जो है, उसमें फफुंद लगा हुआ है, सोयाबीन बड़ी में घुन लगा हुआ है, वह गर्भवती महिलाओं के लिये आया है । अध्यक्ष महोदय, कूपोषण रोकथाम जैसे, संवेदनशील विषय के लिये विभाग द्वारा इतनी गंभीर लापरवाही की गयी है, क्या आप उन अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय विधायक जी के माध्यम से यह जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है, अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं तो मुझे अवगत करा दीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- उनकी शिकायतों को देख लीजिए और कार्यवाही कर दीजिए। ठीक है, सिन्हा जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, छत्तीसगढ़ में कूपोषण दूर करने के लिये सरकार लगी हुई है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार कूपोषण को दूर करने का पूरा प्रयास कर रही है और अपने प्रयास में सफल भी हुई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुमको देखकर कौन बोलेगा कि इतना कूपोषण है ? (हंसी) प्रदेश में कूपोषण हैं बोलेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं क्षेत्र की जनता की बात कर रही हूँ । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, ऐ दीदी ओ, महिला मन के बात म ...(व्यवधान) झौंहा-झौंहा दे दिही त ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आदरणीय संगीता जी, बच्चों के सूपोषण के लिये बोल रही है, अपने लिये नहीं बोल रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- बाकी में आप हस्तक्षेप करते हो तो समझ आता है, महिला एवं बाल विकास में आप मत करिये । कृपया बैठे रहिये । उनको बोलने दीजिए, पीछे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- श्रीमती सिन्हा जी को देखकर कौन कहेगा कि कूपोषित है करके ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रही हूँ, वहां की जनता की बात कर रही हूँ, जिनके निवाला को आप लोग छीन रहे हैं, छीनने का प्रयास कर रहे हैं, छीन लिये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में 50 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और साथ में लगभग 22 लाख से ज्यादा बच्चे हैं और 2 लाख 40 हजार से अधिक महिलायें हैं। अध्यक्ष महोदय, यह रेडी टू ईट को बंद किये हैं, इससे सभी बच्चे और महिलायें प्रभावित हो रही है । आप महिलाओं और बच्चों को सिर्फ दाल-भात और नाश्ते में पोहा परोसा जा रहा है, यह क्या पौष्टिक तत्व हैं ? अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार में रेडी टू ईट के माध्यम से हमने बहुत सूपोषण अभियान चलाया और सफल भी हुये हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, आपने उसका समर्थन भी किया है । अध्यक्ष महोदय जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज की स्थिति में बच्चे कूपोषित होते जा रहे हैं, महिलायें भी कूपोषित हो रही हैं । अध्यक्ष महोदय जी, मैं महिला बाल विकास मंत्री महोदया से एक ही मांग करती हूँ कि आज की तारीख में....।

श्री रामविचार नेताम :- इतने जल्दी कूपोषित दिखने लगे ? लोग इतने जल्दी कूपोषित हो रहे हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आपने जो 6 महीने में काम किया है, आपने सप्लाई बंद कर दिया है, सरकार को अभी 6 महीने हुये हैं ।

श्री रामविचार नेताम :- 6 महीना में यह हाल है तो 5 साल में कैसा रहेगा । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- यह सब सूपोषित दिखाई दे रहे हैं, मंत्री कूपोषित दिखाई दे रहे हैं । (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा माननीय मंत्री महोदया जी से सिर्फ एक मांग है कि आज की तारीख में, प्रदेश में सूपोषण की स्थिति के जो आंकड़ें हैं, वह बता दें या आप सूपोषण या कूपोषण की जांच करायेंगे क्या ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी के प्रश्न के आधार पर अभी की तिथि में कुपोषण दर कम हुआ है । यह मैं आपको अवगत करा रही हूं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह बताना चाहूंगी कि रेडी टू इट पहुंच नहीं रहा है तो सुपोषित कैसे हो गए ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष जी, मैं इस चीज को स्वीकार कर रही हूं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप स्वीकार कर रही हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए । टेक्नीकल इश्यू की वजह से हम कुछ समय के लिए रेडी टू इट नहीं पहुंचा पाये, लेकिन आज की तिथि में सभी जगह रेडी टू इट पहुंच गई है और अभी 2023-24 में कुपोषण 16.24 प्रतिशत हो गई है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, रेडी टू इट में सामान नहीं पहुंचा है, उसका पैसा कहां गया ? यह आप बताएंगी । आपकी डबल इंजन की सरकार है । आप यह बता दीजिए कि डेढ़ महीने का पैसा कहां गया, जो रेडी टू इट में जाता है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान हुआ है, तब रेडी टू इट का वितरण हुआ है । यह प्रश्न उद्भूत होता ही नहीं है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- कैसे उद्भूत नहीं होता है । रेडी टू इट पूरक पोषण आहार से संबंधित है । यह प्रश्न उद्भूत क्यों नहीं होता ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, सुपोषण अभियान के अंतर्गत दो महीने का पैसा आया है, वह पैसा कहां गया ? आप इतना बता दीजिए । वह टेक्निकल इश्यू में नहीं जाएगा ।

(श्री अजय चन्द्राकर के खड़े होने पर)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- यह महिलाओं की बात है, आप बैठिए । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की बात है, आप इसमें कहां आ गए ? आप बैठिए । महिला मंत्री से हम महिलाएं निपट रही हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आप मत खड़े होईए । यह स्पष्ट हो गया कि इस विभाग का मंत्री कभी कुपोषित नहीं रहता । (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए, आप इतनी वरिष्ठ हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि आपके पक्ष के लोग यह कहकर चिल्ला रहे थे कि महिला समूह के साथ अन्याय हुआ है, आपने इतना हल्ला किया था ।

सुश्री लता उसेण्डी :- आप लोगों ने महिलाओं के अधिकार को छीना, उसके बारे में भी बता दीजिए । (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपकी सरकार को 7 महीना हो गया है इसीलिए तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमारी एक मांग है । सुपोषण की स्थिति आज की तारीख में जारी कर दीजिए । (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मंत्री महोदय जल्दी सुपोषित होकर आएं, इसलिए हमने प्रश्न लगाया है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि पिछले बजट सत्र में ट्रेजरी बेंच से यह घोषणा की गई थी कि यह जो व्यवस्था है, उसको बंद किया जाएगा और फिर से स्व सहायता समूह को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया जाएगा और आजतक उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है । यह व्यवस्था आप कब लागू करेंगे, सदस्यों की चिन्ता यह है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कब तक कर सकते हैं ?

(श्री अजय चन्द्राकर के खड़े होने पर)

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, मंत्री आप हैं । (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं का प्रश्न है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- यह महिलाओं का नहीं, यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपके कुछ निर्णयों को पलटा गया है, वैसे ही धीरे-धीरे सब हो जाएगा । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- हो जाएगा, समय में जल्दी से कर लेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आप रेडी टू इट कब तक सप्लाई करेंगे, केवल यह बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- यह बोल दीजिए कि शीघ्र कर लेंगे ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले एक बात पूर्व मुख्यमंत्री कका जी से कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुपोषित हूं तो इससे साफ प्रतीत होता है कि आपने पॉच साल में कुछ ज्यादा ही खा लिया इसलिए ज्यादा मोटे हो गए हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आपने कम खा लिया है क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- इसे फिटनेश कहते हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग पॉच साल में नहीं, हम लोग जन्मजात खाते-पीते लोग हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को अपने विषय का जवाब देना चाहिए । इस तरीके से बोलना उचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कम बोलिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मुझे एक उत्तर चाहिए कि आप कब तक सप्लाई शुरू करेंगी ?

अध्यक्ष महोदय :- बस एक लाईन का प्रश्न है । द्वारिकाधीश जी, आप बैठिए । भूपेश जी बोल चुके हैं, संगीता जी ने आखरी प्रश्न कर लिया, आखिरी में मंत्री जी जवाब दे दीजिए कि कब तक शुरू कर सकते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है, इसको बहुत जल्दी हम मोदी जी के नेतृत्व में कर लेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी कर लेंगी । चलिए, ठीक है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- समय-सीमा निर्धारित कर दीजिए, हम बैठ जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने जल्दी शुरू करने की बात कह दी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा बता दीजिए कि एक महीने, दो महीने, तीन महीने में हो जाएगा । आप तिथि निर्धारित कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- शीघ्र हो जाएगा ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें समय-सीमा निर्धारित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बोल दिया है कि शीघ्र करेंगे ।

श्री देवेन्द्र यादव :- स्पष्ट जवाब आना चाहिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए, समय सीमा बता दीजिये ? यह जनता का सवाल है। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, यह बच्चों और महिलाओं का विषय है, इस पर स्पष्टता आनी चाहिए। जितनी साफगोई से मंत्री जी राजनीतिक जवाब सकती हैं, उतना जनता के प्रश्नों का भी जवाब दे सकती हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों को रेडी टू इट सप्लाई नहीं होने के वजह की जांच होनी चाहिए। केवल टेक्नीकल कहना जवाब नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमको जवाब चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- यथाशीघ्र।

श्री देवेन्द्र यादव :- यथाशीघ्र ? जनता के लिए यथाशीघ्र और इनके लिए अगले सत्र तक, ऐसा नहीं होगा। हमको जवाब चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, हो गया।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट हैं, इसलिए बहिर्गमन करते हैं।

समय
3.50 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दल के सदस्यों द्वारा शासन के जवाब के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के जवाब के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

3.51 बजे **नियम 267-क के अधीन शून्यकाल कल सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर,
2. श्री बघेल लखेश्वर,
3. श्री रोहित साहू,
4. श्रीमती अनिला भेंडिया.

समय

3.51 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

1. श्री धरम लाल कौशिक,
2. श्री अजय चन्द्राकर.

समय

3.52 बजे **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूर अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान**

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान। अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी, परम्परा अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती है और इस पर एक साथ चर्चा होगी। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत करें। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा। माननीय वित्त मंत्री जी।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 55, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 79 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मिलाकर सात हजार तीन सौ उनतीस करोड़, पैंतीस लाख, बासठ हजार, सात सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री उमेश पटेल जी।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमारे विपक्ष के साथी इस बात को बहुत जोर से बोलते थे, विधानसभा में भी इस बात को कई बार उठाया, मीडिया के जरिये भी इस बात को कई बार उठाया कि भूपेश बघेल जी की सरकार कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ को डूबा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल में लगभग 50 हजार करोड़ रूपये का कर्ज लिया। इस सरकार ने दिसम्बर, 2023 से अपना कार्यकाल शुरू किया है, लेकिन इस सरकार ने अभी तक जो कर्ज लिया है, उसमें दिसम्बर 23 में लगभग 929 करोड़ रूपये, जनवरी 24 में लगभग 4 हजार करोड़ रूपये, फरवरी, 24 में लगभग 10,222 करोड़ रूपये, मार्च में लगभग 10,383 करोड़ रूपये और अप्रैल में 34 करोड़ रूपये का कर्ज लिया है। यदि आप इन सभी को जोड़ेंगे तो यह लगभग 25 हजार करोड़ रूपये होता है। अभी 7 महीने का नये कार्यकाल में 25 हजार करोड़ रूपये के कर्ज पर यह सरकार बैठी हुई है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सत्ताधारी पक्ष के लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो सरकार 5 साल में लगभग 50 हजार करोड़ रूपये कर्ज लेती थी, जिसने कोरोना काल को भी झेला, जिस समय केन्द्र सरकार ने अपने कर्ज की सीमा को बढ़ाया और सभी राज्य सरकारों को कहा कि कोरोना काल से निपटने के लिए आप कर्ज ले सकते हैं, उस परिस्थिति को झेलते हुए यह कर्ज लिया गया था, लेकिन अभी 7 महीने नहीं हुए हैं और इस सरकार ने 25,000 करोड़ रूपये का कर्ज ले लिया है। इसका मतलब यह है कि माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 सालों में जो कर्ज लिया था, उसका आधा कर्ज यह सरकार 7 महीने में ले चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात सही थी कि छत्तीसगढ़ की पुरानी सरकारों ने कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ को डुबाया तो अभी की सरकार कर्ज लेकर क्या चिभोर रही है ? आप समझे न ? आप चिभोरना मतलब समझ गये न ? यह सरकार छत्तीसगढ़ को चिभोर रही है। अब सांस भी नहीं आ रही है। अजय जी, आप भी सुन रहे हैं न ?

समय :
4.00 बजे

श्री अजय चंद्राकर :- मैं दोनों कानों से सुन रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने हमारी वित्तीय स्थिति के बारे में कहा। यह बजट लगभग 7,329 करोड़ रूपये का है, जिसमें से अधिकतम पार्ट महतारी वंदन योजना के लिए

प्रावधान किया गया है। लगभग 4,000 करोड़ रूपये के ऊपर, 500 के आसपास महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान किया गया है लेकिन जो बाकी बजट बचा है, वह कई कार्यों के लिए उपयोग हुआ है। मेरी जिज्ञासा थी कि किस-किस जगह और कहां-कहां काम हुआ ? अमर अग्रवाल जी को उनके विधान सभा क्षेत्र में कुछ मिला होगा, अजय चंद्राकर जी को कुछ मिला होगा। हम लोग तो मानकर बैठे हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमको लगा कि कौशिक जी को कुछ मिला होगा, मोहले जी को कुछ मिला होगा, चंद्राकर जी कुछ पाये होंगे।

श्री भूपेश बघेल :- वह इधर वाले हैं। अध्यक्ष जी, क्या है कि यह लोग सत्ताधारी विपक्षी हैं। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा कि माननीय उप मुख्यमंत्री अरूण साव जी को कुछ मिला होगा, संसदीय कार्य मंत्री जी को कुछ मिला होगा, टंकराम वर्मा जी को कुछ मिला होगा, बघेल जी को कुछ मिला होगा। यह तो ट्रेजरी बेंच के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सीमित रह गई। एक कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में, दूसरा रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र में और तीसरा कुनकुरी विधान सभा क्षेत्र में, वह योजना सिर्फ तीन विधान सभा क्षेत्रों में सीमित रह गई। कौशिक जी, आपको पता है कि आप लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं ।

श्री रामकुमार यादव :- 87 झन इहां दस्तखत करे बर आहे अऊ ओ 3 झन बस आही ।

श्री उमेश पटेल :- आपको क्या मिला है ? कुछ नहीं । आप तो ट्रेजरी बेंच वाले नहीं हैं। आप लोगों को भी कुछ नहीं मिला। आप तो पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री हैं। आप भी अपने लिए नहीं लड़े। मैं पी.डब्ल्यू.डी. का बजट देख रहा था कि इसमें पुल-पुलिया निर्माण की बात की गई है।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, अभी यह वित्त मंत्री जी से लड़ने लायक नहीं हैं। न मुख्यमंत्री जी की चल रही है और न ही उप मुख्यमंत्री जी की चल रही है। चल तो उन्हीं की रही है। वह चौधरी साहब से कहां लड़ेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- ओ दिल्ली जाथे ता सबके पोटा हा कापत रहिथे कि का लेके आही न का करके। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पी.डब्ल्यू.डी. का भी बजट देख रहा था। इसमें भी पुलिया निर्माण की जगह बगीचा से जुड़ापाली (जिला-जशपुर), घटमुड़ा से रजौरी (जिला-जशपुर), गढ़उमरिया से पुसौर (रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र), चम्पा से बांदा (जिला-जशपुर), बतौली से बगीचा (जिला-जशपुर), चम्पा से इचौली (जिला-जशपुर), पण्डरीपानी से डुमरिया (जिला-जशपुर), परमसाला से सहटोली (जिला-जशपुर)। आप समझ रहे हैं ? यहां सरगुजा के लोग भी बैठे हैं, बिलासपुर के लोग भी बैठे हैं और आप सब लोग भी बैठे हैं। अग्रवाल जी, कुछ नहीं है। आपके लिए कुछ नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- कर्जा ला हमन छूटबो अऊ एमन 3 ठन मा लेहे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ 3 विधान सभा क्षेत्रों के मुख्यमंत्री हैं ? बाकी यहां पर 90 सदस्य अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो क्या उनके विधान सभा क्षेत्र में कोई काम नहीं होगा ? यह पीड़ा इन सबकी है। पार्टी में रहते हुए यह इनकी मजबूरी है। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन मैं आपकी आवाज उठाने के लिए हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि आपके विधान सभा क्षेत्र में भी एक काम नहीं हुआ। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, ये लोग तो फिर भी बैठे हैं, आप कुनकुरी का इतना सारा बता दिए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी संतुष्ट नहीं हैं और ओ.पी. चौधरी जी से नाराज होकर आज उनके सप्लीमेंट्री बजट में भी उपस्थित नहीं हैं और एक उप मुख्य मंत्री भी असंतुष्ट हैं, वह भी नहीं आए हैं। यह स्थिति है। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि यह अनुपूरक बजट है। मैं यह उम्मीद रखूंगा कि आने वाले अनुपूरक बजट या मुख्य बजट में पूरे छत्तीसगढ़ के विजन को लेकर चलेंगे। आप मुख्य मंत्री एक, दो या तीन विधान सभा के नहीं हैं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं इसलिए आवश्यकता के अनुसार काम करिए। कुछ राजनीतिक आवश्यकताएं रहती हैं, ठीक है लेकिन आप ज्यादातर काम आवश्यकता के अनुसार कीजिए, यही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग को भी पैसा दिया गया है। हम इस पुलिस विभाग को पैसा क्यों दें?हम इस पुलिस विभाग को पैसा इसलिए दें ताकि रायपुर में बाहर के लोग आकर गोलीकांड कर सकें और उस आदमी की इतनी हिम्मत कि वह सोशल मीडिया में यह जारी करे कि हॉ मैंने यह गोलीबारी की है? कोई बाहर का आदमी हमारे यहां सुरक्षित नहीं हो सकता, ऐसी पुलिस को हम पैसा दें? अभी उड़ीसा में एक गोलीबारी हुई, पेपरों में हमने पढ़ा कि वह गोलीबारी करने वाले हमारे रायगढ़ के निवासी थे। रायगढ़ के लोग जाकर उड़ीसा में कोई साइडिंग है, उसकी लड़ाई उड़ीसा में लड़ रहे थे और गोलीबारी किए। क्या पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? ठीक है कि उड़ीसा में वह घटना हुई और हमारे यहां कार्रवाई नहीं हो सकती लेकिन मैंने मांग रखी थी और मैंने इसे लिखित में दिया था कि जो-जो लोग गोलीबारी में हिस्सेदार थे, क्या उनके यहां सर्चिंग हुई कि उनके यहां जो बंदूक है, उसका लायसेंस है या नहीं है? आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें रायगढ़ जिले में कभी इस तरह की गोलीबारी सुनाई नहीं दी थी, यह पहली बार हुआ है। क्या पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है? सर्चिंग की? नहीं की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटेलीजेंस का इतना बड़ा फेलियर बलौदा बाजार में हमें देखने को मिला।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बजट से जल्दी गाड़ी उतर गई! बजट में चार लाइन बोलकर सीधे विनियोग में आ गए?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी बजट में तो कुछ है नहीं। आप बताओ ना कि आपको क्या मिला है? उसको छोड़ो।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस को, इंटेलीजेंस को हम लोग पैसा क्यों दें जबकि इतना बड़े इंटेलीजेंस फेलियर के कारण बलौदा बाजार की घटना हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें स्थगन के माध्यम से इस पर बात करने का मौका नहीं मिला। मेरा आरोप है और मैं इस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आप लोग द्वेषपूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग बलौदा बाजार की घटना के पीछे कांग्रेस के लोगों को अंदर करने का काम कर रहे हैं। यह मेरा आप लोगों के ऊपर आरोप है। उस दिन का एक-एक विडियो फुटेज पुलिस के पास उपलब्ध है कि किसने आगजनी की, कौन वहां उपस्थित था, किस आदमी ने वहां पत्थर फेके। यह सब विडियो फुटेज में है। वहॉं आठ हजार लोग उपस्थित थे और इन आठ हजार लोगों में से 159 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई लोगों को सिर्फ इस बात के लिए उठाया गया क्योंकि वे युवा कांग्रेस के सदस्य हैं। सिर्फ इसलिए कि वह एन.एस.यू.आई. का अध्यक्ष है। मैंने बताया न कि एक दीपक मेरी नामक लड़का था, जिसकी मृत्यु 3 महीने पूर्व हो चुकी है, उसके घर भी पुलिस पहुंच गई। उसकी मां रोते हुए बोली कि मेरा बेटा तो 3 महीने पहले गुजर चुका है। ऐसी घटना भी हुई है। सिर्फ वह यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, एन.एस.यू.आई. का अध्यक्ष है, उसकी वजह से आपने उस पर 307 की धारा लगा दी। उसका क्या सबूत है ? मोबाईल टॉवर। क्या आपके पास वीडियो फूटेज है, जिसमें उसका चेहरा सामने नजर आ रहा हो ? हम तो चाहते हैं कि इसमें जो लोग भी दोषी हैं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिसने भी छत्तीसगढ़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो, उससे सख्ती से निपटा जाये, हम लोग इसके पक्षधर है। लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई न हो। लोग डरते हुए फिर रहे हैं। इसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सबका नाम है, कोई बयान में किसी का भी नाम लिखा है। अध्यक्ष महोदय, किनको पकड़ा गया ? दो बिहार के लोगों को पकड़ा गया। आज की स्थिति में वे कहां हैं ? आज की स्थिति में वे लोग यहां है ही नहीं, उनकी जमानत हो गयी और जमानत होने के बाद वे लोग कहां हैं, यह किसी को नहीं पता। ऐसा क्यों किया गया ?

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। अभी अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है। इससे पहले सम्मानित सदस्य उस विषय पर अपना स्थगन ला चुके हैं, जिसको आपने अग्राह्य किया है। विषय वस्तु पर बात करने की बजाय वह पुन: पूरे सदन को दिग्भ्रमित करने की व्यवस्था दे रहे हैं। मैं उसमें आपसे प्वाईंट ऑफ ऑर्डर चाह रहा हूं कि वह मूल विषय पर आये। आपसे निवेदन है कि अनुपूरक विषय पर चर्चा हो रही है, आप मूल विषय पर आईये।

श्री रामकुमार यादव :- पुलिस के बारे में बोलत हे साहब। ते मन जो पुलिस ला पैसा देथन, ओला कहां करत हे, तेला बोलत हे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विनियोग बजट भी है और विनियोग भी है और अजय जी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि आप बजट से तुरंत विनियोग में आ गये। आप उसमें आपत्ति मत लीजिए। आप थोड़ा बैठिये, सुनिये, समझिये, उसके बाद बोलिये। आपको सीखना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वह नये विधायक हैं। आप उनको प्रोत्साहित कीजिए। उन्होंने पहली बार प्वाईंट ऑफ ऑर्डर लिया है। आप उनको प्रोत्साहित कीजिए की प्वाईंट ऑफ ऑर्डर कैसे होता है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही बोल रहा हूं कि आप बैठिये, सुनिये, समझिये, फिर आगे कुछ बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके आदेश पर खड़ा हूं और आपके आदेश पर बोल रहा हूं। यदि आप आदेश करेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जारी रखें। आप आराम से बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कह रहा था कि हम लोग पुलिस को क्यों पैसा दे रहे हैं ? जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उस दिन जो घटना हुई, उससे पहले जिन लोगों ने उग्र आंदोलन का ज्ञापन सौंपा, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई ? उस दिन जो मंच पर आपकी ही पार्टी के लोग उपस्थित थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई ? नहीं हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ईमानदारी से एक बात बताईये। मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। क्या उस दिन बी.जे.पी. वाले मंच पर उपस्थित थे ? उस मंच पर इस सदन के सदस्य उपस्थित थे, उस बारे में आप कुछ बोलेंगे। मैं आपको फोटोग्राफ दिखा सकता हूं।

(माननीय सदस्य, श्री रिकेश सेन द्वारा सदन में तस्वीर प्रदर्शित की गयी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आपकी बगैर अनुमति के कोई तस्वीर नहीं दिखा सकता। यह घोर आपत्तिजनक बात है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, किसी भी सार्वजनिक आंदोलन में जाने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, हम भी फोटोग्राफ लायेंगे। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी घोर आपत्ति है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, जब हमने चर्चा करने की बात की तब यह सामने नहीं आये। अभी फोटोग्राफ लेकर आ गये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं रोक रहा हूं।

श्री दिलीप लहरिया :- आप फोटोग्राफ कैसे लेकर आ गये ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो रिकेश सेन जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने तस्वीर का प्रदर्शन किया। यह सत्ता पक्ष के द्वारा हुआ है। यह हमारे लिये अच्छी बात है कि हम लोगों को भी इस तरह की अनुमति मिल गई है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से लगातार यह पूछा जा रहा था कि षडयंत्र किसका है। मैं यह बता रहा हूं कि किसका षडयंत्र था।

श्री भूपेश बघेल :- मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं। बिल्कुल, आप यह काम जिसके लिए किये हैं, आपको हृदय से धन्यवाद्।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, दो दिन से छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती थी कि बलौदा बाजार में किसका षडयंत्र था। यह षडयंत्र इधर से होता है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- आज आप फोटो लेकर आए हैं। इसका मतलब आप स्वयं षड़यंत्रकारी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए। इस बार अच्छी बात है कि इस सदन में बहुत सारे सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं। इस सदन की कुछ परम्पराएं और मर्यादाएं हैं। उसका हम सब अक्षरश: पालन करते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए जो पहली बार जीतकर आये हैं, उनको और जो सीनियर सदस्य हैं उनसे आग्रह यह है कि सदन में बैनर, पोस्टर दिखाना प्रतिबंधित है। यह बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस पर कई बार कार्यवाही भी होती है। इसलिए कृपा करके, सदन के अंदर कोई भी सदस्य बिना अनुमति के कभी बैनर, पोस्टर प्रदर्शित नहीं कर सकते। यह आापको भी बता रहा हूँ और पूरे सदन को भी बता रहा हूँ। आप अपना भाषण जारी रखिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ। अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो उस पर निष्पक्ष कार्यवाही हो। हम लोग यह चाहते हैं कि इसमें सही में जिन लोगों ने गलत किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि इसके कारण किसी निर्दोष को न फंसाया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों ने किसानों की समस्या को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव लाया था। मैं तो माननीय मंत्री जी की तारीफ करूंगा जिन्होंने इस बात को माना कि हां, यहां खाद की कमी है। जिन्होंने इस बात को माना कि हां, इस प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है। जिन्होंने इस बात को माना कि हां, यहां पर अमानक बीज बांटे गये हैं। उन्होंने यह अपने वक्तव्य में माना।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य जी ने गलत सुना था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी ने आगे क्या कहा था, यदि आपको बोलना है तो उसे आप पूरा बोलिए। आप आधी-अधूरी बात क्यों बोलते हैं?

श्री केदार कश्यप :- उस समय आपने, माननीय मंत्री जी का पूरा उत्तर सुना या नहीं सुना? आप अपनी तरफ से मनगढ़त कहानियां मत बनाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत अच्छे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, स्वयं मंत्री जी ने डी.ए.पी. में कमी की बात स्वीकार की है और केन्द्र सरकार से नहीं आ रहा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनके उत्तर को देख लीजिए। उन्होंने यह कहा कि हमारे पास डी.ए.पी. की कमी है। कई जगह ऐसी शिकायतें आयी हैं कि अमानक बीज प्राप्त हुए हैं, बांटे गये हैं। मैं, इस पर क्या बोलूं? हमारे सामने उदाहरण है। मुझे एक किसान का फोन आया। जिसने मुझसे कहा कि प्राप्त बीजों में केवल 10 प्रतिशत बीज ही काम कर रहा है। जो बीज उनको प्राप्त हुए, वह अमानक है। उनको समय पर खाद नहीं मिल रहा है। इसके अलावा नहर में जो पानी आने की बात होती है। वहां नहरों में टाईम से पानी नहीं आया। इस बार हमारे ऊपर इन्द्र देवता थोड़े से मेहरबान नहीं रहे। अभी तक बस्तर के लोगों ही ज्यादा पानी दिया है। हमारे क्षेत्रों में थोड़ा कम पानी है। हम लोग नहर के पानी से इसका उपाय करना चाहते थे, लेकिन नहर का पानी भी समय पर नहीं छोड़ा गया। इस बार इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या बिजली कटौती को लेकर पैदा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर सदन में उपस्थित हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार जितनी बिजली कटौती हुई है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के इतिहास में इससे पहले अभी तक और कभी इतनी बिजली कटौती नहीं हुई थी। यह आपके शासन में रिकॉर्ड बना है। यह रिकॉर्ड ऐसा बना है कि रायगढ़ मुख्यालय लगातार 26-26 घण्टे तक बिजली से अवरूद्ध रहा। मैं मुख्यालय की बात बता रहा हूँ। वहां मुख्यालय में कभी 26-26 घण्टे तक बिजली बंद नहीं रही। चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे आपकी भी सरकार रही हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी भी हमारी सरकार है।

श्री उमेश पटेल :- अभी आप मंत्री नहीं है। जब आप ट्रेजरी में थे। तब भी कभी यह घटनाक्रम नहीं हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपने यह रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा जिस तरह से ट्रांसफार्मर हो रहा है, प्रदेश में किस तरह से ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी सदस्य इससे सहमत होंगे कि एक भी ट्रांसफार्मर दो दिन, तीन दिन से ज्यादा टिक ही नहीं रहा है। पता नहीं, आप लोगों ने क्या सप्लाई की है। गर्मी के समय, बरसात से पहले मेंटेनेंस होता था, इस साल मेंटेनेंस हुआ ही नहीं। पूरे प्रदेश में किसी तरह के पेड़ की कटाई, तारों का कहां पर झूल, झोल हुआ है उसका कोई काम ही नहीं हुआ है। उसके कारण से बरसात के समय में 5-5, 6-6 घण्टे बिजली की कटौती हो रही है। वहां पर पम्प में बिजली की कटौती हो रही है, पंप में बिजली की कटौती हो रही है। हम लोगों को फाल्ट के कारण कई दिनों तक 12-12 घंटे बिजली नहीं मिली है। फाल्ट के कारण 12 घंटे तक

बिजली नहीं आई और 4 घंटे की कटौती, पूरा दिन बिजली गायब हो जा रही है। इस तरह से आप लोग किसानों को परेशान करना बंद कर दें। किसानों के नाम पर आप लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने घोषणा की थी कि 2500 रुपये में धान खरीदी करेंगे। हम लोगों ने 2500 रुपये में धान खरीदी की। लेकिन जब-जब केन्द्र सरकार ने मूल्य की वृद्धि की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये से उतने रुपये आगे बढ़ाया। क्या आप लोग भी यह करने वाले हैं? क्या आप लोग 3100 रुपये को बढ़ायेंगे? आप लोग नहीं बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों के मंत्रियों से ऐसा जवाब आया है। आपके मंत्रियों ने ये कहा है कि हम 3100 रुपये देने की बात किये थे और 3100 रुपये ही देंगे, उससे ज्यादा धान का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ेगा। आप लोग यह किसानों के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? यह किसानों के साथ धोखा है। आप उसको बढ़ाईये। आप जो 3100 रुपये रेट दे रहे हैं, बोनस देने की जरूरत पड़ रही हैं, अगर केन्द्र सरकार समर्थन मूल्य को बढ़ाती है तो आपको भी वह रेट बढ़ाना चाहिए। अभी 2024-25 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 2300 रुपये के आसपास हुआ है, 117 रुपये की वृद्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर साल धान का रेट बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी जब विपक्ष में थे तो हर बार मेरे से एक सवाल करते थे कि यहां 18 लाख बेरोजगार उपस्थित हैं और आप कितने को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप 05 साल में मंत्री रहते हुए बेरोजगारी की परिभाषा ही नहीं तय कर पाये। आप बताईये यह बात सही है या गलत है ?

श्री उमेश पटेल :- हो गया न। मेरे बाद आपका नंबर है, आप अपने समय में बोलियेगा। यह हमेशा बोलते रहे हैं कि आप 18 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को बने हुए 7 महीने हो गये, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ ? अजय जी, आपका वह प्रश्न कहां गया ? आप क्यों नहीं करते ? आप मंत्री बनने वाले नहीं हैं, भूल जाईये। आप विधायक के रूप में प्रश्न करिये। आपको पूरा सदन देख रहा है। यहां के बेरोजगार बच्चे भी आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। वही 18 लाख लोगों की बात आप फिर से करिये, लेकिन आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जितना अजय चन्द्राकर जी बोलते और पूछते हैं, अब इससे आगे और क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कल से लाठी लेकर आयें ?

श्री दलेश्वर साहू :- वह मुख्यमंत्री को दबाव बनाने के लिये है।

श्री रामकुमार यादव :- 05 साल बहुत मेहनत किये लेकिन अंतिम में उनको कुछ नहीं मिला।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये, यादव जी, अभी तक आप इतने सारे नोट को देखकर जिंदा हैं, मैं इसी में आश्चर्यचकित हूं, पूरी 500-500 रुपये की नोट थी।

श्री भूपेश बघेल :- धर्मजीत भैया, और कितना प्रश्न पूछेंगे। वैसे रोज ध्यानाकर्षण में, प्रश्न में पूछ रहे हैं, लेकिन अजय चन्द्राकर जी की क्षमता को हम सब जानते हैं। उनके तेवर को भी हम लोगों ने देखा, सहा और झेला है, लेकिन उस हिसाब से अभी बहुत कम है। मुश्किल यह है जैसे आई.ए.एस. अधिकारियों के बारे में यह कहा जाता है न कि मालिक रहे नहीं, नौकर बन नहीं पाये। यह किसी सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी ने मुझसे कहा था। जब अंग्रेज गये, उसके बाद अब ये नौकर बन नहीं पाये हैं, मालिक हैं नहीं। वैसे ही अजय चन्द्राकर जी के साथ है। मंत्री बन नहीं पाये हैं, विधायक... तो आप थोड़ी मानसिकता चेंज करिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ते को बंद कर दिया गया है। इस बजट में अगर बड़ा फंड एलोकेट किया गया है तो महतारी वंदन योजना में किया गया है। लगभग 4900 करोड़ रुपये महतारी वंदन योजना में प्रावधान किया गया है। मोटा-मोटा 5 हजार करोड़ रुपये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है । माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट यह रहता है कि 70 लाख से ऊपर महिलाओं को एक हजार रूपये प्रति महिला के हिसाब से 650 करोड़ रूपये दिया जाता है। एक महिने में 650 करोड़ रूपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी, मैं इसका गणित नहीं समझ पाया कि 70 लाख से ऊपर महिलाओं को एक हजार प्रति महिला दिया जाएगा तो 700 करोड़ रूपये से तो ऊपर हुआ। आप यह 50 करोड़ रूपये का झोलमाल कैसे कर रहे हैं? 50 करोड़ कम कैसे हो रहा है, यह मेरे समझ से परे हैं। उसमें 50 करोड़ की कमी दिखने लगी है। जब मैं इसमें पता करते गया तो मुझे यह पता चला कि जो महिलाएं पेंशन पा रही हैं, उसमें आपने 500 रूपये की कटौती की है। अगर आपने यह कटौती की है तो क्या आपने घोषणा-पत्र में इस बात को रखा था, क्या आपने कहा था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो पेंशन प्राप्त महिलाएं हैं, उनको महतारी वंदन योजना का आधा पैसा देंगे। आपने नहीं कहा था इसलिए मैं कहता हूं कि आप महिलाओं को धोखा दे रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धोखा दे रहे हैं जो हमारी मातास्वरूप हैं। जब उनकी हाय लगेगी तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने महतारी वंदन योजना की घोषणा में यह कहा था कि हम लोग प्रत्येक विवाहित महिला को पैसा देंगे और अभी यह क्या कर रहे हैं कि जब से उनका सर्वर या पोर्टल बंद है, वह तब से खुल ही नहीं रहा है। कई महिलाएं नई शादी होकर आ गईं, वह इंतजार कर रही हैं कि हम उसमें कब फार्म भरें। आप उस पोर्टल को खुलवाईये, वह भी अपना नया फार्म भरेंगी। आप तो सबको देंगे बोले थे तो आप बाकी लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं। आप बाकी लोगों को भी पैसा दीजिये। आप लोग यह महतारी वंदन योजना के नाम से धोखा देना बंद करिये।

अध्यक्ष महोदय :- उमेश जी, आप कितना समय लेंगे क्योंकि 30 मिनट हो चुका है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आधा समय तो इन लोगों ने ले लिया।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको जानकारी के लिए बात दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए 1 घंटा 10 मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुल 1 घंटा 48 मिनट समय है, इसमें से आपने 30 मिनट समय लिया है। आप कितना समय लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं एकदम संक्षिप्त में खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जो भी समय लें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अभी सदन को बता रहा था, आप पूरे छत्तीसगढ़ की विजन लेकर चलिये। आप सिर्फ तीन विधान सभा में पैसा देने का काम मत करिये। दूसरा चीज यह है कि आज पुन्नूलाल मोहले जी ने प्रश्न उठाया था और आपने देखा था कि उसका असर सभी सदस्यों के ऊपर था।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये, पुन्नूलाल जी ने प्रश्न उठाया था। आप बजट पढ़ लेते, प्रश्नों को सुनते। मान लीजिये कि यदि मुंगेली में जमीन होती तो वे अभी तक वहां हवाई अड्डा बनवा दिये होते। वह अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए इतने लगे रहते हैं इसलिए उसका उदाहरण ऐसे दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप मेरी बात सुनिये तो, नहीं तो अध्यक्ष जी मेरा समय काट देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुन्नूलाल मोहले जी ने जो प्रश्न उठाया था, उसमें जितने विधायकों ने भाग लिया, आपको भी अहसास हुआ होगा कि बजटेड चीजों पर सेंक्शन नहीं हो रहा है, पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है, समय-सीमा कोई नहीं है। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने यह प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा था कि कोई प्रक्रिया है या नहीं है? मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, आपने कहा कि सभी एम.एल.ए. को लिख कर दीजिये कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कितना समय लगेगा। लेकिन बजट में कोई चीज सेंक्शन हो चुका है, उसके लिए क्या हम लोग डिपेंडेंट रहे, क्या हमको पीछे-पीछे दौड़ना पड़ेगा कि यह काम करा दीजिये, इसमें सेंक्शन दे दीजिए? बजट हो गया, इस विधान सभा में जिसको पारित कर दिया गया, क्या उसको भी आप काट देंगे, क्या उसको भी लेप्स करा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे सदन को आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं, चूंकि आप बड़े दुख में रो रहे हैं । आपके राज में 5 सालों में मेरे विधानसभा में एक सड़क नहीं बनी । (शेम-शेम की आवाज)

श्री उमेश पटेल :- सुनिये जी, अभी भी आप [xx] में हो न तो बस वहीं रहिये। आपको भी [xx] ही मिला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही संरक्षण चाहता हूं कि बजट में जितना सेंक्शन है, हमारे सभी साथियों का, इधर के भी साथियों का सेंक्शन है उसका फंड रिलीज किया जाये, उसको न काटा जाये और अगर काटा भी जाये तो यदि कोई विशेष कारण हो तभी काटा जाये और उसे भी अवगत कराकर काटा जाये ताकि हमारे सदस्यों को पता रहे । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ओर बहुत मुखातिब होकर उमेश पटेल जी बोल रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा विषय और बजट आपके लिये समर्पित था ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनको पढ़ा-लिखा समझता था । लेकिन इस नौजवान लड़के ने मेरा भ्रम तोड़ दिया कि पढ़ा-लिखा है । हम लोगों ने इसको बड़ी हसरत से पढ़ाया था । भाईसाहब बोलते थे कि लड़का होशियार है । निकल गये [xx] ऐसा बोलूंगा तो असंसदीय हो जायेगा । (हंसी) मेरा भ्रम तोड़वा दिये । कभी भाईसाहब के पास कोई जायेगा, चूंकि पितर का महीना आने वाला है, मैं चिट्ठी लिखूंगा कि भाईसाहब यह लड़का ठीक नहीं है, अभी पढ़ता-वढ़ता नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत व्यय में इस बजट में 500 करोड़ रूपये के आसपास आयेगा । यदि आप मूल बजट को जोड़ दें, 1 लाख 47,000 करोड़ रूपये के और 500 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय जिसको आप 3 विधानसभा में बोल रहे थे तो आपको यह संतुलित बजट दिखेगा । आप एक जगह की बात कर रहे हैं कि साहब इन 3 जगह को आपने पढ़ दिया । 500 करोड़ के अंदर है न, सिर्फ 500 करोड़ । 1 लाख 47,000 करोड़ रूपये जिसको आप राई का पहाड़ बना रहे थे । एक सदी तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 विधानसभा का मुख्यमंत्री या वित्तमंत्री जी को 3 विधानसभा का मुख्यमंत्री कह रहे थे । एक सदी तक पाटन विधानसभा में कुछ करने की जरूरत नहीं है । आप बजट की बात करते हैं । एक सदी तक, एक विधानसभा का मुख्यमंत्री यदि कोई था तो वह श्री भूपेश बघेल थे । इसको नोट कर लीजिये ।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आप सदन में कुछ और बोलते हैं और बाहर कुछ और बोलते हैं । बाहर बोलते हैं कि यह क्या हो रहा है और इधर आकर उल्टा भड़कने लगते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, यह 3 विधानसभा का बोल रहे थे । आप सुन लीजिये । दंतेवाड़ा में नया महाविद्यालय । कौन सा महाविद्यालय इनसे पढ़वा लेना। मेडिकल कॉलेज । समझे न, बजट में है । दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज ।

श्री कवासी लखमा :- कोई नयी बात थोड़ी न है ।

श्री अजय चंद्राकर :- जो भूपेश बघेल जी बोलें वह कायदा । आपके राज में कोई नियम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई कानून नहीं । जो भूपेश बघेल जी बोलें वह कायदा । अब विकसित भारत के लिये छत्तीसगढ़ की भूमिका क्या होगी, वर्ष 2047 का डॉक्यूमेंट, उसका विजन । यदि आपके पास विजन हो तो आप दीजिये न । आप पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं ।

श्री उमेश पटेल :- आपको क्या लगता है कि आंकड़े ऐसे ही आ जा रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप पढ़े हैं बोलते हैं यह मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । नवीन कानून संहिता जो आजादी के बाद भारतीयों को न्याय संहिता कही गयी । अंग्रेजों के समय के दंड संहिता के स्थान को लेने वाला कानून बना उसके क्रियान्वयन के लिये बजट में पैसा है, आप पढ़ लीजिये । एस.डी.आर.एफ. अभी आपका पुराना स्थगन लगा था ।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, मैंने इसमें बात ही नहीं की । मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री सड़क योजना को देख लो, एक-बार फिर से पढ़ लो । क्या है कि आप उतनी ही बात करते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं पूरे बजट की बात कर रहा हूं । मैं आपकी आंख को खोल रहा हूं, मैं आपके दृष्टिकोण को चौड़ा कर रहा हूं कि जानने और पूछने के पहले क्या दृष्टिकोण होना चाहिए ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात रखी उसको ये तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- क्यों, यह बजट में नहीं है ?

श्री उमेश पटेल :- आपको जो बोलना है वह बोलिए लेकिन आप मेरे नाम का उल्लेख कर रहे हैं न । उसको सही करके बोलिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने तीर्थयात्रा बंद कर दी । तीर्थयात्रा योजना के लिये उसमें 8 करोड़ रूपये रखे गये । आपने तेंदूपत्ता संग्राहकों को, वनवासी क्षेत्र के लोग जो आते हैं, उस काम में लगते हैं उसको आप गरीब नहीं मानते । उसके कांटे चुभने को, उसके पैर के चोट से आपको दर्द नहीं होता था। आज उस मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया। अभी जहां पर मैं बोल रहा था..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष जी, तेंदूपत्ता में मानक दर हमारी सरकार ने बढ़ाया था।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके जो चरण पादुका योजना की बात की है, उसमें परिवार में एक महिला को मिलेगा, बाकी सब नंगे पैर जायेंगे, सबके पैरों पर काटे चुभेंगे। अगर देना है तो पूरे परिवार को दीजिये।

श्री दलेश्वर साहू :- चंद्राकर जी, उसमें भी एक चप्पल छोटा रहेगा और एक चप्पल बड़ा रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखो भोला भैया, फिर आप यहां पर धरना देना, फिर आपकी मांग पूरी होगी। चिंता मत करो और बिना धरना दिये हम आपकी मांग पूरी करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- बढिया चप्पल ला कंपनी वाला ला देहौ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते होश में कइसे हस, तिही में ते बेहोश हस। समझ गे हस न।

श्री रामकुमार यादव :- बने दिहौ तुमन चप्पल ला। अइसने झन दिहौ। तुमन पहनथौ स्केचर के, तुमन पहनथौ बड़े-बड़े कंपनी के, अउ ओमन ला ठगे बर धराथस।

श्री उमेश पटेल :- क्या अजय भैया, आज आप तैयारी करके नहीं आये हो। आज आपको सही से डेटा नहीं मिला है क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रधानमंत्री आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे। ये पढ़ना नहीं है। आपने महतारी वंदन योजना कही है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि आपने बंद कर दिया, अभी उसमें देश भर में बहस चल रही । नोटिफिकेशन हो गया भारत सरकार का कि 25 जून..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, महतारी वंदन योजना की आपने बात की? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि आपने जो विधवा महिलाओं को जो बुजुर्ग महिलाओं का 500 रूपया काटकर 500 रूपये दे रहे हैं, ये तो आपके घोषणा पत्र में नहीं था, आप इसका पहले जवाब दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपके जितने प्रश्न हैं, संगीता जी और सभी सदस्य, आपको अवसर मिलेगा, उस समय उठा लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- 25 जून को भारत सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। जिन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी उसके लिए फिर से सम्मान निधि, जय प्रकाश सम्मान निधि बहाल करने की घोषणा हुई। (मेजों की थपथपाहट) लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी कौन है? याद करिए मैं नाम नहीं लेता। पूरी दुनिया में लोकतंत्र को यहां कलंकित किया गया।

श्री उमेश पटेल :- वही पार्टी जिसने पूरे एजेंसियों को अपने अंदर कर लिया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- वही पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये आपका टूल किट और नेरिटिव है। इसमें कोई दम नहीं है।

श्री देवेन्द्र यादव :- जो गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकती, वह पार्टी लोकतंत्र और संविधान की हत्यारी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपकी ओर आ रहा हूं। आप पोस्टर में बहुत छाये हो।

श्री रामकुमार यादव :- [xx] [3] (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- और पोस्टर की बात है तो माननीय सोशल मीडिया पर आज भी एक तस्वीर नहीं ला पाये हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब इमरजेंसी लगी थी तब आप पैदा नहीं हुए थे। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं तो कल गया भी था। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- जिसने आजादी के 50 साल बाद भी अपने कार्यालय में झंडा नहीं लगाया, वह देश की भावना विरोधी पार्टी है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- देशप्रेमी है, जिसने देश को आजाद कराया वो देशप्रेमी है। (व्यवधान)

---

[33] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री उमेश पटेल :- आप द्वेष की भावना से काम कर रहे हो। आप द्वेष का सहयोग कर रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रधानमंत्री जन-मन-योजना है। देश में प्रधानमंत्री होते थे। वर्ष 1984 से 1989 के बीच। छत्तीसगढ़ में पर्यटन में दुगली, कुल्हाड़ी कोट में आये थे। दुगली में भी कमार रहते हैं, कुल्हाड़ी कोट में भी कमार रहते हैं। मेरे जिले में दुगली है। उन प्रीमिटिव ट्राइब्स की जन-जीवन दशा उस पर्यटन के बाद आज 40 साल बाद नहीं सुधरी है। देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन-मन-योजना लागू की। छत्तीसगढ़ के विधायक हैं। उधर भावना जी बैठी हैं। कवर्धा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। नारायणपुर के मंत्री जी हैं। आप उनको पूछ लीजिए कि उन भुंजिया लोगों के लिए, उन कमार लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है और उसमें स्टेट का पैसा लगे, 20 करोड़ रूपये उसके लिए दिया गया। एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं।

श्री विक्रम मंडावी :- आज वे डायरिया से क्यों मर रहे हैं? बैगा जनजाति के लोगों की वहां डायरिया से मौत हो रही है?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है अच्छी बातें कांग्रेसियों को देर से समझ में आती है। उसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी विशेषता यह है कि आप कांग्रेसी हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- अगर इतनी संवेदनशीलता है तो आपका आना कितनी बात हुआ? आप जनप्रतिनिधि हैं न तो क्या आपने क्षेत्र में आकर देखा है? इतनी संवेदनशीलता है तो आकर देखिए। यहां बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बार आकर आप देखिए। कभी हमारे लोगों से भी मिलिए।

श्री उमेश पटेल :- भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कांग्रेस वाले। आप क्या समझ रहे हैं? ये हर बार कांग्रेसी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- मैं बैगा जनजाति के बारे में बोल रहा हूं। आपके क्षेत्र के बारे में नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- हमारे क्षेत्र में भी बैगा जनजाति है, आप एक बार वहां पर भी आकर देखिए।

श्री भूपेश बघेल :- उमेश ऐसा है कि अजय जी की बात तो हम लोगों को समझ में नहीं आती। आपकी बात तो भा.ज.पा. वाले ही नहीं समझते। (हंसी) हम लोगों को कहां से समझ में आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- ई-यातायात आज की जरूरत है । उसकी शुरूआत करने के लिए 3 करोड़ रूपए ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, ये केवल इधर ही देखते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है दादी, शक्ल-ओ-सूरत से बेज़ार नज़र आते हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है । आप मुख्यमंत्री थे, चुनाव के पहले कुरूद विधान सभा क्षेत्र गए और आपने

चार घोषणाएं की थीं । भखारा को तहसील बनाने के लिए, नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए और एक पांच वर्षीय एल-एल. बी. कॉलेज खोलने के लिए । जो लोग कह रहे थे कि हमको ऐसा मिला, उनका उत्तर दे रहा हूं । मैं यहीं पर भूपेश बघेल जी के पास गया। मुख्यमंत्री इंस्टीट्यूशन होता है, वह कांग्रेस-भाजपा का नहीं होता । जो मुख्यमंत्री की घोषणा है उसको पूरा करिये । मुझे संकल्प लाना पड़ा, तब घोषणा हुई कि भखारा को तहसील बनाएंगे । संयोग से भूपेश बघेल जी ने उस समय कहा कि हम अनुविभागीय अधिकारी, तहसील, उपतहसील खोलेंगे तो एक मांग पूरी हो गई । मैं विष्णु शासन को या चौधरी शासन को बधाई देता हूं कि बाकी जो तीन घोषणाएं हैं । उसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज मुख्य बजट में आ गया, पहले बजट में । पांच वर्षीय एल-एल.बी इस बजट में आया है, आप पढ़िए । उसके बाद आखिरी में चौथी घोषणा की बात करूंगा । लेकिन इनके अतिरिक्त आप पढ़िए सिर्री में एक महाविद्यालय आया है, बी.एड. कॉलेज आया है, इसके अतिरिक्त आप पढ़िए कि मिल्क रूट बनेगा, नया चिलिंग प्लांट लगेगा । यह सिर्फ तीन विधान सभा क्षेत्र के लिए नहीं है, पूरा पढ़ोगे तो अनेक विधान सभा क्षेत्रों के लिए चाहे एक हो या चार हो, मौजूद है । छोटे से पूंजीगत् व्यय में सारी घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्पर्श किया गया । मैं इस नवजवान मंत्री को बधाई देता हूं, उन्होंने ये काम किया ।

विष्णु का सुशासन, जिस पर आप लोग हंस रहे थे । (श्री उमेश पटेल की ओर संकेत करते हुए) मैं आपको बधाई देता हूं पिताजी के क्षेत्र में नकली होलोग्राम बरामद हुआ । आपने पेपर में नहीं पढ़ा कि नकली होलोग्राम बरामत हुआ ? ए पितर में तोर पिता जी करा चिट्ठी जरूर भेजहूं काकरो मुसरिया मा दबाके । तोर टूरा पेपर ठीक से पढ़त नइ हे । नकली होलोग्राम बरामद हुआ है और उस होलोग्राम से जुड़े मुद्दों को ई.ओ.डब्ल्यू. ने 60 दिनों के अंदर जांच करके चालान प्रस्तुत कर दिया, ये विष्णु का सुशासन है (मेजो की थपथपाहट) । माननीय महोदय, सुशासन और अभिसरण विभाग नया बनाया गया, ये विष्णु का सुशासन है ।

श्री उमेश पटेल :- इस सुशासन में एक चीज और जोड़ लीजिए । माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी और कुछ दिन बाद वह ट्वीट डिलिट हो जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 1987 में राजीव गांधी जी के कार्यकाल के 30 साल बाद इस देश को नई शिक्षा नीति मिली थी । 2017 में नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश को नई शिक्षा नीति दी । कस्तूरी रंगन जैसे वैज्ञानिक ने उसको बनाया । आपने राजनीतिक विद्वेष से उसको लागू नहीं होने दिया । उसको लागू करना किसी ने शुरू किया तो विष्णुदेव साय ने शुरू किया, यह सुशासन है (मेजो की थपथपाहट) । ये पढ़ाई-लिखाई की बात समझ थोड़े ही आएगी । महोदय, आप बोल रहे थे कि आप जल्दी आ गए । बलौदाबाजार की घटना में बोल रहे थे । मेरा आरोप है कि इस सदन में मौजूद एक विधायक ने वहां के खाने-पीने का, टेंट का खर्चा उठाया है, कांग्रेस पक्ष का विधायक है (शेम-शेम की आवाज़) । मेरा आरोप

है । यदि वह सतनामी समाज का कार्यक्रम था तो कांग्रेस के दो विधायक मंच पर क्या कर रहे थे? क्या एन.एस.यू.आई. का अध्यक्ष होने से, क्या युवक कांग्रेस का अध्यक्ष होने से अपराध करने का लायसेंस मिल जाता है (व्यवधान) ।

श्री विक्रम मंडावी :- और भाजपा के लोग क्यों गए थे ?

श्री उमेश पटेल :- भाजपा के लोग मंच पर उपस्थित थे, उन पर कार्यवाहीं क्यों नहीं हो रही है (व्यवधान) ।

श्री विक्रम मंडावी :- भाजपा के लोग भी तो गये थे। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- क्यों कार्रवाई नहीं की गयी। आप गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्वाईंट मैं जांच आयोग के सामने रखूंगा। इस बिंदु को शामिल किया जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलकर बोलूंगा। इस सदन में उपस्थित विधायक उस सतनामी समाज के मंच पर क्या कर रहे थे ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, एक मिनट। बैठिए। चलिए आप उठाईए।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, नये सदस्य यदि कुछ बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा परंपरा को सीखिए जानिए। माननीय अजय जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। ट्रेजरी बेंच में भी रहे हैं और विपक्ष में भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वे हमेशा नियम प्रक्रिया की बात करते हैं। अभी आपने आरोप लगाया, क्या किसी भी सदस्य के खिलाफ यदि आप आरोप लगाते हैं, क्या लिखित सूचना विधान सभा सचिवालय को दी गयी है और क्या विधान सभा सचिवालय से अनुमति मिली है ? जिसमें इतना तीखा अंदाज में आपने आरोप लगाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। यदि मैं व्यक्तिगत नाम लेकर आरोप लगाऊंगा तो निश्चित रूप से अनुमति लूंगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया और मैं जिसका भी नाम लूंगा जांच आयोग के सामने बताऊंगा कि ये आदमी मंच में मौजूद था और इन्होंने टेंट और खाना का खर्चा दिया। इसमें जांच होनी चाहिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास इतनी स्पष्ट जानकारी है तो हम लोग कल इस विषय पर स्थगन में चर्चा करना चाहते थे, उसमें आप लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे थे ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- तब आयोग की बात आ रही थी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- आप लोग इस विषय पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहते हैं ? विधान सभा में चर्चा करना क्यों नहीं चाहते हैं ? आरोप लगाने से नहीं चलेगा, आप सत्ता में हैं, आपको सच सामने लाना पड़ेगा और आपको चर्चा करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी व्यवस्था चाहूंगा कि सदन में किसी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं होगा, सुस्पष्ट होगा। माननीय अजय जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह बेहद आपत्तिजनक है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। एक विषय जो भूपेश जी ने उठाया, वह मैं पूरी ध्यान से सुन रहा था। अजय चंद्राकर जी ने अपने भाषण के दौरान किसी भी सदस्य का नाम नहीं लिया है। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भा.ज.पा. की पहली सरकार सन् 2000 में बनी। उसको अस्थिर करने की कोशिश हुई। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास जानता है कि नगद पैसे 40, 42 लाख रूपए बरामद हुए। किसका नाम आया पूरा प्रदेश जानता है। बर्दाश्त नहीं हुआ कि भा.ज.पा. जीत सकती है, विष्णु जी का शासन आया, भा.ज.पा. का शासन आया। [XX][4] को यह पसंद नहीं आया। एक इनोसेंट समाज को, एक इनोसेंट लोगों को सामने रखकर उसके पीछे [XX] के नामधारी लोगों की ताकत और अस्थिर करने की कोशिश की गयी। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- आपको प्रूफ करना पड़ेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- है हिम्मत तो आप नाम लीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। (व्यवधान) हम ऐसे में चर्चा नहीं करेंगे।

श्री विक्रम मंडावी :- आपको नाम लेना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप जोर से बोलेंगे तो हम लोग डर जाएंगे। क्या समझते हैं ? आप धमकी दे रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- हिम्मत है तो आप नाम लीजिए। (व्यवधान)

---

44 [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हिम्मत है तो आप नाम बताईए। आप ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, बैठिये । आप बैठिये । बैठिये आप लोग (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माफी मांगे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, जब बलौदाबाजार की बात हो रही थी तो इसी सदन में अजय चन्द्राकर जी ने कहा था कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसमें आयोग का गठन होगा । आज वह खुले आम आयोग ....(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह आरोप है तो चर्चा ला दीजिए, हम इस पर चर्चा करेंगे । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, बार-बार यही आरोप लगा रहे हैं । आप आरोप क्यों लगा रहे हो, आप सत्ता पक्ष के हो, नहीं हो । आप जांच करा लें । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप जांच कराईये ना, साबित हो जायेगा । जांच कराकर साबित कीजिए, अगर हम दोषी हैं तो । हम तैयार हैं । आप जांच करा सकते हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की एक बात तो सही निकली कि इस बजट में बताने के लिये कुछ है नहीं, जो बताना था उमेश जी ने पहले ही बता दिया, इसलिये ये बजट में बात न करके आरोप-प्रत्यारोप....(व्यवधान) अगर हिम्मत है तो स्थगन आपने क्यों नहीं लाया ...(व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- शांतिप्रिय भीड़ को...(व्यवधान) अगर सच दिखाया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है तो आपको आपत्ति होती है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- अजय चन्द्राकर जी माफी मांगे.... (व्यवधान)

(नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मनिट के लयिे स्थगति की जाती है ।

(4.47 बजे से 4.59 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
4.59 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिस प्रकार से पहले व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग किया, मैंने प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया, आपकी तरफ से व्यवस्था आ गई कि माननीय अजय जी ने किसी का नाम नहीं लिया है और कार्यवाही आगे बढ़ी । उसके पास पूरे विपक्ष के सदस्यों के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विपक्ष के साथियों को षडयंत्रकारी बताया, यह तो बर्दाश्त के बाहर है । हम तो यही निवेदन करेंगे कि अजय जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । वे इस सदन से क्षमा मांगे, अपना वक्तव्य वापस लें, यह हम आपसे चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । बातचीत के दौरान बहुत सारे विषय, कुछ व्यंगात्मक बातें आ जाती हैं, उससे काफी सदस्यों को कुछ आहत महसूस हुआ । मुझे लगता है कि इससे सदन की गरिमा और आप जितने वरिष्ठ सदस्य हैं, कुछ कहना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय भूपेश बघेल जी के लिए आज तक कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने **(xx)**[5] कहा। परन्तु आपको उसमें से कोई भाषा ऐसा लगता है तो आप उसको संशोधित करवा सकते हैं, विलोपित करवा सकते हैं। अगर सदन में **(xx)** दल का नाम नहीं ले सकते तो किसका नाम लेंगे ? वह आपके विवेक पर है। वह मेरे लिए कोई प्रेस्टिजियस नहीं है, कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। सदन अच्छा चले, यह सबसे महत्वपूर्ण है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो खेद व्यक्त किया ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं क्यों खेद व्यक्त करूं ? मैंने तो अध्यक्ष महोदय के विवेक पर छोड़ा है। जो अप्रिय चीजें हैं, वह आपके विवेक पर है, वह आप देख लीजियेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक अजय जी क्षमा नहीं मांगेंगे, हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ हैं। जब तक अजय चन्द्राकर जी सदन से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग सदन की कार्यवाही में भाग लेने में ...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप लोग बैठिये। आपने काफी लंबे समय से इस प्रदेश को चलाया है, आप सदन को बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है कि जिस विषय को लेकर अजय चन्द्राकर जी ने कुछ विषय, जो आप लोगों को लगता है कि ठेस पहुंचाने वाली है, मैं उसको देखकर कार्यवाही से सब निकाल दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इतने में तो नहीं होगा। क्योंकि यह पहली बार नहीं है। अजय जी की भाषा हर बार रहा है। जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे, अध्यक्ष महोदय, आपने आसंदी से व्यवस्था दे दी है, आपका आदेश शिरोधार्य है। हमारा कांग्रेस विधायक दल यह तय कर रहा है कि जब तक अजय जी भाषण देंगे, वह किसी भी सत्र में भाषण देंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे।

[5] (xx) अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार विलोपित

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय
5.02 बजे

बहिष्कार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा प्रयुक्त कथन व क्षमा ना मांगने के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के द्वारा प्रयुक्त कथन एवं क्षमा नहीं मांगने के विरोध में उनके भाषण का बहिष्कार किया गया)

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं ?

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, आप कन्टीन्यू करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, बातें कांग्रेस को बुरी लगी, यह बात पूरे समाचार-पत्रों में छाया है कि कांग्रेस के एक विधायक को बलौदा बाजार काण्ड में पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया। क्या यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है ? अगर वह अपराधी नहीं है तो सदन में सामना करना चाहिए, यह बात कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस का कोई भी विधायक शामिल नहीं है और पुलिस जो बयान दिलवा रही है, वह उचित नहीं है, आज कांग्रेस के नेता की भूमिका निभाते हुए यह बात श्री भूपेश बघेल को कहना चाहिए। मैं तो स्पष्ट तौर पर नाम ले रहा हूं कि श्री देवेन्द्र यादव को पुलिस ने 3 बार पूछताछ के लिए बुलाया। क्यों बुलाया, किसलिए बुलाया, क्या भूमिका थी ? मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस के एक आदमी ने उनको टैंट मुहैय्या कराया, खाने का खर्च मुहैय्या कराया, यह मैं जांच आयोग को बताऊंगा। कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, एक विधायक, दो-तीन और बड़े नेता, चूंकि वे सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, घटनास्थल पर क्या कर रहे थे ? भजन गा रहे थे ? माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पास नैतिक रूप से ताकत नहीं है। आपातकाल लगाते हो, छत्तीसगढ़ में खरीदी करते हो, चाहे आपके शासन को इस तरह से एक इनोसेंट समाज को सामने करके, षड़यंत्र करके लड़ाने का काम हो, अस्थिर करने की कोशिश हो, मैं फिर से दोहराता हूं कि यह कांग्रेस का ही काम है। घुटने के नीचे, कमर के नीचे आक्रमण कर सकती है तो यह कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और ये लोग कर सकते हैं, जो आज पलायन करके गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे इन लोगों के लिए एक आग्रह करूंगा। शासन का थोड़ा इकबाल दिखना चाहिए, इकबाल कैसे दिखना चाहिए ? ये जो लंबी-लंबी बातें

कर रहे हैं, इनके 5 साल इतने कुकर्म हैं, पी.डी.एस. में संचालित दुकान के बारे में पिछले सत्र की घोषणाओं में सिर्फ एक कमेटी बनी है, श्री पुन्नूलाल मोहले जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। तेलीबांधा में डिवाइडर का प्रश्न, यह मेरा प्रश्न था। आपने उसकी उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की है। यदि हम विधानसभा की घोषणाओं का पालन नहीं करते हैं तो इन खाये-पीये, घूमे लोगों का मनोबल बढ़ता है। यदि उसकी घोषणा पर अमल नहीं होगा तो आज और अभी यह विधान सभा की अवमानना मानी जाएगी। यदि कोई अधिकारी अपने हितों के कारण इसको रोकने की कोशिश करता है तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आपसे इस बात की मांग करता हूं। स्वामी आत्मानंद स्कूल के भवनों के पुनर्निर्माण पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने जांच की घोषणा की थी। डी.एम.एफ. मद से स्कूल में जो राशि खर्च की गई, उसमें तत्कालीन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने श्वेत पत्र जारी करने का आश्वासन दिया था। स्मार्ट सिटी के कार्यों में आवास एवं पर्यावरण मंत्री माननीय ओ.पी. चौधरी जी ने जांच की घोषणा की। इसमें शराब दुकानों से प्राप्त राजस्व संबंधी प्रश्न पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी द्वारा जांच की घोषणा की गई। यदि यह जांच धरती में उतरती तो क्या इनकी यह हिम्मत होती ? यह हमसे क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। हमने पिछले 5 सालों में इनके कौन-कौन से तौर-तरीके झेले हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के रिश्तेदार 3 महीने तक अकारण जेल में थे। अश्रु गैस फोड़ने वाले, लाठी चलाने वाले हमको बोलना सिखाएंगे। यह एक बात को असंसदीय साबित नहीं कर रहे हैं और क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैं आसंदी से रोज क्षमा मांग सकता हूं। मैंने इस बात को आसंदी के ऊपर छोड़ा कि आपको जो अप्रिय लगे, वह आप कर लीजिये। भूपेश बघेल जी इसको निर्धारित नहीं करेंगे कि कौन सा शब्द संसदीय है और कौन सा शब्द असंसदीय है। तारांकित प्रश्न-धरसींवा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध प्लॉटिंग में टंकराम वर्मा जी द्वारा जांच की घोषणा की गई। माननीय टंकराम जी कहां हैं? राजीव युवा मितान क्लब के ऊपर आज माननीय राजेश मूणत जी का ध्यानाकर्षण था। चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी के द्वारा उसकी जांच करवाने की घोषणा की गई। औद्योगिक पार्क हेतु बजट की चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री (गृह) विजय शर्मा जी के द्वारा रीपा की जांच की घोषणा की गई। यह सब इन्हीं के खाये-पीये टकराहा लोगों के काम हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इसको क्यों नहीं कर रहे हैं और आपका इकबाल क्यों नहीं दिख रहा हैं ? रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन संबंधी प्रश्न पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी के द्वारा जांच कराने की घोषणा की गई। बिरनपुर में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री (गृह) जी के द्वारा सी.बी.आई. जांच कराने की घोषणा की गई। शायद यह हो गया, इसलिए आपको बधाई हो। आप जो करेंगे, उसकी आपको बधाई हो। जिला सरगुजा में अपराधों के दर्ज प्रकरण संबंधी चर्चा के दौरान लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी द्वारा जांच कराने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री जी, मुझे

लगता है कि आपको बजट चर्चा में उनकी अनुपस्थिति की जांच करवानी पड़ेगी। (हंसी) पॉवर प्लांट एवं उद्योगों में कार्यरत् श्रमिक के संबंध में चर्चा के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन जी द्वारा जांच की घोषणा की गई। माननीय मंत्री जी, आपको यह याद है या नहीं है ? क्या आप बताएंगे कि यह कब तक क्रियान्वित होगा ? 6 महीने निकल गये हैं और पार्टी भी इसकी समीक्षा कर रही है। हम इसी को उसमें रख देंगे। यह जांच की घोषणा हुई है तो आप इसी को क्रियान्वित करवा दीजिए। इससे कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचारी हैं, वह कहीं न कहीं उचित स्थान पर सम्मान पाते हुए दिखेंगे। इनके ऑर्डर को मानने वाले बेचारे ब्यूरोक्रेट लोग जबरदस्ती इसको भोग रहे हैं। हम लोग इतना बढ़िया जेल बनवाये हैं। आप समझ रहे हैं न ? यह गृहमंत्री जी से आग्रह कर देंगे कि वह हमारे राजनीतिक साथी हैं तो इन लोगों को आप थोड़ी विशिष्ट सुविधा दें। आप इसको करवाएंगे, तब तो यह होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनके लिए सब सुविधाएं हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- धर्मजीत जी बता रहे हैं कि उनके लिए सब सुविधाएं हैं। हम हमारी कमेटी का एक दौरा करवा देते।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैया, पहले तो वहां पूरी सुविधा थी। ब्यूटी पार्लर भी वहीं था। सब कुछ तो वहीं था। मुझे अभी का मालूम नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत यांत्रिकी सेवा विभाग की सड़क संधारण संबंधी प्रश्न पर लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी द्वारा जांच कराने की घोषणा की गई। यह मेरा प्रश्न था कि पैरादान व उसके परिवहन के भुगतान पर चर्चा के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच कराने की घोषणा की गई। जहां तक मेरी सूचना है कि इसको अभी तक सरकार के द्वारा प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपा नहीं गया है कि यह-यह दस्तावेज हैं, इसको आप ले जाएं। बाकी विधान सभा सचिवालय बताएगा। जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मैं विधान सभा के बारे में अधिकृत रूप से कुछ बोल नहीं सकता हूं। गोबर खरीदी में बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जॉच कराने की घोषणा की गई। जिला खनिज न्यास दंतेवाड़ा के उपयोग संबंधी प्रश्न पर चर्चा के दौरान श्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा जांच कराए जाने की घोषणा की गई। तारांकित प्रश्न संख्या 11, अंग्रेजी शराब की आपूर्ति, ओवररेट, अवैध विक्रय कार्रवाई संबंधी चर्चा के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा जांच की घोषणा की गई। रायपुर स्थित जंगल सफारी में वन्य जीवों की बड़ी मात्रा में आकस्मिक मृत्यु होने पर श्री केदार कश्यप जी द्वारा जॉच कराये जाने की घोषणा की गई। केदार कश्यप जी कहॉ हैं, अभी तो थे?शताब्दी नगर, तेलीबांधा। शताब्दी नगर, तेलीबांधा वाले भी बलौदा बाजार में घटना स्थल पर उपस्थित थे। भवन पर नियम विरूद्ध कब्जा कर अनियमितता किए जाने संबंधी उप मुख्य मंत्री नगरीय प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की घोषणा की गई। आप तो है, सरकार से उच्च

स्तरीय, मध्यम स्तरीय, निम्न स्तरीय आदि कुछ हुआ है? कुछ भी स्तरीय हो, उसकी घोषणा तो कर दीजिए। हम लोगों तक तो नहीं पहुंची, कमेटी जांच करेगी। आपने जादू की सड़क में भी कहा था कि कमिश्नर जांच करेंगे। राजनांदगांव में दैनिक वेतनभोगी दर पर अनियमित नियुक्ति किए जाने संबंधी ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा जांच कराये जाने की घोषणा की गई। इनकी हिम्मत है किइतनी जांच हो जाए तो यहां आकर कॉय-कॉय करें। विधान सभा आने के बजाय आधे लोग और जो इनके साथी हैं, जो कि सदन में नहीं आ पाए, वे 22 लाख की बिल्डिंग में ऐश करेंगे। ये भड़क रहे हैं! इनमें से जितने फर्जी हैं, कितने फर्जी हैं, ये प्रमाणित तौर पर पाये जायेंगे, प्रमाणित तौर पर। और मैं जॉचकर्ता अधिकारी नहीं हूं। जो विधान सभा में हमारे प्रश्नोत्तर हैं, यदि उसी की जांच कर लें, जो सरकार ने उत्तर दिया है, उसमें जॉच कर लें। आप लोगों ने समय-समय पर जो उत्तर दिया है, उसमें जॉच कर लें। कॉग्रेस के आदमी होने से कोई निरपराध नहीं हो जाता। एन.एस.यू.आई. का अध्यक्ष, एक विधायक से जॉच की गई, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी से पूछताछ की गई। यह आरोप बिल्कुल राजनीतिक है कि सरकार का दृष्टिकोण किसी दो, तीन या चार विधान सभा तक केन्द्रित है। विष्णु के सुशासन का अर्थ ही सम्यक विकास होता है और सरकार पहले बजट से ही सम्यक विकास के काम कर रही है लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, जिस पर मैं पॉच साल तक लड़ता रहा।जो अनियमितता हुई, उसकी आप जांच कर लें। जायसवाल जी भी हैं, पेट स्कैन और गामा मशीन के चालू कीजिए। एक रुपए का भुगतान उन मशीनों का भाजपा शानकाल में नहीं हुआ। उनका भुगतान कांग्रेस शासनकाल में हुआ औश्र मशीन ये लोग खाए, ये जांच का विषय है और डी.के.एस. जो कि मध्य भारत का हमारा सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पेट स्कैन और गामा मशीन शुरु होने के बाद गरीबों को कैंसर की सुविधा मिली। सात4 महीने हो गए, कोई भी प्रक्रियागत त्रुटि यदि अधिकारियों ने की होगी, तो आप कैबिनेट में जाइए, उन्हें प्रताड़ित कीजिए जिन्होंने भी गलत किया है लेकिन पेट स्कैन और गामा मशीन शुरु होना चाहिए, यह मेरली मांग है। यदि मैं सहसहीसही कहूं तो वह रहे या न रहे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे जरुर इस बात से फर्क पड़ रहा है कि नौजवान गृह मंत्री हैं, नौजवान वित्त मंत्री हैं, आपका इकबाल नहीं दिख रहा है। मैंने इतने सरे जांच पढ़े, अभी तक खेल हो जाना था। अभी तो वह लोग खेला कर रहे हैं और इतनी लंबी-लंबी बात कर रहे हैं, तो मैं यही अपेक्षा करता हूं कि यह सब जांच समय सीमा के अंदर घोषित होगी। कोई इस दबाव में नहीं आएंगे कि जांच करवाना ही हमारा काम नहीं है लेकिन जो गड़बड़ी हो गई है, उसकी जांच होगी और हम विकास के पथ पर आपके सम्यक बजट से आगे बढ़ेंगे। माननीय चौधरी जी, अब एक बात है। मैं अपने विषय में बोलता नहीं, मैंने चिट्ठी लिखी। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी मुंगेली के बारे में बहुत बोलते हैं, यदि मुंगेली में जमीन होती तो वह हवाई अड्डे की मांग जरुर किए होते। मैंने चिट्टी लिखी, पतरी लिखी, मेरा एक विषय आपने छोड़ दिया। आप उत्तर देते समय उसकी या तो घोषणा कर दीजिये या तो मुझे कान में बता दीजिये कि आप उसको कैसे

पूरा करेंगे ? लेकिन आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस समवेत् सदन की भावनाओं का ख्याल रखते हुए मुख्य बजट से लेकर प्रथम अनुपूरक को एक समयक और सुव्यवहारित तरीके से पेश किया है, मैं इसके लिये आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा के सत्र में यह अनुपूरक बजट जो लगभग 7,329 करोड़ रूपये का है, मैं इस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले जब हमारे नये वित्त मंत्री ने बजट सत्र में अपना बजट प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ का विजन डाक्यूमेंट, 2047 रखा था। आप देखिये कि अनुपूरक बजट में जहां जिला जेल के लिये 31 करोड़ रूपये मिलता है, वहीं माध्यमिक शिक्षा भवनों के उद्धार के लिये 1.25 करोड़ रूपये मिल रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ का विजन देने की बात हुई थी। आज यह हालत है कि बिलासपुर जिले में कोटा विधान सभा क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में डायरिया और मलेरिया फैला हुआ है। कर्वधा जिले के सभी गांवों में मलेरिया फैला हुआ है। हमारे विक्रम मण्डावी जी के बस्तर क्षेत्र में मलेरिया और डायरिया फैला हुआ है। इसके लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास गाड़ियां नहीं हैं। आपने इसके लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। क्या यही विजन, 2047 है ? आम आदमी रोटी, कपड़ा, मकान और ईलाज के लिये मर रहा है परंतु आपका विजन, 2047 कहां जा रहा है ? यहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने एक योजना शुरू की कि मां के नाम एक पेड़ लगाया जाये। हम उसका स्वागत करते हैं कि हम अपनी मां के नाम का एक पेड़ लगायेंगे परंतु हमारे पूर्वजों ने हसदेव में बहुत सारे पेड़ लगाये थे, उनको आज उद्योगपतियों के लिये काटा जा रहा है, उसका क्या होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा ? अभी मैंने केवल मलेरिया और डायरिया की बात की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सांप काटने की दवाई उपलब्ध नहीं है। सांप काटने से आदमी मर रहा है। यही आपका विजन, 2047 चल रहा है कि सांप काटने से आदमी मरते जा रहा है ? आम आदमी को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभी आप जाकर पता कीजिये कि कितने अस्पतालों में टी.बी. की दवाई खत्म हो चुकी है। इसके लिये आपका विजन कहा है ? आपको मालूम है कि बरसात का समय आता है तो यह बीमारी फैलती है । वर्ष 2009-10 में इसी बरसात के समय में कोटा विधान सभा में डायरिया से 100 लोगों की मौत हुई थी। जब अधिकारियों को यह मालूम है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है, तो उसकी पहले से तैयारियां शुरू क्यों नहीं की जाती ? उसके लिये पहले से बजट का प्रावधान क्यों नहीं किया जाता ? जब अनुपूरक बजट आता है तो उस अनुपूरक बजट में भी मरने वालों का कोई स्थान नहीं है। आपका अनुपूरक बजट

विजन, 2047 की तरफ बढ़ रहा है। जब आपने 06 महीने में 25 हजार करोड़ रूपये कर्ज ले लिया तो विजन, 2047 के समय इस छत्तीसगढ़ का कहीं दिवालिया न निकल जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पी.एस.सी. की बात चल रही थी तो आपने बहुत बड़ी बातें कही थी कि आप उसमें सी.बी.आई. जांच करायेंगे। अभी आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से शीघ्रलेखन और टाईपिंग की परीक्षा ली। उसमें लगभग 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी। आपने 150 रूपये, 300 रूपये और 400 रूपये उसकी फीस रखी। जब छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी तो परीक्षा में लगने वाली फीस में छूट प्रदान की गयी थी परंतु आपने परीक्षा की 150 रूपये, 300 रूपये और 400 रूपये फीस ली और उस परीक्षा को निरस्त कर दिया। उन बेरोजगारों का पैसा कौन वापस करेगा ? क्या उसके लिये अनुपूरक बजट में कोई प्रावधान है कि इन बेरोजगारों के लिये कोई प्रावधान किया जा सकता है ? अध्यक्ष महोदय, अभी जल, जंगल, जीवन की बात हुई। अभी यहां हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी जगहों पर जल जीवन मिशन का काम खराब चल रहा है, बहुत जगहों पर अच्छा काम किया गया है, टंकियां बनी हैं, पानी की सप्लाई पूरी तरह से हो रही है। परंतु कई जगहों पर ऐसा है, जहां पर टंकियां लगा दी गयी है, पाईपलाईन बिछा दी गयी है, परंतु बोरिंग नहीं हुआ है। जब बोरिंग का ही काम नहीं हुआ है तो कैसे गांव में पाईप से पानी पहुंचेगा ? यह अनियमितताएं हैं। आपने देखा कि ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी आपसे पूछा था कि मेरे कोटा विधान सभा क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर की जरूरत है। आपने उत्तर में निरंक लिखा था, तब माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि आपके क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लग जायेंगे। हमारे बिलासपुर जिले में एक एस.डी. इलेक्ट्रिकल करके पूने की कंपनी है जिसको 100 करोड़ रूपये का यह ठेका मिला हुआ है कि वह बिलासपुर जिले के सभी जगहों पर 100 करोड़ रूपये की लागत से ट्रांसफार्मर और लाईन बिछायेगी। अभी तक उसने 6 प्रतिशत काम किया है। आपकी सरकार को 7 महीने का समय हो गया, पर अभी तक गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं था तो गरीबों, किसानों का गर्मी का धान खराब हुआ। यहां स्नैक बाइटिंग का काम आ रहा है क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एस.डी. इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है, उसे काली सूची में डाला जाए और गांवों में बिजली पहले पहुंचायी जाये। पहले हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सरप्लस स्टेट कहा जाता था। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है। हम अपना कोयला, पानी देते हैं। हम प्रदूषण की राख खाते हैं, पर आज गांव-गांव में जो बिजली की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या हमारी बिजली पर हमारा हक नहीं है। जो हम अपना कोयला, पानी देते हैं तो हमें बिजली पाने का भी हक है। मुझे तो यह डर है कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली बिजली कहीं उन उद्योगपतियों के हाथ में

पिछले दरवाजे से न भेजी जा रही हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर बिजली गांवों में नहीं पहुंच रही है तो यह बिजली कहां जा रही है ?

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक बजट रखा, पर हमारे प्रदेश के गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए आपका विज़न कहां हैं ? वह विजन कब आएगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विजन को लाईये। आपने जिस विजन 2047 की बात की थी, जिसमें लोगों को बिजली, पानी और शिक्षा उपलब्ध होगी। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अटल श्रीवास्तव जी किसी ठेके के बारे में बात कर रहे थे। पूर्व में आपकी सरकार ने ही 86 करोड़ रूपये का ठेका दिया है। डेढ़ सालों से वह ठेका पेंडिंग है न तो आपने कोई काम होने दिया, न उसके ऊपर एक्शन लिया, न उसमें दो खम्भे गड़ पायें। अभी आप कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए तो हम लोगों ने एक्शन के लिए प्रश्न पूछा है। यह सरकार एक्शन के लिए उस दिशा में बढ़ गई है। अगर वह नहीं करेंगे तो और कोई करेगा। हमारी सरकार का रूपया है, इस प्रदेश की जनता हमारी है। यह विभाग हमारा है। किसी ठेकेदार के रहमोंकरम पर इस प्रदेश की सरकार नहीं चलने वाली है। हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, चाहे उत्पादन कितना भी हो, आपके पास पानी कितना भी हो, अगर आपके पास गुण्डी और पानी रखने का ड्रम नहीं रहेगा तो आप पानी कहां रखेंगे ? आपको सब स्टेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत सी मंजूरी है, लेकिन आप लोगों ने सब स्टेशन के लिए जगह की समस्या का समाधान नहीं किया। हम उसको भी हल कर रहे हैं। यह बात सही है कि यहां पर बिजली की समस्या है, लेकिन उसके लिए आप विष्णु देव साय जी को सरकार को पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आंशिक रूप से वे भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन पूर्व में आपकी सरकार की सारी जिम्मेदारी थी क्योंकि आपके बिजली के विभाग की व्यवस्था ठीक नहीं थी। हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी हमारी भाभी जी, आदरणीया अनिला भेंडिया जी का स्वर बदला हुआ दिखा। आपने ही तो रेडी टू ईट को छिना था। आपने ही तो बीज निगम को मशीन से बनाने के लिए दिया था। आप कहां, कब से ..।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अब आपकी सरकार को 7 महीने हो गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है। आप 5 सालों तक रेडी टू ईट को पूरा ईट कर रहे थे तो यहां पर उसके लिए आप लोग क्यों बेकार का तमाशा कर रहे हैं ? हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं,

व्यवस्था सुधार रहे हैं, व्यवस्था होगी। 6 महीने में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम छुवाएं और प्रदेश की सारी समस्याओं का हल हो जाए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बच्चों, माताओं को रेडी टू ईट नहीं दे रहे हैं तो 7 महीने में आप लोग रेडी टू ईट खा गये क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय,5 सालों तक रेडी टू ईट को कौन ईट किया ? बीज निगम में ईट हुआ। वहां पर रेडी टू ईट बना। अब थोड़ा ईट हुआ है तो उसे निकालने दीजिए। इधर हम रेडी टू ईट बनवाएंगे फिर सबको ईट करवाएंगे। हम सबको ईट करवाएंगे। आप लोगों को भी मिलेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम में भी सही से नहीं पहुंच रहा है। वह यहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है।

श्रीमती अनिला भेंडिया:- क्या है, बीज निगम को राशि भी नहीं दे रहे हैं। सब उधर ही जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप चिंता मत करिये। यहां पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राईस मिलरों को भी होटल में बुला-बुला कर, कहा जा रहा है। आप समझ रहे हैं न ?

श्री देवेन्द्र यादव :- 7 महीने गुजर गए।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिए। आपकी सरकार में राईस मिलरों को क्या कहा जाता था ।

श्री उमेश पटेल :- उनको कहां, क्या कहा जाता था, वह भी समझ लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सदस्य आप बताईये। आप आरोप लगाईये।

श्री रामकुमार यादव :- राईस मिलर मन ला 5 सितारा होटल में बुलाए जावत हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- केवल यहां आपके कह देने से कोई होटल में नहीं जाएगा। अभी आपके खाद्य मंत्री जी का क्या हाल हुआ है, आप यह पता कर रहे हैं या नहीं ? यहीं बैठते थे, मेरे ख्याल से आपकी कुर्सी में बैठते थे।

श्री उमेश पटेल :- और क्या होने वाला है, वह भी समझ लीजियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिये, वह देखेंगे। पटेल साहब, आपने कहा था कि 3 विधान सभा में ही काम हुआ है। आप देखिये, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तो आपकी कदर भी करते हैं। इस अनुपूरक बजट में 7 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है, उसमें 5 हजार करोड़ रुपये तो महतारी वंदन योजना के लिए है। आप लोग विष्णुदेव साय जी को महतारी लोगों को वंदन करने देंगे या नहीं देंगे ? विष्णुदेव साय जी हमारी माताओं, बहनों को वंदन करना चाहते हैं।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- आप लोग अभी गर्भवती माताओं का, शिशुओं का रेडी टू ईट खा जा रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई नहीं खा रहे हैं। 5 हजार करोड़ रुपये उनके खाते में जायेगा। यह डॉयरेक्ट, इनडॉयरेक्ट वाला सब खेल बंद है, इसमें सब डॉयरेक्ट खाते में पैसा जायेगा।

श्री उमेश पटेल :- उनका कहना है कि जो 500 रुपये की कटौती हो रही है, उसको कहां उपयोग कर रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है, उसको बोलिये। उसको मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। वहां बैठे हैं, वह सुन रहे हैं। आपको बहुत तकलीफ है, 500 रुपये कटौती करके अगर 500 रुपये मिल रहा है, इसमें तकलीफ है तो उनको बोलिये। वह 2000 रुपये कर देंगे, हमको क्या तकलीफ है। आप बात करिये, बोलिये। आप जनहित में आवाज उठाईये, यह सरकार सुन रही है। सरकार के मुख्यमंत्री और दोनों उप-मुख्यमंत्री बैठे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- इस बात के दु:ख हे कि आप मन यही बात कह के चुनाव जीत के आये हव, तेकर बात हे। तुमन यही ला कह के चुनाव जीत के आये हव कि 1 हजार रुपये देबो।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम दिये तो हैं।

श्री रामकुमार यादव :- जनता के साथ धोखा होईस या नई होईस ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप 12 हजार रुपये देने के लिए बोले थे, आपकी बात नहीं चली। क्या कोई ने 12 हजार रुपये को माना ?

श्री रामकुमार यादव :- जनता के साथ धोखा होईस या नई होईस ? 1 हजार रुपये देबो कहकर जीत के आ गये और 4 नोट धरावत हे तो जनता के साथ धोखा होईस या नई होईस ? एला टी.व्ही में जाकर कहिहा कि हां 1 हजार रुपये कहे रहेन, 500 रुपये देत हन, एकर सती माफी मांगय लागही।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारे 1 हजार रुपये को मान लिये न। फिर इसी के नाम पर नगरपालिका में, पंचायत में भी मनवायेंगे। आप बोल रहे थे कि विष्णुदेव साय जी के कुनकुरी, बस्तर, हमारे उप-मुख्यमंत्री जी के कवर्धा, रायगढ में पूरा बजट गया। 5 हजार करोड़ रुपये महतारी वंदन योजना में, 1500 करोड़ रुपये सरकार के कंपलसरी खर्च में गया, मुश्किल से 800 या 1 हजार करोड़ रुपये विभिन्न किस्म के प्रावधान के साथ, अगर ये तीन लोग अपने क्षेत्र में काम करा लिये, भैया, जब हम वहां बैठ करके बात करते थे न, सारी चीज दुर्ग जिले में जाती थी। क्योंकि वहां 3 बड़े-बड़े महारथी थे। आप नाम बोलिये तो उनका नाम बता दूं। कुछ कवर्धा जिले में भी जाता था। क्योंकि वहां के भी एक मंत्री मुख्यमंत्री के ठीक पीछे बैठते थे, वह बहुत पावरफुल थे। साजा जाता था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय, आप तो कम से कम ऐसा मत बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्यों ?

श्री उमेश पटेल :- आपको याद है उच्च शिक्षा का जब भी बजट हुआ, एक-एक एरिया में दिया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरे क्षेत्र में आपने 1 करोड़ रुपये दिये, उसके लिए मैंने विधान सभा में आपकी तारीफ भी किया था, धन्यवाद भी दिया था। जो काम आपने किया, वह मैंने बोला। जब भी कोई मुख्यमंत्री वहां बैठता है, अगर वह अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर लिया तो उसको इतना तूल नहीं देना चाहिए। मेरा यह कहने का मतलब है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार नियद नेल्लानार योजना चला रही है, उसके लिए अनुपूरक बजट में 5 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या बुराई है? वहां सी.आर.पी.एफ. के 53 कैंप बनने हैं, अच्छा गांव मिले, हमारे गरीब आदिवासी भाईयों और बहनों को वहां पर सुरक्षा मिले, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? तीर्थयात्रा योजना के लिए 25 करोड रुपये का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। आप भी उसमें तीर्थयात्रा में जा सकती हैं। लेकिन आपको जाने से पहले आपके नेता से अनुमति लेनी होगी। क्योंकि हम लोग अयोध्या भेजते हैं और आप लोगों को अधोध्या जाने में तकलीफ होती है।

श्री देवेन्द्र यादव :- हमारे इंडिया गठबंधन ने अयोध्या जीती है। हम लोग अयोध्या जायेंगे, हमारे सांसद जी से भी मिलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- कौन जीता, हारा, वह तो छोड़िये, चुनाव हो गया है। आपके नेता अभी तक बड़े बाल वाले एक नेता के चक्कर में अयोध्या नहीं गये।

श्री उमेश पटेल :- क्या शंकराचार्य जी लोग अयोध्या गये ?

श्री धर्मजीत सिंह :- शंकराचार्य जायें या मत जायें, आप जाईये न।

श्री उमेश पटेल :- शंकराचार्य जी लोगों ने क्या कहा ?

श्री रामकुमार यादव :- शंकराचार्य जी लोग आप मन ला श्राप देय हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग शंकराचार्य जी से पूछकर जब मुहूर्त निकालेंगे, तब हम आपको अयोध्या भेज देंगे। लेकिन अगर प्रदेश की जनता अयोध्या जाना चाह रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं, उसके लिए अनुपूरक बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, आप लोगों का क्या तकलीफ है ? महंत जी क्यों बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या चले गये..।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्य सूची के पद क्रमांक-06 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं कि सभा सहमत हैं।

सभा द्वारा सहमतति प्रदान की गई।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी आप अयोध्या चले गये, बेर का सीजन नहीं है। आपको कितना बेर चाहिए? चलिये, मैं आपको नांदघाट में बेर दिलवाता हूं। आजकल कौन सा ऐसा वृक्ष है, जिसका सीजन में फल आता है। हर फल हर सीजन में मिलता है। यही तो राम भगवान की इस देश के ऊपर कृपा है (मेजों की थपथपाहट) और उसको अपने आराध्य भगवान को पूजा करने के लिए लेकर गये हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं तो बोलता हूं कि आप बड़ा दिल दिखाईये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, शिवरीनारायण के बेर की बात थी।

श्रीमती शेषराज हरबंश :- अध्यक्ष महोदय, शिवरीनारायण की बेर की बात हो रही थी। शिवरीनारायण में अभी बेर नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- आप इंग्लैण्ड के बेर ला छोड़ा। इंग्लैण्ड के बेर ला नई बोले हे, ये शिवरीनारायण के बेर के बात करे हे। आप विदेश के बेर ला खय हस ता काय मतलब। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप एक बार इन सबको चिट्ठी लिख कर भेजिये। डॉ. चरण दास महंत जी, भूपेश बघेल जी से लेकर इन सबको अयोध्या हवाई जहाज में जाने के लिए निमंत्रण भेजिये, उसके बाद इन सबका कलई खुल जाएगा कि यह लोग जायेंगे या नहीं जायेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भैया, शिवरीनारायण मा कहां बोइर खोजे हस तेला बता दे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको चिट्ठी लिखना है। आप एक बोइंग फ्लाईट कराईये और सबको बुलाईये। इसमें पूरे 90 विधायक जायेंगे और जो नहीं आयेंगे मैं उनको फिर अयोध्या के बारे में नहीं बोलने वाला।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भैया, शिवरीनारायण मा कहां बोई फरे हे?

श्री धर्मजीत सिंह :- छोड़िये न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं ओइ ला ता कहत हौं कि शिवरीनारायण मा कहां बोइर फरे हावय?

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या शबरी माता ने शिवरीनारायण का ही बेर खिलाई थी या गिरौद का खिलाई थी? यह कोई देखा है क्या ? उस इलाके में जहां बेर फला हो, वह भगवान राम का बेर था, शबरी माता का बेर था। भावना देखिये। भगवान राम को शबरी माता का बेर पसंद है। शबरी माता हमारे छत्तीसगढ़ में रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री शबरी माता का फल लेकर उनके पास गये, उनके चरणों में समर्पित कर दिये। यह भावनाओं की बात है। अब हम महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को पैसा दे ही रहे हैं। हम धान खरीदी में किसानों से धान पूरी तरह से खरीदकर एकमुश्त भुगतान कर रहे हैं। सब मिलेगा, आप चिंता मत करिये, यह विष्णु साय की सरकार है। आप लोग जो बार-बार विष्णु देव साय के बारे में साय-साय को अपमानजनक तरीके से बोलते हैं, उसका खामियाजा भी आपको लोक सभा के चुनाव में उठाना पड़ा है। इस लोक सभा चुनाव में आप लोगों ने जहां-जहां जाकर विष्णु देव साय की सरकार का साय-साय बोलकर अपमान किया है, वहां-वहां आप भाय-भाय चुनाव हारे हैं। (मेजों की

अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

थपथपाहट) माननीय वित्त मंत्री, मैं आपका तारीफ कर दिया ही हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जहां खोला है या नहीं खोला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो आप मेरे क्षेत्र में जरूर हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और पुल-पुलिया सब देंगे और अभी हमको चार साल रहना है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैं दो-तीन तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बिलासपुर हवाई सेवा के लिए मैं अपने सभी बिलासपुर के साथियों की ओर से चाहे वह इधर के हों या चाहे उधर के हों, मैं सबकी तरफ से आपसे कुछ विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। मेरा आग्रह यह है कि मैंने नाईट लैंडिंग के लिए यहां प्रश्न पूछा था, आपके तरफ से जवाब आया था। नाईट लैंडिंग डी.जी.सी.ए. (डायरेक्टर जनरल सिविल एवियेशन) के अनुसार डी.बी.ओ.आर. नामक उपकरण एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक है, लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी इस उपकरण के बजाय पी.बी.एन. (परफार्मेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी) के उपयोग के पक्ष में है, जोकि विवाद का विषय है। मैं बोल रहा हूं कि डी.बी.ओ.आर. नाम के उपकरण को क्यों नहीं लगवा देते। अगर डी.बी.ओ.आर. नाम का उपकरण लगेगा, हमारे बिलासपुर में हवाई जहाज उतरेगा और बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा के लोग वहां से हवाई जहाज में उड़ेंगे तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? माननीय मंत्री जी, आप इसको विशेष रूप से रूचि लेकर बता करिएगा।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- सी.एम. साहब हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं सी.एम. साहब को ही बोल रहा हूं, लेकिन आप वित्त मंत्री हैं, माल-टाल की व्यवस्था तो आप ही करेंगे। 1012 एकड़ जमीन सेना के कब्जे में थी। भूपेश बघेल जी ने उसके लिए प्रयास किया था। उसकी वापसी की सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। राज्य सरकार का 90 करोड़ रूपये रक्षा मंत्रालय को दिया जा चुका है। सेना ने पहले 287 एकड़ जमीन की वापसी पर सहमति दी। 287 एकड़ जमीन मिलने के बाद यह जमीन एयरपोर्ट में शामिल होगा। इसका सीमांकन छः माह से पेंडिंग है। मैं चाहता हूं कि जनहित में 287 एकड़ जमीन का सीमांकन तत्काल करवाईये और उसे 90 करोड़ रूपये दे देने के बाद अपने कब्जे में उसको आप ले लीजिये । दिनांक 4 अप्रेल को सीमांकन प्रारंभ हुआ था परंतु आज तक पेंडिंग है और 4-सी एयरपोर्ट के लिये रनवे की लंबाई 1500 मीटर से बढ़ाकर 2200 मीटर करना बहुत जरूरी है । इस 287 एकड़ के बाद वह एयरपोर्ट 4-सी एयरपोर्ट की कैटेगरी में आ सकता है, बोइंग और एयरबस वहां पर लेण्ड कर सकता है इसिलये इसकी लंबाई बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसके खर्च के लिये 200 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी । माननीय वित्तमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे बिलासपुर में रेल्वे का सबसे बड़ा जोन है, हमारे बिलासपुर में एनटीपीसी के बड़े-बड़े प्लांट हैं, हमारे बिलासपुर में कोल इण्डिया का हेड क्वार्टर है, हमारे बिलासपुर में हाईकोर्ट का न्यायालय है, हमारे चिरमिरी-कोरबा सब जगह बड़े-बड़े प्लांट हैं । वहां के लोगों को एयर कनेक्टिविटी देना हम सब लोगों न केवल धर्म है बल्कि यह वहां की एक आवश्यकता

है । इस आवश्यकता में रोड़े अटक रहे हैं और इस रोड़े को तोड़ने का काम, माननीय विष्णुदेव साय जी आपसे निवेदन है और हमारे काबिल, योग्य और युवा वित्तमंत्री जी आपसे उम्मीद है कि आप 200-300 जितने करोड़ रूपये भी लगे, हमें भी हवाईजहाज में बैठने का सौभाग्य प्रदान कराईये । वहां की जनता को हवाईजहाज में चढ़ने का अधिकार है, रेल्वे के माध्यम से हम कमाई देते हैं, एन.टी.पी.सी. के माध्यम से बिजली देते हैं, कोल इण्डिया के माध्यम से पूरे देश को कोयला देते हैं और हम हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते । हम क्यों यहां चढ़ने के लिये आयेंगे ? मजबूरी में आते हैं इसलिये आप इसको टॉप प्रॉयोरिटी में रखकर बिलासपुर के एयरपोर्ट के बारे में जरूर करियेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ दिन पहले टी.एस. बाबा के यहां अंबिकापुर गया था। वहां पर मुझे सरगुजा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के लोग मिले, उनका यह कहना है कि वहां पर दो प्रकार के डीजल-पेट्रोल की एजेंसी दी जाती है । एक उद्योग को देने वाला और एक जनरल पेट्रोम पम्प का, डीजल में वेट टैक्स का बड़ा खेल । हर साल सरकार को 200 करोड़ रूपये का चूना । यह वाड्रफ नगर या सरगुजा के पास से, उत्तरप्रदेश से लाते हैं या झारखंड से लाते हैं । वहां पेट्रोल की कीमत साढ़े 7 रूपये लीटर कम है क्योंकि वहां पर वेट टैक्स कम है । वहां से लाकर आपके लाईसेंस से यहां कोरबा, रायपुर सब जगह सप्लाई करते हैं । उसको बंद कराईये । वहां का टैक्स उत्तरप्रदेश में नहीं जायेगा, वहां के लोग छत्तीसगढ़ से लें उसके बाद भी उनको गुंजाईश है कि वे अपना काम कर सकते हैं और यहां की एजेंसियों को सप्लाई कर सकते हैं । यह पूरा कागज मेरे पास है । मैं इसे आपको जरूर दे दूंगा और आप इसमें कृपापूर्वक संज्ञान लीजियेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रेत का आपसे बोला ही था कि हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिये, चलते हैं । मशीनें मिलेंगी, आपने कार्रवाई की लेकिन अभी भी और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है । रेत माफियाओं को कुचलना बहुत जरूरी है और वह आप कुचल सकते हैं । आप थोड़ा बोलिये, मुख्यमंत्री जी तो बोल ही रहे हैं । मैं उन्हीं के सामने बोल रहा हूं मतलब आप कलेक्टर साहब लोगों से थोड़ा बोल दीजिये। शराब के बारे में आपने बहुत अच्छा किया । पिछली सरकार में शराब का बहुत अच्छा उद्योग धंधा था, करोड़ों रूपये की हेराफेरी, रेट के नाम से, इसके नाम से उसका कई पंचायती चल रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन पहले जो चखना की दुकानें चलती थीं वह चखना की दुकान सिफारिशों में दी जाती थी, वह सरकार के रिकॉर्ड में नहीं रहता था । नेताओं को या उनके समर्थकों को उपकृत करने के लिये लेकिन आपने उसका जो टेंडर किया है, मैं उससे असहमत हूं क्योंकि यह टेंडर करके कितने करोड़ मिला होगा, 50-100 करोड़ रूपये । शराब की दुकान के सामने कई किलोमीटर तक कोई दिखाई नहीं देना चाहिए । साहब, उसमें बुल्डोजर चलवाकर उसको तोड़वाईये । वहां की माताओं-बहनों को निकलना मुश्किल होता है और यह जो शेड वगैरह लगाकर शराब बेच रहे हैं और चखना दुकान चला रहे

हैं वह बहुत गलत है। हमारी माताओं और बहनों का निकलना मुश्किल हो गया है । क्या विष्णुदेव साय की सरकार इतनी कमजोर है कि 100-150 करोड़ रूपये अगर नहीं आयेगा तो सरकार का कुछ बाल बांका होगा ।

श्री उमेश पटेल :- नया टेंडर हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, ठीक है । जो हुआ है, मैं उसको भी तो बोल रहा हूं। यह सब तोड़वाईये । शराब की दुकान और शराब के धंधे में जो अवैध काम हो रहे थे। एफ-एल 10 और क्या-क्या सब गड़बड है, आपने उसको जो सब खत्म किया । मैं आपको इसके लिये बहुत बधाई देना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट) इसमें शराब में होलोग्राम वगैरह में भी ठीक-ठाक रखिए। ओव्हर रेट भी नहीं होना चाहिए साहब और ये शराब में जो इस तरीके से इन-डायरेक्ट घुसने का जो काम हो रहा है, बहुत ही बेकार काम है। इसको खत्म करिए, तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, निरस्त कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है।

श्री दिलीप लहरिया :- आप शराबबंदी की भी मांग कर दीजिये न। आप उस समय करते थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग तो गंगा जल रखकर कसम खाये थे फिर किये क्या? हम लोग गंगा जल क्या, कोई भी जल रखकर कसम नहीं खाते। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग गंगा जल लेकर कसम खाते हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- स्कूलों में अहाता निर्माण नहीं है, लेकिन आपकी सरकार ने चखना दुकान में, शराब दुकान में अहाता निर्माण किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है।

श्री धर्मजीत सिंह :- लहरिया जी, पिछली बार आप विधायक नहीं थे। आपकी सरकार जो आयी थी न, इलाहाबाद के संगम के गंगा जल को हाथ में रखकर कसम खाकर बोले थे कि हम बंद कर देंगे। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप असत्य बोल रहे हैं। असत्य बोलकर यहां पर आये हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आपका काम ही है असत्य बोलना। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- हमने तो कसम नहीं खाया है। न विष्णु देव साय कसम खाये हैं। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- कम से कम असत्य तो मत बोलिए। असत्य तो मत बोलिए। कोई गंगा जल से दारू के लिए कसम नहीं खाये थे, हम लोग अभी भी कसम खाते हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- कर्जा हमने माफ किया था। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिए, खारून का जल पकड़े हैं। कहीं का तो पकड़े होंगे। डंकनी-शंखनी का जल पकड़े होंगे पर पकड़े तो हो। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- क्या है ये शुरू से असत्य बोलते आये हैं। आप लोग आज तक असत्य बोलकर आ रहे हैं। यही असत्य बोलकर आप यहां पर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह असत्य बात है। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- यह गलत है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आर.पी.एन. सिंह तो आजकल आपकी पार्टी में चले गए हैं, राज्यसभा सदस्य हो गए हैं। उन्होंने गंगा जल उठाई । क्यों उठाई? क्योंकि एक पत्र जारी हुआ था और उस पत्र में ये था कि कांग्रेस भले घोषणा कर रही है ऋण माफी करेंगे, 2500 रूपये में खरीदेंगे, लेकिन ये खरीदने वाले नहीं हैं। दस्तखत हमारी पार्टी के जो महामंत्री है उसके और जो संचार विभाग के अध्यक्ष हैं उसके हैं। इस नाम से फर्जी जारी किया गया था। हम लोग एफ.आई.आर. भी किए और उस समय आर.पी. एन. सिंह, हम लोग नहीं थे। आर.पी. एन. सिंह गंगा जल हाथ में उठाकर बोले कि हम ऋण माफी करेंगे और 2500 रूपये में धान भी खरीदेंगे और ये असत्य, भैया आप तो सब दल घूम लिये हैं और सब दल की जानकारी रखते हैं, लेकिन कम से कम आप मत बोलिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- आर.पी.एन. सिंह आपके महासचिव थे।

श्री उमेश पटेल :- क्या है आपसे उम्मीद नहीं है। सुनिए ना आपसे उम्मीद नहीं है अभी आप इनके रंग में रंगे नहीं हो तो आपसे इस तरह से असत्य बोलने की उम्मीद नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- आपके रंग में तो बहुत रंगा था, कितना रंगे हो मुझे, मैं तो जान रहा हूं न? मैं जहां हूं, अभी ठीक से तो हूं, ईमानदारी से हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान मांगों पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित है। अभी तक एक घंटा 45 मिनट का समय लग चुका है। सूची के अनुसार 19 सदस्यों को बोलना है। अभी केवल चार सदस्य बोले हैं 15 को और बोलना है। मेरा आप सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि आप अपना संक्षिप्त भाषण 3 मिनट, 5 मिनट में समाप्त करें, आप भी अपनी बात जल्दी पूरा करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं 2 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं, सर। प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 3 लाख टन कोयला प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में जलता है। उसका मैं एक-एक ब्रेक अप कौन से इंडस्ट्री में कितने मेगावॉट में कितना कोयला जलता है ये बता सकता हूं और छत्तीसगढ़ से लगे हुए एरिया में उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में टोटल 10 लाख मीट्रिक टन कोयला प्रतिदिन ज्वलनशील पदार्थ के रूप में जलता है। आखिर ये धुआं जाता कहां होगा साहब? छत्तीसगढ़ हमारा वनों से 44 प्रतिशत आच्छादित है। हमारी यही जिंदगी है, हमारी सांस है, हमारी आत्मा है। उसमें ये उद्योग के नाम पर इसको कम कराइए, रोक लगाइए, उसमें कोई और सुधार हो सकते हैं तो करिए कोई कड़ाई करिए, लेकिन यहां के प्रदूषण को बचाइए साहब मैं तो याद करता हूं दिलीप सिंह जूदेव साहब को जिन्होंने जशपुर जिले को उद्योग से दूर रखा। अगर वो रखते तो वो सुंदरता भी खत्म हो जाती। नक्सलियों के कारण बस्तर बचा हुआ है क्योंकि वहां पर उद्योग उनके आतंक के कारण नहीं लग पा रहा है। लेकिन जहां-जहां जगह मिल रही है, धकाधक उद्योग लगाए जा रहे हैं और ये उद्योग प्रदूषण और पर्यावरण के नियमों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं कि कैसा करना है, लेकिन आपका यह प्रयास

सराहनीय है। आपने यात्रा का भी ध्यान रखा, आपने कॉलेज, स्कूल को भी खोला। आपने बच्चों का भी ख्याल रखा, आंगनबाड़ी का भी ख्याल रखा, नियद-निल्ला-नार गांव को भी सुंदर बनाने का आपने काम किया, आपने महतारी वंदन योजना का भी काम किया, आपने बहुत से अच्छे काम किये और ये तो बजट बहुत छोटा सा बजट होता है। हम लोग अपने राजनीति जीवन में हर बार सप्लीमेंट्री बजट देखते हैं। यह सप्लीमेंट्री बजट सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है । मुख्य बजट तो वह होता है जो मार्च में आता है । उस मार्च के बजट में हमारा और सभी लोगों का आप पूरा ख्याल रखिएगा और अब इस बजट में ही हमारी पूरी आशा है । किसी भी विधान सभा के कार्यकाल में शुरू के 2 या 3 बजट ही महत्वपूर्ण होते हैं । आपके आखिरी के 2 बजट का कोई महत्व नहीं है । यदि कोई आखिरी के दो बजट में प्रावधान करने की बात करेगा तो हम उसे प्रावधान नहीं मानते हैं । इसलिए हमारे पास दो बजट और है आप हमारी भावना, हमारे काम और हमारे कमिटमेंट का ख्याल रखिएगा । विष्णुदेव साय साहब, आपका सांय-सांय वाला काम बिल्कुल चलने दीजिए। आप जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन से आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे बना है इसको कैसे बदनाम किया जाए और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं । लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, आप मजबूती से डटे रहिएगा। इस प्रदेश की जनता आप पर पूरा विश्वास कर रही है । विधान सभा में बहुमत तो आपका है ही, कोई बाल बांका नहीं कर सकता । लेकिन इस प्रदेश की जनता आपके भाषण को सुनना चाहती है । जब आप सांय सांय बोलते हैं तो जनता को बहुत अच्छा लगता है (मेजो की थपथपाहट) इसलिए आप परवाह मत करिए और आप तो सीधे आदमी हैं, आप सच्चे और सरल आदमी हैं । आपने आदिवासी परिवार के दर्द और तकलीफ को देखा है । इसलिए आप इन तकलीफों को ज्यादा अच्छे से दूर कर सकेंगे । आप लगे रहिए, आगे बढ़िए । प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी है और आप सांय सांय करके आगे चलते रहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद् (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री लखेश्वर बघेल :- धर्म भइया । षड्यंत्र सत्ता पक्ष के वरिष्ठ लोग ही कर रहे हैं, यह भी मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्री दिलीप लहरिया :- आदरणीय, जब हम लोग सांय सांय बोलते हैं तो तकलीफ होती है और आप स्वयं सांय सांय बोल रहे हैं । यानी आप लोग अच्छा बोल रहे हो ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती अनिला भेंडिया जी ।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं । माननीय धर्मजीत भइया बोल रहे थे, आदिवासी मुख्यमंत्री आप लोगों के हैं । वे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हैं इसलिए मैं सबसे पहले आदिवासी क्षेत्रों के बारे में कहना चाहूंगी क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं । आपने आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राओं की

बात करें या उन क्षेत्रों की स्कूलों के बारे में बात करें तो आप इन क्षेत्रों के लिए बजट देखिए । उन क्षेत्रों के लिए बजट निल है । मैं यह कहना चाहूंगी बस्तर क्षेत्र में शिक्षा विभाग के छात्रावास को देखिए और ट्रायबल के छात्रावासों को देखिए, वहां बच्चों के रहने के लिए न तो कमरे हैं, न वहां सुरक्षा की व्यवस्था है और बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था भी नहीं है । यदि कहीं प्रकरण हो रहा है, यदि आदिवासी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, जहां आदिवासी अधिकारी रहते हैं तो आदिवासी अधिकारियों पर मामला बन रहा है । यदि हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं तो क्यों आदिवासी क्षेत्र में चाहे अधिकारी हों या हमारे छात्रावासों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं हों, उनके लिए बजट तैयार क्यों नहीं करते ? रही सुरक्षा की बात तो पुलिस विभाग के पास इतना बड़ा फोर्स है । हमारे प्रदेश में जो हुआ है वह देख ही रहे हैं । परंतु आज आप देखिए हमारे स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से होम गार्ड, आपके शासन में ही था कि हर छात्रावास में हम होमगार्ड की व्यवस्था करेंगे । हर छात्रावास में सुरक्षा की दृष्टि से आहाता देंगे, वहां अच्छा गेट होगा । किंतु यह तो बताइए कि यह सब कहां है ? आज सामने ही पुलिस चौकी है लेकिन एक गार्ड भी वहां नहीं लगा पा रहे हैं । उन छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक पुलिस बल नहीं दे पा रहे हैं । आप इतनी व्यवस्था इधर-उधर करते हैं । एक विधायक को आप तीन-तीन स्टाफ दे रहे हो, आप एक स्टाफ हटा दीजिए । उस स्टाफ को आप छात्रावास में दे दीजिए, क्यों नहीं देते हैं ? इस चीज को आप देखिए। आप आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं । मैं उसी क्षेत्र में स्कूलों की बात कर रही हूं । मैंने प्राथमिक शाला के बारे में प्रश्न लगाया था, सभी स्कूलों में भवन है, ऐसा उत्तर दिया है। आज आप गांवों में जाकर देखिए, कहीं पर सामुदायिक भवन में स्कूल लग रहा है, कहीं पर सहकारी समिति के भवन में स्कूल लग रहा है। उसके बाद आपकी सरकार में बैठे लोग, आपके शासन में बैठे लोग आपको इस तरह से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे बच्चों के लिए स्कूल, अहाता, शौचालय की पूरी व्यवस्था है। यहां तक कि कन्या शालाओं में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारी बच्चियां रात में बाहर में शौचालय जाती हैं। शौचालय में दरवाजा नहीं है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप लोग मोदी जी के सुशासन में बेटी बचाव, बेटी पढ़ाव बोलते हैं। हमारी बेटी कहां सुरक्षित है। आप इसके लिए कुछ व्यवस्था करिए। वैसे ही आप आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 500 आंगनबाड़ी स्वीकृत करने के लिए केबिनेट में पास किया था, प्रक्रिया भी चालू थी। अभी कम से कम उस प्रक्रिया को बढ़ाते हुए काम करिए। हमारी आंगनबाड़ी के लिए आपके बजट में कुछ नहीं है। जो केन्द्र प्रवर्तित योजना है, उसमें कम से कम हमारी राज्य सरकार के द्वारा भवनों के लिए बजट होना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से हमारे जो अनुपूरक पोषण आहार है, उसमें भी बढ़ोत्तरी करना चाहिए। क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। हमारी गर्भवती महिलाओं की संख्या बढ़ रही हैं, शिशवती महिलाओं की संख्या बढ़ रही हैं, परंतु आपने उसमें पूरी कटौती

कर दी है। हमारी महिला बहनों को कोई पूरक पोषण आहार मिल ही नहीं रहा है। आज आप लोग महिलाओं की बात कह रहे हैं। महतारी वंदन योजना से क्या सब कुछ हो जाएगा ? क्या उस घर में उन महिलाओं की जरूरतें 1 हजार रूपए में पूरी हो जाएगी ? आप लोग उस बजट में जीरो हैं। इस बजट में आपने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, आप लोग स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, आज आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जाईए, वहां पर न आपका स्टाफ है, न कोई कर्मचारी है, वहां गांव से कोई ईलाज कराने के लिए जाएगा तो प्राथमिक उपचार करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। यह हमारे अस्पतालों की स्थिति है। अभी बरसात के कारण मलेरिया, डायरिया, बहुत सी बीमारियां फैल रही है। पहले गांवों में क्या होता था, मच्छर मारने की व्यवस्थाएं, उनमें दवाईयों का छिड़काव, कुंआ, बोरिंग में सबमें बोरिंग पाउडरों की व्यवस्था होती थी। आज स्वास्थ्य विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए आज पूरे राज्य में बीमारियां फैल रही हैं। आप जब यह सब काम जनता के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें बजट देने की क्या आवश्यकता है ? यह बजट औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बहुत सी गांवों की जो सड़कें हैं, पुल हैं, उनका आवागमन बरसात के कारण टूटा हुआ है, ऐसी जगहों को भी आप लोगों को चिन्हांकित करके बजट में रखना चाहिए। आप लोगों ने दो चार जगहों को चिन्हांकित करके ऐसी व्यवस्था की है। मैं मानती हूं कि यह बहुत छोटा बजट है। परंतु मेन बजट में पूरे प्रदेश का जो बजट कार्य हुआ है, उस कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता है। क्योंकि उसमें सबका बहुत जरूरी काम है। चाहे वह पुल, पुलिया हो, चाहे सड़क हो, चाहे पहुंच मार्ग हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जो बजट में आ गया उसको लैप्स नहीं होने देना चाहिए। आप पूरे बजट को प्रशासकीय स्वीकृति के माध्यम से पूरा करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन कर रही हूं कि इस पूरे कार्य को आप सरकार से कराने की कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रेणुका सिंह जी । नहीं बोलना है, भावना बोहरा जी ।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया है । मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को और साथ में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि अनुपूरक बजट में बहुत सारे विषयों का समावेश किया गया है और निश्चित ही चाहे मेन बजट की बात करूं या अनुपूरक बजट की बात करूं, मुझे लगता है कि काफी सारे विषय हैं, जो कि लगता था कि संभव नहीं हो पायेंगे, इस बजट में असंभव को भी संभव करके दिखाया गया है । मेन बजट में कुछ अंश जो छूटे हुये थे, उसको इसमें समाहित किया गया है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अभिनंदन

करना चाहूंगी कि समस्त महिलाओं की ओर से, छत्तीसगढ़ के 70 लाख महिलाओं की ओर से, जो सरकार बनने के तुरंत बाद बिना किसी उसकी मांग के आदरणीय विष्णु देव साय जी ने एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने का परिचय देकर कैबिनेट में महतारी वंदन योजना को तुरन्त सेंक्शन किया और लगातार पिछले तीन से चार महीने से महतारी वंदन का किश्त बिल्कुल समय पर माताओं के खाते में मिल रहा है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो इस विषय पर चर्चा होती है, महिलायें जब आपस में बैठती हैं, किसी मोहल्ले में जाती है, यहां सबसे पहले विषय यही आता है कि पहली बार ऐसी सरकार है जो बिना मांगे घोषणा पत्र में जो चीजें थी, उसको पूरी की गई है । अध्यक्ष महोदय, अभी लगातार हमारी बहनों के माध्यम से विषय आ रहा था कि आप लोग 500 रूपये काट कर दे रहे हैं, मैं हमारी बहनों को पूछना चाहूंगी कि बहनें इतनी संवेदनशीलता दिखाती है, कई बहनें पिछले कार्यकाल में भी थी, जब यहां कांग्रेस की सरकार थी । अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ उस समय क्या आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनसे इस विषय पर चर्चा की है कि हम बहनों को क्या मुंह दिखायेंगे कि हम जाकर क्षेत्र में बता नहीं पा रहे हैं कि हमने 500 रूपये देने की घोषणा की थी और हम उनको 500 रूपया नहीं दे पा रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, उनको खुशी होनी चाहिये कि विष्णुदेव साय जी की सरकार 1000 रूपये महिलाओं के खाते में डाल रही है, बजट में साफ-साफ दिखाई दे रहा है, लगभग 5 हजार करोड़ का बजट है यानी पूरी बजट का 70 भाग महिलाओं को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि महिला विधायक भले ही विपक्षी हों, आपको इसका स्वागत करना चाहिये, इसका समर्थन करना चाहिये । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय है कि हमारे विपक्षी भाईयों को अचानक महिला स्व-सहायता समूहों की चिन्ता होने लगी है, वह शायद भूल गये हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 6 से 7 महीने हो गये हैं, यहां पर बैठने की मेरी सीट नहीं थी, यह नंबर मेरा नहीं था, लेकिन लगातार टी.वी. में बैठकर बजट सत्र हम सुनते थे, कहीं न कहीं यह उम्मीद रहती थी, उस समय के मुख्यमंत्री थे, वह अपने आपको किसान पुत्र बताते थे, हमारी जो बहनें है छत्तीसगढ़ का बेटा बताती हैं.. ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह तो किसान पुत्र हैं ही । हमारे मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं ।

श्रीमती भावना बोहरा :- किसान पुत्र सभी हैं, किसान इस सदन के अंदर हैं । मैं उससे मना कहां कर रही हूँ ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसमें प्रश्न क्यों है ?

श्रीमती भावना बोहरा :- मैं तो मान रही हूँ कि भारत माता और छत्तीसगढ़ के बेटे हैं, और न ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, बल्कि यहां पर बैठै हुये सारे लोग भारत माता और छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियां हैं, इसलिये छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी की चिन्ता करके आज 5 हजार करोड़ का बजट...।

श्री रामकुमार यादव :- अतके फरक हे, कोई नकली हे, कोई असली हे । सही किसान ए हरै । सही अऊ नकली में अंतर करव ।

श्रीमती भावना बोहरा :- थोरिकन बैठ जा भाई, बहुत बेर ले सुने हन । बैठ जा। सही किसान काय होथे, तेला बता ? काला सही किसान कइथे, तहीं बता दे ? तब मैं अपन बोलना स्टार्ट करहूँ । सही किसान काला कइथे ?

श्री रामकुमार यादव :- मैं बताथंव सुन ले । अब कहै त सुन बहनी मोर । छत्तीसगढ़ में पहला मुख्यमंत्री जी हरै भूपेश बघेल जी, जेन किसान के धान ला वोतका दिस । तुमन डर में केहे हव । मैं तोला पूछंथव, तुमन 1000 महिला मन ला देबो बोले रेहे हव, 500 काबर देवथव ? 500 रूपया काबर काटके देवथव ?

श्रीमती भावना बोहरा :- त महुं तोर से पूछथंव, एक चीज बता, धान के पैसा जब चार किश्त म देवत रेहेव, त घोषणा पत्र में काबर नई लिखेव ?

श्रीमती गोमती साय :- रामकुमार भाई, एक महिला बोल रही है, थोड़ा शांति से बैठकर सुनना चाहिये ।

श्रीमती भावना बोहरा :- बोलने दीजिए । इनको महिलाओं को सुनने का आदत नहीं है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, किसान इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा परेशान था । धान के बोरा के लिये तरसना पड़ा था ।

अध्यक्ष महोदय :- सभी माननीय विधायकगणों से आग्रह है कि सदन के अंदर सीधी बातचीत नहीं होती । आपको जो भी बोलना है, आसंदी के माध्यम से बोलें । इस प्रकार के डायलाग अच्छा नहीं होता । यह परम्परा भी नहीं है, कृपा करके ध्यान रखें कि जो भी कुछ कहना है, आसंदी के माध्यम से बोलिये, सीधे बातचीत करना उचित नहीं है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगी कि भाजपा की सरकार को 7 महीने हुये हैं, सरकार ने अपना मेन बजट और अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है, पिछले 6 से 7 महीनों में इस बात का बहुत गर्व है कि भाजपा की आदरणीय विष्णु देव साय जी की सरकार में एक भी भ्रष्ट्राचार या वादाखिलाफी का आरोप नहीं लगा है । जब कांग्रेस की 5 साल सरकार थी, तब कितने भ्रष्ट्राचार के आरोप लगे हैं ? गौठान घोटाले से स्टार्ट करें, चाहें हम शराब घोटाले की बात करें, गोबर घोटाले की बात करें, रेडी टू ईट की बात करें, मैं बताना चाहूंगी कि पिछले सात महीनों में आदरणीय विष्णु देव साय जी की सरकार ने सिर्फ अपने घोषणा पत्र में घोषणा-पत्र में फोकस किया है, उन विषयों पर लगातार फोकस किया है चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात घोषणा-पत्र में रही हो, चाहे महतारी वंदन का विषय रहा हो, बहुत सारे विषय जो घोषणा-पत्र में थे, वह पूरे करते आ रहे हैं ।

समय :
6:00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि पहले के वक्ताओं को इसी बात की तकलीफ थी कि जनता आज भी इनके सपोर्ट में कैसे है ? हमारी एक बहन अपना वक्तव्य दे रही थीं कि अगर आज चुनाव होगा तो पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है । मैं अपनी बहन को याद दिलाना चाहूंगी कि थोड़े समय पहले ही चुनाव हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता ने ही लोकसभा चुनाव में मतदान किया है और जनता ने ही बता दिया है कि न सिर्फ विधान सभा चुनाव में, बल्कि 6 महीने निकलने के बाद भी जनता को भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा है इसलिए 11 लोकसभा सीट में से आज भी हम 10 सीट जीतकर आये हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विषय हैं, चाहे मैं रामलला के दर्शन की बात करूं, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की बात करूं, जिसकी शुरूआत फिर से की गई है और जिसके कारण क्षेत्र में लगातार उत्साह बनता है । अभी भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं या बहुत सारे वरिष्ठ हैं, जो रामलला के दर्शन के लिए बहुत उत्साहित हैं और हर महीने 20 से 40 लोगों की टोली हर जगह प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रही है । जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना थी, उसके लिए भी 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि छत्तीसगढ़ में जब आप मुख्यमंत्री थे, उस समय जिसकी शुरूआत आपके माध्यम से की गई थी, आज उसे सुचारू रूप से यहां जारी रखा गया है तो कहीं न कहीं हम एक श्रवण बेटे की बात करते हैं, आज भी उस विषय को भाजपा की सरकार ने अपने बजट में शामिल किया है ।

समय :
6.02 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जिस पर चर्चा करनी थी, लेकिन कुछ विषय मुझे अपने क्षेत्र के रखने हैं, आपने 4 से 5 मिनट का समय दिया है तो मेरे क्षेत्र के जो मुख्य विषय हैं, उस ओर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि मेरा क्षेत्र वनांचल क्षेत्र भी आता है, बहुत सारी आबादी, लगभग 60 प्रतिशत आबादी वनांचल बैगा आदिवासी भाई बहनों की है । मेरा एक निवेदन यह है कि भैंसादार नामक एक क्षेत्र है, जो कुकदूर क्षेत्र में आता है । बहुत दिनों से उसकी मांग है कि उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाये क्योंकि वहां पर न ही आय के साधन हैं और वह नेचुरल ब्यूटी है। मेरा निवेदन है, मैंने पहले भी आग्रह किया था कि वहां को पर्यटन स्थल के रूप में शामिल किया जाये ।

सभापति महोदय, दूसरा, जो शुगर फैक्ट्री है, यह विषय बार-बार आता है । वहां शुगर फैक्ट्री है क्योंकि धान के साथ-साथ वहां पर गन्ना का भी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और लगातार जो केपेसिटी है, उसके एक्सपांशन की बात आ रही है तो मेरा निवेदन है कि इसका बजट 80 करोड़ के आसपास नहीं है, उसका बजट शायद थोड़ा ऊपर जाएगा तो एक बार आप विषय पर जरूर जानकारी डालें । संभव हो सके तो जो गन्ना क्षेत्र है, वहां पर इसका एक्सपांशन जरूर किया जाये । तीसरा, एक बकेला बैराज की मांग बहुत जोर-शोर से आती है क्योंकि पण्डरिया लगभग ड्राई एरिया हो गया है, वहां के 30 से 40 प्रतिशत गांव जो ड्राई एरिया पर है, जहां पर पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है, वहां पर जो बकेला गांव है, वहां पर बैराज की मांग किए हुए भी लगभग 20 से 30 वर्ष हो गए हैं, जो बहुतायत मात्रा में जिसकी मांग है तो इन तीनों विषयों पर मुझे लगता है कि आप एक बार पुनर्विचार करके इसको जरूर आने वाले समय में बजट में शामिल करेंगे । मैं पुन: आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करूंगी कि लगभग सारे विषयों को इस अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है । निश्चित ही हम सब इस बजट का समर्थन करते हैं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूं ।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस अनुपूरक बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। आपके बजट अनुमान में वनों के सुधार के लिए प्रावधान किया गया है । सभापति जी, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहती हूं कि वनों के सुधार के लिए जरूरत कदम उठाएं जायें क्योंकि पूरा प्रदेश वनाच्छादित प्रदेश है और हमारे पूर्वजों ने वनों की सुरक्षा की है, लेकिन आज पूरा वन असुरक्षित है । मैं आपको बताना चाहती हूं कि सीतानदी अभ्यारण्य क्षेत्र में जहां पर वनों की कटाई में रोक लगी हुई है क्योंकि वह अभ्यारण्य क्षेत्र है । वहां पर उड़ीसा से तस्कर आकर वनों की कटाई कर रहे हैं, सागौन लकड़ी की ढुलाई कर रहे हैं। आप चाहे तो आपको फोटों भी दिखा दूंगी, उसका वीडियों क्लिपिंग भी दिखा दूंगी। इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, उड़ीसा में भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या आपकी मिलीभगत है जो वहां के तस्करों द्वारा छत्तीसगढ़ से सप्लाई हो रही है ? यह बड़ी चिंता का विषय है। यह ईमारती लकड़ी है, सागौन की लकड़ी है, जिसकी इतनी तस्करी हो रही है। वहां रातो-रात तस्कार आकर सागौन की लकड़ी को पार कर रहे हैं और यह प्रदेश के लिए बड़ा चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जनमन में कमारों की आवास की बात हो रही थी। माननीय सदस्य द्वारा कहा जा रहा था कि कमारों के लिए बहुत आवास बन रहे हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन मैं खुद अपने नगरी क्षेत्र में दौरे पर गई थी। वहां लगभग 10 कमारों का घर ऐसा है, जहां उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, ना उनको पट्टा मिल रहा है, ना उनको आवास मिल रहा है। क्या उनको आवास मिलेगा ? कितने दिनों में आवास मिलेगा ? यह प्रधानमंत्री जनमन योजना, केन्द्र

सरकार की योजना है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, केन्द्र में भी आपकी सरकार है। आप वनों की कटाई भी रोक सकते हैं, आप आवास भी बना सकते हैं। आपको हर क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी-अभी स्कूल का अहाता गिरने से एक कमार बच्ची का निधन भी हो गया था। स्कूलों के अहाते की स्थिति जर्जर है, स्कूलों की स्थिति जर्जर है। ऐसी स्थिति को कौन देखेगा ? माननीय सभापति महोदय, मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों की जर्जर स्थिति में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत बहुत सारे ऐसे स्कूलों के भवन बने थे। लेकिन बहुत से भवनों की राशि को सरकार बदलते ही वापस बुला लिया गया। क्या फिर से वापस स्कूल के लिए राशि स्वीकृत होगा ? वापस स्कूल बनेगा या नहीं ? उनके लिए अहाता बनेगा या नहीं ? उनके स्कूलों में शौचालय बनेंगे गया नहीं ? यह चिंता का विषय है। ऐसे जर्जर स्कूलों की स्थिति को सुधारने की जरूरत है। आज कई स्कूलों में बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। आज बरसात का समय है, ट्रायबल क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। वहां पर ना भवन है, ना स्कूल है, तो आखिर बच्चें कहां पर बैठेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, छात्रावास की व्यवस्था के बारे में हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा कहा जा रहा था। छात्रावासों की स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है। जैसे मेरा गट्टासिली गांव है, जहां कई वर्ष पूर्व से 20 बिस्तर छात्रावास है। तो मैं इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहती हूं कि वहां पर 50 बिस्तर छात्रावास खोला जाये। दूसरी बात, मेरा बोरइ क्षेत्र, अभ्यारण्य क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है और नगरी से करीब 40 किलोमीटर दूर है, जहां विद्युत की व्यवस्था बहुत ही खराब है। अभी-अभी कुछ दिन पहले जन समस्या निवारण शिविर आयोजित हुआ तो वहां की जनता ने उस शिविर का बहिष्कार किया था। वहां की जनता ने इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि वहां बोरइ में बिजली बस्तर क्षेत्र के विश्रामपुरी से आया हुआ है और बोरइ धमतरी जिले में आता है। तो वहां की स्थिति ऐसी है कि ना तो वह धमतरी क्षेत्र के अधिकारी को बोल पाते हैं और ना कांकेर क्षेत्र के अधिकारी को बोल पाते हैं। तो वहां की स्थिति कैसे ठीक होगी ? वहां पर लो-वोल्टेज की समस्या है। इस लो-वोल्टेज से ना तो किसानों का पंप चल पा रहा है ना वहां पर नहर-नाली बना हुआ है। वहां सिंचाई की अनुपलब्धता है। वहां पर उनको ना तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकता है और ना ही बिजली उपलब्ध हो सकता है। तो वहां के लोग कैसे जीवन जीयेंगे ? तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूं कि वहां अभी-अभी सब स्टेशन स्वीकृत हुआ है। जब जन समस्या निवारण शिविर में अधिकारियों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि सब स्टेशन बनने वाला है। जब सब स्टेशन बनने वाला है तो वह तत्काल तो नहीं बन जाता है, तब तक के लिए वहां पर कुछ व्यवस्था की जाए या कांकेर क्षेत्र से आप नया ट्रांसफॉर्मर लगवाएं। वहां पर बिजली की उपलब्धता अच्छे से हो, लो-वोल्टेज की समस्या दूर हो। ऐसी समस्याओं को दूर करने की बहुत नितांत

आवश्यकता है। वहां पर हॉस्पिटल है। बोरई क्षेत्र में 20 बिस्तर हॉस्पिटल खोला गया है, लेकिन वहां पर कोई स्टाफ नहीं है, न बिल्डिंग है और न स्टाफ के रहने की जगह है। सभापति महोदय, वहां पर कैसे हॉस्पिटल संचालित होगा? वहां पर एम्बुलेंस था, लेकिन वह एम्बुलेंस भी खराब हो गया है। रिसगांव क्षेत्र अभ्यारण्य क्षेत्र है। वहां पर भी एम्बुलेंस था, लेकिन वहां के एम्बुलेंस को वापस बुला लिया गया है। अभी डिलीवरी वालों और बीमार आदमियों को ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है। मैं पिछले 1 महीने से लगातार कह रही हूं कि वहां पर तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि नगरी से उसकी दूरी 40-45 किलोमीटर है। चाहे आप बोरई का देख लीजिए, चाहे रिसगांव क्षेत्र का देख लीजिए। सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर समस्या है, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र आदिवासियों, वन अभ्यारण्यों और नदी-नालों से घिरा हुआ है, लेकिन उस क्षेत्र में न तो पुल-पुलिया है, न बिजली की व्यवस्था है, न जाने की व्यवस्था है और न ही किसी साधन की व्यवस्था है। वहां पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है इसलिए माननीय मंत्री जी, आप विशेषकर उस क्षेत्र पर ध्यान दीजिए और बजट में उसके लिए प्रावधान कीजिए। मैं देख रही थी कि इस बजट अनुमान में कहीं पर भी धमतरी जिले के लिए प्रावधान नहीं रखा गया है इसलिए आने वाले बजट में इसके लिए जरूर प्रावधान कीजिये। मैंने मुख्य बजट में मेरे गांव गट्टासिल्ली में चौकी की भी मांग रखी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और उस क्षेत्र में तत्काल इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसी तरह से दुगली से मेघा मार्ग पिछले 3 सालों से बजट में आ चुका है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह रोड क्यों नहीं बन पा रही है ? उस रोड में पूरे गड्ढे भरे पड़े हैं और बार-बार पूछने पर यही कहा जाता है कि फॉरेस्ट की एन.ओ.सी. नहीं मिलने के कारण से वह रोड नहीं बन पा रही है। अभी मीटिंग होगी, तभी मीटिंग होगी तो आखिर कब उसकी मीटिंग होगी, कब उसको स्वीकृति मिलेगी और कब वह रोड बनेगी? यदि 3 साल तक नहीं बनती है तो बजट से उसको कैन्सिल कर दिया जाता है। क्या कुकरेल से बनबगौद और दुगली से मेघा मार्ग बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं। अभी मैं आपको बहुत ही आवश्यक चीजों को बता रही हूं। यह बहुत आवश्यक चीजें हैं क्योंकि हम लोगों को रोज वहां से गुजरना है। इसमें स्टेडियम के लिए भी प्रावधान रखा गया है। मेरे क्षेत्र में भी स्टेडियम की मांग आयी है तो मेरी मांग को पूरा किया जाए। मैं आपके बजट से मोहेरा और भण्डारवाड़ी में 2 जगह स्टेडियम की मांग कर रही हूं। माननीय मंत्री जी, मुझे यह दिया जाए।

सभापति महोदय :- कृपया आप समाप्त कीजिए। आपको 10 मिनट हो गये।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- धन्यवाद। अनुज शर्मा जी।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति जी, मुझे लगता है कि अभी 10-11 वक्ता शेष हैं तो रात्रि भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। क्या आप लोग तैयार हैं ? या तो फिर जल्दी कीजिए (हंसी)

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने यह जो बजट रखा है, उसके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि लोग हमसे जल रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में मुख्य बजट जिस तरह से प्रस्तुत किया था, उस बजट के प्रस्तुत करने के तरीके से समझ में आ गया था कि यह छत्तीसगढ़ नई उँचाइयों को हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ बनने वाला है। उस बजट के समर्थन में एक और अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं।

माननीय सभापति जी, एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए लोग जानते थे और जब हम छत्तीसगढ़ से बाहर दिल्ली, बंबई जाते थे, तो हमारे दोस्त, यार ऐसा समझते थे कि रायपुर एयरपोर्ट में उतरते ही गन लिए हुए हरे वर्दी में नक्सली लोग होंगे और उन्हें तुरंत गोली मार देंगे। पहले ऐसा परसेप्सन सेट कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय की सरकार बनने के बाद जिस तरह से कार्रवाईयां हुई हैं, वह दुनिया के लिए नजीर बनेगी और निश्चित तौर पर हम इस वामपंथ उग्रवाद से छुटकारा पाएंगे। इसको देखते हुएप्रभावित पांच जिलों दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में 'नियद नेल्लानार योजना' अर्थात् 'हमारा सुंदर गांव योजना' प्रारंभ की गई है और इसके लिए 53 सी.आर.पी.एफ. कैंपों के निर्माण के लिए 05 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए यह महत्वपूर्ण बजट साबित होगा। उस क्षेत्र के विकास के लिए और इन्हीं जगहों पर खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में 02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सुदूर अंचल में कहीं न कहीं एक वातावरण बनाना होगा और ऐसा वातावरण जो वहां के युवा को खेल-कूद की ओर, देश के विकास की ओर प्रेरित करे। दो नवीन छात्रावासों के लिए 86 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत में एक महत्वपूर्ण बात अभी हुई, जब 01 जुलाई, 2024 से तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू किया गया। यह समय के हिसाब से छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला बजट है। इसके सफलतापूर्वकक्रियान्वयन, प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधीमदों में अनुपूरक बजट के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला अनुपूरक बजट

होगा। इसमें कहीं न कहीं इस बात का संकेत मिलता है कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है, उसकी दूरदर्शिता दिखाई दे रही है।

माननीय सभापति जी, समयाभाव है। हमारे अजय चन्द्राकर जी एक बात कह रहे थे कि पिछली सरकार में जितने घोटाले हुए हैं, जो लोग जांच के दायरे में आयेंगे, जिनको सजा होगी, उनके लिए जेल में बैरकों की भी तो जरुरत होगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने उनका भी ख्याल रखा है कि उनको भी कोई दिक्कत न हो और उसके लिए उन्होंने 31 करोड़ 65 लाख रुपए का इंतजाम किया है कि 100 क्षमता वाले 22 और 50 की क्षमता वाले नये बंदी बैरकों का निर्माण हो, ताकि जो नए मेहमान जाएंगे, उनकी सेवा में किसी तरह से कोई कमी न हो। मैं उसके लिए भी उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सभापति जी, कहने के लिए बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सात महीनों में दुनिया में अगर किसी सरकार ने सबसे तेजी से अपने वायदों को निभाया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई सरकार, विष्णु देव की सरकार है, जिसने अपने एक-एक वायदे को पूरा करना शुरु किया है। अपने इस समर्थन के वक्तव्य को समाप्त करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि-

सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरुरी तो नहीं
जिन्दगी राहे सफर है यूँ ही चलते रहना
तुम चिरागों की तरह राह में जलते रहना
हर अंधेरे को उजाले में बदलते रहना। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- धन्यवाद। कृपया सभी सदस्यों से निवेदन है कि 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। अभी 10 से ज्यादा सदस्य हैं। श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के विरोध में बोलने के लिये खड़ी हुई है। मेरा विरोध इसलिए है कि सरकार ने बड़ी-बड़ी बातें की हैं। मेरे पास अनुपूरक बजट में पैसों के प्रावधान की पूरी लिस्ट है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात बोलना चाहती हूं कि जो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री है, उनका संरक्षण है, आदिवासी समाज का संरक्षण है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहती हूं कि जो अनुपूरक बजट में बड़ी-बड़ी बातें आयी हैं, उसको थोड़ा संक्षिप्त करके, जो मूलभूत सुविधा है, उसकी बात करें तो ज्यादा उचित होगा। मैं अभी कुछ दिन पहले पखांजूर क्षेत्र के छोटे बेठिया गांव में गयी थी। वहां एक घटना हुई थी, जहां एक बच्ची गर्भवती थी, उसमें एक जांच समिति का गठन हुआ था, मैं उसमें सदस्य थी। जब हमने वह छात्रावास देखा, उस छात्रावास में 80 बच्चियां हैं और 80 बच्चियों के लिये सिर्फ 2 कमरे हैं। जब हमने उस कमरे में जाकर देखा तो उस कमरे में जो बिस्तर बिछा हुआ था, उसमें बिल्कुल गेप नहीं था। यहां से लेकर वहां तक बिस्तर बिछा हुआ था। उसमें बच्चियां ऐसे घुसी हुई थीं, जैसे गायों को एक साथ भर दिया जाता है, वैसे

ही बच्चियों को घुसा दिया गया था। उस छात्रावास में कम से कम यह सुविधा होनी चाहिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने बच्चों की सुविधा के लिए उनको वहां भेजते हैं कि सरकारी छात्रावास में हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद हम तुरंत वॉशरूम की तरफ गये। वहां पर बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है। वहां पर खुली जगह में बच्चियां स्नान करती हैं। मुझे यहां यह बात कहते हुए बहुत दु:ख हो रहा है। वह हमारी बेटियां हैं और वहां यह घटना हुई है। वहां न कोई बाऊण्ड्रीवॉल है, न कोई सुरक्षा है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारी बड़ी बहन को बड़ी देर में याद आया। यह 5 साल तक सत्ता पक्ष में थे और यह समस्याएं उनके द्वारा स्थापित की गयी थी परंतु ध्यानाकर्षण करने में देर हो गयी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं मानती हूं। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते।

श्री सुशांत शुक्ला :- हम जिम्मेदारी से निभ रहे हैं, इसलिए सरकार में बैठकर लोगों को राहत दे रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं इसीलिए आपके संज्ञान में ला रही हूं। आपने इस अनुपूरक बजट में बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लाया है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा होती है, उसमें बात करिये। आप हर समय पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर झोंक कर अपनी जिम्मेदारी से क्यों मुकर जाते हैं ? हम जो बता रहे हैं, आप उसमें भी काम करिये। वहां की बच्चियों की स्थिति खराब है, हम उस बात को आपके संज्ञान में ला रहे हैं। आपको जिस चीज में पैसा देना चाहिए, आप उसमें पैसा दीजिए। बच्चियों के लिये हॉस्टल बनाईये, उन्हें मूलभूत सुविधा दीजिए। आज हमारी अनिला दीदी ने एक बात रखी कि वहां बच्चियों के साथ सोने के लिये कोई वार्डन नहीं है। वहां पर एक वॉचमेन नहीं है, जबकि यह नियम के विरूद्ध है। वह बालिका छात्रावास है, वहां एक वॉचमेन होना चाहिए। आप यह सुविधा उपलब्ध कराईये, इसमें खर्च कीजिये। आप सिर्फ नारा लगाते हैं कि "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"। आप उसमें कायम रहिये। आप बेटियों के लिये काम कीजिए। सभापति महोदय, यह मेरा निवेदन है कि कम से कम आदिवासी छात्रावस में सभी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाये।

सभापति महोदय, बहुत दिनों से महतारी वंदन योजना की बात चल रही है। हमारे सभी साथियों ने उसमें अपनी बातें रखी। मैं उसमें भी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि इसमें 4,900 करोड़ रूपये आया है। जबकि आपने 70 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ देने का वादा किया है। वह घोषणा पत्र में है। उसके बाद आपने इस अनुपूरक बजट में 6,050 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। मेरा प्रश्न केवल यही है कि इसमें जो 50 करोड़ रूपये की कमी है, वह आप कहां से पूरा करेंगे ? उसमें भी आपने ध्यान नहीं दिया। जबकि यह महत्वपूर्ण योजना है। आप इसी योजना के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कारण सरकार में आये हैं। इसलिए मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित भी कर रही हूँ। जो पेंशनधारी महिलाएं, माताएं हैं उनको 500 रूपये काट कर दिया जा रहा है, लेकिन आपने कभी यह नहीं कहा । आपने अपने घोषणा पत्र में हर महिला को 1000 रूपये देने की बात की है। आपने उनका 500 रूपये काटा। उसके बाद जब हमारी यह बच्चियां जो शादी होकर जा रही हैं, वह आज इस योजना से वंचित हैं। आप उनके लिए भी पोर्टल खोलिए। अगर आप उनके लिए पोर्टल नहीं खोल रहे हैं तो यह भी धोखा देने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं स्कूल शिक्षा में आऊंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो स्कूलों का उन्नयन हुआ है। आज तक जब से यह सरकार बैठी है। मैंने कई बार कलेक्टर साहब, डी.ओ. साहब से सेटअप बैठाने की बात की। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मेवारीकला और तरौद में आवश्यकता है। आज तक वहां पर कोई शिक्षक नहीं है। इसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। प्रदेश में केवल स्कूलों के भवन बनाने से नहीं होता है। आप शिक्षा के स्तर को सुधारिये। जब आप बच्चों को शिक्षा, संस्कार देंगे तब आपका काम होगा। माननीय सभापति महोदय, स्कूलों से शिक्षकों का ट्रांसफर होता है यहां से आप लोग शिक्षक भेज देते हैं, लेकिन उनको वापस नहीं लाते हैं। वहां पर एक शिक्षक पहली से लेकर कक्षा पांचवी तक को पढ़ाता है । आप उस पर ध्यान दीजिए कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही हाल है। आज ही की बात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 प्रसव के प्रकरण आयें, हमारे जिला अस्पताल में उनको ले जाया जा रहा है, वहां के डॉक्टर लोग छुट्टी पर जा रहे हैं। यह आज ही की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में दो लोगों की सांप काटने से मौत हुई है। अगर वहां किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके लिए दवाई नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए। वहां पर जो धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स हैं, जिसमें कम रेट पर दवाई दी जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज यह धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स बंद होने के कगार पर है। जो हमारी हाट बाजार क्लिनिक योजना चल रही थी, उसमें सभी वर्ग के लोग लाभ प्राप्त कर रहे थे उस योजना को चलाईये। उसमें बहुत गरीबों का भला हो रहा था। उसको भी संज्ञान में लेकर, आप उस योजना को चलाईये। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बोरी नाला गांव है। मैंने आज सुबह भी प्रश्नकाल में इस बात को कहा है। मुझे यह इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बोरी नाला गांव है, वह टापू बन चुका है। आज उसकी सभी गांवों से कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में बरसात हुई है। दो दिन पहले खूब बारिश हुई है जो मैंने, उसे खुद पैसा लगाकर ठीक करवाया था, जो पूरा बह चुका है। उसको तुरंत अधिकारी वर्ग संज्ञान में लें और उसका टेण्डर लगाकर, तुरंत उसका कार्य जारी करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जेल के बारे में भी कहना चाहूंगी। जब मैं थोड़ा जेल का दौरा करने गई तब मैंने देखा कि वहां पर जितनी जनसंख्या है, मतलब वहां पर केवल 200 लोग रह सकते हैं, उसकी जगह 500 लोगों को घुसा के रखा गया है। इस ओर भी ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं इस प्रथम अनुपूरक अनुमान में देखूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र और मेरे जिले के लिए कुछ भी नहीं है जिसकी मैं तारीफ कर सकूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर बालोद जिला पूरा जीरो हो गया है। न आपने वहां सड़कों के लिए कुछ दिया है, वहां पर कई जगहों पर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। वहां कुछ-कुछ जगहों पर काम बच गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों के भवन नहीं है। वहां पर एक स्कूल की क्लास में दो-दो कक्षाओं की पढ़ाई होती है। इस प्रथम अनुपूरक अनुमान में वहां के लिए भवन भी नहीं दिया गया है। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। मेरा समय हो गया है, मैं यह समझ रही हूँ। मैं इस माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार के प्रथम अनुपूरक अनुमान की घोर निन्दा करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री सुशान्त शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष के अनुपूरक अनुमान में जब माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा तब विपक्ष के साथियों का केवल विरोध करने का कारण समझ में नहीं आता। क्या यह छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को महतारी वंदन योजना के नाम से सशक्तिकरण दिये जाने का विरोध है? क्या यह छत्तीसगढ़ में भांचा राम के दर्शन की व्यवस्था करना, इन राम विरोधियों के चेहरे को उजागर करने का विरोध है। आज मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ, पर जब मैं इनसे पूछता हूँ। दिलीप जी मैं उसको बोलूंगा, पर आपको सुनना होगा।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आप हमें राम विरोधी मत बोलिए। आप इस शब्द को विलोपित करिये। आपकी और हमारी उम्र बराबर है। हम 35 सालों से ...।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय दिलीप जी, अभी आप तो 22 साल के लग रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले मतदान किया है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, हम 35 सालों से रामायण गा रहे हैं। आप बताईये कि आप भगवान राम के बारे में क्या जानते हैं?

श्री सुशान्त शुक्ला :- मैं पूछ रहा हूँ। आप जवाब दीजिए।

श्री दिलीप लहरिया :- आपने कभी रामायण गाया है?

श्री सुशांत शुक्ला :- आपका भी अवसर आयेगा तो आप जवाब दीजियेगा।

सभापति महोदय :- कृपया आपस में बात न करें, समय आने पर अपनी बात रखियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- राम-राम जपना, पराया माल अपना, एला जानथे।

श्री सुशांत शुक्ला :- यादव जी, इतना जहर दूध पीकर नहीं घोलते हैं। प्रदेश की माताओं, बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण दिया जाना, उनके परिवार को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या हमारी प्रतिबद्धता का विरोध है ? अनुपूरक बजट में महतारी वंदना योजना के माध्यम से हमने 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1 हजार, साल के 12 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान किया है। क्या इस अनुपूरक बजट का विरोध करना, इसको मातृशक्ति का विरोध न माना जाये ? आज यह हमारे विपक्ष के साथी स्पष्ट करेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- शुक्ला जी, 1000 रुपये मत बोलिये, 500 रुपये बोलियेगा। ..(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप 500 रुपये बोलिये, आप 1 हजार रुपये नहीं बोल सकते। आप 1 हजार रुपये तब बोलेंगे, जब आप उन माताओं को पूरा 1 हजार रुपये देंगे, तब आप 1 हजार रुपये बोल सकते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- इसी हरकतों के कारण आप लोग विपक्ष में आ चुके हैं। प्रदेश की महतारी शक्ति का विरोध किया जाना, इनको विपक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है। आज इस बात द्योतक है और यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। परंतु मेरे साथी नहीं समझेंगे।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- भैया, उन महतारी मन तो आप लोगों के लाये हैं तो उनको 1 हजार रुपये दो न।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, 500 रुपये का वादा किये थे, मेरी बहन संगीता जी को याद नहीं है। माननीय टी.एस.सिंहदेव जी के नेतृत्व में जन घोषणा पत्र बना था। गंगा जल की सौगंध खाकर, आज गंगा जी ने इनको तिरष्कारित कर दिया है और जनता ने जनादेश वापिस लेकर विपक्ष में बैठने की व्यवस्था दी है।

श्री लखेश्वर बघेल :- आप फिर असत्य बोल रहे हैं?

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं कहां असत्य बोल रहा हूं। आपके जन घोषणा पत्र के जो बिंदु थे, उसमें गंगा जल की सौगंध लेकर कहे गये थे। आपने घोषणा पत्र में जो गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी, उसमें पूरे बिन्दु लिखे हुए थे। आप गलत बात मत बताईये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारे यहां के किसी ने गंगा जल की कसम नहीं खाई है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गंगा जल वाली बात को साबित करके दिखाईये न।

सभापति महोदय :- कृपया आपस में बात न करें। (व्यवधान)

सुश्री लता उसेण्डी :- आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कोण्डागांव की आम सभा में गंगा जल लेकर कसम खाई थी। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गंगा जल वाली बात को साबित करके दिखायें। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप हर समय असत्य बोलते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। आप अपनी बात रखिये।

सुश्री लता उसेंडी :- महिलाओं के लिये असत्य बोलने की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती गोमती साय :- गंगा जल की शपथ ली थी। (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- असत्य बोल रहे हैं (व्यवधान)

सुश्री लता उसेंडी :- आप क्या बोला चाहते हैं ? कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र में आपके पूर्व अध्यक्ष जो इस सदन के विधायक रहे हैं, वह हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाये और उस समय आपके राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी साथ में खड़े थे। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया:- माननीय सभापति महोदय, गंगा जल की कसम नहीं खाई गई थी। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, गंगा जल की कसम नहीं खाई है। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप बात को प्रमाणित कीजिए न। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- लखेश्वर जी, आप चिंता न करें। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बात को प्रमाणित कीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बाद में बात रखियेगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- हम आरोप लगायेंगे तो प्रमाणित करके लगायेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- लता जी, आप बैठिये। मैं खडा हुआ हूं, आप बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- सावन के महीने में असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- यह असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप सदन में असत्य बोलना बंद करिये।

श्री दिलीप लहरिया :- आप समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बलौदाबाजार में जो घटना हुई है, सिर्फ आपकी गलती के कारण हुई है, उसे भी स्वीकार करें।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप विषय को सुन लीजिए। आप लोग बड़े तिलमिलाये हुए हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- विषय की बात नहीं है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिये। पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर अपनी बात रखियेगा। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, अभी इसके पहले भी जब ये बात हुई थी।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह जो आरोप लगा रहे हैं, इसको विलोपित करियेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- क्यों विलोपित करें, मैंने किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आरोप को प्रमाणित करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप इस वाक्य को विलोपित कीजिए।

सभापति महोदय :- मैं कार्यवाही को देख करके, उसमें जो भी होगा, देख लेंगे। आप लोग बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप इस बात को स्वीकार कीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम असत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह असत्य बोल क्या दिखा रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- अगर वह सही बोल रहे हैं तो उस बात को प्रमाणित करें। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैंने कहा कि उनकी बातों को कार्यवाही देख करके, देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह बात दोबारा नहीं आनी चाहिए। जब देखिये, गंगाजल, गंगाजल की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री संशात शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब मेरे सीनियर सदस्य सुनकर तिलमिला रहे हैं तब इस अनुपूरक बजट का विरोध किया जाना स्वाभाविक रूप से सवाल खड़ा होता है।

श्री लखेश्वर बघेल :- (व्यवधान) किसने बोला है, वह आप साबित करिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने आपत्ति दर्ज की है क्योंकि वह आरोप लगा रहे हैं और आरोप बिना लिखित बयान के नहीं लगा सकते हैं इसलिए इन्होंने आपसे व्यवस्था की मांग की है कि इसको विलोपित करें।

सभापति महोदय :- मैंने कहा कि कार्यवाही देखकर उसमें निर्णय लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह गंगाजल की बात बोले हैं तो इन लोगों को बोल देना चाहिए कि छोकरा नाला का पानी कोण्डागांव लेकर गये थे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री लखेश्वर बघेल :- आप असत्य बोल रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप असत्य बोल सकते हैं, हमारे में असत्य बोलने का नहीं है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- असत्य बोलने का काम आपका है। आपने 15 साल तक बात किया था। असत्य बोलने का काम आपका है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, वह वरिष्ठ सदस्य होकर असत्य बोलने के लिए सिखा रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, यह गलत बात बोल रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं असत्य बोलने के लिए नहीं सिखा रहा हूं। वह गंगाजल कर बोल दिए तो आपको इतना बुरा लग गया इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप छोकरा नाला का पानी बोल दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। गंगाजल हम सबके लिए पवित्र हैं। हम गंगाजल की कसम खाते हैं। अभी माननीय धरमलाल कौशिक जी बोल रहे हैं कि वह गंगाजल नहीं था, वह छोकरा नाला का पानी था। गंगाजल और छोकरा नाला का पानी में बहुत अंतर है। गंगाजल को पूरे देश में बहुत ही सम्मान से देखा जाता हैं। आप गंगाजल और छोकरा नाला के पानी में तुलना मत करियेगा, गंगाजल का अपमान मत करिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। यदि गंगाजल के बोलने से आप लोगों को चिड़चिड़ाहट हो रही है तो मैं मैंने कहा कि छोकरा नाला का पानी बोल दीजिये, क्यों गंगाजल में इतना चिढ़ने की जरूरत है।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, यह गलत बात है।

सभापति महोदय :- कृपया आप बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- उन्होंने गंगाजल बोल दिया तो आपको चिढ़ने की क्या जरूरत है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम क्यों बर्दास्त करेंगे क्योंकि किसी सदस्य ने (व्यवधान) नहीं पाया है। वह साबित करें। (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- आप अपमान कर रहे हैं। किसके सामने बोले हैं, वह आप साबित करिये।

सभापति महोदय :- बघेल जी, बैठिये। मैंने जो कहा है कि जो अनुचित शब्द होगा, उसको देखेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- आप असत्य बोलने का काम कर रहे हैं। हम लोग कितने साल से सुनते रहेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, सच कितना कड़वा होता है, यह आज इस सदन में दिख रहा है।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात जल्दी पूरा करिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप क्या सच बोल रहे हैं, उसको आप प्रमाणित करिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप अपनी बता कहिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इस अनुपूरक बजट का विरोध करना यानी छत्तीसगढ़ के भांचा राम का विरोध करना है क्योंकि अयोध्या में भांचा श्री रामचन्द्र जी के भव्य टाट से ठाठ में आने

के अवसर पर जब छत्तीसगढ़ सरकार संकल्प लेती है कि हमारे मर्यादा भांचा राम का दर्शन का संकल्प पूर्ण करेंगे और इस अनुपूरक बजट का विरोध करना यानी राम विरोधी चेहरा स्पष्ट तौर पर साबित होता है। (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, अगर माननीय विष्णु देव साय जी और माननीय ओ.पी. चौधरी जी श्रवण कुमार की भूमिका में आते हैं और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लागू करते हैं तो छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना का ..।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, इनको राम वन गमन मालूम है या नहीं है? यह कभी अपने जीवन में रामायण गाये हैं या नहीं गाये हैं?

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- कब से बोल रहे हैं कि नहीं गाये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इसीलिए तो आपको यू.पी. की जनता ने ठुकराया है। वहां अपनी स्थिति देखिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और माननीय ओ.पी. चौधरी जी श्रवण कुमार की भूमिका में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लागू करते हैं। (व्यवधान) बुजुर्गों को तीर्थयात्रा ले जाकर उनका सम्मान करना चाहते हैं। अगर यह लोग इस अनुदान मांग का विरोध करते हैं तो आज यह छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह इससे साबित हो जाता है।

श्री दिलीप लहरिया :- हम दिखावा नहीं करते हैं। आप आईये, मैं आपको सीना चीर कर दिखाता हूं, आप भगवान देखेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- रायगढ़ में दृष्टि-श्रवणबाधित छात्रों के लिए नवीन छात्रावास की स्थापना होती है तो क्या यह विरोध नहीं कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान की शुरूआत होती है तो क्या यह इस अनुदान बजट का विरोध करके अपना विरोधी चेहरा नहीं दिखा रही है, यह मैं पूछना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आप बताईये न कि जन-मन योजना का विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जब बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरवा, अबूझमाड़िया परिवार चिन्हांकित करते हुए उनके लिए नवीन आवास निर्माण की अनुपूरक बजट में शामिल करते हैं और इसका ये विरोध करते हैं और इसका ये विरोध करते हैं तो इस सदन के अंदर इसको स्पष्ट करें कि क्या ये उन पिछड़ी जातियों का विरोध नहीं कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 साल की सरकार में न तो नवीन सड़कों का निर्माण किया गया है और न ही 15 वर्षों की सरकार में हमारे द्वारा निर्मित सड़कों का संधारण किया गया । अगर ये इस अनुदान बजट का विरोध करते हैं तो क्या छत्तीसगढ़ के विकास पथ का विरोध नहीं कर रहे हैं ?

आज इस सदन के अंदर इस बात को स्पष्ट करें । लेकिन इनका विरोधी चेहरा छत्तीसगढ़ की आस्था और सम्मान का विरोध स्पष्ट तौर पर इस अनुदान बजट के विरोध में खड़े होने से स्पष्ट होता है । मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि ये नियद नेल्लानार योजना का विरोध कर रहे हैं । 5 जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर इन 5 सालों में इन्होंने इन जिलों में कुछ नहीं किया । अगर हम करने जा रहे थे तो क्या इस अनुदान बजट का विरोध करके ये उस दलित और पिछड़े क्षेत्रों का विरोध नहीं कर रहे हैं ? लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है वह खेलों का है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी सदन में माननीय लता उसेंडी जी का एक प्रश्न आया था जिसमें ये 5 सालों तक खेल अलंकरण पुरस्कार आयोजित नहीं कर पाये और आज जब हम खेलों की सुविधाओं के विस्तारीकरण की बात करते हैं और अगर ये इस अनुदान बजट का विरोध करते हैं तो आज इस सदन के अंदर इस बात को स्पष्ट करें कि क्या ये छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का विरोध दर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ? लेकिन यह बोलेंगे नहीं क्योंकि 5 साल तो इन्होंने केवल भ्रष्टाचार की गाथा लिखी है । माननीय सभापति महोदय, विश्व के विश्व कीर्तिमान का भ्रष्टाचार स्थापित किया है, यह स्थापना की व्यवस्था है लेकिन मैं आपके माध्यम से इस अनुदान बजट में खेल और खिलाड़ियों के उन्नयन के लिये माननीय वित्तमंत्री जी से मांग करूंगा कि खेल संस्थान और मैदान शासन द्वारा जरूर बनाये जा रहे हैं लेकिन इसके संरक्षण और संवर्धन के लिये कोई स्थायी मद नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्तमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनके संरक्षण और संवर्धन के लिये स्थायी तौर पर बजट में एक मद की व्यवस्था हो जिससे खेल मैदान सुरक्षित रह सके ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्ति की ओर हूं । भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दिनांक 25 जून, 1975 काले दिन के रूप में माना जाता है और मुझे गर्व है कि देश के सबसे पहले लोकतंत्र सैनानी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी का मैं सदस्य हूं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो सबसे पहले बलिदान देकर स्थापित करने की व्यवस्था बनायी ऐसे पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी का मैं सदस्य हूं । इन्होंने आपातकाल लागू किया । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अंग्रेज मन करा माफी कौन मांगे रिहिस हे ? अंग्रेज मन करा घुटना कौन टेके रिहिस ? (व्यवधान) अंग्रेज मन के घोड़ा ला कौन धोवत रिहिस हे ? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस अधिसूचित किया गया है परंतु लोकतंत्र पर इनका विश्वास ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- सावरकर ।

सभापति महोदय :- बैठिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है । अभी तत्काल में बलौदाबाजार का कांड हुआ है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर उस बाबा गुरू घासीदास जी के शांति के प्रतीक समाज को परदे के पीछे रहकर आक्रोशित करने वाले लोन कौन थे ? (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उनको संसाधन देकर आक्रोशित करके आगजनी कराने वाले लोग कौन थे ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- कांग्रेस हा देश ला आजाद नइ कराये रहितिस ता आप विधायक नइ बन पाये रहितेओ । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस समाज वर्ग के थे ? परंतु इनके पास जवाब नहीं होगा ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र सैनानियों को जिनको हम मीसाबंदी कहते हैं, उनको अगर सम्मान राशि मिलती है तो क्या लोकतंत्र का इनका विरोधी चेहरा छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आता ? इनको आज इस सदन में इसे स्पष्ट करना होगा । माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस अनुदान बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और आपके माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों का छत्तीसगढ़ विरोधी चेहरा, राम विरोधी चेहरा, लोकतंत्र विरोधी चेहरा इस अनुदान बजट का विरोध करने से स्पष्ट हो चुका है और छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी । आने वाले समय में भी इनका जनादेश हमेशा वापस लेते रहेगी, यह स्पष्ट हो चुका है । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, हमर युवा हृदय सम्राट कलेक्टर रहकर के बहुत सारा कारनामा ये प्रदेश में करे हे, ओला जियत-जियत ले नइ भुलावन अइसे कलेक्टर आज मंत्री बने हे । ओहा अनुपूरक नाने हे अउ अनुपूरक हा मोर मन नइ अइस हे तेखर खातिर मैं हा ओकर विरोध मा खड़े हंओं । ऐखर खातिर कि हम विपक्ष मा हन ता केवल विरोध करना यानी अइसे नइ हे कि हम विरोध ही करबो । जो अच्छा काम करथे ता हमन ओला अच्छा भी कहिथन लेकिन आज जिस प्रकार से ये मन, चूंकि 5 साल से हमर सरकार चलत रिहिस हे । हमन ओ तरफ बइठन अउ ऐमन ओ तरफ बइठे । ऐमन के गोठ-बात ला देखन ता अइसे लागय । छत्तीसगढ़ी में कहावत हे बड़का-बड़का भाठा ला एमन के गोठ बात ला देखथन तो अइसे लागे एमन के जादू के छड़ी हे। जैसे ही छतीसगढ़ में सरकार बनबो, ये मस्त करबो, अइसे घुमाबो तो सब स्कूल म गुरूजी चल दिही, सबके खाता में एक-एक हजार रूपया चल दिही। ये मन ए कहे। का कहे अइसे अइसे सपना बताइस डबल इंजन के सरकार बनाइए, वहां भी दिल्ली में बनाइए, यहां भी बनाएंगे, ऐसे होगा वैसा होगा, एमन बन तो गिन, अब बने के

बाद आठ महीना होगे। आठ महीने का दशा ला देखिहौ त पूरा छत्तीसगढ़ जजंग-बजंग होगे हे। एमन तीन झन मंत्री मन ला जब देखन तो दिल्ली में ही बइठे हे। उहां खार खाके छत्तीसगढ़ के भवन के जो कर्मचारी मन हे ओमन कहात रहिन हे कि का करिहौ साहब इहां देखिहौ तो मंत्री मन सूतेच हे थे। ए मन कोन जाने का करे बर जाथे। इहां का समझाओ, उहां 3-3 मंत्री मन सूते हे। छत्तीसगढ़ म एमन हा जब ले सरकार में बइठे हे एमन ला काम कुछ करना नहीं हे, सिर्फ एमन हा छत्तीसगढ़ ला गुमराह करके रखथे, मैं कहना चाहथव कि शिक्षा के क्षेत्र में आज आप मन तो मंत्री, मिनिस्टर हव। अउ एती बइठे हे तेन बड़का-बड़का कलेक्टर कमिश्नर मन बन बैइठे हे। एमन के लोक-लइका हा बड़े-बड़े डी.पी.एस. स्कूल में पढ़थे, कंप्यूटर हे, ए.सी. रूम में पढ़थे, लेकिन जेखर वोट ला लेकर के आप मन यहां पर मंत्री बने हव, जेखर आशीर्वाद से हमन यहां पर सदन में आये हन जाके ओखर लइका ला देखव जैसे मैं विधायक बने के पहले मैं गांव में गरवा चरावव। गांव भर में एक वर्दी ला लेकर गांव में भाठा में ठोके रहौ। उसी प्रकार के आज गरीब के लइका, किसान के लइका कमजोर के लइका, वो आदिवासी समाज के लइका आज स्कूल में जाके धंधाये हे, एक गुरूजी हा पढ़ो कहाते अउ सुतथे। आज वो स्थिति रहतिस तो हमर ओ.पी. चौधरी साहब हा कलेक्टर बने हे ना तो कांग्रेस के राज़ के गुरूजी हा पढ़ाके ओला कलेक्टर बनाए हे? आप ही के राज में रहतिस न तो अ के अनार नहीं जानतिस ओहा। आज मैं कहना चाहथव कि शिक्षा के जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ला आप मन सुधारवौ काबर आप मन तो आइकॉन, इंग्लिश भाषा हे का एहा, मैं तो नहीं जानौ भई, आप मन तो आईकॉन हव, मतलब युवा मन के आंखी हृदय सम्राट। आज मैं कहना चाहथव बहुत अच्छा आप मन करे हव। कोई चीज़ के मैं जो अच्छा करे हव ओला मैं अच्छा भी कहथव। जोन मितानिन मन ला ऑनलाइन पेमेंट देथौ, बहुत अच्छी बात है, हमन पैसा बढ़ाये रहन, तुमन सिर्फ देत जावत हवव। कोई बात नहीं ऑनलाइन अच्छी बात हे। आप मन आंगनबाड़ी, ओ कार्यकर्ता, ओ स्वीपर, जेमन आप मन चुनाव में कहे रहौ, ये मोदी का गारंटी है, ये मोदी का गारंटी है, आप लोग वोट दीजिए कांग्रेस को हराए, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन बनाइए। सबको रेगुलर कर देंगे, पैसा से आपका झोला को पूरा भर देंगे। कब दिया साहेब ओला? कब दिया ओला? आप एमा विचार करौ, सब सुनथै, सब समझथे, भोरा में मत रहिहौ और मैं कहना चाहथव, अभी हमर महाराज जी हा पिछड़ा वर्ग के बारे में बोलत रहिस । साहब जी, लोकतंत्र में जब ये देश आजाद नहीं होये रहिस, हम अंग्रेज के गुलाम रहे हन, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बिस्मिल्ला खां जी, तमाम नेता मन और बाबा साहब अम्बेडकर जी मन देश ला आजाद करइस अउ ओखर बाद संविधान बनिस। संविधान में कहे गे हावय, जिसका जितना संख्या भारी, उसका उतना हिस्सेदारी। हमर ओ.पी. चौधरी साहब हा ओ.बी.सी. के कोटा से बने हे। हमर वर्मा जी हे, ये हमर जायसवाल जी हे, हम लोग ओ.बी.सी. कोटा से बने हे, हमरे कोटा से मंत्री बने हे, लेकिन आज मैं आप ला कहना चाहथव अउ पूरा प्रदेश हा ए बात ला देखथे कि ए प्रदेश में 32 प्रतिशत आदिवासी समाज 32 ठक कुर्सी ए प्रदेश में एस.सी. वर्ग ला भी जनसंख्या

के अनुपात में मिलत हे। ओखर बाद 48 से 52 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग हे। जेमन गद-गद ले वोट दे दिही तो तुमन बबा नहीं बांचव। ओमन हा ए पहली के सरकार हा इहां ले बिल पास करके तुम्हरो दस्तखत हे, हमरो दस्तखत हे, हमर ओ समय के रमन सिंह जी के भी दस्तखत हे, ओ समय ओमन हा विधायक रहिस, पूर्व मुख्यमंत्री हे, ओखरो दस्तखत हे, सबके तुम्हर दस्तखत हे, अउ ओला दियार खाथे।

श्री मोतीलाल साहू :- हाईकोर्ट कोन गे रहिसे?

श्री रामकुमार यादव :- आप।

श्री मोतीलाल साहू :- हाईकोर्ट कोन गे रहिसे, तेला बता देकर। हाईकोर्ट कोन गे रहिसे, तेला बता दे। ओखर बाद आयोग के अध्यक्ष कौन रहिसे, तेला बता दे। सब्बो ला बतान भाई। बने बताना गोठिया न। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- साहू जी, तुम्हरो कनी जवाब मांगही। इहां सिर्फ आरोप लगाये से नहीं बने। मैं चैलेंज के साथ कहाथव, ओ.बी.सी. समाज जाग चुके हे, कतका दिन तुमन ठग के रखिहौ। (व्यवधान)

श्री मोतीलाल साहू :- सुनथन अउ बतावथन गा। कोनो इतना पढ़े-लिखे नहीं हन भाई। ओ दियार खाथे तेला बताथस। सुनथन यादव जी, जागे हे तभे तो एती ले ओती हौ। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि हाईकोर्ट कौन गया है ? आप हमसे पूछ रहे हैं, आप सार्वजनिक कीजिए, सदन को अवगत कराइए कि हाईकोर्ट कौन गया था और किस स्वरूप में गए थे, यह बताइए ?

श्री मोतीलाल साहू :- सबको पता है कौन गया था । हाईकोर्ट में कैसे स्टे हुआ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप अधूरा प्रश्न क्यों कर रहे हैं ?

सभापति महोदय :- कृपया, आपस में चर्चा न करें ।

श्री रामकुमार यादव :- साहू जी, आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहत हौं, चलो बताओ ?

श्री मोतीलाल साहू :- ये हल्ला तो तुमन राष्ट्रीय स्तर मा भी करे हौ । लोकतंत्र खतरा मा रहिस हे, आरक्षण खतरा मा रहिस हे । देश के जनता जवाब दे दिस ।

श्री रामकुमार यादव :- आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ? पिछड़ा समाज ला, साहू समाज ला, गरीब समाज ला आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए । सभापति जी, दुर्भाग्य है कि पिछड़ा वर्ग के वोट ला, साहू समाज के वोट पाकर विधायक बनकर आ जाथे अउ इहां आके उहीं मन के दुश्मन बन जाथे । आज मैं कहना चाहत हौं । आप ला सही मायने में ओला पास कराना चाहिए, न्याय के लिए करना चाहिए, समतामूलक समाज बनाए के लिए ।

महोदय जी, अब मैं मोर क्षेत्र के विकास पर आ जाथौं । देखौ साहब, वोट होथे, लोकतंत्र हे, कहूं मेर कांग्रेस जीतथे, कहूं मेर भाजपा जीतथे कोनो मेर हमर गोंडवाना जीत जाथे । लेकिन एमन का करत हे, पूर्व सरकार, पूर्व अधिकारी मन जो स्वीकृत करे हे 300 रोड । जहां पर सही मा रोड नइ हे, मोर क्षेत्र मा तो अइसना हे आज भी जाहू तो मोला बहुत तकलीफ होथे । 75 साल, अउ 15 साल तुम्हर सरकार रहे के बाद भी हमर गांव मा रोड नइ हे । कोनो बीमार पड़ जाथे ता निकाले नइ सकय। वो समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हा स्वीकृति दिस, प्रशासकीय स्वीकृति होगे, टेंडर भी हो गे लेकिन वाह मोर भाजपा के सरकार हो, डबल इंजन के सरकार हो ।

श्री आसाराम नेताम :- रामकुमार जी, पांच साल ले सुते रहे का ?

श्री रामकुमार नेताम :- सुते नइ हौं, पास हो गे, टेंडर हो गे ।

श्री आसाराम नेताम :- ता ओला करवाना रहिस हे ना ।

श्री रामकुमार यादव :- उही ला तो तुमन ला कहत हौं, ओला काबर रोक के रखे हौ ?

श्री आसाराम नेताम :- आरोप क्यों लगा रहे हो, पांच साल तो आप लोगों का शासन था, पूरा मैदान आप लोगों का था । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जतना रोड पास हो गे हे,सबो ला फिर वित्त विभाग भेजे गे हे । हमन स्वीकृत कराबो तब वो पास हो ही । मंत्री जी ला बोलो ना कि ओला पास करके दे दे । आप सत्ता पक्ष के हो, आप मंत्री जी ला बोलो । आप लोगों को वैसे भी कुछ नहीं मिला है, चिल्लाने से भी नहीं मिलेगा ।

श्री आसाराम नेताम :- ओकरे तो बजट पास करत हे । विरोध में खड़ हो तो कहां ले पास हो ही ।

श्री रामकुमार यादव :- दुश्मनी राम कुमार से करौ, क्षेत्र की जनता से मत करौ । एखर खातिर मैं कहना चाहत हौं कि मोर क्षेत्र मा जो रोड हे खरसिया से मौहापाली, कटहर्रापाली-बेनीपाली-ओड़ेकेरा-निमोही-देवरघट्टा-करइडीह-खर्री और कलमी-चिखरी-कोटसिंघरा-खरसिया रोड, ये सबो प्रशासकीय स्वीकृति होके टेंडर हो गे हे । एमन दुर्भावनावश धर के राखे हे । रामकुमार से दुश्मनी करौ लेकिन क्षेत्र के जनता ला दुश्मन मत बनावव । मैं आपसे यही निवेदन करते हुए यह कहना चाहत हौं कि दुर्भावनावश काम मत करौ । ये जो बजट लाने हौ, ये बजट ला सिर्फ अपन खाए पिए बर लाने हौ, क्षेत्र के विकास बर नइ लाने हौ । डबल इंजन फेल है काबर के तुमन डबल इंजन के हिसाब से काम नइ करत हौ । तेखर खातिर मैं विरोध नइ तुमन बजट के घोर विरोध करते हुए अपन वाणी ला विराम देवत हौं ।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपुनूरक बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । समय बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए मैं बहस का कोई मुद्दा न छेड़ते हुए सीधे यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में जो व्यवस्था दी गई है और जो अनुपूरक मांगें रखी गई हैं वह एक-एक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग समर्थन योग्य है, छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए है । मैं अभी यहां बहस को देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे वक्तव्य के समय भी सब लोग खड़े होकर विरोध न कर दें । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक कोई खड़ा नहीं हुए। मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं । मैं बस्तर से आता हूं इसलिए बस्तर की बात करना चाहूंगा । इस सदन के माध्यम से सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार बस्तर को रायपुर से जुड़ने का सीधा मौका मिलने के लिए रेल्वे की स्वीकृति हुई है । जो रावघाट से जगदलपुर तक रेल्वे लाईन जुड़ने की सौगात मिली हुई है । दूसरी स्वीकृति धमतरी से लेकर केशकाल विधान सभा को जोड़ते हुए कोण्डागांव तक जाने के लिए रेल्वे के सर्वे की स्वीकृति मिली है, मैं उसके लिए भी केन्द्र सरकार को इस सदन के माध्यम से और हमारे बस्तर संभाग के सभी विधायक साथियों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें मेरा यही आग्रह रहेगा कि जब यह रेल्वे का सर्वे किया जाए तो जो लिखमा स्टेशन है, हमारी मरकाम बहन की विधान सभा में आता है, वहां से केशकाल में जोड़ा जाए और फरसगांव होते हुए, कोण्डागांव को जोड़ते हुए, इस रेल्वे लाईन को अगर ले जाया जाएगा तो इसकी सुविधा, इसका फायदा बहुत अच्छा होगा। मैं सदन को एक और सौगात के बारे में बताना चाहूंगा। धमतरी से लेकर जगदलपुर को जोड़ने के लिए दो हजार करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गयी है, वह भी हमारे बस्तर के विकास के लिए एक बड़ा ही सुनहारा पन्ना साबित होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। इसके साथ ही साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो केशकाल घाट है, केशकाल घाट मध्य भारत को दक्षिण भारत के साथ जोड़ने का एक सबसे बड़ा साधन है लेकिन हम सभी जान रहे हैं कि इस समय केशकाल घाट हमेशा बाधित रहता है और आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में विचार करना होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो 11 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें केशकाल घाट और केशकाल शहर भी है, इसको स्टेट में शामिल किया जाए ताकि इसका संधारण ठीक प्रकार से हो सके। मैं हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके सुदृणीकरण के लिए लगभग 45 करोड़ का जो बजट रखा गया है, उसको मंजूरी दी जाए ताकि केशकाल घाट और केशकाल शहर की जो स्थिति है, उसमें सुधार हो सके।

आदरणीय सभापति महोदय, हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है, केशकाल विधान सभा में मांझीनगढ़ से लेकर चेरा मोरे तक का जो पर्यटन क्षेत्र है, इसको विकसित करने की आवश्यकता है जिससे वहां के हजारों नवयुवकों को और हमारे ऐसे बेरोजगार जो कि अपने रास्ते से भटक गये थे, नक्सलवाद के रास्ते में चले गये थे, उन लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकता है। इस क्षेत्र को जल्द से जल्द पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि मांझीनगढ़ से लेकर चेरा मोरे तक बीच में जितने भी पर्यटन स्थल चाहे

टाटामारी हो, चाहे कुंएमारी हो, ऐसे अनेकों स्थल हैं जो पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है। आने वाले समय में बजट में उस पर प्रावधान किया जाए ताकि वहां पर बदलाव हो सके। मेरे क्षेत्र की और भी मांग है, जिसमें हमारे विश्रामपुरी को सीधा कांकेर जिले से जोड़ने के लिए बैजनपुरी से लेकर रावस तक के सड़क की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है जिसकी स्वीकृति अगर मिलती है तो जनता को इसकी सुविधा मिल जाएगी। मैं और अधिक समय न लेते हुए, हमारे जो वरिष्ठ विधायगण हैं, हमारे जो अग्रज लोग हैं। अभी कुछ देर पहले काफी तनाव भरी स्थिति भी निर्मित हुई लेकिन इसका फायदा यह हुआ कि यहां सदन में बैठने वालों की संख्या बढ़ गयी। बाहर के सारे लोग अंदर आ गए। वैसे तो आ नहीं रहे थे। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट की अनुदान मांगों के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध इस बात का है कि पिछले मुख्य बजट में जो बातें रखी गयी थी, उसमें भी हमें आश्वासन दिया गया था कि अनुपूरक में जो चीजें बच गयी हैं, जो विकास के काम बच गये हैं, उसमें भी आपके क्षेत्र को महत्व मिलेगा। नहीं है फिर भी मैं सभापति के माध्यम से सुनाना चाहूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप चाहें तो लिखकर दे सकते हैं, आपका सब काम पूरा होगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं उस समय लिखकर दे दिया था ।

श्री केदार कश्यप :- आप लिखकर दे दीजिए, आपका सब काम पूरा होगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नई होय हे ? होय रतिस त बोलतेव नई ? होय रतिस त धन्यवाद दे रंतेव । माननीय सभापति महोदय, यह भेदभाव जो बजट में दिख रहा है, यह छत्तीसगढ़ का पूरा बजट केवल 3 विधान सभा में समाहित है, जशपुर, रायगढ़, कुनकुरी और कहीं-कहीं पर कबीरधाम है, ऐसा दिखता है । माननीय सभापति महोदय, इस सदन में 90 विधायक हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी के साथ एक छलावा हुआ है । सभापति महोदय, एक उम्मीद थी कि 7 हजार 329 करोड़ के बजट में कुछ तो मिलेगा, लेकिन 4900 करोड़ महतारी वंदन के नाम से और बाकी विभागों में केवल झुनझुना पकड़ाने का काम हुआ है । सभापति महोदय, मैं देखता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत से ऐसे विभाग हैं, मछली पालन विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, मैं उस वर्ग और उस समाज से आता हूँ, मुझे विश्वास और अपेक्षा थी कि जून और जुलाई का महीना बिडिंग का होता है, चूंकि मछली के व्यवसाय से जुड़े हैं, इसलिये हम जानते हैं कि शासन से मत्स्य को, मछली कृषकों को, मछली के बीज दिये जाते हैं, जब आपके बजट में ही नहीं है तो आप इसका प्रावधान

कैसे करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, यह 20-22 लाख समाज के लोगों के साथ छलावा है, मैं आपसे चाहूंगा कि इस बजट में कटौती कर उस समाज के लिये भी बजट में प्रावधान रखें । सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी आ गये हैं, माननीय चौधरी साहब से बात हुई थी और कुछ प्रेम पत्र भी व्यावहारिक रूप से आपको लिखकर दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, मैंने दो स्कूलों के बारे में आपसे कहा था कि यह अनुदान प्राप्त स्कूल है, यह वर्ष 1964 और वर्ष 1969 से संचालित है, भाठागांव बी और एक है श्री राम विद्या मंदिर पैरी, वर्ष 1969 से संचालित है । सभापति महोदय, जब हमारे विधान सभा अध्यक्ष जी, भण्डेरा में गये थे और उन्होंने घोषणा की थी, जब आप लोग नहीं कर पाये तो उस स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करके मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी के सपने को पूरा किया था, मुझे भी उम्मीद है कि आप भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किये हैं, उसे पूरा करेंगे । सभापति महोदय, वर्ष 1964 और वर्ष 1969 से यह स्कूल संचालित है, यह अनुदान प्राप्त स्कूल है, भाठागांव बी का स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने 25 करोड़ तीर्थयात्री के लिये, 10 करोड़ विशिष्ट अतिथि के लिये रखा है तो करोड़ रूपये का प्रावधान इन स्कूलों के लिये रखेंगे, जहां बच्चे शिक्षा अर्जित करके आप और हमारे जैसे बनते हैं । माननीय सभापति महोदय, अभी स्कूल के उन्नयन की बात आई है, बालोद जिले में हम तीन विधायक, माननीय अनिला भेंडिया जी, संगीता सिन्हा जी और मैं स्वयं आते हैं, बालोद जिले में एक भी स्कूल का उन्नयन नहीं हुआ है । माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा में 5 स्कूल का नाम दिया हूँ, खेरूद का दिया हूँ प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला उन्नयन में, सरेखा का हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेण्डरी में किया जाना है, गणेश खपरी जो आदिवासी एरिया आता है, माध्यमिक शाला का उन्नयन हाई स्कूल में किया जाना है, पिछले साल एक बच्चा पुल से डूबकर खत्म हो गया था, केवल नदी से उस पार घर जाने के लिये निकला था, अचानक बाढ़ आई और खत्म हो गया था । मैं चाहता हूँ कि उस गांव में खुज्जी विधान सभा लग जाता है और इधर राजनांदगांव विधान सभा और इधर डोंगरगांव विधान सभा है । सभापति महोदय, यह विधान सभा का अंतिम गांव होता है और यदि वहां हाई स्कूल बन जाये तो निश्चित ही वहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा । सभापति महोदय, बुंदेली जो डौंडीलोहारा विधान सभा और गुंडरदेही विधान सभा के बीच बार्डर में है, अगर वहां पर माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उननयन हो जाये तो निश्चित रूप से वहां के बच्चों को सुविधा मिल सकती है । माननीय सभापति महोदय, सड़क की बात करूं तो न मुख्यमंत्री सड़क योजना से और न ही प्रधानमंत्री सड़क योजना से, न ही पी.डब्लू.डी.विभाग से बालोद जिले में कोई भी स्वीकृति नहीं मिलती है । सभापति महोदय, मैंने 64 से 65 मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिये और केवल 2 प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिये दिया था, जो आज गड्ढ़े हो चुके हैं, अमूमन उस गांव के लोग विरोध कर रहे थे, लोक सभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, मैंने वादा किया था, माननीय मंत्री जी से बात हो गई, संबंधित अधिकारी से बात हुई, उसे पूरा करेंगे,

केवल 2 सड़क है, खल्लारी से मुंदेला पहुंच सड़क मार्ग केवल डेढ़ किलोमीटर का सड़क है और डंगनिया से परसदा मार्ग है, यह दो प्रधानमंत्री सड़क योजना बन जायेगा तो लगभग 8 से 10 गावों की आवाजें उधर से आती है, उनको इसका लाभ मिल सकता है । अभी हमारे कुछ साथियों ने राम भगवान को लेकर जो विचार रखा है, मैं तो उस वर्ग से आता हूं, जिसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है । जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था तो विशेष अतिथि का दर्जा गुह राज निषाद जी को मिला था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहां पर ढाई करोड़ मछुआरों को उपेक्षित किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि आप अयोध्या और चित्रकोट, दोनों जगह चुनाव हार गए । आपने इस समाज के साथ अन्याय किया और आज भी आपने बजट में निषाद समाज के लिए कुछ भी नहीं रखा है, इसका भी परिणाम भविष्य में आपको मिल सकता है । सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मछुआरों के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखें क्योंकि यह बीडिंग का का समय है, जून और जुलाई बीडिंग का समय होता है । हम लोग मछली बीज डालते हैं, वह शासन से मिलता है, लेकिन इसमें प्रावधान नहीं है तो मैं सशंकित हूं कि प्रावधान नहीं है तो हम कैसे मछुआरों को शासन के द्वारा दी जाने वाली मछली बीज सप्लाई करेंगे या नहीं ?

सभापति महोदय, मैं किसान आंव तो ओतका ला घलो बोलहूं । खाद-बीज से लेके सारा बात आवथे । आप अपन घोषणा में केहे रेहेव कि हमन भूमिहीन कृषक मजदूर मन ला घलो योजना के राशि 10 हजार रूपिया देबो अउ ओकर बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथा किश्त के राशि बचे हे, तहू ला देबो, केहे रेहेव, लेकिन ए बजट में प्रावधान नहीं हे तो किसान मन ह ठगे जईसे महसूस करथे तो ओकर बारे में जरूर सोचव और बालोद जिला में आप सबके लापरवाही के नतीजा, आपके सरकार के नतीजा, आपके सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के लापरवाही के नतीजा के कारण 27 हजार क्विंटल धान शार्टेज होए हे अउ समिति मन ला नोटिस जारी करे गे हे कि जेन सोसायटी ला, जेन समिति ला लाभांश के राशि मिलथे, ओकर राशि से हमन से शार्टेज ला पूरा करबो तो कईसे होही। अईसे मत होए कि आपके गलती के खामियाजा किसान मन भुगतें तो वह शार्टेज राशि ला आप कईसे पूरा करहू, आप जानव । आपके सरकार हे । लेकिन लाभांश के राशि के किसान मन के हक होथे, किसान मन के अधिकार होथे, ओ ह कम से कम किसान मन ला मिलय, मैं बस यही चाहथौं । मैं पुन: बस अतका कहना चाहहूं कि जेन-जेन माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करे हंव, ओला जरूर गौर करौ । बस यही निवेदन के साथ मैं अपन बात ला समाप्त करथौं । आप बोले के अवसर देव, लेकिन मैं एकर विरोध में बात करे हंव, तेकर बर मैं आपला बहुत-बहुत धन्यवाद देवथव ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट के समर्थन में बोले बर खड़े होए हव अउ जोन-जोन प्रावधान ये बजट में आए हे, निश्चित तौर पे यह मोदी गांरटी के साथ विष्णु सुशासन के प्रतीक हे और निश्चित तौर पर एमा माता बहिनी

मन के लिए, महिला मन के लिए, छोटे बच्चा मन के लिए, लोग लईका मन के लिए, सियान मन के लिए, दिव्यांग मन के लिए अनेक प्रकार के योजना, किसान मन के लिए कृषक उन्नत योजना के माध्यम से समुचित छत्तीसगढ़ के विकास जेन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 2047 के विजन हे, वह 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के शुरूआत हो चुके हे अउ ये जो अनुपूरक बजट हे, जेन जनहितकारी हे और जेन प्रकार से मैं देखत रेहेंव कि हमर विपक्षी संगवारी मन ह मोला अईसे लागत रिहीसे कि एमन पॉच साल काहीं नहीं कर सकय, ओकरे मलाल ला खड़ा होकर अभी निकालत रिहीसे, तईसे लागत रिहीसे । काबर कि जब ले सरकार बने हे, तब ले जौन-जौन घोषणा होए रिहीसे, तौन-तौन काम ला हमर विष्णु देव सरकार के नेतृत्व में लगातार निरंतर प्रगति की ओर हन और लगभग जेन पूरा वादा हे, वह पूरा होए बर जावथे तो निश्चित तौर पर मलाल निकलना स्वाभाविक हे अउ जेन प्रकार से 2018 में एमन घोषणा पत्र में जेन घोषणा करे रिहीसे अउ काहीं बुता ला नहीं करे सकिन अउ झूठा वादा करिन ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं सभापति के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम मलाल नहीं निकाल रहे हैं । आपको अपने विधान सभा क्षेत्र में कितनी स्वीकृति मिली है, यह बता दीजिए । आप हमारे चिन्ता तो छोड़िए । आप निराधार आरोप मत लगाईए न ।

श्री मोतीलाल साहू :- मैं बताथौं न गा । उहूं ला बताहूं भाई ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप अपने क्षेत्र के बारे में बता दीजिए ।

श्री मोती लाल साहू :- अभी तो शुरू करे हव। जेन प्रकार से अपन विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरा छत्तीसगढ़ के जनता के विकास अउ हर वर्ग के विकास के प्रावधान ये अनुपूरक मा समाहित हे। ओला सबो जनता महसूस करत हे कि कांग्रेस के समय मा 5 साल ले कैसे ठगाय रहिस हे। 15 साल मा डॉ. रमन सिंह के समय मा सुशासन होय रहिस हे अउ ये 15 साल मा जेन विकास होय रहिस हे, जेन सड़क के निर्माण होय रहिस हे, ये मन तो गड्ढा तक ला रिपेयर नइ कर पाय रहिस हे, ये मन ऐसे स्थिति निर्मित करके रखे रहिस हे। चारो तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त रहिस हे। ये मन एक ठन निशानी तक ला बता देय कि 5 साल मा ये बुता ला करे हन। ये मन आज की तारीख मा एक ठन निशानी बताय के स्थिति मा नइ हे अउ ओखरे सेतिर तरह-तरह के विरोध के बात ला ये अनुपूरक मा करत हावय।

सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा बाल ला नइ बोलव। अभी हमर संगवारी मन कहत रहिन हे कि बलौदा बाजार मा अनेक प्रकार के जेन हिंसा के घटना घटे हे, सचमुच ये मन ला ऐसा लगत हे कि सत्ता से बाहर होय के बाद अनुचित साधन अउ कौन प्रकार से असत्य फैलाकर के फिर से 5 साल तक कैसे कूटरचना रचीन, जेकर कारण फिर से सत्ता में आय के गलत तरीके से रास्ता करत हे, यह स्पष्ट तौर पर स्पष्ट हो चुके हे।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, हमर समाज हा असत्य फैलाय के काम करत हे ? हमर पार्टी हा असत्य फैलाय के काम करत हे, आप मन ला लागत हे ? एखर निष्पक्ष जांच होना चाहिए दूध के दूध अउ पानी के पानी होना चाही कि ऐ काम ला कोन करे हे।

श्री मोती लाल साहू :- ओ न्यायिक जांच चलत हावय, वह स्पष्ट, दूध के दूध अउ पानी के पानी हो जाही।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- बार-बार समाज, समाज, समाज, पार्टी-पार्टी बोल रहे हैं।

श्री मोती लाल साहू :- एखर पीछे काकर हाथ हावय, ये शांति के टापू छत्तीसगढ़ ला कोन बदनाम करे के कोशिश करत हे, कोन बरबाद करे के कोशिश करते हे, दूध के दूध अउ पानी के पानी हो जाही, ओमा चिंता करे के विषय नइ हावय। लेकिन जेन रास्ता ला अख्तियार करत हव, वह रास्ता ठीक नइ हावय, ये मैं आप मन ला बताना चाहत हंव। जो रास्ता मा चलत हावव, ओ रास्ता ठीक नइ हे।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- हम खुद चाहत हन। ये आपके सरकार मा होय हावय। सुशासन के सरकार इही ला बोलथे का ?

श्री मोती लाल साहू :- बिलकुल सुशासन हे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपके परिवार के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा रहा ?

सभापति महोदय :- आपस में बात ना करें।

श्री मोती लाल साहू :- ये सुशासन ला ही देखके घबरा गय। ये सुशासन ला देखके घबराय के कारण ही ये षड़यंत्र रचे गय रहिस हे अउ षड़यंत्र के कारण ही हिंसा होइस।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- घबराय नइ हन। डबल इंजन के सरकार बोलत हव, हम ही बनाये हैं, हम ही संवारेंगे, बोलत हव। कहां बनाये हैं और कहां संवार रहे हैं, यह सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं।

श्री मोती लाल साहू :- ये घबराहट के कारण ही उहां षड़यंत्रपूर्वक हिंसा कराय गय हे न। तो ये बात हे। गलत तरीका से इहां छत्तीसगढ़ मा सत्ता नहीं आ जा सकय। छत्तीसगढ़ के जनता एक बार धोखा पा गय हे। अब विष्णु देव के सुशासन चलत हे। पूरा विकास के पटरी में छत्तीसगढ़ दौड़ चुके हे, पूरा जनता मा खुशाहाली हे। हर वर्ग मा खुशहाली हे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सदस्य जी, सतनामी समाज मा खुशहाली नइ हे। अभी सतनामी समाज के सारे युवा बच्चे 19 साल से लेकर 27 साल तक के बच्चें जेल में सड़ रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो रहा है, अभी उन बच्चों को दोषी नहीं ठहराया गया है, वे अभी दोषी नहीं है तो उन बच्चों को क्यों रिहा नहीं कर देते ? उनको रिहा करवा दीजिये, अभी वे दोषी नहीं हैं। जब तक दोषसिद्ध नहीं हो जाते तब उन्हें कैसे जेल में रखा गया है ?

श्री मोती लाल साहू :- बहन जी, उसके पीछे किसका हाथ है ? ओखर पीछे काखर हाथ हावय ओला सोचव, चिंता करव। कौन गय रहिस हे, कौन मन भाषण दे रहिस हे, कौन हिंसा भड़काय हावय, येला थोकन देखव, समझे के कोशिश करव।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन किए हैं, कहां से आये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- साहू जी, बलौदा बाजार की पुलिस कैसे कार्यवाही कर रही है, आप पत्रकार वार्ता लेकर स्टेटमेंट दिए हैं। आप स्वयं पुलिस की कार्यवाही से पीड़ित हैं। आपके भतीजे सड़क से गुजर रहे थे, उसको कैसे पीटा गया है।

श्री मोती लाल साहू :- भाई साहब, वो विषय अउ ये विषय मा अंतर हे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- घटना के बाद पुलिस कैसे कार्यवाही कर रही है, वह आप बहुत करीब से देखे हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये, बैठिये। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- घटना के बाद पुलिस कैसे कार्यवाही कर रही है, यह मेरे बोलने का आशय है।

श्री मोती लाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, इनको यह विकास नहीं देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास अउ तरक्की ला देखत हावय तो घबरा गय हे तो का तरीका हो सकत हे ? ऐके तरीका हो सकत हे कि इहां छत्तीसगढ़ मा अव्यवस्था होय, तो अव्यवस्था करे के प्रयास हमारी संगवारी मन के द्वारा, हमर विपक्षी मन के द्वारा करे जावत हावय। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के जनता समझ गय हे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ला मोर तरफ से धन्यवाद देहू जो मोर माना क्षेत्र मा 30 बिस्तर अस्पताल हे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गय रहिस हे, उहां जाय के बाद घोषणा करके आय रहिस हावय कि सौ बिस्तर के ये अस्पताल ला ठीक से चलवाय के व्यवस्था ला करहूं, जो संसाधन के कमी हे, तेला पूरा करहू, कहे रहिस हे। तो ये अनुपूरक मांग मा आ गय हे। ओमा सौ की जगह डेढ़ सौ बिस्तर के अस्पताल, प्रांतीय स्तर के नेत्र चिकित्सालय हा बजट मा आय हे। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री अउ माननीय मुख्यमंत्री जी ला एखर लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवत हावव कि ये अनुपूरक मा स्थान देय हे। लेकिन ऐखरे संग निवेदन भी करत हव कि ओमा सभी रोग के ईलाज के व्यवस्था हो जातिस तो ज्यादा अच्छा रहिस हे। शहर के लगे हुए जगह हे, बाकी जो करे हे तेखर लिए धन्यवाद देवत हंव। एक कनि अउ थोकन गोठयाहूं। मुख्य बजट में मोर दू ठन हाई स्कूल के हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन के मांग रीहिस हे। ओमा हाई स्कूल उन्नयन के त्रुटि होगे तो ओला हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दुहुं अऊ ओहा भवन निर्माण सहित हे तो आप मनके बड़ा कृपा होही। यही बात कहत हुए कि मैं अभी-अभी अनुपूरक बजट ला पढ़त रहे हव ता ओमा बहुत सुघ्घर प्रावधान हे। ओमा शुद्ध जल, हमर पुराना जलाशय, नाला, पोखर के लिए प्रावधान हे तो माननीय वित्त मंत्री जी ला अच्छी तरह से पता हे कि मोर क्षेत्र मा गजराज बांध हे, जेन हा लगभग 230 एकड़ में फैले हुए हे, ओला आप सुंदर बना देहुं। ओहा आसपास के क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन अऊ पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा जगह हे। उही प्रकार से दलदल सिवनी में इंदरा वन करके जगह हे। ए सब ला आप व्यवस्थित अऊ सुसज्जित कर दुहुं तो निश्चित तौर पर मोर क्षेत्र में आम जनता के सुविधा के लिए बढ़िया जगह बन सकत हे। आप सबसे यही निवेदन करत हुए कि यह बहुत बढ़िया अनुपूरक बजट है अऊ मैं एखर समर्थन करत हो। मैं हमर माननीय मुख्यमंत्री जी अऊ वित्त मंत्री ला बहुत-बहुत बधाई देत हो। सभापति महोदय, आप मन मोला बोले के अवसर देओ, एखर लिये आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव जी।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अनुपूरक बजट के विपक्ष में अपनी बातों को रखने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। यह जो पिछले 7 महीने से सरकार चल रही है, इस सरकार के आने के पहले और सरकार बनने के बाद दोनों में सरकार के सम्मानित नेताओं के जो चेहरें और बातें हैं, वह बदले-बदले दिख रहे हैं। जब यह सरकार विपक्ष में थी तो इनके नारे कुछ और हुआ करते थे और आज जब यह सत्ता में पहुंची है तो इनकी बातें कुछ और हो गई हैं। आप देखेंगे कि जब इनकी सरकार नहीं थी तो जनता के बीच में यह अपना वचन पत्र और मोदी की गारंटी लेकर गये। इन्होंने लोगों के बीच में ऐसी गारंटी प्रचारित की कि ये लोग लोगों की भावनाओं को अपने प्रति आकर्षित करने में सफल हुए। चलिये, आपने लोगों की भावनाओं को आकर्षित कर लिया, लेकिन आकर्षण एक बार का होता है उसको लोगों के बीच में स्थाई भावना बनाना एक अलग बात होती है। आप देखेंगे कि यह सरकार कैसे आई? भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने चुनाव के पहले यह गारंटी दी कि हम गवर्नमेंट की 1 लाख रिक्त भर्तियों को जल्द से जल्द समयावधि पर प्रकाशित करके उसकी भर्ती करेंगे। यह बड़ी बात है। लोगों और युवाओं को इस बात को लेकर खुशी हुई होगी। लोगों और युवाओं ने खुश होकर इनको मतदान भी दे दिया। हम गारंटी तो देते हैं लेकिन जब उस गारंटी को पूरी करने की बात आती है तो मुझे पिछले कुछ दिनों में ऐसा दिखता है। मेरी किसी के ऊपर आरोप लगाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं। मैं केवल आपको पुरानी बातों को भी याद दिलाना चाहता हूं और वर्तमान की बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की गारंटी की बात होती है और जब सरकार बन जाती है, तब यह बात होती है कि हम पैसे कहां से लाएंगे और जितने आवेदन करेंगे, क्या उन सबको नौकरी मिल जाएगी? यहां विरोधाभास दिखता है। वैसे ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं ने उस समय

चुनाव में बड़े-बड़े वायदे किये। इन्होंने एक बड़ा वायदा यह किया कि हम हर गरीब महिला को 500 रूपये में सिलेण्डर देंगे। हमने देखा कि बड़े-बड़े पोस्टर लग गये। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। जहां जाओ, वहां सुनते थे कि हर महिला को हर माह 1,000 रूपये और 500 रूपये में सिलेण्डर दिया जाएगा। सबका परिवार है तो सिलेण्डर को लेकर सबके मन में यह भावना होती है कि सस्ती गैस मिल जाए। कहां वर्ष 2014 में सिलेण्डर की कीमत 350-400 रूपये थी और अब वह 1,100 रूपये को पार गया है। वह सिलेंडर 500 रुपए में देने का वायदा किया गया। इसके बाद कहां गई वह गारंटी? उस गारंटी पर आज कोई चर्चा नहीं हो रही है। बड़े-बड़े discussions किए गए, content deliver किए गए और कहा गया कि हम monthly travel allowance देंगे। बच्चों के आने-जाने के लिए सरकार मासिक रुप से उनको भत्ता/खर्च देगी। कहाँ है भत्ते की बात, कहॉ है खर्च की बात? मुझे लगता है कि विपक्ष में जब रहते हैं, तब ये सब बातें होती हैं और जब सत्ता में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों को हमारी वर्तमान सरकार के मंत्री संज्ञान में ले रहे हैं। बात होती है innovation hub बनाने की। कहॉ है innovation hub? अनुपूरक भी आ गया, इसके पहले का बजट भी आ गया, पर उसकी कोई चर्चा नहीं है। इस बजट में चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि जब पिछली सरकार स्टेट वेयर हाउस कार्पोरेशन के जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनको चार हजार रुपए सम्मान निधि देने की बात करती है, तो उस समय वर्तमान के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित और इस प्रदेश सरकार के मंत्रीगण वहां जाते हैं और वायदे करते हैं और वहां पर अपनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब सरकार आती है तो उनको वहीं धरना स्थल पर कोई सुनने भी नहीं जाता, कोई उनका ज्ञापन लेने भी नहीं जाता। इससे दोहरा चरित्र दिखता है, इससे विरोधाभाष दिखता है कि जब आप विपक्ष में हैं, तो लोगों को किसी भी तरह अपने पक्ष में करने के लिए कैसे भी वायदे कर दो लेकिन सत्ता में रहते हुए लोगों की जनभावना आप भूल जाते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, मेरे युवा साथी बड़ा अच्छा भाषण दे रहे हैं लेकिन शायद पांच साल तक दृष्टि भ्रम के शिकार थे। श्रवण की स्थिति भी थोड़ी कमजोर थी। पिछले पांच सालों में इन्होंने महतारियों को 500 रुपए देने के जो वायदे किए, उसे वे पांच साल तक पूरा नहीं कर पाए और उस संबंध में अपनी सरकार का ध्यानाकर्षण नहीं करा पाए और ये युवाओं की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जो युवा स्वप्न दिखाया गया था, उस पर भी ये जवाब दें ना। लेकिन ये बोलेंगे नहीं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को समझता हूं कि अपनी उपस्थिति दर्ज करानी तो जरुरी है। कुछ नए साथी आए हैं, थोड़ी भीड़ ज्यादा है, उम्मीद थी नहीं कि सरकार आएगी, अब आ गई है तो कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोग अपनी बात कहेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी को कहना है, हाथ उठाकर कह सकता है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।

सभापति महोदय, हम आगे बढ़ते हैं। हम पिछले छः-सात महीने की सरकार में क्या देख रहे हैं? खुद की बात आई तो बड़े-बड़े पोस्टर-बैनर। आज हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने यहां एक बहुत बड़ा विषय प्रश्नोत्तर में उठाया, जिस विषय की गहराई को आप समझिए। आप देखेंगे कि यह वर्तमान सरकार किस पर काम कर रही है। ये वर्तमान सरकार केवल और केवल बैनर और पोस्टर पर काम कर रही है। ये वर्तमान सरकार के सम्मानित मंत्री प्रश्नकाल में इस बात की सहमति देते हैं कि 18 लाख मकानों की बात थी, उसमें साढ़े तीन हजार आवास हमारे शहरी क्षेत्र के थे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, देवेन्द्र जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बोलता हूं, मैंने अभी अंदर भी एक बात कही थी कि ऊंगली उठाने के पहले तीन ऊंगली अपनी तरफ आती है। इसी हाऊस के अंदर पूर्व मुख्य मंत्री का पोस्टर लहराता हुआ पूरे शहर में लगा था, जिसके अंदर कहा गया कि पांच लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, नौकरी दिया और इसी हाऊस में वर्तमान में सदस्य अभी भी हैं, धरम लाल कौशिक जी के प्रश्न के उत्तर में आया कि 19288 लोगों को नौकरी दी गई, तो जो पोस्टर लगा था, वह सही है या विधान सभा में जो उत्तर आया था, वह सही है? ऐसी कई चीजें हैं इसीलिए मैंने कहा ना कि जीवन में ऊंगली उठाने के पहले तीन ऊंगली अपनी तरफ भी आती है। इतिहास के पन्ने वहीं से चालू होते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, वह पांच लाख नौकरियों वाले पोस्टर दूसरे दिन उतर भी गये थे। पोस्टर की राजनीति कौन करता है, वह आज छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, अभी सुशांत जी कह रहे थे कि दृष्टि बाधित हो गये हैं, श्रवण बाधित हो गये हैं। हमने पांच साल में दो साल बेरोजगारी भत्ता दिया। यह सरकार अभी-अभी बनी है और जब बेरोजगार लोग हमारे वित्त मंत्री जी के पास पहुंचते हैं कि रोजगार के लिये क्या कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री जी का वीडियो वायरल होता है कि हमारी सरकार पांच साल के लिये चुनी गयी है, हम चौथे और पांचवें साल में देखेंगे कि बेरोजगारी का क्या करना है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमने 6 महीने के अंदर अपने संकल्प की पूर्ति 60 प्रतिशत से ज्यादा कर दी है। छत्तीसगढ़ की जनता यह देख रही है। अभी एक वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता पूछना चाहती है कि पांच साल तक वही इरादे पूर्ण करने की बात क्यों करते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यदि आप इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे पुराने पन्नों पर या पुराने विषयों पर जाने की बहुत ज्यादा रूचि नहीं है। क्योंकि जनता जानती है कि किसने कैसा काम किया और किसने छत्तीसगढ़ को एक दिशा दी। यदि मैं पूर्ववर्ती सरकार की बात कहूं तो आज किसानों के हित में जितनी भी योजनाएं लागू हो रही है या की जा रही है तो उसके पीछे यदि कोई है तो पूर्ववर्ती सरकार और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा और कोई नहीं है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि जो शहरी

आवास के साढ़े 3 हजार मकान, उन मकानों में सम्मिलित थे, उसका आज तक न कोई पैसा स्वीकृत हुआ है, न प्रक्रिया हुई है, लेकिन पोस्टर बड़े-बड़े लग गये कि हम इतने मकान बना रहे हैं। वह मकान कहां है, यह कोई नहीं जानता। आज आप देखिये कि प्रदेश में क्या हालात हो गये हैं ? आप कानून व्यवस्था देखिये। कानून व्यवस्था चरमरा गयी है। हम देखते हैं कि लोरमी के सघन इलाकों में जंगलों में हमारे आदिवासी भाइयों को वहां के रेंजर मारते पीटते हैं। उनके पीठ की तस्वीर, घायल अवस्था की तस्वीर मीडिया में आती है। हम देखते हैं कि कभी भिलाई में गोली कांड हो रहा है, कभी रायपुर में गोली चल रही है, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं बलात्कार के मामले आ रहे हैं। उसके बाद हम यह समझते हैं कि हम समाज में है तो समाज में कुछ बुराइयां भी होती है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि आप सुशासन की सरकार चला रहे हैं। यह आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं और इसकी सजा कोई और नहीं आप ही भुगतेंगे। आज इस सदन में बैठे हुए हमारे सम्मानित जो पहली-पहली बार के विधायक बने हैं, वह अभी पीठ थपथपा रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं लेकिन वे मन ही मन कितने परेशान हैं, यह इनके चेहरे से बताता है। न कहीं सुनवाई है, न किसी की पूछ परख है और न जाने कितने पॉवर सेंटर बने हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पीड़ा तो मेरे युवा साथी की भी है कि उनके दल में क्षेत्र बदलकर चुनाव लड़वा दिया जा रहा है। उनकी यह भी पीड़ा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- कृपया आप समाप्त करें। 10 मिनट हो गये।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, यदि आप मुझे बोलने का अवसर देंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- देवेन्द्र यादव जी, आपने केवल विधायक के ऊपर बोला। मेरा अंदाजा तो यह है कि अनुपूरक बजट से केवल विधायक नहीं बल्कि तीन नेताओं के अतिरिक्त कोई भी भा.ज.पा. के बाजू वाले मंत्री भी खुश नहीं है। क्योंकि उनका भी कोई विभाग सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, हम कानून व्यवस्था पर बात कर रहे थे। आप देखेंगे कि कर्वधा में साधराम यादव की हत्याकांड होती है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। जब समाज के लोग वहां इकट्ठे होते हैं तो सरकार मजबूरन उसमें आगे बढ़ती है। आप देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में मजदूरों के बहुत सारे मुद्दे हैं। कंपनियों में लेबर एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। हमारे बहुत सारे मजदूर श्रमिक साथियों की कार्य करते हुए, मृत्यु हो जाती है, कोई लेबर कमिश्नर, कोई लेबर कमीशन उनकी कोई पूछ-परख कोई सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध नहीं कराते हैं। उस हिसाब से जो कार्यवाही नहीं चाहिए, वह पूरी तरह लचर दिखती है। हम कहीं दूर की बात न करें। आप देखिए बिलासपुर जिले के सम्मानित विधायक यहां पर हमारे साथ में हैं। महोदय, वहां पर डायरिया का इतना बड़ा इश्यू हो गया, यहां उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। वहां हम लोग देखने गये थे वहां पर मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध नहीं

है। बिलासपुर जिले में कई लोगों की मौतें हो गईं। यह सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारा सुशासन है। यह सरकार साय-साय है। इसका क्या मतलब है ? आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं क्या ? या लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हो ? आपने केवल आरोप लगाने के लिए कुर्सी मांगी थी क्या? या आपको लोगों के काम करने के लिए कुर्सी दी गई है। केवल भाषण या अपने वचन पत्र में वायदे करने के लिए कुर्सी में बैठे थे क्या ?

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने यह गारण्टी ली थी कि प्रदेश के लोगों को आप 500 रूपये में गैस सिलेण्डर देंगे तो आपको इस प्रदेश के लोगों को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर देना होगा।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें। आपको 10 मिनट ज्यादा समय दिया गया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, आपने यह गारण्टी ली थी कि इस प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों की भर्ती होगी तो यहां पर आपको रिक्त पदों की भर्ती करने पड़ेगी। आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। मैं, आपसे इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि पूर्व में यहां पर सम्मानित, वरिष्ठ विधायक ने मेरा नाम लेकर बहुत सारी बातें कहीं और आरोप लगाएं। चूंकि मैं चाहता था कि इस पर चर्चा हो तो हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन ठीक है। यह विनियोग का भी भाग बनता है, मैं यहां पर अपनी बात रख सकता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जो घटना बलौदा बाजार में घटी है आप उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे तो उसके बहुत व्यापक दृष्टिकोण हैं। आपको, इस सरकार को यह समझने की आवश्यकता है कि एक समाज जो शांतिप्रिय है तो सतनाम के रास्ते पर चलता है, वहां पर उनको किस तरीके से उकसा कर, जो हिंसा हुई और वहां जिसने भी, जैसे भी हिंसा की, वह निन्दनीय है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन क्या यह बात सही है कि निर्दोष लोगों के ऊपर भी कार्यवाही हो ? जहां तक मेरी बात है कि मैं वहां पर क्यों पहुंचा ? यह मेरा नैतिक कर्त्तव्य, धर्म है कि कहीं पर अन्याय होगा, अगर कहीं पर भी कोई भी वर्ग अपनी बात सरकार से कहने के लिए आन्दोलन करेगा तो हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हम उनके साथ खड़े थे। आज भी मैं, आपको कहना चाहता हूँ कि यहां पर पक्ष के सभी लोग बैठे हैं। 10 तारीख की घटना के बाद, मैंने उस दिन भी कहा था। मेरी सोशल मीडिया एकाउंट में जो तस्वीर डली हुई है उसके अलावा आप एक तस्वीर ला दीजिए तो आप जो बोलेंगे, मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात का दु:ख है कि इतनी लचर, कमजोर, बेबस सरकार है कि वह एक तस्वीर नहीं ला पायी। लेकिन तुरंत उनके तीन मंत्री खड़े होकर, आरोप-प्रत्यारोप करने में लग गये कि इसने यह करा दिया, उसने यह करा दिया। आप लज्जा करिये। आप लोग आरोप लगाने के लिए सत्ता में नहीं बैठे हैं, आप

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस प्रदेश की समस्याओं का समाधान करने के लिए सत्ता में बैठे हैं। आपका आरोप लगाने का काम नहीं है। आपको यहां की समस्याओं का समाधान करना है और जनता को सुरक्षा देनी है। वहां पर जिन लोगों, कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को जानबूझकर अंदर भेजा गया, जेल में डाला गया। यह गलत है। हम उसकी निन्दा करते हैं। उस समय भी कर रहे थे और आज भी निंदा कर रहे हैं। जहां तक मेरी बात है मेरे नाम पर, यह कहा गया कि देवेन्द्र यादव को 3 नोटिस दिया गया। उन नोटिसों की गहराई को भी जानने की जरूरत है। जब पहला नोटिस दिया गया उसके 5 दिन पहले मेरी टिकट दिल्ली की थी और मैं दिल्ली जा रहा था, मैंने सूचना दी थी।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें। आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट अपनी बात और कहूंगा। उसके बाद जब मुझे दूसरा नोटिस आया तब मैंने उसकी जानकारी दी की मैं उच्च न्यायालय में इस पूरे विषय को लेकर गया हूँ। माननीय उच्च न्यायालय जैसा निर्देश देगा, हम उस दिशा में बढ़ेंगे। उसके बाद न जाने इस सरकार को कितनी जल्दी है इस पर लिपापोती करने का कितना डर बैठा है और न जाने किसका दबाव है ? फिर उसके दो दिनों के बाद मुझे नोटिस दिया गया, मैंने जिसका जवाब दिया कि मैं 17 तारीख की सुबह से लेकर 22 तारीख की सुबह तक पारिवारिक कारणों से बाहर हूँ, मैंने दो महीने पहले जिसकी टिकट करवायी थी। मैं पटल पर उसके दस्तावेज भी रखना चाहता हूँ। वहां मैंने पुलिस विभाग को दस्तावेज दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इस बात का संरक्षण चाहता हूँ कि मेरे टिकट और डिटेल जानकारी देने के बाद भी, मेरे घर जाकर पुलिस ने जो तमाशा किया, विडियो बनाएं। वहां मेरे परिवार के लोग डरे, मेरे कार्यकर्त्ता डरे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इस सरकार को क्या डर है? इस सरकार को उस पूरे विषय में जिन्होंने हिंसा की, उसको पकड़ना चाहिए न कि इसकी राजनीति करनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं अगर इनको मुझे इतना बुलाने का शौक है, मैं तो कल गया भी था, एक ही सवाल को दो घंटे पूछते रहे, मैं उसका जवाब भी दिया।

सभापति महोदय :- आप बैठिये, हो गया, आपकी पूरी बात आ गई। श्री गुरू खुशवंत साहेब।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरी दो मिनट और बात है।

सभापति महोदय :- आपको बहुत समय मिला, आप अपनी बात रख लिये, आप बैठिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि भाजपा के जिलाध्यक्ष को जिसने वहां पर अनुमति ली, उसको आज तक पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया ? यदि बुलाया तो उसको सार्वजनिक करें। भाजपा के न जाने कितने कार्यकर्ता वहां मंच पर बैठे हुए थे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया ? आप इसमें विरोधाभास कर रहे हैं, हम इसको सहन नहीं करेंगे। हम नहीं डरते। हम न्यायपालिका में, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे कहने का मौका दिया, अपने क्षेत्र की भी दो बातें कहूंगा।

सभापति महोदय :- समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- सरकार के बारे में एक बात कहूंगा।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण विषय है, व्यक्तिगत है, बहुत आरोप लगाये हैं, उसके ऊपर बोल रहे हैं। इसलिए उनको थोड़ा समय दीजिए।

सभापति महोदय :- इसीलिए मैंने बहुत समय दिया, उनकी बात को सुना। अब जल्दी समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, बलौदाबाजार के प्रकरण में आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप संरक्षण दें, राजनीतिकरण न हो और इसकी स्पष्ट जांच हो। सी.बी.आई. की जांच हो। मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने भी बात रखूंगा और पार्टी की तरफ से भी इस बात को रखने का निवेदन करूंगा कि इसकी सी.बी.आई. जांच हो और इस पर स्पष्ट जानकारी आये। मेरी अंतिम बात है। भिलाई के अंदर बी.एस.पी. क्षेत्र में हमने पहले बहुत सारे विकास के काम कराये। सरकार बदलते ही उन कार्यों को बंद करा दिया गया। उसके भुगतान रूकवा दिये गये, नये कामों को रोक दिया। चलिये, मान गये कि रोड, नाली नहीं बनाना था, आपको हमसे बदला लेना होगा, आपने करा दिया। लेकिन मैं इस सरकार के माननीय मंत्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि हमारी पूर्व की सरकार ने महिलाओं के लिये सी-मार्केट खोला था, उससे क्या दिक्कत है ? महिलाओं को स्वरोजगार मिलता, उसको भी बंद करा दिया। भिलाई में एक गारमेंट फैक्टरी खुल रही थी, वह पिछली सरकार में आधी पूर्ण हो गई थी, पिछले 07 महीने से वहां पर एक ईंटा नहीं रखा गया। क्योंकि इस सरकार ने उस फैक्टरी को भी बंद करने के लिए कहा है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन सभी विषयों को देखें।

सभापति महोदय :- चलिये, आपका हो गया, आप बैठिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, अंतिम में मैं इस बजट का विरोध करते हुए यह आरोप लगाता हूं कि यह सरकार 40 प्रतिशत कमीशन की सरकार है। यह सरकार में कमीशनखोरी के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रथम अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। यह आपकी सरकार रही होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। यह कमीशन लेकर के काम करने वाली सरकार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि यह सरकार.. इसको विलोपित करायें।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह सरकार 40 प्रतिशत कमीशन की सरकार है या नहीं है ?

श्री केदार कश्यप :- आप करते रहे होंगे, आपकी सरकार करती रही होगी।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने तथ्यहीन आरोप लगाये हैं जो कि गलत हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आप स्वयं आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में होता रहा होगा या हुआ। आप जैसा आरोप लगाये हैं, वैसा आरोप वह भी लगाये हैं।

श्री केदार कश्यप :- आपकी सरकार में होता रहा होगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कमीशन की बात कही है जो तथ्यविहीन हैं। यह सदन के अंदर कहना गलत बात है।

श्री केदार कश्यप :- यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री देवेन्द्र यादव :- यह भ्रष्टाचार से भरी, अपनी गारंटियों से भागने वाली सरकार है।

श्री केदार कश्यप :- कौन सा भ्रष्टाचार ? क्या 07 महीने का भ्रष्टाचार और आपके 05 साल के कार्यकाल का भ्रष्टाचार निकालकर दिखायेंगे ? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ललित चन्द्राकर :- पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कितने नेता लोग बेल मे हैं और कितने अधिकारी जेल में हैं। कमीशन और भ्रष्टाचार कौन किया है ?

सभापति महोदय :- कृपया आपस में बात न करें। आप लोग बैठिये। श्री गुरू खुशवंत साहेब अपनी बात रखें।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, यह बजट आने वाले वर्ष 2047 तक इस भारत देश को विकसित भारत बनाने के लिए है। यह छत्तीसगढ़ का जो प्रथम अनुपूरक बजट है, वह रोडमैप को तय करता है। यह विकसित छत्तीसगढ़ बनने वाला बजट है। इस बजट में अनेक काम दिखाई देते हैं। हर वर्ग को इस बजट में सम्मिलित किया गया है, जिसमें मैं पहले यह बोलना चाहूंगा कि यह लोग अपने आप को किसान हितैषी सरकार बोलती थी, किसानों को संरक्षण करने की बात कहती थी, लेकिन किसानों के बोनस का जो चौथी किश्त है, उसको भी इन्होंने डकार दिया, उसको नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने किसान कृषक उन्नत योजना के माध्यम से ..।

श्री रामकुमार यादव :- गुरू बबा, मैं तुंहर बर ही बोल देवत हौं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भैया, ओ चौथ किश्त हा आप मन के ही बजट मा रिहीस हे। ओला आप मन घोषणा करे रहेओ। हमारी सरकार चौथी किश्त देने का वादा किया था, लेकिन उस समय आचार संहिता लगा था और आपकी सरकार ने देने का वादा किया था।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आपने चौथा किश्त डकार दिया। आपकी सरकार रहते आप दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। आप किसान हितैषी नहीं है, आप किसान विरोधी हैं। (शेम-शेम की आवाज)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, किसी भी सरकार में भुगतान करने की जो नियत तिथि थी, उस समय आपकी सरकार बन गई थी।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- क्या आपको नियत तिथि मालूम नहीं था? यदि चुनाव का समय आ गया था तो आप पहले ही भुगतान कर देते। आप किसानों को किश्तों में पैसा देते थे।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, किसानों को धान का पैसा किश्त-किश्त में मिलता था, किसानों को जरूरत के समय पैसा मिलता था।

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आपकी नीयत अच्छी नहीं थी। आप लोग जानते थे, लेकिन आप लोग चाहते थे कि किसान आगे न बढ़ पाये, इसलिए आप लोग उनको चार किश्तों में बांटकर पैसा देते थे, ताकि वह पैसा उनका कोई काम ना आ सके और आपने चौथा किश्त का पैसा दिया ही नहीं, आपने लोगों ने उसको डकार लिया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गुरू जी, आप किसान मन ला पूछौं कि किश्त मा पइसा मिले हे तेला बताबे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप बैठिये।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, हमारी किसान कृषक उन्नत योजना के माध्यम से 25 लाख किसानों को 13,500 करोड़ रूपये आदान राशि सहित 1 लाख 45 हजार मीट्रिक टन धान के माध्यम से उन लोगों को पैसा दी है।

श्री उमेश पटेल :- संसदीय कार्य मंत्री जी, किसानों को चौथा किश्त दे रहे हैं, यह बता दीजिये।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों को उन्नत बनाने के लिए लगातार काम कर ही है और किसान के बेटों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा नीति को लगातार लागू कर रही है, जबकि ये लोग किसानों के बेटों को गलत रास्ते में डालते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिये थे। हर जगह शराब बिकती थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके शासनकाल में शराब भट्ठी खुल रही है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, अभी शराब खुलेआम बिक रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग टोका-टाकी मत करिये। आप लोग बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोगों ने कहा था कि कोई भी शराब भट्ठी नहीं खोलेंगे। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- आप लोगों ने किसानों पर डंडा बरसाया था, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोगों ने आपके शासनकाल में किसानों के ऊपर डंड बरसाया था। आपके शासनकाल में धमतरी में किसानों के ऊपर डंडा चला था। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- आप लोग किसानों के हितैषी बनना चाहते हैं?

श्री उमेश पटेल :- आप लोगों ने किसानों को जिस तरह से लूटने का काम किया है। आपकी सरकार किसानों की चौथी किश्त खाने वाली सरकार है।

श्री केदार कश्यप :- आपका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। (व्यवधान)

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए । उनको अपनी बात रखने दीजिये । आप बैठिए । यह तरीका ठीक नहीं है । बैठिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, शराबबंदी की बात आयी इसलिये मैं बोल रहा हूं । मैं लगातार डी.एस.पी. से शिकायत कर रहा हूं लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई । (व्यवधान) मैं खुला बता देना चाहता हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपके शासनकाल में मेरे करहीबदर गांव में नया दारू भट्ठी खुला है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिए । बाकी और सदस्य हैं वे बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा में नया दारू भट्ठी खुला है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था । कैबिनेट की बैठक में कहा था, दारू भट्ठी नहीं खुलेगा ।

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए । आपको अवसर मिला था । (व्यवधान)

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आपकी सरकार में कोंटा जैसे क्षेत्रों में... (व्यवधान)

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित ।

(सायं 7.46 से 7.55 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
7.55 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय :- गुरूजी संक्षिप्त करिए। बहुत विषय आ गये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के लिए तो कुछ किया नहीं। इसके अलावा किसानों के गायों जिनको गौ माता मानते हैं । हम सब गौ माता की पूज़ा करते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ पूरा भारत देश गौ माता को मानता है और इन्होंने गौ माता के नाम से भी पूरे छत्तीसगढ़ में गौठान के नाम से भ्रष्टाचार किया। कहीं इन्होंने गौठान नहीं बनाया। गायों को कहीं पर भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिया। उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया, कहीं पर गौठान बना हुआ दिखाई नहीं देता। सिर्फ लीपापोती का काम दिखाई देता है। आज भी हम देखते हैं और पूरे 5 साल इनकी सरकार में हमने देखा कि गौ माता पूरे रोड में हमेशा चलती हुई दिखाई देती थीं। बैठी हुई दिखाई देती थीं। गायों की हत्या होती थी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गुरूजी, अभी घर में हे का?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- ये काम करते हुए और साथ ही एक बड़ा उदाहरण भी है। इनका एक बड़ा कार्यक्रम नया रायपुर में जब हुआ था तो वहां भी इन्होंने जो वहां पर खाने की जो व्यवस्था की थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस खाने को फेंक दिया था और उस खाने को खाकर कई हमारी गौ माता की हत्या हो गई थी। इनके कारण मर गए थे? लेकिन हमारी सरकार गौ माता को संरक्षित करने के लिए गौ अभ्यारण्य बनाने जा रही है, जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया है ताकि गौ माताओं को वहां पर रखा जा सके।

अध्यक्ष महोदय :- अपने क्षेत्र की कुछ मांग रख लें। आपकी विधान सभा के कुछ मांग रख लें, वित्त मंत्री जी बैठे हैं तो अच्छा होगा।

श्री दिलीप लहरिया :- मांग पूरा नहीं होगी, लेकिन आप मांग रखिए। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- वित्त मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की बहुत सारी मांगें लगातार पूरी हो रही हैं। मैं सदस्य लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत सारे चाहे मेरे स्कूल की मांग हो, उन्नयन की मांग हो, करोड़ों रुपए देने की बात हो। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- गुरू जी, आपकी मांग मंत्री वाली है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- चुनाव के पहले आपको वहां के लिए वादा किये थे। उसको मांग लीजिए, इधर आने के लिए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- मैं कुछ और बताना चाहता हूं, बलौदाबाजार कांड के बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं वर्ष 2018 से वर्ष 2023 इस 5 साल में ये सतनामी समाज का हितैषी बनने का भी जो ढोंग रच रहे हैं इस 5 साल में एक रूपये का भी काम गिरौदपुरी धाम सतनामी समाज का सबसे बड़ा आस्था का केन्द्र जहां 1 रूपये का काम नहीं किया गया और आपको ये भी बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपके माध्यम

से गिरौदपुरी धाम में गुरु घासीदास बाबा जी का जो घर है, जो बन रहा था, उसको भी जब वर्ष 2018 में इनकी सरकार आई तो उसको भी रोकने का काम इनकी सरकार ने किया था। ये सतनामी समाज का हितैषी बनने का ढोंग करते हैं और एक बात और बताना चाहता हूं।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में, हर तहसील में जैत स्तंभ बनाने की शुरूआत माननीय बघेल साहब ने की है। उन्हें आप लोंगों ने कैंसिल किया है। आप गलत बात कर रहे हैं, जो काम माननीय बघेल साहब किए हैं, उनको आप लोग रद्द कर रहे हैं, यह मैं सुना हूं। जहां हर तहसील में जैत स्तंभ और हर जगह पूजा अर्चना होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, हो गया। आप समाप्त करिए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- मैं वर्ष 2018 से वर्ष 2023 की बात कर रहा हूं। इन्होंने विकास कार्य तो किया नहीं, अनगिनत जैतखाम को खंडित करने का काम किया। धरमपुरा कांड कवर्धा जिला का आप जानते हो, जहां जैतखाम को जलाने का काम किया। सतनामी समाज ने अपने खून-पसीने से भवन बनाया था तो उसको तोड़े और वहां के सतनामी समाज को लहूलुहान करने का काम इनके पार्टी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अनेक उदाहरण हैं जो इन्होंने काम किया था और साथ ही बलौदाबाजार कांड के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसमें सतनामी समाज का जब ये जैतखाम का कांड अमर गुफा में हुआ तो निश्चित ही हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में तत्काल अड़तालीस घंटे के भीतर में तीन अपराधियों को पकड़ के जेल में डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यदि इसी को हल कर लिए रहते गुरुदेव तो ये बलौदाबाजार जैसे कांड नहीं होता । डुप्लीकेट अपराधियों को पकड़ने में और आपकी सरकार को बोलने में आप नाकाम रहे हैं।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। हमारे समाज को एक डाउट था कि वो तीन अपराधियों के साथ और किसी की संलिप्तता है, जिन्होंने इस कृत्य को इस काम किया है तो इसके लिए हमारे माननीय गृह मंत्री ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी।

श्री दिलीप लहरिया :- आप समाज की जो भावना है, उसके विपरीत बात कर रहे हैं। वे लोग तो फर्जी अपराधी कहे थे, आप उसे सही ठहरा रहे हैं। इसलिए आप समाज के विपरीत बात कर रहे हैं।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- 10 तारीख से पहले 9 तारीख को न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी ताकि न्यायिक जांच हो और एक सही आरोपी और कोई आरोपी अगर इसमें संलिप्त है तो वो भी पकड़ाए, इसके लिए न्यायिक जांच की भी घोषणा कर दी थी। उसके बाद हमारे सतनामी समाज के साथी चाहते थे कि वे उस आंदोलन में हम हमारे जो विष्णु देव साय जी की जो सरकार है, उसका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि न्यायिक जांच होगी और उसमें और जो भी आरोपी इसमें

संलिप्त होंगे, वे पकड़ायेंगे। लेकिन इन लोगों को वह मंजूर नहीं था जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 5 साल में सतनामी समाज के लिए 1 रूपये का काम नहीं किया साथ ही साथ गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के दिन [xx] तक कहा गया। लेकिन इनमें से किसी का मुंह नहीं खुला (शेम शेम की आवाज) । ये सतनामी विरोधी हैं । यही सतनामी विरोधी यह जानते थे कि यदि कोई लिप्त है तो वह भी विष्णुदेव साय की सुशासन में पकड़ा जाएगा । ऐसा न हो इस कारण इन लोगों ने वहां गाड़ियों की व्यवस्था करके, खाने-पीने की व्यवस्था करके भीड़ जुटाई और असामाजिक तत्वों को वहां भेजकर इस कृत्य को किया, इस कांड को करने का काम इन्होंने किया । वह पूर्ण रूप से एक धार्मिक आंदोलन था, आस्था के लिए आंदोलन था । लेकिन बहुत सारे असामाजिक तत्व वहां गए और उनके साथ मिलकर इस कांड को अंजाम देने का काम किया गया गया है । लेकिन आज मैं सतनामी समाज का साथी हूं और संतुष्ट हूं कि इसमें न्यायिक जांच हो रही है और जब न्यायिक जांच होगी तो जो भी संलिप्त होगा, वह पकड़ाएगा (मेजो की थपथपाहट) । आप अगर उसमें गए थे और आप अपराधी नहीं हो तो आपको बयान के लिए बुलाया जा रहा है तो स्वयं जाइए । इसमें राजनीति मत कीजिए ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- उसमें सीबीआई जांच करवाइए ना । हम लोग भी चाहते हैं, सीबीआई जांच करवाइए ना । दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए । समाज के इतने सारे युवा जेल में हैं आप उनसे संतुष्ट हैं ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- यह धर्म का काम है, आस्था का काम है । इसमें राजनीति मत कीजिए । आप बयान दीजिए ।

श्री दिलीप लहरिया :- समाज को इतना मारा जा रहा है । शर्ट उतारकर मीडिया में बताया जा रहा है ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- आप उससे संतुष्ट हैं ।

श्री दिलीप लहरिया :- आपको अच्छा लग रहा है । आप सीबीआई जांच की मांग करवाइए, हम आपसे सहमत हैं ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- असामाजिक तत्वों की न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है । ऐसा गलत काम जिसने किया होगा, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- इतने सारे लोगों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है और आप संतुष्ट हैं ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- कलेक्टर के ऑफिस को जलाना बिल्कुल उचित नहीं है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं । अगर किसी ने गलत कार्य किया है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । वीडियो और फुटेज के माध्यम से जो दिख रहा है उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है । निश्चित रूप से मैं इस बजट का अंत:मन से समर्थन करता हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद् ।

श्री द्वरिकाधीश यादव :- जब बिरनपुर में सीबीआई जांच हो सकती है तो इसमें क्यों नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय :- राघवेन्द्र जी । अपने क्षेत्र तक सीमित रहिए ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- धन्यवाद् माननीय अध्यक्ष महोदय । आज मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के विरोध में यहां खड़ा हुआ हूं । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट और जितने अनुपूरक बजट आते हैं ये सारे कहीं न कहीं जनता की अपेक्षाओं और आक्षांओं के लिए होते हैं । जो बात हम लोग चुनाव के पहले करते हैं, जो वायदे करते हैं ये उसी पर आकर टिकता है । मैं कम समय में अपनी बात कहूंगा, क्षेत्र तक सीमित रहूंगा । जब पहला अनुपूरक आया तब मोदी जी की गारंटी की बात हुई । जब मुख्य बजट आया तो मोदी जी की गारंटी वायदे, किसानों की बात, महिलाओं की बात और जब उस समय कुछ कमियों को उजागर करने की कोशिश की गई तो कहा गया कि हम इसे अनुपूरक में ले लेंगे, आप लोग चिंता न करें । लेकिन उसके बाद एक अनुपूरक बजट आया है तो उसमें वह कमियां है, आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं और इसलिए हम लोग अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं । लगभग 7329 करोड़, 35 लाख, 20 हजार, 700 रूपए का यह बजट आया है । इसमें सबसे ज्यादा पैसा 4,900 करोड़ रूपए महतारी वंदन के लिए दिया गया है । महतारी वंदन पर पहले बात हो चुकी है लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि लगभग 23 लाख महिलाएं जिनको पेंशन मिलती थी, उस 500 रूपए में इसको जोड़ दिया गया है । यह बात न घोषणा पत्र में कही गई थी, न ही लोगों को समझाया गया था और न ही फार्म भराते समय यह बात कही गई थी । कहीं न कहीं वृद्ध महिलाएं आज छलावा महसूस कर रही हैं । कई दिनों से उसका पोर्टल भी बंद कर दिया गया है । क्या पिछले 2 महीने, 3 महीने में जिन महिलाओं की शादी हुई है क्या वे इसकी पात्र नहीं बन सकतीं ? इस बारे में हमको सोचना होगा । लगातार भ्रामक प्रचार, गलत आश्वासन, बलौदाबाजार की घटना हुई, कई बातें सामने आईं, मैं उसमें न जाकर अपने विधान सभा क्षेत्र की एक बात आपको बताना चाह रहा हूं । हम लोग हिंदुस्तान में लॉ में हमारा एक प्रिंसपल है, जिसमें हम कहते हैं कि Innocent until proven guilty. लेकिन आप सबने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें पुलिस द्वारा शर्ट उतारकर घर के सामने पीटा जा रहा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह हुआ है । वह निर्दोष है या नहीं, यह तय करने का काम जज का है, न्यायपालिका का काम है । पुलिस को किसने अधिकार दे दिया कि वह किसी के घर जाकर उनको उठाकर इस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत लोग थे जो उस दिन वहां नहीं गये थे, उसके बाद भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं इसके बारे में

सिर्फ एक बात कहूंगा। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय चौरी-चौरा कांड हुआ। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, गांधी जी बहुत ज्यादा दु:खी थे, क्योंकि वहां पर तीन, चार सिविलेंस और 22 पुलिस वालों की मौत हुई थी, वह आजादी की लड़ाई थी। उसके बाद से इतनी बड़ी घटना, पुलिस थाना जलने की और कप्तान के भाग जाने की स्वतंत्र हिन्दुस्तान में नहीं हुई है। आज जो बलौदाबाजार की घटना है, यह किसी सरकार विशेष या पार्टी विशेष के अलावा छत्तीसगढ़ के उपर एक सवाल है और हमें इस बात को समझना होगा। हम गलत तरीके से निर्दोषों को पनिश नहीं कर सकते। इसके लिए इतिहास हमेशा छत्तीसगढ़ के इस दिन को याद रखेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट में अगर जांजगीर जिले की बात करूं। ओ.पी. चौधरी साहब हमारे वित्त मंत्री हैं, वे हमारे यहां कलेक्टर साहब भी रहे हैं, कलेक्टर साहब के बाद वे आज हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं। आज कोयला जितना हमारे केस के मड़वा और जहां-जहां आ रहा है, कोरबा जिले का कोयला भी हम लेते हैं, धान भी हम लगाते हैं, राखड़ भी हम खाते हैं लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने लगातार याचिकाएं लगाई। मैंत्री जी बैठे हैं, बहुत बार बोला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर अनुरोध करूंगा, हम लोगों को बायपास सड़कों की जरूरत है। अकलतरा, बलौदा और जो उसके बीच में गांव पड़ते हैं, वहां पर सामने स्कूल है, हम लोगों को बायपास की जरूरत है। मैं दो दिन पहले की एक इंसीडेंट बता रहा हूं जिसमें एक ओव्हरलोड ट्रक गांव अंदर चला गया, एक इंसान की मृत्यु हो गयी, एक जो दूसरा लड़का था, उसका जबड़ा टूटा हुआ था, जब वह ठीक होकर वापस आया, उसने पेट्रोल पंप पर जाकर परसों अपने आपको आग लगा लिया। यह एक बहुत बड़ी घटना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी हमें बायपास सड़कें दे दें। इसके पहले भी बजट में आया था लेकिन कहीं न कहीं वह पास नहीं हुआ। हमने विधान सभा के समय लगभग 15 से 20 जानें खोई हैं। ग्रामीण सड़क के लिए 40 करोड, ग्रामीण विशेष सहायता के लिए 5 करोड़ रूपए आया है लेकिन PMJSY, MMJSY बिलासपुर संभाग में और जांजगीर जिले के लिए पैसा प्रावधान नहीं है। मंत्री जी, हमें बायपास की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी कर्मचारी लगातार अपने डी.ए. को लेकर विरोध में है। उनका 46 प्रतिशत डी.ए. है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। हाउस रेंट एलाउंस 7वें वेतन आयोग के अनुसार नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना होगा। यात्रा भत्ता कई साल से समीक्षा नहीं की गयी है। अभी कटघोरा में दो दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी, एक इंसीडेट हुआ है, जिसमें वहां पर सांप कांटने से 3 लोगों की मृत्यु हुई, चक्काजाम किया गया और उसके बाद दो का ईलाज जारी है। हमें संज्ञान लेना होगा, जांजगीर जिले में जिस तरीके से डायरिया और मलेरिया फैला हुआ है, हम लोगों को उसमें जरूरत पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग 44 प्रतिशत का फॉरेस्ट कवर अपना स्टेट कहते हैं। इस बार कृषि में 8 करोड़, पौधारोपण के लिए 1 करोड़ 77 लाख, बांस के लिए 10 लाख, बिगड़े वनों के सुधार के लिए

20 करोड़, उसके अलावा 5 करोड़, लघु सिंचित के लिए हमने लगभग 4 करोड़ दिया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी दो करोड़ दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हसदेव बांगो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें अकलतरा और जांजगीर चांपा का पूरा पानी हसदेव बांगों से मिलता है। आज जब हम 3100 रूपये की बात करते हैं, इसके लिए मैं भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 2500 देकर लगातार उस कीमत को बढ़ाने का काम किया और आज जब हमें 3100 मिला लेकिन उसके अलावा हमें जरूरत हैं। हमें आगे आने वाले समय में कृषि की सुविधा कहां जाएगी, अगर हम विजन 2047 की बात कर रहे हैं तो प्रावधान कहां है ? किसी भी लिफ्ट एरिगेशन का कहां प्रावधान है ? किसी भी सर्वे करने का कहां प्रावधान है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर अरपा भैंसाझार की बात नहीं कहना चाहूंगा लेकिन आपके संज्ञान में मैं एक बात लाना चाहता हूं। मुझे अधिकारियों ने एक मैसेज किया कि 20 तारीख को आदरणीय मंत्री जी वहां पर आएंगे और एक बैठक लेंगे, चूंकि वह सवाल मैंने एक्सचेकर का लगाया था, मुझे उसमें बुलाया जाएगा। 17 तारीख को मुझे मैसेज किया गया कि उस मीटिंग का स्वरूप चेंज कर दिया गया है और अब आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमें आपका इतना संरक्षण चाहिए या तो हमें बुलाया जाए, अगर नहीं आना है तो हमको पहले से मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे पास यह लिखित में है। उनके द्वारा यह मैसेज आया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी चीज अपने क्षेत्र का कहना चाहूंगा। हसदेव का जो रेहर नदी है, गेनजेंग और चोन्नई नाला है, इसी से हसदेव में पानी आ रहा है। नकियामोर्गा 1 से 4 गिद्धपुरी पतुरिया और पेंगानी। अगर हम इस पूरे क्यूमिलेटिव माईनिंग को करते हैं। तो 233 स्कवेयर किलोमीटर का डेंस फारेस्ट और 66 किलोमीटर का वैरी डेंस फारेस्ट, हम लोगों का खराब हो रहा है और इसी से हम लोगों को पानी मिलता है । अध्यक्ष महोदय, जरूरत है कि जल्द से जल्द इसका प्रावधान किया जाये, इसका आल्टरनेविट जांजगीर जिले में क्या हो सकता है, इसको हम लोग वहां पर बात करें । सभापति महोदय, जब आप सरकार में थे, आप ही के द्वारा एक पहरिया कॉलेज वहां एनाउँस किया गया था, मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ, लेकिन वह नहीं हो पाया है, आपसे निवेदन है कि उस पर बात करें ।

अध्यक्ष महोदय :- गजेन्द्र यादव जी ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी चीज निवेदन करूंगा कि अकलतरा में एक सी.सी.आई. फैक्ट्री स्थिति है, जिसमें 1 हजार एकड़ संरक्षित है, अभी उसमें स्क्रैप निकाल लिया गया है, वह जमीन बंजर हो चुकी है । छत्तीसगढ़ में एक ड्राई पोर्ट की आवश्यकता है, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया था, अगर हम वहां ड्राई पोर्ट खोलते हैं तो वहां हमारे पास जमीन भी

उपलब्ध है, नेशनल हाईवे पर भी हैं, बाम्बे हावड़ा रूट पर भी है, मैं इसी बात को लेकर आपने जो समय दिया है उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- संक्षिप्त दो मिनट में गजेन्द्र जी ।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- अध्यक्ष महोदय, आपने जो अनुपूरक बजट वर्ष 2024-2025 के लिये बोलने का अवसर दिया है, मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं महतारी वंदन, रामलला दर्शन की बात माननीय सदस्यों ने कह दी है, मैं उसको आगे बढ़ाते हुये श्रद्धेय विष्णुदेव साय सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने इसको और आगे बढ़ाते हुये इस अनुपूरक बजट में वृद्ध और नि:शक्तजन, विकलांगों को भी आपने तीर्थाटन योजना में जोड़ा है, उसके लिये आभार व्यक्त करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने मुख्यमंत्री काल में श्रवण कुमार बनकर एक तीर्थाटन योजना लाया था, इसको माननीय विष्णु देव साय सरकार आगे बढ़ा रही है, उसको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दृष्टि और श्रवण बाधितों के लिये अनुपूरक बजट में रायगढ़ और जगदलपुर में जो हॉस्टल निर्माण बजट में लिये हैं, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि शहरों में बड़ी संख्या में दृष्टि और श्रवण बाधित ऐसे विकलांग बच्चे हैं, हम लोग विधायक हैं, बहुत से लोग ईलाज के लिये आते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिये आते हैं, आपसे आग्रह है कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई के बीच में एक बड़ा सेंटर दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित छात्राओं के लिये सुविधा हो ।, रायगढ़ में तो आप कर रहे हैं, जगदलपुर में भी है, अत: इस पर ध्यान देंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं विष्णु देव साय सरकार का आभार व्यक्त करूंगा और बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि अटल वृद्ध अभ्युदय योजना स्टेट एक्शन प्लॉन के तहत लिया है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में ज्यादातर देखा गया है कि वन फेम्ली, वन चाईल्ड परम्परा विकसित हो रही है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनके जो वृद्ध हैं, घर में कोई रहता नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं रहता है या रिटायरमेंट के बाद ऐसी स्थिति रहती है कि बच्चा ध्यान नहीं देता है, सीनियर सिटीजन बहुत सारे अभावों में जीते हैं और सुविधाओं के लिये तरसते रहते हैं, आपने उसे स्टेट एक्शन प्लॉन के रूप में लिया है, मैं उसके लिये बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करता हूँ कि ग्रामीण एरिया में तो कहीं न कहीं अपने वृद्धजनों को सम्मान करते हैं, लेकिन शहरों में देखरेख करने वाला नहीं है, यह जो स्टेट एक्शन प्लान जो चालू कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरूआत बड़े शहरों से जैसे रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव से हो, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों के लिये 2.5 लाख से लेकर 8 लाख तक का प्रावधान किया है और एक बड़ा विषय गौठान का है, जिस पर हमारे माननीय सदस्यों ने बात कही है । अध्यक्ष महोदय, हम लगातार देख रहे हैं कि लोग गौ वंश पालना भूल गये हैं, गाय सड़क पर रहती है और बछड़े सड़क पर

दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या कुत्ता उस जानवर को बहुत नोंच-नोंच कर खाते हैं, यह बहुत दुर्भाग्यजनक दृश्य होता है । अध्यक्ष महोदय, आपने गौवंश की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है, उसके लिये जो सोचा है, अत: मैं आभार व्यक्त करता हूँ । सभापति महोदय, जो लगातार गौवंश में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, उसे रोकने के लिये सरकार सार्थक पहल करे तो वह इससे रूकेगी । अध्यक्ष महोदय, आपने इस बजट में गौ अभ्यारण्य का प्रावधान किया है, उसके लिये बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने इस बजट में मक्का खेती के लिये 87 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिये आभार व्यक्त करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ कि पहले बस्तर में ज्यादातर मक्का खेती होती थी, लेकिन फसल चक्र परिवर्तन आपके समय जो प्रारंभ हुआ, उसका एक अच्छा प्रभाव हमारे दुर्ग जिले में बड़ी संख्या में लोग मक्का खेती करते हैं । वहां पर मात्र सहकारी सोसायटी समिति, नारधा और पाटन, दुर्ग जिले में दो ही जगह मक्के की सरकारी खरीदी होती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मक्का की खेती प्राथमिक सहकारी सोसायटी में ज्यादा से ज्यादा दुर्ग जिले में भी खुलवाएं, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने समय में सहकारी सोसाटियों को कम्प्यूटराईज करने की पहल की, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने बढ़ावा दिया । आज जो पैसा सांय-सांय एक बटन में हर किसानों के खाते में, 8 लाख किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, उसकी देन आप हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है । अभी इस बजट में आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है । शहर के लोग पहले आटो रिक्शा में घूमते थे, बड़ी समस्या रहती थी। आपने ई रिक्शा का प्लान इस प्रदेश को दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं । उसको आगे बढ़ाते हुए अभी हरित परिवहन के तहत ई बस सेवा आप इस योजना के तहत प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आपने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा को लिया है । मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करता हूं कि जो हमारी हरित परिवहन योजना है, इसको हम पहले शहरों में चलाएं, गांव में सवारी मिलने में दिक्कत होती है ।

श्री रामकुमार यादव :- मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन के मांग कर दे न ।

श्री गजेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पहले जमाने में पूरे शहरों में आटो रिक्शा चलता था, लोग धुंआ से परेशान थे, आज वह आटो रिक्शा शहरों में लगभग समाप्त हो गया है । आटो ने ई रिक्शा का स्वरूप ले लिया है, आज बहुत आसानी से सहुलियत भरा आवागमन का साधन हो गया । ई रिक्शा को भी हम बहुत अच्छे से करें तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा जो महानगर है, उसके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक निवेदन करता हूं कि आपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए सब्सिडी दी है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही साथ सोलर प्लांट के लिए आपने हॉस्टलों

में, लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाऊस में जो प्लांट स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको और आगे बढ़ाते हुए जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं, नगर पालिका के जो मुख्यालय हैं, उसमें यह सोलर प्लांट लागू हो, जिसमें बिजली बिल की भी बचत हो, मैं यही आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों का विरोध करते हैं और इसमें 7329 करोड़, 35 लाख, 62 हजार, 700 रूपए का अनुपूरक है । इस अनुपूरक में ज्यादा कुछ है भी नहीं । क्योंकि 4900 करोड़ रूपए तो केवल महतारी वंदन का है । थोड़ी सी राशि है, जिसमें कुछ निर्माण कार्य हैं, कुछ स्वीकृतियां हैं, उसकी चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सरकार बनते ही लगातार कर्ज लेते जा रहे हैं, उधार लेकर घी पी रहे हैं और अभी तक इन 7 महीनों में इस सरकार ने 25569 करोड़ रूपए का उधार लिया है । हम लोगों ने 5 साल में 50 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया और इन्होंने 7 महीनों में ही 25 हजार करोड़ से अधिक की राशि लोन ले ली । डबल इंजन की सरकार की बात होती है । भारत सरकार से जो सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं ले पा रहे हैं । या तो इनकी सुनते नहीं हैं या ये बोल नहीं पाते । अभी भी केन्द्रीय बजट आया है, सारा पैसा आंध्रप्रदेश और बिहार को चला गया। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को कुछ नहीं मिला ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बनते ही कैबिनेट में जो फैसला लिया गया कि 18 लाख आवास बनाएंगे, पूरे प्रदेश में होल्डिंग लगी हुई है और आज ही जब मैंने शहरी विकास मंत्री जी से प्रश्न किया तो पता चला कि इस वित्तीय वर्ष में एक भी स्वीकृति में नहीं हुई है और यही हाल करीब-करीब पंचायत विभाग का भी है, उसका भी प्रश्न लगा था, उसमें भी कोई स्वीकृति नहीं है । इस अनुपूरक बजट में भी इसका उल्लेख नहीं है तो पहले कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में आजतक क्रियान्वयन की दिशा में आप एक कदम नहीं बढ़े हैं और 18 लाख आवास की चर्चा पूरे प्रदेश में कर रहे हैं । हर बैठक में, हर सभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा यह कहा जाता है कि 18 लाख आवास बनेंगे। लेकिन अनुपूरक में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्रियान्वयन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप गरीबों के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? एक तरफ अनुपूरक में कुछ शामिल नहीं, दूसरी तरफ जो बजट में शामिल है, उसका भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अनुपूरक में देखेंगे तो पता चलेगा कि आपने नाम बदल दिया। हम लोगों ने भूमि श्रमिक न्याय योजना नाम दिया था, आपने उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से किया है। आपने कहा कि प्रति महीने 10 हजार रूपये देंगे, आपने बजट में 500 करोड़ रूपया रखा है। लेकिन आप कब उसका वितरण करेंगे ? उनको 7 हजार रूपये मिल रहे थे, अब वह भी मिलना बंद हो गया है। आपने 10 हजार रूपये का सपना दिखाया, लेकिन उसकी शुरूआत नहीं हो रही

है। उसी प्रकार से प्रथम अनुपूरक अनुदान में देखेंगे कि आपने बेरोजगारी भत्ता जारी रखा, उसमें 250 करोड़ रूपये का उल्लेख है। लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। हमारे साथी लोग तो गैस सिलेण्डर की बात कर रहे थे। जो बजट में, आप उसको तो दो। उसका वितरण करने के लिए किसने रोका है ? आपने विधान सभा से पारित करवाया है, आपने विधान सभा के अनुमति ली है, आपने राज्यपाल महोदय से हस्ताक्षर करवाया है और आपको यह अधिकार मिला है तो उसके बाद भी आपने गरीबों को देना बंद कर दिया है, नवजवानों को देना बंद कर दिया, गरीबों को देना बंद कर दिया है। आपने आवास बंद कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, आप जो कहते हैं, वह तो करें। आप तो मोदी जी की गारन्टी देते हैं, आप विष्णु जी के सुशासन की बात करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है ? उसके विपरीत इस पवित्र विधानसभा में जिन विषयों को पारित करवाया है, आपने जिनके लिए बजट स्वीकृत कराया है, आप कम से कम उसको तो कर लेते।

अध्यक्ष महोदय, अब तो हमारे बृजमोहन भाई तो हैं नहीं, आपने उनको षड़यंत्र पूर्वक सांसद बनाकर भेज दिया है। वह जाना भी नहीं चाहते थे, वह छः महीने रहूंगा बोले, आपने उनसे जबर्दस्ती इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने घोषणा की थी कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी, आपने इसी सदन में घोषणा की थी, लेकिन उस भर्ती का कोई अता-पता नहीं है। वित्त मंत्री जी का बाहर एक वीडियो देखने को मिलता है कि भूल जाओ, कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है। केवल 31 सौ रूपया मिलेगा और महतारी वंदन योजना का पैसा मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो पढ़े-लिखे हैं, काबिल हैं, आई.ए.एस. हैं। विष्णु जी, हम लोग भी आई.ए.एस. के साथ काम कर चुके हैं। अब आप काम कर रहे हैं। आप नये वित्तीय स्त्रोत बनाने की व्यवस्था करें, खर्च करना तो आसान काम है। सवाल यह है कि आप वित्तीय संसाधन तो जुटाईये। आप कर्ज लेते जायेंगे, आपकी सरकार का एक साल पूरा नहीं हुआ है, साढ़े पच्चीस हजार रूपये कर्ज ले चुके हैं। फिर अक्टूबर-नवम्बर का महीना आयेगा, आप फिर बाजार से पैसा लेंगे। कैसे चलेगा ? आपसे अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है। आपने जो विधानसभा से पारित करवाया है, आपने जो कैबिनेट से पास किया है, आप उसका भी पालन नहीं करा पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 हजार शिक्षकों के बारे में बात हो गई, व्यायाम शिक्षक की अलग मांग है। आपने घोषणा-पत्र में सौ दिन की गारन्टी दी थी। रसोईयां हड़ताल में हैं। आपने उनका वेतन डेढ़ गुना करने की बात कही, वह नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे मोदी जी ने भी कहा था कि हम लोग सौ दिन की योजना बना रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार बनी भी है, 45 दिन से ऊपर हो गया है, 50 दिन से ऊपर हो गया है, बजट भी आ गया, लेकिन उस सौ दिन का पता नहीं है। आप जो सौ दिन की बात बोले थे, उसका क्या हुआ ? आपने कहा था कि हम सौ दिन में ये-ये करेंगे। उसमें एकाध काम तो कर देते।

अध्यक्ष महोदय, आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, अभी गोबर घोटले की बात कर रहे थे। गौठान में घोटाला हो गया। आपको जांच करने से किसने रोका है ? आपकी सरकार है, आपकी एजेंसी है, सब कुछ आपका है। आपने क्या पाया ? गोबर घोटाला में क्या होना है ? पेमेन्ट आनलाईन जा रहा है। वर्मी कम्पोस्ट आज भी बना हुआ रखा हुआ है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी सहित संपूर्ण मंत्रिमण्डल से यह पूछना चाहता हूं कि आपने गोबर खरीदी योजना को किस तारीख और किस आदेश के तहत बंद की? आप सदन के पटल पर उस आदेश की कॉपी को रख दीजिए। आपने गोबर खरीदी बंद की, लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि किस विभाग से उसका आदेश निकला? बिना आदेश के गोबर खरीदी, गौठान सब बंद हो गया। आपने उसकी जांच की घोषणा कर दी। आप जांच की घोषणा करें। उसकी जांच होती भी है। चाहे स्कूल शिक्षा विभाग की जांच हो, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की जांच हो या किसी भी विभाग की जांच हो तो क्या आप उस विभाग को बंद कर देते हैं? क्या आप उसकी योजना को बंद कर देते हैं? जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप लग रहा है तो क्या आपने उसको बंद कर दिया? क्योंकि वह गरीब की आवाज नहीं है, इस कारण से आपने गोबर खरीदी का पेमेण्ट नहीं किया है और जो वर्मी कम्पोस्ट बना है, उसका पेमेण्ट नहीं किया है। उसका क्या दोष है? आप उसका पेमेण्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कम से कम आप उसका पेमेण्ट तो कर दीजिए। पैसे रखे हुए हैं, लेकिन वह पैसे कहां जा रहे हैं? गौठान का शेष लगा है लेकिन उस पैसे का क्या उपयोग है? आप केवल आरोप लगा रहे हैं। पी.एस.सी. घोटाले पर मैंने स्वयं कल प्रश्न लगाया था। कल मेरा 17-18वें नंबर पर प्रश्न था। मेरा स्वयं का प्रश्न है कि पी.एस.सी. घोटाले का क्या हुआ? आप लोक आयोग में सुधार करेंगे, उसका क्या हुआ? आपने जो सदस्य नियुक्त किये थे, उसमें एन.टी.ए. के चेयरमेन स्वयं फंसे हुए हैं और उनको आपने सलाहकार रखा हुआ है। आप पी.एस.सी. की परीक्षा को यू.पी.एस.सी. की तर्ज पर करेंगे और यू.पी.एस.सी. के चेयरमेन ही इस्तीफा दे रहे हैं। वहां एक-सेक घोटाले नजर आ रहे हैं। आप पी.एस.सी. की परीक्षा को यू.पी.एस.सी. की तर्ज पर करेंगे तो क्या अभी जैसे हो रहा है, वैसे ही करेंगे? आप जो पी.एस.सी. घोटाले की जांच की बात कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? रोज हल्ला हो रहा है कि शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि उसकी जांच कर रहे हैं। पहले आई.टी. ने उसकी जांच की, फिर ई.डी. ने जांच की और वह सब बंद हो गया तो अब ई.ओ.डब्ल्यू. जांच कर रही है लेकिन सरकार ने क्या फैसला किया है ? आपने नकली होलोग्राम का आरोप लगा दिया। ठीक है, लेकिन उस होलोग्राम का सप्लायर अभी भी वही है। आपने कहा कि इसमें प्लेसमेंट एजेंसी गड़बड़ी कर रही है, लेकिन वह प्लेसमेंट एजेंसी वही है। जो सप्लाई कर रहे हैं, वह भी वही हैं। अध्यक्ष महोदय, या तो वह केवल राजनीतिक आरोप था या तो आप भी उसमें लिप्त हैं। (मेजों की थपथपाहट) (शेम-शेम की आवाज) पिछले 7 महीने से आप भी उसमें लिप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पता नहीं कि पुलिस विभाग को क्या हो जाता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो नक्सली हमले की शिकायत,

फर्जी एन्काउंटर, फर्जी गिरफ्तारियां होती थीं। साय जी, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मड़कम हिड़मे नाम की 16 साल की एक जवान लड़की थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर में एक दर्जन गोलियां लगी थीं, लेकिन मजाल है कि उसके कपड़े में एक भी छेद हो। ऐसी गोली आज तक दुनिया में किसी ने नहीं चलाई है कि उसके शरीर में दर्जन भर गोलियां लगी हों और उसके कपड़े में छेद न हो। वही काम अभी और कर दिया। अभी एक साथी ने कहा कि नकली होलोग्राम पकड़ा गया। बहुत बढ़िया बात है। उसकी प्रक्रिया क्या है कि जिसके खेत में जाए, जिसके घर में जाए, जिसकी बाड़ी में जाए तो कम से कम उसको साथ में रखें। पहला, किसी के घर में जाते हैं। दूसरा, जो जे.सी.बी. लेकर गये और 6 फीट गहरा खोदे। मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस कमाल के काम को कर दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, वह जो पुट्ठे का कार्टून है वह 6 फीट नीचे से जे.सी.बी. से खोदकर निकाला गया। समाचार पत्र और यूट्यूब में जो फोटो छपी, उसके एक-एक शब्द को आप पढ़ सकते हैं। मतलब, मिट्टी में 6 फीट नीचे दबा हुआ कार्टून खराब नहीं हुआ। (हंसी) कोई टीने या लोहे का बक्सा नहीं है, वह बिल्कुल साबूत निकला। अध्यक्ष महोदय, जब भी पुरातात्विक खुदाई होती है, तो बारीक छीनी, हथौड़ी से खोदते हैं, ताकि कोई मूर्ति खराब न हो लेकिन यहॉ जे.सी.बी. से खोदे और कार्टून बिल्कुल साबूत निकला। उसमें स्क्रेच नहीं है और मजेदार बात यह है कि जलाये गये होलोग्राम में मिट्टी का एक टुकड़ा भी नहीं है, एक कंकड़ तक नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ही कर सकती है। ये स्थिति इस प्रदेश की है। फिर आरोप लगा कि राईस मिल में बड़ा घोटाला हुआ, 120 रुपए मिलिंग चार्ज! आपने बंद क्यों नहीं कर दिया, 40 रुपए क्यों नहीं किया। सरकार बनते सबसे पहले वही काम करना था। तब तो आप आरोप लगाने के अधिकारी थे, लेकिन आरोप लगाए कि 20 रुपए प्रति क्विंटल ले रहे हैं, 120 रुपए मिलिंग चार्ज दिया गया। आप भी 120 रुपए दे रहे हैं लेकिन सुनने में आ रहा है कि वह 130 रुपए हो गया है। आरोप आप 20 रुपए का लगाए और वसूली 30 रुपए की हो रही है। पूरा प्रदेश जान रहा है क्योंकि देने वाले सब बता चुके हैं। कौन-कौन लोग थे, उसके बारे में सब जानकारी है लेकिन बोले कौन, डबल इंजन की सरकार है, जांच एजेंसी तो वही है। एफ.आई.आर. तो सबमें हैं, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? अभी धर्मजीत भैय्या बढ़िया बोले कि ये FL-10 बंद कर दिया। टेंडर आपने किया हुजूर, टेंडर करने की अलग वसूली। लहर गिनने का काम, लहर से पैसा वसूलने का काम जो बीरबल ने सिखाया था ना। हॉ, बिल्कुल, चूना मार्का लगाओ या लहर गिनो तो टेंडर करने का अलग, निरस्त करने का अलग, देने का अलग, क्या चल रहा है? सब भोग लग रहे हैं, पंचामृत चल रहा है। अब भोग बंट रहा है उड़ीसा में, झारखंड में। अध्यक्ष महोदय, या तो आप जांच करें, कार्रवाई करें लेकिन अब आरोप लगा दिए, मजबूरी है सब एक-एक करके घोषणा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं-जांच कर रहे हैं लेकिन रिपोर्ट क्या है? कुछ नहीं होना है। प्रदेश में यह स्थिति मत लाइए। गौठान के बारे में आप बोल दिए, आरोप लगा दिए। बढ़िया है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? आपके पास है, 07 महीना हो गया। रीपा में आपने जांच की घोषणा

कर दी, क्या हुआ? लेकिन उसको चलाओ तो। अब संकोच है कि अब करें क्या, आरोप तो लगा दिए हैं। रीपा बना हुआ है, नौजवान इंतजार कर रहे हैं लेकिन आपने लोगों का नुकसान कर दिया। जितने भी काम कर रहे थे, वह बंद हो गए। जितने सी-मार्ट बनाए थे, वह बंद कर दिये। जितनी खरीदियां हो रही थीं, वे बंद हो गईं। जितने स्व सहायता समूह शासन के विभागों में सप्लाई कर रहे थे, उन सबको बंद कर दिया। विष्णु जी, इन अधिकारियों के चक्कर में आप मत पड़िए। इनको काम करना ना पड़े, वह सबसे अच्छा है क्योंकि तनख्वाह मिलनी है, कुर्सी में बैठे रहेंगे, ए.सी. रूम में रहेंगे। इनसे काम लीजिए, फील्ड में दौड़ाइए। यदि गौठान गलत है तो इसे आप सुधारिए लेकिन स्ट्रक्चर बना हुआ है। कौन अंधा कहता है कि वहां स्ट्रक्चर नहीं बना है? स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको जो सुधार करना है, आप करिए, क्योंकि वह नई व्यवस्था थी। मैं पहले भी बोलता था कि नई व्यवस्था है, इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। आप उसमें करिए। आपके उस फंड में पैसा भी है लेकिन आप गरीबों के पैसे को मत मारिए। उनको पेमेंट तो कर दीजिए। अभी बरसात लग गई, रोपा लगने के बाद क्या स्थिति है। आप अभी बिलासपुर चले जाईये, एक दिन में 18,000 जानवर मरे पड़े मिल रहे हैं। जानवरों की तस्करी हो रही है। यही स्थिति रही तो छत्तीसगढ़ में जानवर नहीं मिलेंगे। चाहे वह उड़ीसा बॉर्डर से जाये, चाहे महाराष्ट्र बॉर्डर से जाये, चाहे आपके जिले से जाये, लेकिन लगातार मवेशियों की तस्करी चल रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस व्यवस्था को इसलिए शुरू किया था ताकि हमारी फसल बचे, इसकी शुरूआत वहां से हुई है। यहां जो फसल चराई है, रायपुर के Cow catcher पकड़ते थे और चाहे अभनपुर के गांव हो, चाहे धरसींवा के गांव हो, चाहे पाटन के गांव हो, वहां छोड़ देते थे। वहां जानवर गये तो दूसरे गांव उठा के ले गये, फिर दूसरे गांव से तीसरे गांव का झगड़ा हो रहा है। अभी फिर झगड़ा शुरू होगा। आप इस संकोच को छोड़ दीजिये। यह सदन है, हम इस सदन में विरोधी दल में है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हम सब का यह उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ समृद्ध छत्तीगसढ़ बने, यहां के लोगों को सुविधा मिले, यहां के नौजवानों को रोजगार मिले। आज आपने स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म कर दिया। पांच साल में उल्टी, दस्त, मलेरिया से लोगों की मौत नहीं हुई थी। लेकिन आपकी सरकार में यह पहली बरसात में ही लोगों की मौत होना शुरू हो गयी। हर जिलों में हजारों की तादाद में उल्टी, दस्त की शिकायतें मिल रही हैं। हमने हॉट बाजार क्लिनिक योजना की व्यवस्था की थी, इसलिए कि यहां के लोग हॉस्पिटल भले न जाये, लेकिन बाजार जरूर जाते हैं। यह छत्तीसगढ़ की परंपरा है, हमारे आदिवासियों की परंपरा है। वे वहां जाते हैं तो वहीं जांच करा लेते हैं, उसमें 10 प्रकार के खून की जांच मुफ्त में हो रही थी। आपने सब बंद करा दिया। आपके पास तो टी.बी. की दवाई भी नहीं है। अभी हमारे साथी ने कहा कि आपके पास सांप के काटने की एंटी वेनम वैक्सीन भी नहीं है। सांप के काटने से कटघोरा में तीन लोगों की मौत हो गयी और दो लोगों का ले देकर इलाज शुरू हुआ। यह स्थिति मत बनाईये। आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने इस पवित्र सदन में जो वादा किया है, आप उसे तो पूरा करिये। चाहे

शिक्षकों की बात हो, चाहे व्यायाम शिक्षकों की बात हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो, चाहे आपके घोषणा पत्र में गरीब लोगों की बात हो। जब आपकी सरकार थी तो आपने 15 सालों में रसोइयों का मानदेय 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,200 रूपये किया था। जब हमारी सरकार बनी तो हमने उसको बढ़ाकर 2,000 रूपये किया। फिर आपने 100 दिनों के भीतर 3,000 रूपये करने का वादा किया। आप कम से कम उसको तो पूरा कर दीजिये। अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि सब सदस्य जानते हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। वैसे भी सप्लीमेंट्री बजट में बहुत कम राशि रहती है, लेकिन सारे लोग बोल रहे हैं कि सब जगह unrest है। पूरे प्रदेश से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह खबरें आ रही है। सत्ता पक्ष के लोग मांग के रूप में रख देते हैं, हम लोग शिकायत के रूप में कह देते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में unrest है। आपने केवल धान के किसानों को 3,100 रूपये दे दिया, लेकिन जो मिलेट्स वाले किसान हैं, उनका क्या होगा ? जो फल सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, उनका क्या होगा ? उनको कुछ नहीं मिलेगा। हम दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। आपने महुआ खरीदी बंद कर दी। आपने लघु वनोपज खरीदी बंद कर दी। क्या आदिवासी केवल तेंदूपत्ता तोड़ते हैं? हम लोग 65 प्रकार के लघु वनोपज खरीद रहे थे। हम कोदो, कुटकी, रागी खरीदते थे। आपने सब बंद कर दिया। यह कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन कहां होता है ? आदिवासी अंचलों में होता है। लेकिन आपने बंद कर दिया। आदिवासी होकर आदिवासियों का अहित ? आप कम से कम यह तो न होने दे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको जितनी जांच कराना है, आप करा लीजिए लेकिन दुर्भावना से मत कराईये। जब जिसने जैतखाम को आरी से काटा, उस समय समाज के लोगों ने सी.बी.आई. जांच की मांग की थी, यदि आप उसको मान लेते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आपके अधिकारी के पास यह निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उसे देखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको राजनीतिक निर्णय लेने होंगे। आपने निर्णय नहीं लिये, इस कारण हमारे ऊपर यह कलंक लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कलेक्टोरेट कम्पोजिट बिल्डिंग में आग लगी, तोड़-फोड़ हुई। सरकार आपकी हो या किसी की भी हो, लेकिन यह कलंक तो लग गया। यह आज तक कभी नहीं हुआ था। यहां इतनी बड़ी-बड़ी नक्सली घटनाएं हुईं। आप 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, मैं 5 साल तक रहा लेकिन नक्सली क्षेत्रों में भी कभी किसी कलेक्टोरेट में आग नहीं लगी थी। लेकिन आपने मैदान में, बलौदा बाजार में, जो रायपुर से 70 कि.मी. दूर है, आप यहां से वहां पर फोर्स नहीं भेज सकते थे ? आपके आई.जी. को दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है, जो इन कामों को देखे। मैं आपसे इस प्रकार कहना चाहता हूँ कि आप इन पर लगाम लगाईये, इनसे काम लीजिए, यह काम करने के लिए हैं। अगर यह काम नहीं करते हैं तो इनको बदल दीजिये, लेकिन यहां पर पता नहीं, इस सरकार में किसकी चलती है? हमें यही पता नहीं है कि यहां रामविचार नेताम जी की चलती है, केदार कश्यप जी की चलती है या उसके पीछे जो बैठे हैं उनकी चलती है। इस सरकार में इधर चलता है, उधर चलता है या यहां जो संविधानेत्तर जो शक्तियां हैं उनकी

चलती है। हसदेव बांगों में अदृश्य शक्तियां पेड़ कटवा देती हैं। यहां पर सब अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, आप इस पर रोक लगाईये। अभी आपकी शुरूआत है। यह भड़काने का काम कर रहे है आप उससे मत भड़कीये। हम लोग तोड़-फोड़ करने वाले नहीं है आपकी सरकार को अस्थिर करने वाले लोग नहीं हैं। आपको जनमत मिला है, भले पर्ची से कोई मुख्यमंत्री बने, हमें कोई लेना-देना नहीं है, आपकी पार्टी की सरकार बनी है। मैं आपसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में आप सरकार चलाईये। हमारा तोड़-फोड़ करने का काम नहीं है, लेकिन आपने विधान सभा से लेकर लोक सभा चुनाव तक इतने लोगों को अपनी पार्टी में मिला लिया है तो कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, लेकिन आप कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी क्यों बना रहे हैं ? (मेजों की थपथपाहट) आप लोग जिसे अपशब्द कह रहे हैं उसे ही भारतीय जनता पार्टी में मिला रहे हैं। आप पूरे देश में यह कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में भी कर रहे हैं। कम से कम माननीय विष्णु जी यह मत करिये। आपसे मेरा यह निवेदन है कि सदन में जो बात कही जाती है, जो घोषणाएं की जाती हैं उनका क्रियान्वयन हो, यह मैं आपसे चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय वित्त मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के खड़े होने पर मेज थपथपाई है, मैंने किसी के भाषण पर मेज नहीं थपथपाई है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें उनसे यह अपेक्षा भी नहीं है। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम अनुपूरक....।

श्री दिलीप लहरिया :- अगर आपने माफी मांग ली होती तो यह बात भी नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय :- मान लीजिए आपने मेज थपथपा भी दी तो यहां पर उसको बोलने की क्या जरूरत है ? (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक कट्टी है कल वह यहां आ जाएंगे या यह वहां चले जाएंगे।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने के पूर्व सदन को वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट एवं राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित कुछ आंकड़े याद दिलाना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 के राज्य के मुख्य बजट का आकार 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रूपये है जिसमें राजस्व व्यय 1 लाख 24 हजार 840 करोड़ रूपये है और जो Capital expenditure (पूंजीगत व्यय) है, वह 22 हजार 300 करोड़ रूपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा है। कुल बजट के साईज के Comparison में 15 प्रतिशत कुल बजट का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट का राजस्व आधिक्य है, वह 1 हजार 60 करोड़ रूपये का है। राजकोषीय घाटा 16 हजार 295

करोड़ रूपये अनुमानित है, जो राज्य के जी.एस.डी.पी. का 2.87 प्रतिशत है। अभी हमारे विपक्ष के सम्मानीय सदस्यों ने बहुत सारे बिन्दु रखें और लोन के विषय पर चर्चा की। यहां पर सदन में कई बिन्दु रखने के प्रयास कियें। मैं इस सदन के सामने यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लोन लेने की भारत सरकार की सीमा है, जो नियम हैं हम, उसका पूरी तरीके से पालन करते हुए, वित्तीय व्यवस्था को संचालित करेंगे और Financially Prudent तरीके से छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था का संचालन होगा। हम सारी गारण्टियों को पूरा करते हुए भी वित्तीय अनुशासन को बनाये रखेंगे। हमारी सरकार माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में यह करके दिखाएगी। जब पूर्व में पहली बार आपकी सरकार थी तो आप भी डाटा देख लीजिएगा कि आपके घोषणा पत्र की तत्काल गारण्टियों को पूरा करने के लिए कितना लोन लेना पड़ा था और अभी हम लोगों ने जितने लोन लिये हैं, उससे डेढ़ गुना से ज्यादा केवल किसानों, माताओं और बहनों के लिए पेमेण्ट करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- ए पहली बार हे कि लोन ले बर मेज थपथपावत हे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वित्तीय अनुशासन है..।

श्री भूपेश बघेल :- क्या आप यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि आपने लोन धान खरीदने के लिए, महतारी वंदन योजना के लिये लिया है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौधरी जी, आप महतारी को, किसान को दीजिए, लेकिन गोठान समिति, राजीव मितान क्लब इस तरह के धोखे से भी मत बनाना। आज टंकराम वर्मा जी बताये हैं कि 57 करोड़ रुपये का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। वैसे गोल-माल के लिए लोन मत लीजियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- पहली बजट आईस तो आप कम्पयूटर में पढ़े, अब कागज में आ गये हैं, मोला हंसी लागत हे, वित्त मंत्री के कने पैसा नई हे। पहले बजट में कम्पयूटर लेकर आये रहव।

श्री ओ.पी.चौधरी :- रामकुमार जी, यह बजट भाषण नहीं है, टीप नोट किया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि जितना हमने लोन लिया है, किसी एक परपज को डिफाइन करके लोन ऐसे नहीं लिया गया है। मैं यह बोलना चाह रहा हूं, जो मैंने कहा है उसको रिपीट कर रहा हूं। जो भी लोन लिया गया है, उससे डेढ गुना ज्यादा हमने केवल इन्हीं बिन्दुओं पर पेमेंट करने का काम किया है। जो सरकार की मंशा को दिखाता है। वह कोई जेब में रखने के लिए, पैसा को उल्टा-सीधा घुमा करके भ्रष्टाचारियों की जेब में पहुंचाने के लिए नहीं लिया गया है, जैसे पहले किया जाता था। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वित्तीय अनुशासन के नाम्र्स हैं, एफ.आर.बी.एम. एक्ट कहता है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी लोन लिया, ठीक है। लेकिन पहले क्या भ्रष्टाचार किया, आप उसको भी बता दीजिए। आप तो सरकार में हैं, जांच कराईये न। आप यह

क्यों बार-बार आरोप लगाते रहते हैं ? जांच कराईये और जांच कराकर सीधा सबूत को रखिये, कार्रवाई करिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अब तो होलोग्राम भी नकली निकल रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सबकी जांच एक ही साथ कराईये।

श्री उमेश पटेल :- आप विपक्ष में थे, आरोप लगाते थे, मान गये।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच भी चल रही है, चार्जशीट भी प्रस्तुत हो गई है और बहुत सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे भी जायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- चार्जशीट प्रस्तुत किये हैं तो उसको प्रस्तुत करिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- और तिजोरी में पैसा भी जा रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, हम लोगों ने एक बार भी नहीं टोका। जो बातें रखनी थीं, आप लोगों ने रखा। आप लोग शांति के साथ में अब हमारे वित्त मंत्री जी को थोड़ा सुन लीजिये। सबके के सब क्यों खडे हो रहे हैं ? इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो रही है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय कौशिक जी, सदन में गुटखा खाकर प्वाईन्ट में नहीं बोला जाता।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- यह असंसदीय है। आप खेद व्यक्त करिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- क्या आपने वह सोने वाली माला पहनी है, जिसका आरोप आप लोग हमारे समय में लगाते थे ?

श्री रामकुमार यादव :- ओकर बर अमेरिका से डॉयरेक्ट आये हे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, बैगा जनजाति की माला है। माननीय सदस्य उसका अपमान कर रहे हैं। वह हमारी आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। .. (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। पिछली बार इसका आरोप लगाकर आपने अपमान किया था।

श्री अनुज शर्मा :- हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई माला उन्होंने पहली हुई है। आदिवासी संस्कृति की शान है। उस माला के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अनुचित है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अनुज भाई आपको पता नहीं है, इसी माला को लेकर आप लोगों ने आरोप लगाया था कि सोने की माला भेंट की गई है। यही बैगा संस्कृति की माला है। आपको पता नहीं है इसलिए मैं बता देता हूं कि इसी माला को लेकर आपकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया था।

श्री रामकुमार यादव :- आप बैगा जनजाति के लंगोट ला घलो पहन लो।

श्री रामविचार नेताम :- सुन लीजिए न। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि दूध का जला छांछ को भी फूंककर पी रहे हैं। आपकी वह हालत है। यह हमारे ट्राइवल संस्कृति का द्योतक है। हमारे बैगा

जनजाति के छात्र आये थे, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, वहां के बच्चे आये थे। श्रीमती भावना बोहरा जी अभी नहीं हैं, उनके क्षेत्र के बच्चे थे। वह बच्चों ने बड़े प्यार से इसको पहनाया है। उसको मैंने बोला कि इतना प्यार से पहनाया है तो इस माला को आज तो पहनने का हक बनता है। इस माला जैसे आपके माला की रही बात तो आपकी माला 50-50 लाख रुपये की थी। उस माला को लेकर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में दिखाया कि यह आपकी कमाई की 50-50 लाख रुपये की माला भूपेश बघेल जी बांटे हैं। यही बात है न।

श्री केदार कश्यप :- माला तो माला, आप लोगों ने रोड भी गुलाब से सजा दी थी, वह भी आप सोच लीजियेगा।

श्री रामविचार नेताम :- वह गुलाब की पंखुडी, जीवन में वैसा नहीं देखा था, उसकी पिक्चर बनी है, उसके हीरो आप ही हो।

श्री उमेश पटेल :- राम विचार जी, आपको वह माला मिला था क्या?

श्री राम विचार नेताम :- क्या मैं कांग्रेस पार्टी का हूं जो मुझको माला मिलेगी। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- भैया, 50 लाख रूपये का माला है, यह आपको कैसे पता चला? आप यह बताईये।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, जैसे गंगाजल का बात असत्य है, वैसे ही 50 लाख की माला का भी एक असत्य इन्होंने पूरा सदन के सामने स्वीकार कर लिया है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह सदन में सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं।

श्री राम विचार नेताम :- यह छत्तीसगढ़ की जनता ने बताया, मैंने नहीं बताया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने माना है।

श्री उमेश पटेल :- नेताम जी, आप क्यों असत्य बोलते हैं? आपको इतना क्यों लग गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चौधरी जी, आप रूकिये मत। आप continue अपना भाषण करिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जी। जो वित्तीय नार्म्स हैं, उसमें एफ.आर.बी.एम. एक्ट में किसी भी राज्य की सरकार को जी.एस.डी.पी. का 3 प्रतिशत तक लोन लेने का अधिकार होता है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में एफ.आर.बी.एम. के नार्म्स को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और आने वाले पांच सालों तक करते रहेंगे। (मेजों की थपथपाहट) दूसरा नार्म्स होता है, जो पंद्रहवें वित्त आयोग ने नार्म्स सेट किया है, उसमें जो टोटल लोन होता है, वह जी.एस.डी.पी. का 25 प्रतिशत तक लोन लेने का नार्म्स है, उसका भी हम अच्छी तरह से पालन करते रहेंगे और पूरे पांच साल तक करके दिखायेंगे, यह मैं आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय वित्त मंत्री जी, मैंने अपने भाषण में जिस बात को रखा है, उसकी मूल भावना यह थी कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उन्होंने इस बात को पूरे प्रदेश में फैलाया कि कांग्रेस की सरकार ने कर्ज लेकर पूरे छत्तीसगढ़ को डूबा दिया है। मैंने इस भावना से बात कही थी। मुझे पता है कि आप एफ.आर.बी.एम. के अंडर में आ रहे हैं, उसको लेकर मैंने बात नहीं की थी। मैंने यही कहा कि आपने 25 हजार करोड़ रूपये का कर्ज ले लिया, जोकि भूपेश बघेल जी के सरकार का पूरे पांच साल का आधा हो जाता है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, अगर आप आब्सेल्युट नंबर में तुलना करेंगे, जब आप 15 साल तक मुख्यमंत्री थे तो आपने 15 साल में मात्र 41 करोड़ रूपये का लोन लिया था। उसका तुलना करेंगे तो अलग-अलग बातें होंगी, लेकिन मैं मूल रूप से बोलना चाह रहा हूं कि आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जी.एस.डी.पी. के 25 प्रतिशत को हम 5 साल तक पालन करके दिखायेंगे, हम एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के लोन में जो जी.एस.डी.पी. है, उसका 3 प्रतिशत का पालन करके दिखायेंगे और डेड टू रेवेन्यू रिसीट का जो रेसियो है, उसे सिंगल डिजीट में मेंटेन करके दिखायेंगे, जबकि सभी स्टेट का एवरेज 12-13 प्रतिशत तक है। यह हम सारे फाइनेंसियल नार्म्स को पूरी तरीके से पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम अनुपूरक के कुछ प्रमुख आंकड़े सदन के समक्ष रखता हूं। प्रथम अनुपूरक बजट का जो टोटल आकार है। यह अनुपूरक बजट है, हम कोई पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इस बीच में हमको कुछ अर्जेंट जरूरतें पड़ी है, उसके आधार पर हम माननीय सदन के समक्ष इस विषय को लेकर आए हैं। अब इन्होंने इसको भी बड़े साईज का बजट बना दिया। हमें बड़ा आश्यचर्य हो रहा था कि बहुत सारे सदस्य यह बोल रहे थे कि यह नहीं है, वह नहीं है। जो मूल बजट है, उसके साथ में जोड़ कर पढ़ा जाता है, हमें बड़ा आश्यचर्य हुआ और हमारे कई जनप्रतिनिधियों के इस तरह के सतही सोच को जान कर बड़ा दु:ख भी हुआ कि केवल 7300 करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट, जिसमें 4900 करोड़ रूपये महतारी वंदन योजना मात्र के लिए है और पुराने बजट को साथ में पढ़े बिना कुछ भी आरोप लगा रहे थे। इस तरह सतही आरोपों से लोकतंत्र नहीं चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा Depth के साथ बात करें जैसा कि बहुत सारे सदस्य बात करते हैं। मैं उनकी सराहना भी करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक बजट में 4900 करोड़ रूपये महतारी वंदन योजना के लिए है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कई सारे विपक्ष के सम्माननीय सदस्य आरोप लगा रहे थे कि महतारी वंदन योजना की राशि केवल तीन जिलों में बंट गया, चार जिलों में बंट गया, उस पर मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस अनुपूरक बजट में कुल 500 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय रखा गया है, जिसमें 125 करोड़ रूपये विद्युत कंपनी का है, वह अलग हट गया। नगरीय प्रशासन विभाग के लिए 130 करोड़ रूपये है, वह अलग चला गया। 50

करोड़ रूपये गृह, पुलिस एवं जेल विभाग के लिए है, वह अलग चला गया तो 500 करोड़ रूपये में लगभग 300 करोड़ रूपये सिर्फ इन तीन विषयों में चले गये, बाकी 200 करोड़ रूपये की राशि जिसको पूंजीगत में निर्धारित किया गया है, उस 200 करोड़ रूपये के लिए विपक्ष के कई सम्माननीय सदस्य अपने सतही सोच के कारण आरोप लगा रहे थे कि 200 करोड़ रूपये 3 जिलों में बंट गया, पूरा बजट बंट गया, पूरा बजट इन्हीं 3 जिलों में चला गया। मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में चला गया । पुल-पुलिया और चंद सड़कें हैं, मूल बजट के साथ जोड़कर इसको पढ़ें । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि 22,300 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय मूल बजट में है और 200 करोड़ रूपये पर यहां पर लांछन लगाया जा रहा था, इस तरह की सतही सोच के सतही लांछन की मैं निंदा करता हूं और भविष्य में अपेक्षा करता हूं कि इस तरह के सतही विचार प्रस्तुत न किये जायें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह निंदा शब्द वगैरह न कहें । सभी विद्वान सदस्य होते हैं । बार-बार सतही भी मत कहिये ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी, अगर मेरा शब्द गलत है तो मैं उसके लिये...।

श्री भूपेश बघेल :- चूंकि आप पहली बार बोल रहे हैं इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि आप निंदा मत करिये । आप निंदा करिये तो निंदा प्रस्ताव लाईये । दूसरी बात यह है कि सतही सोच मत कहिये क्योंकि सारे विद्वान सदस्य होते हैं ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सतही विचार रखे हैं । मैं उसमें निवेदन करता हूं कि ऐसा न हो ।

श्री रामकुमार यादव :- कलेक्टर साहब, हमन भले ही बड़े विचार ला नइ पढ़े हन लेकिन अतेक बड़े सतही वाला, छोटेच वाला नो हन । तुंहर बर हमू मन टक्कर वाला हन।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बार-बार सतही सोच की बात कर रहे हैं । मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक-बार मेरे भाषण को उठाकर देख लीजिये । मैंने उसमें मुख्यमंत्री सड़क और पुल-पुलिया पर ही बात की है। मैंने यह स्पेसिफिक बात कही थी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भाषण दिया उस समय भी यह बात आयी थी और अभी भी माननीय वित्तमंत्री जी भाषण दे रहे हैं तो भी सुझाव आ रहे हैं कि ये विद्वान हैं, वह है, ये शब्द है, माफी मांगनी चाहिए । छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहां पर कई लोगों ने छत्तीसगढ़ी में भी भाषण दिया है । संसद में, मध्यप्रदेश में दोनों जगह कौन-कौन से शब्द संसदीय हैं, कौन-कौन से असंसदीय हैं इसका फिर से निर्धारण किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में संसदीय-असंसदीय शब्द कौन से हैं इसका निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है तो कई लोगों को भी होशियारी मारने का मौका मिल जाता है तो इसलिये आपसे आग्रह है कि चूंकि हम छत्तीसगढ़ी में

भी मुहावरे, लोकोक्ति और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कम से कम एक-बार कांग्रेस के सदस्यों के साथ बैठकर इस बारे में एक कमेटी बनायें कि छत्तीसगढ़ी, हिंदी चूंकि नये शब्द जुड़े हैं, हर साल नये शब्द जुड़ते हैं । मैंने पिछली बार लूट का उदाहरण दिया था उसमें भी आपत्ति हो गयी थी तो एक-बार फिर से निर्धारण हो जाये नहीं तो क्या होगा कि एक पार्टी को, अभी मैं किसी पार्टी का नाम लूंगा तो फिर गड़बड़ हो जायेगा तो एक पार्टी को आलोचना के शब्द भी संशोधित अर्थों में पसंद है इसलिये उसको निर्धारित करने की जरूरत है, यह मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषक उन्नति योजना का अभी बहुत सारी मोदी की गारंटी पर बात हुई । हमारी विष्णुदेव जी की सरकार को मात्र आठवां महीने का समय चल रहा है ऐसी स्थिति में जितनी मोदी की गारंटी पूर्ण की गयी है उसको भी देखना और सदन के समक्ष रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है । 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी की मोदी की गारंटी का वादा विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरा करके दिखाया है और उसके लिये 24 लाख 72,000 से अधिक पंजीकृत किसानों को मात्र 13,300 करोड़ रूपये की अंतर की राशि का भुगतान किया है । (मेजों की थपथपाहट) आज तक के धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए इस सीजन में 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और उसको भी आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरा करके दिखाया है । दो साल के बोनस की बहुत बातें होती हैं, ठीक है उस समय जो भी बात थी लेकिन वर्ष 2018 के घोषणा-पत्र में, कांग्रेस के साथियों ने अपने घोषणा-पत्र में उस दो साल के बोनस को देने का वादा किया था और उस दो साल के बोनस को 5 साल तक नहीं दिया गया था । उसको भी अपने संकल्प पत्र के अनुसार विष्णुदेव साय जी की हमारी सरकार ने पूरा करके दिखाया है (मेजों की थपथपाहट) और 12 लाख किसानों को 3716 करोड़ रूपये का भुगतान इसी 8 महीने में सरकार बनने के, शपथ लेने के 12 दिन के भीतर श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी की जयंती पर जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया । दिनांक 25 दिसम्बर को यह 3716 करोड़ रूपये का भुगतान हमारी सरकार ने किया है । अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन योजना पर तमाम तरह की बातें हुईं। मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगभग 70 लाख से अधिक माताओं और बहनों को 655 करोड़ रूपये प्रति माह भुगतान कर रही है। उस पर भी कई तरह के विचार आये। कई तरह की बातें आईं कि ये गणित कैसे बैठ रहा है? इस तरह की बातें आईं। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी माता और बहनों को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कवर किया गया है, उनको कुल पहले कोई योजना में जो मिल रहा था, कुल उनको 1 हजार रूपये का भुगतान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना देश के अनेक राज्यों में माताओं, बहनों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। अनेक राज्यों में चल रही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन की योजना सर्वाधिक प्रतिशत माताओं बहनों को कवर करती है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के डेटा से

तुलना कर लें। कर्नाटक में हमारे विपक्ष के साथियों के कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां का भी डेटा उठाकर देख लें, मैक्सिमम परसेंटेज का कवरेज छत्तीसगढ़ में है। अध्यक्ष महोदय और यहां पर ये बात रखना अत्यंत आवश्यक है कि वर्ष 2018 के घोषणा पत्र में हमारे कांग्रेस के साथियों ने जब घोषणा पत्र बनाया तो उन्होंने ऐलान किया था कि प्रति माह 500 रूपये की दर से माताओं और बहनों को भुगतान किया जाएगा, लेकिन दुखद है कि 500 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से अगर 60 महीने तक भुगतान किया गया होता तो एक-एक माता-बहनों को 30-30 हजार रूपये मिले होते। अध्यक्ष महोदय, लेकिन कांग्रेस के साथियों ने उन 30-30 हजार रूपये प्रत्येक माता बहन को ठगने का काम किया है और आज यही कारण है कि वे विपक्ष में बैठे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निराश्रित पेंशनधारियों को 500 रूपये का था। आप फिर से गलतबयानी ना करें। जो निर्णय होना था, हो गया जो रिजल्ट आना था, वह आ गया। आप अपनी घोषणा पत्र में आ जाए ।

श्री उमेश पटेल :- इनको भी ज़रा सतही ज्ञान है, लग रहा है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं उसकी प्रति सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। उसमें क्या लिखा है, पूरा सदन पढ़ सकता है। माता-बहनों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान की बात लिखी गई थी। बड़ा दुखद है कि हमारे सम्माननीय विपक्ष के सदस्य भूल भी गए हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- 500 रूपये में सिलेंडर देने की भी बात लिखी गयी थी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- महतारी वंदन योजना में आपके घोषणा पत्र में भी लिखा गया था।

श्री ओ.पी. चौधरी :- महतारी वंदन योजना में बात कर लीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- हर गरीब महिला को 500 रूपये में सिलेंडर।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, वो 15-15 लाख रूपये के बात रहिस। वो 15-15 लाख रूपया ला दे देतव तो का हो जातिस।

श्री देवेन्द्र यादव :- हर गरीब महिला को 500 रूपये में सिलेंडर और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है। सरकारी नौकरी की भी बात हुई थी समयावधि में।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, हाई लेवल के सोच वाला हो, 15-15 लाख रूपये ला कब दिहौ। ले मैं सतही हव। तैं तो बड़का हाई लेवल के हस, तो 15 लाख रूपया ला दो न।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, यादव जी, बैठिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन योजना को लेकर तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करने का भी दुष्प्रयास विपक्ष के साथियों द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि वे बोल रहे थे कि महतारी वन्दन योजना का लाभ

किसको मिला है? किसको नहीं मिला? बहुत तरह से बयान उनकी ओर से मेरी ओर से मीडिया में चल रहा था तो मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में 79,626 माता बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहटी)

श्री रामकुमार यादव :- उहां तो 1 लाख महिला हे, फिर मिसेस ला काबर मिलिस। तुमन तो सब महिला ला देबो कहे रहौ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 1 मिनट। मुझे तो बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी, 1 मिनट, पाटन का आंकड़ा बता रहे हैं तो एक साथ यह भी बता दीजिए कि जो निराश्रित पेंशन पाते हैं और किसी भी तरह के पेंशन पा रहे हैं, उनको आपने घोषणा पत्र में कहीं पर ये नहीं लिखे थे कि इसको मिलाकर देंगे। उनको 500 को नहीं दे रहे हैं वो आंकड़ा भी एक साथ बताइए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, 500 नहीं दिया जा रहा है..।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों मैंने समीक्षा बैठक की थी। ज्यादा दिन नहीं हुआ, 8-10 दिन पहले ही हुआ है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी और फिर फूड विभाग के अधिकारी के साथ। जितने निराश्रित कार्डधारी हैं, जितने अंत्योदय कार्डधारी हैं, जितने प्राथमिकता वाले हैं, यदि इनको जोड़ें तो अकेले पाटन में 40 प्रतिशत महिलाओं को नहीं मिल रहा है। वह मिलना चाहिए था।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय अंत्योदय कार्डधारी, प्राथमिक राशन कार्डधारी इनमें अनेक पुरुष सदस्य ही रहते हैं। एकल सदस्यीय कार्ड भी रहते हैं जो जनसंख्या का प्रोजेक्शन है। अध्यक्ष महोदय, उसमें इस योजना के माध्यम से बहुत बड़े परसेंटेज को कवरेज मिल रहा है और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने गांव में उनका पैतृक गांव बेलौदी, कुरूदडीह वगैरह हैं । वहां पर जाकर 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित माता बहनों को एक साथ बिठा लें और हाथ खड़ा करवाएं तो 90 परसेंट से ज्यादा लोगों के हाथ उठेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने चुनौती दी थी, मेरे गांव न जाएं और आपके गांव न जाएं । रायपुर का देखते हैं, रायपुर के ही वार्ड में चलिए । मैंने तो आपकी चुनौती स्वीकार की थी, रायपुर के किसी वार्ड में चलते हैं ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- किसी भी जगह जाकर 21 साल से अधिक ।

श्री भूपेश बघेल :- हां हां आप व्यवस्था करिये, हम चलते हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- स्वीकार है ।

श्री रामकुमार यादव :- अइसे लागत हे खेत ला बेचके देत हौ ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री जी के गांव की बात कर रहा था, जहां चाहे वहां जा सकते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यहां पर जब आपका घोषणा पत्र सबके घर गया तो वहां सबको यह बोलकर फार्म भरवाया गया कि सभी विवाहित महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा । एक परिवार में एक को ही मिल रहा है और देवरानी, जेठानी में लड़ाई हो रही है, आप लोगों की सरकार के कारण । अभी भी संदूक में संभालकर आपके फार्म को रखे हैं ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, हमने 21 वर्ष से अधिक की विवाहित महिलाओं का क्राइटेरिया बनाया है और 18 वर्ष विवाह की उम्र होती है लेकिन जो भी हमारी आर्थिक योजनाएं होती हैं वे सामाजिक सुधार का भी माध्यम बनें, इस दृष्टि से 21 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई है क्योंकि 18 वर्ष में तो बच्चियां 12वीं पास हो पाती है । 21 साल के बाद उनकी शादी हो, यह योजना उनको नकारात्मक दिशा में प्रेरित करने वाली योजना न बने । हमारी आर्थिक योजना सामाजिक सुधार का भी कारण बने इस दृष्टिकोण से 21 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, केवल दो क्राइटेरिया लगाये गये हैं । वे इंकम टैक्स पेयी नहीं होना चाहिए । उद्योग समूह के मालिक की पत्नी को क्या 1000 रूपए महतारी वंदन मिलना चाहिए, क्या कलेक्टर की वाइफ को 1000 रूपए महतारी वंदन मिलना चाहिए ?

श्री उमेश पटेल :- वित्त मंत्री जी आप जो कह रहे हैं सब ठीक है । लेकिन चुनाव में आप लोगों ने घर घर जाकर कहा कि सबको मिलेगा । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उस समय ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था ।

श्री रामकुमार यादव :- वही ला सोचकर बोलना रहिस, आप तुमन ला दुनिया भर के ज्ञान आ गे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बार-बार खड़ी हो रही हैं, आपको भी चाहिए क्या ? हम वित्त मंत्री जी को बोलेंगे । हम घोषणा करते हैं ।

श्री उमेश पटेल :- अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया ।

श्री रामकुमार यादव :- गरीबी रेखा में नाम नइ हे, छत्तीसगढ़ के डेढ़ करोड़ महिला ला दे बर लागही तुमन ला । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था । सबो झन ला बोले हो । वोमन संदूक में लेकर इंतजार करत हे ।

श्री उमेश पटेल :- आप अपने भाषण में कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग ज्यादा हल्ला करेंगे तो हम 18000 वालों को फार्म लेकर आपके ऑफिस में भेज देंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम वित्त मंत्री जी से पूछ रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं । हमने दो घंटे में कर्जा माफ किया था, हमने हर वायदा पूरा किया था ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र के तहत 5 रूपए का भी भुगतान नहीं किया .....(व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- प्रत्येक विवाहित महिला ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने 500 रूपए में सिलेंडर देने की बात की थी ।

श्री रामकुमार यादव :- कतको ताली बजवाओ, वो महिला मन सब दुखी हे ।

श्री उमेश पटेल :- जो अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वे दूसरों के घोषणा पत्र के बारे में क्या बात करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोगों ने दारू बंद करने का वादा किया, दारू बंद नहीं किया। आपके लोग जेल में सड़ रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- भैया, तभी तो हम लोग इधर बैठे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बड़े-बड़े आई.ए.एस. अफसर और बड़े-बड़े लोग जो सत्ता में भारी लड़ाई करते थे। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपके लोग दारू तो गली-गली में बंटवा रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- अच्छा हम लोग बैठ गये, इधर आ गये ना। अभी वित्त मंत्री जी ने भाषण में....।(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- जो 8 हजार का भरवाए हो, पहले उनका ख्याल रखिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष जी, उधर जाने के बाद भी साढ़े 8 हजार का फार्म भरवा रहे थे।

श्री उमेश पटेल :- एक मिनट। यह अपने भाषण में बार-बार उल्लेख कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में ये नहीं किया, वह नहीं किया, इसलिए यह बात उठ रही है, आपने जो घोषणा पत्र में कहा था, वह बात पूरी नहीं हो रही है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, छन्नी बोले सुई तेरे पे छेद। यह दुनिया का एक नया अजूबा है। इनकी अविश्वसनीयता जनता जनार्दन के बीच इस कदर थी कि साल का एक लाख रूपए खटाखट-खटाखट देंगे। तब भी जनता ने इनको खटाखट करके सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अटल श्रीवास्तव :- वह 405 का क्या हुआ ? (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- ओला देख डारेन। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 405 का नारा दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए।

श्री रामकुमार यादव :- तब तुंहर सरकार के उपर भरोसा नई हे।

अध्यक्ष महोदय :- उमेश जी आप बैठिए प्लीज।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, 270 सीट नहीं जीत पाए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने 405 का नारा दिया था। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी में टिके हे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, इसके पहले आप लोग सब मिलाकर 19 लोग बोले। किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बोले, कोई हस्तक्षेप कहीं से नहीं हुआ। यदि फायनेंस मिनिस्टर जवाब दे रहा है तो हर प्रश्न पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। उनकी बात को सुनिए, यदि बाद में कोई विषय हो, इंटरप्ट कर देंगे। इसलिए कृपा करके पूरी बात सुनिए। जवाब में सारी बातें आ रही है और इस प्रकार हस्तक्षेप कभी नहीं होता कि फायनेंस मिनिस्टर जी बात कर रहे हैं, उनके हर विषय पर प्रश्न पैदा किए जाएं। आप बोलिए और बात समाप्त करिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता जनार्दन के बीच अविश्वसनीयता इस कदर थी कि एक लाख रूपए पर छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों ने इन पर भरोसा नहीं किया, विष्णुदेव साय जी के 12 हजार रूपए पर भरोसा किया। इनके एक लाख रूपए पर भरोसा नहीं किया। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, रेडी टू ईट पर बहुत बात हुई। जिन लोगों ने ठेकेदारों के हाथ में रेडी टू ईट को ईट कराने के लिए सौंपा था, उन लोगों को इस विषय पर बात करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन विष्णु देव साय जी की सरकार है, जो प्रतिबद्ध है कि छत्तीसगढ़ के स्व सहायता समूहों को माता बहनों को यह काम दिया जाएगा और केबिनेट में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। पूरा एक सिस्टम बना करके अच्छे तरीके से संचालित हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कांग्रेस ने जिन ठेकेदारों को सौंपा था, उसे वापस छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों के हाथों में दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास पर भी बहुत तरह की बातें होती हैं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प पत्र है, उसमें हमने वादा किया है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को

प्रधानमंत्री आवास का लाभ देंगे। केन्द्र की मोदी जी सरकार भी इसके लिए समर्पित है। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ आवास बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। आगामी पांच वर्षों में तीन करोड़ आवास बनाने का निर्णय मोदी जी की सरकार ने पुन: किया है। आज ही सेंट्रल का बजट आया है, उसमें अर्बन हाऊसिंग में ही 1 करोड़ घर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रूपए इनवेस्टमेंट की घोषणा सेंट्रल बजट में की गयी है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार को उस समय ACCC डेटा पर भरोसा नहीं हुआ। जो सोशियो इकोनॉमिक (सामाजिक आर्थिक) सर्वे था उसके डेटा पर भरोसा नहीं किया गया। उसमें जो आवास के लगभग 7, 8 लाख हितग्राही थे, उनको इन्होंने आवास के लिए योग्य नहीं माना। मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, यह ACCC का सर्वे कांग्रेस की नेतृत्व वाली, मनमोहन सिंह जी के प्रधान मंत्रित्व वाली, यू.पी.ए. की सरकार ने यह सर्वे कराया था जिसे तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नकार दिया था। अध्यक्ष महोदय, आवास प्लस का जो डेटा था, उस आवास प्लस के डेटा में जो लाखों हितग्राही थे, उस डेटा को भी नहीं माना गया, जबकि आवास प्लस के डेटा को छत्तीसगढ़ के ग्राम सभाओं ने अनुमोदित किया था, जो कि कांग्रेस के ग्राम सभाओं के प्रति अविश्वास को प्रकट करता है । अध्यक्ष महोदय, उसके बाद एक नया सर्वे कराया गया और नया सर्वे कराकर मात्र लाखों लोगों के बजाय 47,090 आवास की लिस्ट बनाई गई, यह तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया । अध्यक्ष महोदय, 47,090 लोगों को विकास योजना फिर से चालू हो रहा है, राजनीतिक शिगूफा पहुंचाने की कोशिश की गई, प्रत्येक को मात्र 25-25 हजार रूपये की एकमात्र किश्त चुनाव के पहले भेजी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गर्व और खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि उन 47,090 हितग्राहियों को भी आदरणीय विष्णु देव साय की हमारी सरकार ने ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आपके पास जानकारी हो तो 47,090 को कौन-कौन से विकासखण्ड या विधान सभा में दिये गये थे, उसको भी पढ़ दीजिए । आपके ऊपर 3 विधान सभा का आरोप लगा रहे थे, उसका पूरा पोल खुल जायेगा और पता लग जायेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन में गलतबयानी न करें । हमने उस डेटा को भी माना, आवास को भी माना, आवास प्लस को भी माना, यह जो 47,090 के जो आंकड़ें हैं, यह उसमें नहीं थे । भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराई है, उसके कारण से यह आंकड़े आये हैं । केवल 47,090 को पैसा नहीं दिया, 7 लाख को पहले पैसा दिया, कुल मिलाकर 7.5 लाख लोगों को पहली किश्त मिली है । आप केवल 47,090 मत बोलिये, 7.5 लाख लोगों को मिला है ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने जो 47 हजार नई सूची तैयार की थी, उसको बिना किसी पूर्वाग्रह के हमारी सरकार 25 हजार के बाद जो 1 लाख रूपये की किश्त होगी, उसे पैसा देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और इन सभी लोगों का आवास बनाने की हमारी गारण्टी है । अध्यक्ष

महोदय, स्वीकृत आवासों के निर्माण हेतु 40 करोड़ 26 लाख रूपये जारी किये जा चुके हैं और शेष राशि 2024-2025 के बजट में 100 करोड़ का प्रावधान है और जो भी शेष राशि होगी उसे हम जरूर व्यवस्था करेंगे । अध्यक्ष महोदय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि बहुत ही भावनात्मक विषय है, आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 का दिन लोकतंत्र की दृष्टि से भारत के लिये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है । भारत सरकार ने 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस घोषित किया है और इस लोकतंत्र की लड़ाई में 19 महीने तक लगातार लोगों ने संघर्ष किया था । अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने संघर्ष किया था, उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि देने का निर्णय, जब आप मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था । अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस का पता नहीं लोकतंत्र के प्रति क्या भाव था, जबकि खुद आपातकाल के लिये माफी मांग चुके हैं, जब आपातकाल गलत था, उसके खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़े थे, उनकी पेंशन बंद क्यों की गई, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, 5 साल तक उनके पेंशन को रोक दिया गया था, जब आदरणीय विष्णु देव साय जी की हमारी सरकार आई है तो हमने निर्णय लिया कि उनके पेंशन को पुन: बहाल भी करेंगे और 5 सालों तक उनको पेंशन नहीं मिला है, एरियर्स की राशि के रूप में भी देंगे, यह निर्णय हमारी सरकार ने किया है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान नहीं था तो हमने आकस्मिकता निधि से इमरजेंसी मानकर सेंक्शन किया है, जब-जब लोकतंत्र के ऊपर कांग्रेस के द्वारा कुठाराघात किया जायेगा, हम इस तरह से ओव्हर एक्टिव होकर वादों को पूरा करेंगे, एरियर्स भी देंगे । जब भी पेंशन को रोकने का काम करेंगे, हम एरियर्स देने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, नेस्लानार योजना वामपंथ के खिलाफ बड़ी मजबूत लड़ाई आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के लीडरशिप में लड़ी जा रही है, केनद्र का भी भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है, इसमें जो फोर्स है, उसको एक्टिव करने के साथ-साथ दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर इन पांच जिलों में नेस्लानार वहां सारी सुविधाओं का विकास किया जा सके, वहां रेसिडेंशियल स्कूल बनाये जा सके, वहां खेल सुविधाओं का विकास किया जा सके, उसके लिये भी इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जनमन योजना इसे भी जो पीवीटीजी हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, देश में 18 ऐसी जनजाति समूहों को चिनहांकित किया गया है । हमारे छत्तीसगढ़ की पॉच जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिहोर और अबूझमाड़िया, इन पॉच जनजाति समूहों के परिवारों को चिह्नांकित किया गया है और उन्हें हर योजना में सेचुरेट करने का काम किया जा रहा है और बड़े हर्ष के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो केन्द्रीय बजट आया है, उसमें प्रधानमंत्री जनजातिय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा आज की गई है, जिसके तहत 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी भाई बहनों के लिए विभिन्न योजनाओं को सेचुरेट करने की, जो भी योजना है, उसे पूर्णता के साथ देने का काम किया जाएगा । हमारी सदस्य अंबिका मरकाम जी अभी सदन में नहीं हैं, वे

मांग कर रही थीं कि उनके क्षेत्र में जो लोग हैं, उस तरह के लोगों को भी विशेष रूप से इसका लाभ मिल पाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है । जो पीवीटीजी बसाहटों के कुछ और जो भी विकास के मुद्दे हैं, उन पर भी प्रावधान किया गया है । ग्रीन ट्रांसपोर्ट केन्द्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा मिशन है । हर सेक्टर में जो ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्त्रोत हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं । एक विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनने के लिए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से हटकर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की ओर जाना अनिवार्य होता है, जिसे आप एथेनॉल के रूप में देखते हैं, जिसे सोलर एनर्जी के रूप में देखते हैं । इस तरह के बड़े इंवेस्टमेंट आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है । इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है और बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का भी एक ब्लॉक मिला है, जो ई.वी. के विकास के लिए और दुनिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरतों के लिए बहुत इंपारटेंट एलीवेंट है । हमको केन्द्र से 240 बसें मिल रही हैं । उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हपलमेंट के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए भी इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों के संधारण के लिए 150 करोड़ रूपए और 3352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो भारत सरकार की अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा आदि योजनाओं से कन्वर्जेंस करके उसे बनाने का काम किया जाएगा । इस तरह के अनेक विकास कार्यों को जो कि इंपार्टेंट थे, उनको लिया गया है । मूल रूप से अनुपूरक बजट बहुत छोटा सा भाग है और वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से अनुपूरक बजट की साईज लिमिट से बहुत बड़ा होना भी नहीं चाहिए । इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिए गए हैं और 7300 करोड़ में से 4900 करोड़ केवल महतारी वंदन योजना के लिए है । मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विकास कार्यों के लिए एक अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास योजना के अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु भी एक छोटा वित्तीय प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए भी ढाई करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है । जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वह पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत हर्ष का विषय है । त्रेता युग में प्रभु श्री राम चन्द्र जी को जो वनवास हुआ था, वह तो 14 वर्ष में समाप्त हो गया था, लेकिन कलयुग में प्रभु श्री राम चन्द्र जी को जो वनवास हुआ, उसे समाप्त होने में येन केन प्रकारेण टेंट में चलते-चलते 500 सालों का समय लग गया । यह कलयुग में हम सबके लिए शर्म का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है । जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्याधाम में हुई है तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो

हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभु श्री राम चन्द्र जी के श्रद्धालू हैं, उनको अयोध्या का दर्शन कराएंगे, उसके लिए इस अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, ताकि हमारे श्री राम चन्द्र जी के प्रदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्या का दर्शन कराया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत विशेष बात हो रही थी कि आईटी सेक्टर में छत्तीसगढ़ क्यों आगे नहीं बढ़ पाया ? इस पर हर बार चर्चा होती है और हम सबके लिए बहुत अनिवार्य विषय है कि छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर का विकास हो, इस दिशा में भी विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार नवा रायपुर प्लग एवं प्ले मॉडल पर काम कर रही है और चंद महीने के भीतर हम लोगों को आईटी में भी जॉब दे पाएंगे और एक वर्ष के भीतर में हजारों की संख्या में हम आईटी सेक्टर में जॉब दे पाने की स्थिति में रहेंगे । बहुत बड़ी कम्पनियां, टेली परफारमेंस जैसे कम्पनियों ने रूचि ली है और रूचि लेकर आज आ रही हैं । छत्तीसगढ़ के इंन्यूबेशन सेन्टर के निर्माण के लिए केन्द्र की मदद से हम नवा रायपुर में एक इंन्यूबेशन सेन्टर की भी स्थापना कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर को, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब सन् 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई थी, तब देश में बड़ी मुश्किल से तीन सौ- चार सौ स्टार्टअपस हुआ करते थे। आज देश में सवा लाख स्टार्टटपस हैं, जिनमें से 120 यूनिकॉन है, मतलब एक बिलियन डालर से अधिक की कम्पनियां बनकर खड़ी हुई है, जो विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नॉलेज बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड इण्डस्ट्री बहुत जरूरी होती है। जब उस दिशा में देश में काम हो रहा है, तो हमारा छत्तीसगढ़ पीछे ना रहे, उस दृष्टिकोण से भी विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार काम कर रही है।

श्री रामकुमार यादव :- कय ठन ला बेचे हा, सरकारी कम्पनी ला बेचे हा, ओखर सूची हे का ? सरकारी कम्पनी ला बेचे वाला सूची नइ हे ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर नालंदा परिसर का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। नालंदा, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में नालेज बेस्ड सोसायटी, ज्ञान आधारित समाज का प्रतीक था। पूरे दुनिया भर के लोग नालंदा, तक्षशीला में पढ़ाई करने के लिए आते थे। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके लीडरशीप में नालंदा यूनिवर्सिटी की पुनर्स्थापना बिहार में की गई है। आने वाले समय में उसे इंटरनेशनल टूरिजम सेन्टर के रूप में भी विकसित करने की घोषणा आज के केन्द्रीय बजट में की गई है। पूरे भारतीय संस्कृति का नालंदा परिसर एक प्रतीक है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर की लायब्रेरियों के निर्माण का काम हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है। इसमें से 13 नालंदा परिसर हमारी सरकार ने पिछले 7 महीने के अल्प समय के बीच में स्वीकृति दे दिया है, जो एक-डेढ़ साल के बीच में धरातल पर दिख जायेगा। कुल 22 ऐसे नालंदा परिसर बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने जो 5 प्रण देश के समक्ष रखे थे, उनमें से एक प्रण औपनिवेशिक विरासतों से मुक्ति है। जो कानोलियन लेगेसी है, उनसे देश को मुक्ति दिलाना है। इस दृष्टिकोण से भारत के जो कानून थे, दुर्भाग्य से पिछले 70 सालों तक वही कानून चलते रहे। चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, भारतीय साक्ष्य संहिता हो, इनमें नये कानूनों को आगे लाया गया है। इस अनुपूरक में उनसे संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब विषयों पर, ये छोटे विषय हैं, परन्तु एक दिशा में, एक विजन के साथ चलते हुए प्रयास हैं, जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी तरह से पूरा कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन कृषक मजदूरों की जो बात आई, उसे भी इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी की सरकार देने का काम करेगी। भर्ती पर बहुत सारे विषय आये हैं। जैसे शिक्षक भर्ती के ही सम्बन्ध में सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब वर्ष 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस बीच में एक लाख एक हजार शिक्षकों की भर्ती की गई थी। पिछले 5 वर्षों में 19 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई है, कम्पेरेटिव डेटा बहुत स्पष्ट है। सदन में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सदन को अवगत कराना चाहता हूं, पूर्णत: विश्वस्त कराना चाहता हूं कि आने वाले 5 सालों में, पिछले 5 सालों की तुलना में बहुत ज्यादा भर्तियां होंगी, पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां होंगी, इस बात का विश्वास सम्माननीय सदस्यों को, सम्माननीय सदन को दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.एस.सी. में घोटाले की बात आई। उस पर सी.बी.आई. जांच का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। सी.बी.आई. जांच करना प्रारंभ कर दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पी.एस.सी. में जो जांच की घोषणा की है, वह एक वर्ष के की है या जो निवृतमान अध्यक्ष श्री टामन सिंह सोनवानी जी के पूरे कार्यकाल की है ? क्योंकि उसके पूरे कार्यकाल में भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी एक ही सेन्टर से 55-56 लोग सलेक्ट हो गये थे। तो मेरा आपसे यह कहना है कि उसके पूरे कार्यकाल की भर्ती की सी.बी.आई. जांच की जाये, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी। सम्माननीय सदस्य की जो मंशा है, उसे सरकार में जरूर विचार कर उचित कार्यवाही करेगी। जो भी गलत किये हैं, उनको जरूर सजा मिलेगी

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, आप अजय चन्द्राकर जी की मांग पर सी.बी.आई. जांच कर रहे हैं, लेकिन सतनामी समाज की मांग पर सी.बी.आई. जांच क्यों नहीं करवाये ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो वित्तीय स्त्रोत हैं, उनके सुधार की बहुत संजीदगी से प्रयास कर रहे हैं। परन्तु 5 साल की लीगेसी इतनी खतरनाक है कि उसको ठीक करने में थोड़ा समय

लग रहा है। हमने जी.एस.टी. में बिजनेस इंटेलीजेंस यूनिट, बीफा साफ्टवेयर जैसी चीजों का उपयोग किया है, जो ई-वे बिल है, उसमें छोटे व्यापारी परेशान ना हो, हम उसकी भी चिंता कर रहे हैं और सिस्टम में सुधार लाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में 2 जी.एस.टी. कमिश्नर ऐसे रहें, जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहां किस तरह की स्थिति रही होगी, उसकी सहज कल्पना की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक्साइज सेक्टर में भी टैक्स के रिफॉर्म्स कर रही है। एफ.एल.टेन को हटाने का काम किया गया है और एक्साईज ड्यूटी में जो परिवर्तन हुए हैं, उसी बेहतर सिस्टम और उन्हीं चीजों के कारण उसमें आने वाले एक साल में साफ तौर पर इन्क्रीमेंट दिख जाएगा। जब सिस्टम को बिगाड़ा जाता है तो भ्रष्टाचारी की जेब में ज्यादा पैसे जाते हैं और सरकार के exchequer में कम पैसे आते हैं। सिस्टम को सुधारा गया है इसलिए के exchequer में ज्यादा पैसे आएंगे और भ्रष्टाचारियों की जेब में कम पैसे जाएंगे। माइनिंग और कोल में जुलाई, 2020 को रॉयल्टी पर्ची का जो ऑफलाईन सिस्टम कर दिया गया था, जो आपके मुख्यमंत्रित्व काल में ऑनलाईन चलता था, उसे फिर से ऑनलाईन करने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में की थी और तत्काल उसकी ऑनलाईन व्यवस्था करके रॉयल्टी की पर्ची जारी करने से पहले जो वसूली की जाती थी, उसे समाप्त किया गया है। अध्यक्ष महोदय, विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में यह सरकार और हम सब लोग हर फ्रंट पर बहुत एग्रेसिव तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं। पूरी सरकार अच्छी तरीके से काम करके दिखा रही है। मितानिनों के लिए डी.बी.टी. करने का काम आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हुआ है और मितनिन बहनों के खाते में अब सीधे पैसे जाएंगे और उनको डीले जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के रिफॉर्म्स केवल विष्णु देव साय जी की हमारी सुशासन वाली सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी विषय में सुधार के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है। पिछले सालों की गलतियों को ठीक करते हुए चाहे राजस्व कलेक्शन का विषय हो, चाहे बेहतर तरीके से एक्सपेंडीचर करने का विषय हो, उस पर हम समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे जिन सदस्यगण ने भाग लिया, उन्हें भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय अजय चंद्राकर जी, आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीया अनिला भेंडिया जी, आदरणीया भावना बोहरा जी, आदरणीया अंबिका मरकाम जी, आदरणीय अनुज शर्मा जी, आदरणीया संगीता सिन्हा जी, आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, आदरणीय रामकुमार यादव जी, आदरणीय नीलकंठ टेकाम जी, आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी, आदरणीय मोतीलाल साहू जी, आदरणीय देवेन्द्र यादव जी, आदरणीय गुरू खुशवंत साहेब जी, आदरणीय राघवेन्द्र कुमार सिंह जी, आदरणीय गजेन्द्र यादव जी और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज की चर्चा में आप सब सम्मिलित हुए और सबने हर तरह से सक्रियता से भाग लिया। हम विष्णु देव साय जी नेतृत्व में सुशासन के लिए संकल्पित हैं और यह डबल इंजन की

सरकार है। सप्लीमेन्ट्री बजट की सीमा रहती है तो जो कुछ छोटे-छोटे विषय आये हैं, आने वाले समय में हम जरूर consider करते हुए उपयुक्त ढंग से उनको implement करेंगे। जहां-जहां जो अनिवार्य विषय आये हैं, उन्हें बजट में शामिल करेंगे और छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते में बढ़ाएंगे। विकसित भारत का संकल्प आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 के लिए लिया है, उसके साथ कदमताल करते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। बार-बार नकारात्मक तरीके से उस विजन डॉक्यूमेंट और विजन के कामों की आलोचना की जा रही थी, उसके लिए मैं सम्माननीय सदन और सम्माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि इसमें आप लोग भी अपनी हिस्सेदारी दें। मैंने आप सभी कांग्रेस के साथियों को भी डी.ओ. लेटर भेजा है। आप लोग छत्तीसगढ़ का विजन और रोड मैप बनाने में निश्चित रूप से अपना contribution दें। short term में चीजें चलती रहेंगी, लेकिन long term और mid term में छत्तीसगढ़ को कहां पहुंचना है और किन चीजों की जरूरत है, इसमें हम आप सबके अनुभवों का भी लाभ लेना चाहते हैं और वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए संकल्प लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत। (मेजों की थपथपाट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 55, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 79 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सात हजार तीन सौ उनतीस करोड़, पैंतीस लाख, बासठ हजार, सात सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं,छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करताहूं किछत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करताहूं किछत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 के 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(09 बजकर 38 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 (श्रावण 02, शक् संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक 23 जुलाई, 2024 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं